अभिव्यक्ति

दैनिक भास्कर, नई दिल्ली, शनिवार, 6 सितंबर, 2025

प्रेरणा

विपरीत परिस्थितियों में कुछ लोग टूट जाते हैं, तो कुछ लोग रिकॉर्ड तोड़ते हैं। - शिव खेड़ा

संपादकीय

इन जीएसटी सुधारों का सकारात्मक प्रभाव होगा

जीएसटी के चार की जगह दो स्लैब्स, दरें घटाना और रोटी (5%) और पराठे (18%) के फर्क को मिटाकर शून्य करना, निजी स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर टैक्स हटाना लेकिन तम्बाकू-उत्पाद, कार्बोनेटेड या कैफीन पेय आदि पर 28 की जगह 40% टैक्स लगाना सरकार की सकारात्मक सोच को बताता है। केंद्र व राज्यों के प्रतिनिधियों वाली लगभग 10.30 घंटे चली जीएसटी कौंसिल की बैठक के बाद इस फैसले पर मुहर लगी। वित्तमंत्री ने कहा भी कि इस बदलाव से होने वाले राजस्व ह्रास को घाटा कहने की जगह रेवेन्यू इम्प्लिकेशन (राजस्व पर असर) कहा जाना चाहिए। सरकार का मानना है कि कंज्यूमर आइटम्स सस्ते होने से खरीदने की मानसिकता बनेगी और एक क्रमिक प्रतिक्रिया में मैन्युफैक्चरिंग का विस्तार होगा, जिससे नौकरियां बढ़ेंगी और जॉब पाने वाला उपभोग में खर्च करेगा। चार स्लैब्स वाले जीएसटी को लेकर उद्योग और वाणिज्यिक जगत में सालों से विरोध था। सरकार की बैठकों में उद्यमी उदाहरण देते थे कि रेस्तरां में अगर मक्खन और ब्रेड अलग-अलग लिया तो जीएसटी कम, लेकिन मक्खन लगा ब्रेड लिया तो ज्यादा। इससे व्यापारियों को जटिलता का सामना करना पड़ता था और भ्रष्टाचार को भी बढ़ावा मिलता था। इन जीएसटी सुधारों का मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड और उपभोग पर सकारात्मक प्रभाव होगा, जो आज जरूरी है।

जीने की राह

पं. विजयशंकर मेहता
humarehanuman@gmail.com

किसी धर्मस्थल में जाएं तो प्रसाद में शांति लेकर लौटें

इस समय प्रबंधन की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि पाठ्यक्रम में चापलूसी और षड्यंत्र- दो विषय जरूरी हैं। ऐसा सिखाया भी जाता है। आगे बढ़ना हो तो चापलूसी के सारे पैंतरे आने चाहिए और शीर्ष पर बने रहने के लिए दूसरों को वहां आने से रोकने के लिए जितना षड्यंत्र करना पड़े, कर डालिए। ऐसे में चाहे आप नौकरी में हों या कारोबार में, दबाव आना ही है। इसके बीच कोई रास्ता निकालना होगा। तो देखने में आया है कि इस समय देश में 75% लोग इनडोर लाइफ को चेंज करना चाहते हैं और कुछ समय के लिए घूमने निकलना चाहते हैं। इसीलिए धार्मिक पर्यटन एक नए रूप में सामने आ रहा है। हमें इसे नियमित बनाना चाहिए। परिवार के साथ धार्मिक स्थलों पर घूमने जाएं और वहां सुख, साधन और शांति- तीनों की तलाश करें। सामान्य प्रक्रिया यह है कि किसी धार्मिक स्थल से जब हम लौटते हैं तो कुछ ना कुछ प्रसाद लेकर आते हैं। तो हमारा प्रसाद यही होना चाहिए कि हम जिस ताजगी के लिए गए थे, उसके साथ शांति भी लेकर लौटे हैं। • Facebook:Pt. Vijayshankar Mehta

नया विचार • गुरुग्राम से आई तस्वीरें डराने वाली थीं

भारत को अधिक से अधिक ग्रेड-ए शहरों की जरूरत है

विकास

चेतन भगत
अंग्रेजी के उपन्यासकार
chetan.bhagat@gmail.com

गुरुग्राम का उदय इसलिए हुआ था, क्योंकि नई दिल्ली अपनी रियल एस्टेट नीति में विफल रही थी। नई दिल्ली दुनिया के उन इने-गिने शहरों में से होगा, जिसने दशकों तक संगठित निजी रियल एस्टेट विकास को रोके रखा। उसकी भूमि और आवास का ज्यादातर कामकाज डीडीए के पास था, जो फ्लैट, शॉपिंग सेंटर और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाता था। 1990 और 2000 के दशक में उदारीकृत और आईटी की प्रधानता वाले भारत की मांग को पूरा करने के लिए ये डीडीए परियोजनाएं न तो पर्याप्त थीं, और ना ही गुणवत्तापूर्ण। भूमि एवं रियल एस्टेट की अप्रासंगिक नीति के कारण दिल्ली उन लोगों के लिए व्यावहारिक नहीं रही, जो ग्रेड-ए ऑफिस या बेहतर नियोजित व उच्च गुणवत्ता वाले आवासों की तलाश में थे। इसी कमी के चलते यूपी में नोएडा और हरियाणा में गुरुग्राम का उदय हुआ। ये दोनों ही दिल्ली की सीमाओं से सटे हैं और दिल्ली में पूरी नहीं होने वाली जरूरतों को पूरा कर रहे हैं। गुरुग्राम और नोएडा- इन दोनों ने ही विकास किया, लेकिन गुरुग्राम आगे निकल गया। इसका बहुत अधिक श्रेय डीएलएफ डेवलपर को जाता है, जिसके जैसी योजना और नजरिया भारत में शायद ही कहीं देखने को मिले। गुरुग्राम के निर्माण ए-ग्रेड के थे, कुछ ऐसा जो डीडीए फ्लैट्स से भरी दिल्ली ने कभी नहीं देखा था। दिल्ली के धनाढ्य महज एक 'कोठी' (छोटा बंगला) की उम्मीद कर सकते थे, लेकिन गुरुग्राम ने गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, हाई-स्पीड लिफ्ट और सेंट्रल एयर-कंडीशनिंग जैसी सुविधाएं दी।

शुरुआत में लोग गुरुग्राम में केवल रहने के लिए आए, लेकिन काम के लिए दिल्ली जाते थे। फिर आया गेम-चेंजर : ग्रेड-ए ऑफिस स्पेसेस- जो न केवल उत्तर भारत, बल्कि शायद समूचे भारत ने कभी नहीं देखे थे। मुंबई के विपरीत दिल्ली में नरीमन पॉइंट जैसा कुछ नहीं था। अपने कुछ पुराने ऑफिस ब्लॉकों के साथ महज कनॉट प्लेस ही दिल्ली में सब कुछ था। दूसरी ओर, गुरुग्राम में चमचमाते ऑफिस, मॉल और रेस्तरां थे। इस खासियत के चलते यह बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप्स, कॉल सेंटर, मीडिया हाउस और चहलपहल भरी व्यावसायिक गतिविधियों का ठिकाना बना। नौकरियां और पैसा आए। मांग आसमान छूने लगी। जल्द ही दिल्ली के लोग भी कामकाज के लिए गुरुग्राम आने लगे।

यह तब की बात है जब दिल्ली-गुरुग्राम हाईवे भी नहीं था। ट्रैफिक जाम हर दिन की आम बात थी। लेकिन हाईवे शुरू होने के बाद भी गुरुग्राम का विस्तार इतना विस्फोटक था कि राजमार्ग पर भी अब हमेशा जाम ही रहता है। और अगर बारिश हो तो अराजकता छा जाती है। पिछले हफ्ते ही सोशल मीडिया पर गुरुग्राम में मीलों तक फैले जाम के ड्रोन फुटेज की बाढ़ आ गई थी। कुछ यात्रियों ने छह घंटे तक फंसे रहने की शिकायत की। उन इलाकों तक की सड़कें डूब गई थीं, जहां बेहद महंगे अपार्टमेंटों में वरिष्ठ मैनेजर और बिजनेस लीडर रहते हैं। भारत के सम्पदा-सृजन का प्रतीक शहर अचानक बदहाल दिखने लगा। यह भारतीयों को याद दिलाता है कि तुम विश्वस्तरीय जीवन का सपना देखने की हिमाकत मत करो, क्योंकि जल्द ही हकीकत से तुम्हारा सामना होगा। गुरुग्राम की समस्या ये है कि वह भारत के मानकों से बहुत बेहतर है। भारत में अच्छी रिहाइश, ऑफिस, नौकरियों और मनोरंजन सुविधा वाले सुनियोजित शहरों की इतनी कमी है कि जब एक गुरुग्राम उभरता है तो पूरा देश उस पर टूट पड़ता है। यह शायद भारत के उन चार या

आज हमारे पास यदि पांच ग्रेड-ए शहर हैं तो हमें पचास और चाहिए। तभी ग्रेड-ए कंपनियां और प्रतिभाएं इन चंद शहरों में सिमटने के बजाय बाहर निकल सकेंगी। नहीं तो हम गुरुग्राम की तरह अराजकता और ट्रैफिक जाम को सहते रहेंगे।

पांच शहरों में से एक है, जहां 2 लाख रुपए प्रतिमाह से अधिक वेतन वाली नौकरियां बहुतायत में हैं। इन चार-पांच महानगरों से बाहर कदम रखते ही कमाई और ए-ग्रेड की इमारतें तेजी से घट जाती हैं। इसमें छोटे कस्बों की बेरोजगारी को भी जोड़ दें, जिसके कारण युवा बड़े शहरों का रुख कर रहे हैं- तो आप गुरुग्राम की ओर खिंचे चले आएंगे।

यदि दिल्ली ने 1990 के दशक में एक समझदारी भरी रियल एस्टेट नीति बनाई होती तो गुरुग्राम कभी बनता ही नहीं। अगर भारत में शहरों को मास्टर प्लान के अनुसार सुनियोजित किया जाता तो कंपनियों को गुरुग्राम, बेंगलुरु, मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित किया जाता। तब इन महानगरों के हालात इतने भयावह नहीं होते। आखिर सौ शीर्ष भारतीय कंपनियों में ऐसी कितनी हैं, जिनके मुख्यालय इन पांच शहरों से बाहर हैं? फिर इसकी तुलना अमेरिका से करें, जहां कॉर्पोरेट मुख्यालय दर्जनों शहरों में फैले हुए हैं।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

विश्लेषण • अपनी छवि बदलने के प्रयास कर रहा संघ

एक व्यापक-वर्ग तक पहुंचने की कोशिशें नजर आ रही हैं

राष्ट्रनीति

नीरजा चौधरी
वरिष्ठ राजनीतिक टिप्पणीकार
neerja_chowdhury@yahoo.com

संघ के सभी सहयोगी संगठनों की समन्वय समिति- जिसमें भाजपा भी शामिल है- की तीन दिवसीय बैठक जोधपुर में शुरू हो चुकी है। इसका मकसद भविष्य की रणनीति बनाना और मोहन भागवत द्वारा एक व्यापक वर्ग तक पहुंचने की कोशिशों के बाद उभरती हुई स्थिति का आकलन करना है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा भी इसमें शामिल हो रहे हैं। संघ के 100 साल पूरे होने के मौके पर विज्ञान भवन में हाल ही में हुई तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला में संघ ने अपनी छवि बदलने और अपने आलोचकों से भी सम्पर्क करने की कोशिश की थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि संघ का अगला चरण एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम होगा- ताकि अधिक से अधिक लोग उसे स्वीकार करें। भागवत की 240 मिनट से अधिक समय तक चली व्याख्यान श्रृंखला से तीन मुख्य बातें सामने आई हैं।

पहली बात यह थी कि इन व्याख्यानों ने भागवत और नरेंद्र मोदी- जो जल्द ही 75 साल के होने वाले हैं- की सार्वजनिक जीवन में सक्रियता सम्बंधी अटकलों को खत्म कर दिया। भागवत के शब्दों से साफ हुआ कि 2029 के चुनाव में भी मोदी ही पार्टी का नेतृत्व करेंगे। भागवत ने संघ और भाजपा के बीच के संबंधों को यह कहते हुए स्पष्ट करने की कोशिश की कि संघ प्रमुख के तौर पर उनका काम शाखाएं चलाना और स्वयंसेवकों को प्रशिक्षित करना है, जबकि भाजपा का काम देश का कामकाज चलाना है और वे सिर्फ तभी परामर्श देंगे, जब उनसे पूछा जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि अगर भाजपा के नए अध्यक्ष का चुनाव संघ को सौंपा जाता, तो वह अब तक यह कर चुका होता।

लेकिन सच तो यह है कि संघ और भाजपा एक-दूसरे के बिना संचालित नहीं हो सकते और यह कल्पना भी नहीं की जा सकती कि भाजपा का नया अध्यक्ष संघ की राय के बिना चुना जाएगा- भले ही नड्डा ने पिछले साल कहा हो कि भाजपा को अब संघ की मदद की जरूरत नहीं। 2024 के चुनाव परिणामों से पता चला था कि चुनाव के समय संघ के पीछे रहने का क्या असर होता है। उसके बाद हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनाव परिणामों से यह भी पता चला कि जब संघ के स्वयंसेवक जमीन पर भाजपा के लिए सक्रिय होकर प्रचार करते हैं तो उसे कितनी बड़ी जीत मिलती है।

पिछले सरसंघचालकों के विपरीत भागवत एक शक्तिशाली और लोकप्रिय प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली भाजपा के साथ काम कर रहे हैं। इससे कुछ चुनौतियां भी सामने आई हैं। उनके व्याख्यानों की दूसरी बड़ी बात यह थी कि उन्होंने मुस्लिम समुदाय तक पहुंच बनाने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मुसलमान भारत के अपने और हमारा हिस्सा हैं। उन्होंने यह भी कहा कि चाहे आप हिंदू, हिन्दवी, भारतीयता या सनातन कहें, ये सब एक ही बात है। भागवत ने यह भी कहा कि संघ अयोध्या जैसे किसी आंदोलन में हिस्सा नहीं लेगा, हालांकि स्वयंसेवक चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। इससे पहले भी भागवत ने हिंदुओं को हर मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजने से मना किया था। पिछले कुछ सालों में भागवत ने मुस्लिम समाज के प्रतिष्ठित लोगों के साथ कई बार बातचीत की है, ताकि एक-दूसरे की स्थिति को बेहतर ढंग से समझा जा सके। और उम्मीद है कि इस तरह की वार्ताएं आगे भी जारी रहेंगी।

भागवत के व्याख्यानों की तीसरी बड़ी बात तीन बच्चों के नियम को बढ़ावा देने के बारे में थी। उन्होंने 'हम दो हमारे तीन' का नारा दिया। यकीनन, यह हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए नहीं हो सकता, क्योंकि यह नियम मुसलमानों पर भी लागू होगा। आज जब दुनिया के कई देशों की आबादी बुजुर्ग होती जा रही है, तो युवा आबादी

संघ के 100 साल पूरे होने पर विज्ञान भवन में हुई व्याख्यान श्रृंखला में संघ ने छवि बदलने और आलोचकों से भी सम्पर्क करने की कोशिश की थी। इससे यह भी स्पष्ट हो गया कि संघ का अगला चरण एक बड़ा आउटरीच कार्यक्रम होगा।

का विचार आकर्षक लग सकता है। लेकिन सभी को अच्छी शिक्षा, पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित किए बिना जनसांख्यिकीय लाभ या डेमोग्राफिक डिविडेंड दूर की बात रहेगी। फिर तीन बच्चों का नियम महिलाओं की पसंद के अधिकार से भी जुड़ा है।

फिर भी भागवत ने महिलाओं तक उस तरह से पहुंच बनाने का प्रयास नहीं किया, जैसा कि कई लोगों को लगा था। उनसे महिलाओं की बड़ी भूमिका के बारे में कई सवाल पूछे गए। उन्होंने इतना भर कहा कि संघ में महिलाएं भी पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करती हैं और राष्ट्र सेविका संघ तो 1936 से ही सक्रिय है। महिलाएं शाखाओं का हिस्सा नहीं हैं। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, वे अब सिर्फ सहायक भूमिका निभाने को तैयार नहीं हैं। आज हर राजनीतिक पार्टी महिलाओं को लुभाने के लिए कोशिशें कर रही है। वे शायद आज देश में सबसे महत्वाकांक्षी समूह हैं। उनकी क्षमता का सही इस्तेमाल किया जाए तो वे एक परिवर्तनकारी शक्ति बन सकती हैं।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

06 सितंबर के अंक से विशेष अनुबंध के तहत सिर्फ दैनिक भास्कर में

इकोनॉमिस्ट ने डोनाल्ड ट्रम्प की लोकप्रियता में भारी गिरावट के बावजूद उनके सामने डेमोक्रेटिक पार्टी की कमजोर चुनौती के कारणों की पड़ताल की है।

The Economist

अब आप इकोनॉमिस्ट के सभी आर्टिकल DB एप पर हर शनिवार पढ़ सकते हैं। डाउनलोड करें डीबी एप।

वर्ल्ड इन ब्रीफ

अफ्रीकी देशों में बहुमंजिला इमारतें बनाने की शुरुआत

अफ्रीका छोटी इमारतों का महाद्वीप है। वहां 150 मीटर से ऊंची केवल 26 बिल्डिंग हैं, जबकि अकेले दुबई में लगभग 300 हैं। पिछले कुछ वर्षों से अफ्रीकी देशों में बड़ी इमारतों के निर्माण ने तेजी पकड़ी है। इनमें सबसे बड़ी बिल्डिंग मिस्र में है। 2024 में लगभग 400 मीटर ऊंची बिल्डिंग काहिरा के बाहर रेगिस्तान में बनी है। जल्द ही आइवरी कोस्ट के व्यावसायिक शहर आबिदजान में 421 मीटर ऊंचे टावर-टूर एफ का निर्माण पूरा होने वाला है।

यूक्रेन के हमलों से रूस में पेट्रोल, डीजल का संकट

पिछले दो साल से तेल रिफायनरियों और डिपो पर यूक्रेन के हमलों से रूस को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अगस्त में यूक्रेन ने रूस की तेल रिफायनरी और वितरण केंद्रों पर एक दर्जन से अधिक हमले किए हैं। यूक्रेन का कहना है, 2025 में उसके 40 प्रतिशत हमले रूसी रिफायनरियों पर हुए हैं। अनुमान है, रूस की बीस प्रतिशत रिफायनिंग क्षमता खत्म हो गई है। पेट्रोल का उत्पादन रोज लगभग दस लाख बैरल कम हुआ है। इससे देश में इस साल पेट्रोल के थोक मूल्य 54 फीसदी बढ़े हैं।

ब्रिटेन ने दो साल में तैयार कर लिया सुपरकम्प्यूटर

2023 में ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने ब्रिटेन को साइंस, टेक्नोलॉजी की महाशक्ति बनाने का इरादा जताया था। इसके बाद सुपरकंप्यूटर इसामबार्ड एआई खरीदा गया। ब्रिस्टल सुपरकंप्यूटिंग सेंटर के डायरेक्टर मेकिंटॉश स्मिथ कहते हैं, दुनिया में चैटजीपीटी की चर्चा थी। लेकिन ब्रिटेन में एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर शून्य था। सुपरकंप्यूटर बनाने में चार-पांच साल लगते हैं। इसामबार्ड को दो साल से कम में बना लिया गया है। यह दुनिया का 11वां सबसे तेज कम्प्यूटर है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

राजनीति विपक्षी डेमोक्रेटिक पार्टी भ्रम की शिकार, वहीं रिपब्लिकन का ट्रम्प को पूरा सपोर्ट

ट्रम्प की लोकप्रियता माइनस में, लेकिन डेमोक्रेट्स में एक राय नहीं होने से आगामी चुनावों में वे ही मजबूत

अधिकतर अमेरिकी मानते हैं कि एक व्यक्ति का शासन नहीं होना चाहिए। वे इस बात से भी सहमत हैं कि उनकी केंद्र सरकार धीमी और अक्षम है। जाहिर है, ऐसी स्थिति में किसी राजनेता के लिए अपने तरीके से सरकार चलाना मुश्किल होगा। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ऐसा कर रहे हैं। वे शहरों में सेना भेज रहे हैं, टैरिफ लगा रहे हैं, रिजर्व बैंक को काबू में करने की कोशिश में लगे हैं, कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बढ़ा रहे हैं। नागरिकों को डरा रहे हैं। इससे लोकप्रियता में गिरावट आई है। उनकी रेटिंग निगेटिव यानी -14% हो चुकी है।

ज्यादातर अमेरिकी ट्रम्प से असहमत हैं। सवाल ये है ट्रम्प मनमानी कैसे कर रहे हैं। एक जवाब तो है कि वे उन्हें नियंत्रित करने वाली ताकतों से तेज फैसले करते हैं। जून में लॉस एंजिलिस में सेना तैनात करने के फैसले की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट विचार कर रहा है। उधर ट्रम्प शिकागो में ऐसा करने की तैयारियों में हैं।

एक अन्य कारण है कि रिपब्लिकन पार्टी ने ट्रम्प को अपनी मर्जी से काम करने की छूट दी है। पार्टी में उनके समर्थन में रेटिंग 90% है। पार्टी का विचार है कि ट्रम्प हमेशा सही होते हैं। कंपनियां, विश्वविद्यालय या मीडिया जैसे स्वतंत्र संगठन उनका विरोध कर सकते हैं।

ट्रम्प के एकतरफा बर्ताव को देखते हुए डेमोक्रेटिक पार्टी पर अधिक जिम्मेदारी है। लेकिन वह भ्रमित है। पार्टी में कोई वामपंथ पर तो कोई मध्यमार्ग पर चलने की बात करता है। पार्टी के साफ संदेश के अभाव में मूल समर्थक गुस्सा हैं। ट्रम्प की रेटिंग निगेटिव है लेकिन वे डेमोक्रेटिक पार्टी से अधिक पॉपुलर हैं।

डेमोक्रेटिक पार्टी ट्रम्प को कम आंकती है। ट्रम्प चतुराई से उन्हें जाल में फंसा रहे हैं। फेडरल कर्ज की सीमा बढ़ाने के मामले में डेमोक्रेट्स को विदेशी मदद में कटौती और सरकार ठप करने में से किसी रास्ते को चुनना पड़ेगा। शहरों में अपराध से लड़ने के लिए सेना भेजने का मामला पेचीदा है। पार्टी सरकार के बढ़ते दखल का विरोध करेगी तो ट्रम्प उन्हें अपराधियों का समर्थक बता देंगे। डेमोक्रेटिक पार्टी के कई नेताओं की सोच सही है कि ट्रम्प से अमेरिका के लोकतांत्रिक मूल्यों को खतरा है। लेकिन उन्हें स्वयं से भी पूछना चाहिए कि वोटर एक व्यक्ति का शासन कायम करने की कोशिश में लगे राष्ट्रपति के बजाय उन्हें क्यों अतिवादी मानते हैं?

मध्यावधि चुनाव पर बहुत कुछ निर्भर

संसद के मध्यावधि चुनाव एक साल दूर हैं। इस सदी में प्रतिनिधि सदन के 12 में से 10 चुनावों में वोटरों ने राष्ट्रपति की पार्टी का विरोध किया है। यदि डेमोक्रेटिक पार्टी इन चुनावों में जीत जाए तो ट्रम्प पर नियंत्रण किया जा सकता है। हालांकि चुनाव क्षेत्रों को नए सिरे से तय करने के कारण इतने अधिक अलोकप्रिय राष्ट्रपति के 2026 में हारने की संभावना नजर नहीं आती है।

डेमोक्रेटिक पार्टी पिछड़ रही है

वोटर डेमोक्रेट्स पर हेल्थ केयर, पर्यावरण और लोकतंत्र के मामले में सबसे ज्यादा यकीन करते हैं। लेकिन अपराध और इमिग्रेशन जैसे मुद्दों पर वे रिपब्लिकन पार्टी के साथ हैं। रिपब्लिकंस ने अश्वेतों और युवाओं के बीच स्थिति मजबूत की है। श्वेत कामगार वर्ग डेमोक्रेट्स से अलग हो चुका है। हालांकि सबसे अधिक शिक्षित वोटर उन्हें पसंद करते हैं।

विरोधियों के खिलाफ ट्रम्प सख्त

ट्रम्प अपने विरोधियों, आलोचकों से बदला लेते हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपतियों पर स्वतंत्र विशेषज्ञों और कैबिनेट का प्रभाव रहता था। अब राष्ट्रपति के दफ्तर में बॉस से सहमति जताने वाला ही विशेषज्ञ है। आलोचकों को निकाल दिया जाता है। विरोधियों को दरकिनार कर दिया है। व्यवसायियों को दंडित किया गया है। विरोधियों की जांच होती है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

अर्थव्यवस्था

बगदाद में अब तेजी से हो रहे हैं निर्माण कार्य

कई वर्ष तक युद्ध का कहर झेलने वाले इराक में इन दिनों जमकर निर्माण हो रहा है। राजधानी बगदाद में विशाल क्रेनें नजर आती हैं। इराक में राजनीतिक स्थिरता ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित किया है। प्रधानमंत्री मुहम्मद अल सूडानी बताते हैं, वर्षों के युद्ध, अस्थिरता के बाद सरकार की सेवाओं और इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार की बड़ी योजनाएं हैं। 2022 में सूडानी सरकार ने सत्ता में आने के बाद बगदाद में 20 नए पुल बनाए हैं। चार नए अस्पताल खुले हैं। 1700 से अधिक स्कूल खुले हैं। आधा दर्जन बड़े होटल शुरू होने वाले हैं। ब्रिटिश पेट्रोलियम, एक्सॉन मोबिल और शेवरॉन जैसी बड़ी तेल कंपनियां काम शुरू करने वाली हैं। सरकार प्राइवेट-पब्लिक पार्टनरशिप के तहत कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स आगे बढ़ा रही है। इराक की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी अमवाज के चेयरमैन नमिर कहते हैं, जो काम एक या दो साल में होते थे, अब वे कुछ दिन में निपटते हैं। कंपनी बगदाद में कई बड़ी बिल्डिंग्स बना रही है। सुरक्षा की स्थिति बेहतर होने से निवेश बढ़ा है। तेल की पूरी आय अब देश पर खर्च हो रही है। लेकिन इराक में सरकारी कर्मचारियों की संख्या आबादी के अनुपात में ज्यादा है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

ओपिनियन मेटा, गूगल, अमेजन, एपल को नुकसान, छोटे स्टार्टअप को फायदा

इंटरनेट सेंसरशिप से टेक कंपनियों को नुकसान

अर्थशास्त्री फ्रांसिस केर्नक्रॉस ने 1997 में घोषणा की थी कि टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ने कारोबार व निजी जीवन के लिए भूगोल और दूरियों को बेअसर कर दिया है। इंटरनेट सेंसरशिप से प्रभावित चीन को छोड़कर दूरी अर्थहीन रह गई थी। लेकिन आज दूरियों की वापसी हो गई है।

अब कई देशों में सोशल मीडिया पर रोक के कानून लागू हो रहे हैं। यूरोपियन यूनियन (ईयू) ऑनलाइन कॉमर्स, एआई के लिए नियम बना रही है। ईयू कंटेंट न हटाने के लिए एक्स पर जुर्माना लगा सकती है। अप्रैल में एपल और मेटा पर डिजिटल मार्केट्स एक्ट का पालन न करने के लिए जुर्माना लगाया है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे कई देश ऐसे कानूनों पर विचार कर रहे हैं।

दूरियों की वापसी से एपल, मेटा, अल्फाबेट, अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनियां सर्वाधिक प्रभावित होंगी। इनके बिजनेस मॉडल हर जगह एक तरीके से काम करते हैं। इनके पालन का खर्च मामूली रहता है। ऑनलाइन दुनिया राष्ट्रीय व क्षेत्रीय इंटरनेट में विभाजित हो गई है। इससे इन कंपनियों के सामने लागत सीमित रखने जैसी चुनौतियां हैं। 2023 में कनाडा ने सर्च रिजल्ट पर इंटरनेट कंपनियों के लिए मीडिया कंपनियों को पैसा देने का कानून बनाया। गूगल ने सरकार के फंड को 635 करोड़ रु. दिए। मेटा ने धन देने के बजाय कनाडाई यूजर्स के फेसबुक, इंस्टाग्राम अकाउंट्स पर न्यूज साइट्स ब्लॉक कर दीं। कनाडा के नियम ऑस्ट्रेलिया के ऐसे कानून पर आधारित हैं।

पांच बड़ी टेक कंपनियों की 25-60% आय अमेरिका से होती है। बड़े देशों में चीन जैसी सेंसरशिप लगे तो टेक कंपनियों के लिए संबंधित क्षेत्र छोड़ना बेहतर होगा। 2023 के बाद से अल्फाबेट, एपल, मेटा और माइक्रोसॉफ्ट को यूरोप में अपने एआई टूल्स लॉन्च करने में कई माह की देर हुई है। इससे छोटी प्रतिद्वंद्वी कंपनियों को मार्केट में हिस्सेदारी का मौका मिल सकता है।

मेटा ने 970 करोड़ रु. खर्च

पिछले साल मेटा ने यूरोप में नियमों का पालन करने की लागत का ब्योरा दिया है। उसने बताया कि अपने प्रोडक्ट में जरूरी बदलाव के लिए दो साल में 11 हजार से अधिक कर्मचारियों ने 05 लाख 90 हजार घंटे इंजीनियरिंग और टेक्निकल काम किया है। मेटा कर्मचारियों के वेतन को जोड़ें तो इतने काम का खर्च 970 करोड़ रुपए है।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

माइग्रेंट्स ट्रम्प की सख्ती का असर

अमेरिका में चीनी माइग्रेंट्स को शरण देने के मामले अब कम होते जा रहे

इमिग्रेशन कस्टम्स विभाग (आईसीई) की सख्ती से अवैध रूप से अमेरिका पहुंचे आप्रवासी चिंतित हैं। इनमें बड़ी संख्या में चीनी भी शामिल हैं। 2024 में मैक्सिको की सीमा से चीनी नागरिक आह गान अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ अमेरिका पहुंचे हैं। उन्हें वापस भेजे जाने का डर सता रहा है। इनमें अमेरिका की दक्षिणी सीमा से आए 67 हजार चीनी माइग्रेंट्स में शामिल हैं। इनमें से कुछ लोग राजनीतिक प्रताड़ना, कुछ अवसरों की तलाश में पहुंचे हैं। अवैध रूप से सीमा पार करने के बावजूद सभी लोगों ने शरण के लिए आवेदन किया है। उन्हें उम्मीद है कि वे भी अमेरिका में रह रहे 22 लाख चीन इमिग्रेंट्स में शामिल हो जाएंगे।

चीनियों का आना पहले से कम हो गया है। दिसंबर 2023 में लगभग छह हजार चीनी माइग्रेंट्स हर माह मैक्सिको की सीमा से आते थे। इस वर्ष जुलाई में केवल 80 लोग आए।

अमेरिका में चीनियों को शरण देने की संख्या में कमी आई है। 2023 में 50% चीनी आवेदकों को शरण मिली थी। मई 2025 में यह 20% रह गई। माइग्रेंट्स चीनियों को देश भेजने के मामले भी कम हुए हैं।

चीन सहयोग नहीं करता

चीनी माइग्रेंट्स के वकील चेन चुआंगचुआंग कहते हैं, चीन डिपोर्ट किए लोगों को लेने से इंकार तो नहीं करता है। लेकिन सहयोग भी नहीं करता है। ट्रम्प ने आप्रवासियों को वापस भेजने के लिए टैरिफ का इस्तेमाल किया है। लेकिन चीन के खिलाफ ऐसा नहीं किया गया।

© 2022 The Economist Newspaper Limited. All rights reserved

https://t.me/AllNewsPaperPaid

दैनिक इबादत सम्पादकीय

जीएसटी सुधार

सरकार ने चार स्लैब की जटिलता खत्म कर केवल दो दरों - 5% और 18% को लागू किया है। रोजमर्रा की वस्तुएं, स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा टैक्स से मुक्त कर दी गई हैं। वहीं तंबाकू और लग्जरी वस्तुओं पर 40% कर लगाया गया है। यह कदम बताता है कि सरकार की प्राथमिकता गरीब और मध्यम वर्ग की जेब पर बोझ घटाना है, जबकि अपव्ययकारी उपभोग और अस्वस्थ आदतों को हतोत्साहित करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में यह वादा किया था कि देशवासियों को दिवाली से पहले 'नेक्स्ट जेनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स' का तोहफा मिलेगा। आज यह वादा हकीकत बन चुका है। उन्होंने इसे ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि इससे किसान, मध्यम वर्ग, महिला, युवा और छोटे व्यवसाय सभी को लाभ होगा। नए बदलाव का सबसे बड़ा असर आम परिवारों की जेब में महसूस होगा। अब दूध, रोटी, पिज्जाव ब्रेड, पराठा, छेना जैसी आवश्यक खाद्य वस्तुओं पर कोई कर नहीं लगेगा। जीवन रक्षक दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को भी टैक्स से मुक्त किया गया है। इससे लाखों परिवारों को स्वास्थ्य खर्च के बोझ से बड़ी राहत मिलेगी। बीमा सेवाओं को जीएसटी से मुक्त करने का असर व्यापक होगा। पहले स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर 18% जीएसटी लागू होता था, जिससे प्रीमियम महंगा हो जाता था। अब यह हट जाने से बीमा हर वर्ग की पहुंच में आएगा और स्वास्थ्य सुरक्षा का दायरा व्यापक होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट कहा कि व्यक्तिगत जीवन बीमा पॉलिसी, चाहे वह टर्म लाइफ हो, यूलिप हो या एंडोमेंट पॉलिसी, और सभी व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर अब कोई जीएसटी नहीं लगेगा। कहना होगा कि यह कदम प्रधानमंत्री मोदी की उस दृष्टि को पुष्ट करता है, जिसमें हर भारतीय परिवार को आर्थिक और स्वास्थ्य सुरक्षा देने का संकल्प शामिल है। भारत ने 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य तय किया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए सरल, पारदर्शी और भरोसेमंद कर प्रणाली अत्यंत आवश्यक है। नए जीएसटी सुधार विदेशी निवेशकों के लिए भारत को और आकर्षक बनाएंगे। दूसरी ओर घरेलू खपत बढ़ने से जीडीपी में तेजी आएगी। उम्मीद करें कि केंद्र-राज्यों के बीच सहमति से लागू यह सुधार संघीय ढांचे की मजबूती का प्रमाण बनेंगे। उद्योग जगत के लिए यह सुधार नई संभावनाएं खोलता है। वस्त्र उद्योग, जो 4.5 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार देता है और निर्यात में 11 प्रतिशत योगदान करता है, घटे कर से प्रतिस्पर्धात्मक बनेगा। नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में सौर पैनल और उपकरण सस्ते होने से हरित ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर, जो भारत के जीडीपी में 7 प्रतिशत और कुल विनिर्माण में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है, छोटे वाहनों पर टैक्स में कमी से डिमांड में इजाफा देखेगा। इन तीनों क्षेत्रों में रोजगार और उत्पादन की नई लहर उठ सकती है। सरकार का यह कदम वैश्विक परिदृश्य में भी रणनीतिक महत्व रखता है। घरेलू मांग को मजबूत करना और आंतरिक खपत को प्रोत्साहित करना भारत की सबसे बड़ी ताकत साबित हो सकता है।

जीएसटी पर सियासत या राहत

- डॉ सत्यवान सौरभ

भारतीय कर व्यवस्था में वर्ष 2017 से लागू हुआ जीएसटी यानी 'गुड्स एंड सर्विस टैक्स' उस समय एक ऐतिहासिक सुधार माना गया था। इसे 'एक देश, एक टैक्स' की संकल्पना के रूप में प्रस्तुत किया गया और जनता को विश्वास दिलाया गया कि इससे कर व्यवस्था सरल होगी, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और व्यापारियों को सुविधा मिलेगी। शुरुआत में ही सरकार और उसके आर्थिक सलाहकारों ने ऊँचे टैक्स की दरों को जायज़ ठहराते हुए बताया था कि यह राष्ट्रहित में है और दीर्घकाल में इससे राजस्व बढ़ेगा, विकास दर तेज़ होगी तथा राज्यों को भी मज़बूती मिलेगी। लेकिन बीते नौ वर्षों में जनता ने देखा कि जीएसटी का बोझ केवल आम उपभोक्ताओं पर बढ़ता गया। ज़रूरी सामानों से लेकर रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स दरें ऊँची बनी रहीं। महँगाई लगातार बढ़ती रही और हर घर का बजट बिगड़ता गया। व्यापारी समुदाय ने भी कई बार शिकायत की कि जीएसटी की जटिल व्यवस्था और ऊँचे टैक्स स्लैब ने उनके कारोबार को प्रभावित किया। छोटे और मझोले उद्योगों को तो कई बार अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी। अब अचानक वही सरकार यह कह रही है कि जीएसटी की दरें घटाई जाएंगी और इससे जनता को सीधी राहत मिलेगी। नवरात्र के अवसर पर इस घोषणा को 'टैक्स राहत की दिवाली' कहा जा रहा है। निश्चित ही यह कदम आम उपभोक्ता के लिए सुकून भरा संदेश है। जूते, कपड़े, टीवी, डीटीएच जैसी वस्तुओं पर टैक्स घटाना हर परिवार को सीधे प्रभावित करेगा। लोग त्योहारों के समय खरीदारी कर पाएंगे और बाज़ार में चहल-पहल बढ़ेगी। लेकिन सवाल यह उठता है कि जो तर्क पहले ऊँचे टैक्स के समर्थन में दिए गए थे, वही तर्क आज घटाने के समर्थन में क्यों दिए जा रहे हैं? यह विरोधाभास केवल टैक्स दरों तक सीमित नहीं है। यह सरकार की आर्थिक नीतियों की सोच पर भी सवाल खड़े करता है। अगर ऊँचे टैक्स ही विकास का आधार थे, तो नौ साल बाद अचानक उन्हें कम करना कैसे विकास के लिए आवश्यक हो गया? और यदि वास्तव में कम टैक्स से बाज़ार और जनता को राहत मिल सकती है, तो इतने वर्षों तक जनता को ऊँचे टैक्स का बोझ क्यों झेलना पड़ा? आम नागरिक इन सवालों का जवाब चाहता है। वह देख रहा है कि टैक्स नीतियाँ कई बार राजनीति और चुनावी रणनीतियों से जुड़कर बदल जाती हैं। त्योहारों के अवसर पर टैक्स कटौती की घोषणा निश्चित रूप से लोगों को आकर्षित करती है, लेकिन क्या यह दीर्घकालिक समाधान है? कर नीति को समय-समय पर बदलना और हर बार इसे जनता के हित में बताना, पारदर्शिता और विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करता है।

आज जब सरकार कहती है कि टैक्स घटाने से अर्थव्यवस्था को मज़बूती मिलेगी, तो यह बात सही भी है। टैक्स बोझ कम होने पर लोगों की क्रयशक्ति बढ़ती है, उपभोग बढ़ता है और बाज़ार में रौनक आती है। इससे उत्पादन बढ़ता है और रोजगार सृजन भी होता है। लेकिन फिर वही प्रश्न-तो इतने वर्षों तक टैक्स ऊँचे रखकर किस उद्देश्य को साधा गया? क्या उस दौरान जनता केवल राजस्व संग्रह की मशीन बनकर रह गई? सच्चाई यह है कि भारत जैसे विकासशील देश में कर नीति केवल राजस्व जुटाने का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह सामाजिक-आर्थिक संतुलन का आधार भी होनी चाहिए। ज़रूरी सामानों और रोज़मर्रा की वस्तुओं पर टैक्स बोझ कम से कम रखा जाना चाहिए ताकि गरीब और मध्यम वर्ग को राहत मिले। जबकि विलासिता की वस्तुओं पर अपेक्षाकृत ऊँचे टैक्स लगाए जा सकते हैं। लेकिन पिछले वर्षों में हमने देखा कि कई बार यह संतुलन बिगड़ गया और आम नागरिक की जेब पर सीधा असर पड़ा। यह भी ध्यान देने योग्य है कि टैक्स में राहत से सरकार के राजस्व पर भी असर पड़ता है। जब राजस्व घटता है तो सरकार या तो घाटा बढ़ाती है या फिर कहीं और से वसूली करती है। ऐसे में जनता को राहत वास्तव में कितनी मिलती है, यह भी एक बड़ा प्रश्न है। यदि बिजली, ईंधन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं पर सीधे या परोक्ष रूप से टैक्स का बोझ बना रहेगा, तो बाकी वस्तुओं पर टैक्स घटाने का असर सीमित ही होगा। जीएसटी के नाम पर जिस 'एक देश, एक टैक्स' का सपना दिखाया गया था, वह आज भी अधूरा है। अलग-अलग वस्तुओं पर अलग-अलग स्लैब, राज्यों की शिकायतें, जटिल रिटर्न फाइलिंग और बार-बार नियमों का बदलना, ये सब मिलकर इसे जटिल बनाते रहे हैं। अब जबकि टैक्स दरों को घटाने का निर्णय लिया गया है, तो ज़रूरत इस बात की है कि इसे केवल त्योहारों तक सीमित राहत न बनाया जाए, बल्कि पूरी व्यवस्था को स्थिर और संतुलित बनाया जाए। सरकार को चाहिए कि वह टैक्स नीतियों को राजनीति से ऊपर उठाकर, दीर्घकालिक आर्थिक दृष्टि से तय करे। लोगों को यह महसूस होना चाहिए कि टैक्स वास्तव में राष्ट्र निर्माण में उनका योगदान है, न कि केवल बोझ। इसके लिए आवश्यक है कि टैक्स से मिलने वाले राजस्व का सही और पारदर्शी उपयोग हो। यदि जनता देखेगी कि उसके द्वारा दिए गए टैक्स का उपयोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आधारभूत संरचना पर हो रहा है, तो वह टैक्स चुकाने में संकोच नहीं करेगी। आज की टैक्स राहत का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही यह सवाल भी उठाना ज़रूरी है कि क्या यह केवल तात्कालिक आकर्षण है या फिर एक दीर्घकालिक सुधार की शुरुआत। जीएसटी जैसे बड़े सुधार को राजनीति और चुनावी लाभ से जोड़कर देखने के बजाय इसे जनता और अर्थव्यवस्था के वास्तविक हित में आगे बढ़ाना होगा। तभी वास्तव में 'टैक्स राहत की दिवाली' हर नागरिक के जीवन में रोशनी ला सकेगी।

(रिसर्च स्कॉलर इन पोलिटिकल साइंस, दिल्ली यूनिवर्सिटी, कवि, स्वतंत्र पत्रकार एवं स्तंभकार)

जीएसटी का नया दौर - कराधान व्यवस्था क्रांति की ओर

मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू करके पहले ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब इसे और सरल बनाना तथा दो स्लैब्स तक सीमित करना एक क्रांतिकारी सुधार है। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर बोझ घटेगा, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था का असली इंजन जनता की जेब है। जब उपभोक्ता को राहत मिलती है, उसके हाथ में थोड़े अधिक पैसे बचते हैं, तो खपत बढ़ती है।

- ललित गर्ग -

भारतीय कराधान व्यवस्था में जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) का आगमन एक ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी कदम था। इसने अप्रत्यक्ष करों के जटिल और उलझे जाल को जहां सरल बनाने का प्रयास किया, वहीं शासन एवं प्रशासन में पसरे भ्रष्टाचार एवं अफसरशाही को भी काफी सीमा तक नियंत्रित किया। सुधार, सुविधा एवं जनता को राहत देने के लिये किये इस प्रयास के बावजूद इसमें अनेक जटिलताएं एवं भारी-भरकम कराधान जनता को बोझिल किये हुए था, इस बात को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सरकार लम्बे समय से महसूस कर रही थी, इसीलिये इसवर्ष स्वतंत्रता दिवस के लालकिले के उद्बोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने जीएसटी को अधिक सुगम एवं जनता के हित में करने की घोषणा की। अब सरकार ने इसे और सुसंगठित करते हुए केवल दो स्लैब्स में कराधान को समेट दिया है और कर भी काफी कम कर दिये हैं तो निश्चय ही यह उपभोक्ताओं और कारोबारियों दोनों के लिए राहतकारी है। इसमें मिडल एवं लोअर क्लास का व्यापक ध्यान रखते हुए उन्हें राहत दी गयी है, जिससे हर परिवार के पास ज्यादा खर्च करने लायक आमदनी बचेगी और लोग अन्य वस्तुओं एवं सेवाओं पर अधिक खर्च कर सकेंगे। इन बड़े एवं क्रांतिकारी सुधारों से खपत बढ़ेगी, विकास को तीव्र गति मिल सकेगी। निश्चित ही यह एक नए कराधान युग का सूत्रपात है, जिसमें कर प्रणाली अधिक पारदर्शी, सरल और उपयोगी बनने की ओर अग्रसर है। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद घोषित जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू करने करने की घोषणा की गई है। जिसमें अब 12 व 28 फीसदी के दो स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5 व 18 फीसदी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों की कड़ी में एक नई पहल एवं आयाम है, जिससे जीएसटी को तार्किक बनाने व आम जनता को महंगाई से राहत देने का प्रयास हुआ है। वहीं दूसरी ओर विलासिता आदि वस्तुओं के लिये चालीस फीसदी का एक नया स्लैब जोड़ा गया है। विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है, तो सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। जीएसटी के बड़े सुधार को लेकर विपक्ष और विशेषत: कांग्रेस एवं भाजपा के बीच जो आरोप-प्रत्यारोप शुरु हुआ है, वह इसलिये औचित्यहीन, अतार्किक एवं व्यर्थ है, क्योंकि जीएसटी परिषद ने लम्बी विवेचना एवं आम सहमति से यह फैसला लिया है। वहीं कुछ अर्थशास्त्री इस कदम को ट्रंप के टैरिफ वॉर के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया सुरक्षात्मक कदम मानते हैं। जिससे घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात घाटे को कम किया जा सकेगा। वहीं कुछ लोग इसे नवरात्र में दिवाली से पहले सरकार का तोहफा बता रहे हैं। अनेक कर दरों की जटिलता उपभोक्ताओं के लिए हमेशा भ्रम और बोझ का कारण रही। बार-बार की दर-संशोधन प्रक्रियाओं से व्यापार जगत में असमंजस की स्थिति बनी रहती थी। अब दो स्लैब्स की व्यवस्था से यह समस्या काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। उपभोक्ता को वस्तुओं और सेवाओं पर अपेक्षाकृत सरल, न्यायोचित और संतुलित कर ढांचा मिलेगा। इससे न केवल मूल्य स्थिरता आएगी, बल्कि खरीदारी और उपभोग की प्रक्रिया भी सहज होगी। इससे व्यापार एवं उद्योग भी विकास की रफ्तार पकड़ेंगे। यह कहना अनुचित नहीं होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार को नियंत्रित करने के लिए कई प्रभावी कदम उठाए गए हैं। डिजिटलाइजेशन, प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण, आधार लिंकिंग और पारदर्शी तंत्र ने व्यवस्था में विश्वास जगाया है। जीएसटी भी इसी कड़ी का एक क्रांतिकारी सुधार है जिसने 'वन नेशन, वन टैक्स' की अवधारणा को मजबूत किया।

परंतु सच्चाई यह भी है कि जीएसटी विभाग आज भी भ्रष्टाचार की जकड़न से पूरी तरह मुक्त नहीं हो पाया है। छोटे व्यापारियों और उद्यमियों को आए दिन नोटिस, जांच और जटिल प्रक्रियाओं के जाल में उलझाया जाता है। कई बार भ्रष्ट तंत्र इन्हें भयभीत कर अनुचित लाभ उठाता है। यह स्थिति जीएसटी सुधार की भावना के विपरीत है। यदि वास्तव में कराधान को क्रांतिकारी मोड़ देना है, तो जीएसटी व्यवस्था को भी पूर्णत: भ्रष्टाचार मुक्त करना अनिवार्य होगा। यह किसी से छिपा नहीं है कि टैक्स विभाग लंबे समय तक भ्रष्टाचार का गढ़ बना रहा। जटिल कानून और अनेक कर-श्रेणियाँ इस भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती थीं। लेकिन जब कराधान पारदर्शी और सरल होगा, तो अधिकारी और कारोबारी के बीच की अनावश्यक जटिलता भी कम होगी। इससे जनता एवं छोटे व्यापारियों का विश्वास व्यवस्था पर मजबूत होगा। अब आवश्यकता है कि सरकार जीएसटी प्रणाली को तकनीकी और प्रशासनिक स्तर पर और अधिक पारदर्शी बनाए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल ट्रैकिंग का उपयोग कर कर चोरी रोकने के साथ-साथ अधिकारियों की मनमानी और रिश्वतखोरी पर भी अंकुश लगाया जा सकता है। करदाता के अधिकारों की रक्षा हो, ईमानदार व्यापारी को भयमुक्त वातावरण मिले और उपभोक्ता को राहत-तभी जीएसटी सचमुच क्रांति कहलाएगा। जीएसटी का नया दौर एक बड़ी राहत और परिवर्तन का संदेश लेकर आया है। अब अगला कदम यही होना चाहिए कि इसे भ्रष्टाचार से पूरी तरह मुक्त कर ईमानदार करदाताओं का विश्वास जीता जाए। तभी यह कहा जा सकेगा कि भारत ने वास्तव में 'सही अर्थों में एक राष्ट्र, एक कर और एक पारदर्शी कर व्यवस्था' की ओर निर्णायक कदम बढ़ा लिया है। भारत की आर्थिक यात्रा में कुछ फैसले ऐसे होते हैं, जो केवल नीतिगत बदलाव नहीं, बल्कि युगांतरकारी मोड़ साबित होते हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में हालिया सुधार उसी दिशा में उठाया गया एक साहसिक कदम है। कराधान व्यवस्था को सरल बनाने और जनता को सीधी राहत पहुँचाने की दिशा में यह सुधार महज सरकारी निर्णय नहीं, बल्कि एक लोककल्याणकारी दृष्टि का प्रमाण है। आजादी के बाद से भारत में कर-व्यवस्था जटिलताओं, बहुस्तरीय बोझ और भ्रष्टाचार की दलदल में फंसी रही। छोटे व्यापारी हों या आम उपभोक्ता, हर कोई अप्रत्यक्ष करों की इस भूलभुलैया से परेशान था। मोदी सरकार ने जीएसटी को लागू करके पहले ही इस दिशा में बड़ा कदम उठाया था, लेकिन अब इसे और सरल बनाना तथा दो स्लैब्स तक सीमित करना एक क्रांतिकारी सुधार है। इससे न केवल उपभोक्ताओं पर बोझ घटेगा, बल्कि व्यवसाय करने की सुगमता भी बढ़ेगी। अर्थव्यवस्था का असली इंजन जनता की जेब है। जब उपभोक्ता को राहत मिलती है, उसके हाथ में थोड़े अधिक पैसे बचते हैं, तो खपत बढ़ती है। यही खपत उद्योगों को गति देती है, उत्पादन में उछाल लाती है और अंतत: रोजगार के नए अवसर पैदा करती है। जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा असर यही होगा कि यह आर्थिक गतिविधियों को नये पंख देगा और इससे भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थ-व्यवस्थ बन सकेगा। किसी भी लोकतांत्रिक शासन का मूल्यांकन इस बात से होता है कि वह अपने नागरिकों के हितों को किस हद तक प्राथमिकता देता है। मोदी सरकार ने जीएसटी सुधार के जरिए यह स्पष्ट किया है कि उनकी नीतियाँ महज आँकड़ों का खेल नहीं, बल्कि जनजीवन को आसान बनाने की कोशिश हैं। यह सुधार जनता को केवल आर्थिक ही नहीं, बल्कि मानसिक राहत भी देता है। हालाँकि सुधार के साथ चुनौतियाँ भी कम नहीं हैं। राज्यों को राजस्व हानि की भरपाई, छोटे कारोबारियों को नई व्यवस्था में सहज बनाना और कर-प्रशासन में पारदर्शिता बनाए रखना, ये सब गंभीर प्रश्न हैं। लेकिन यदि इन्हें दूर किया गया तो यह सुधार भारत को एक मजबूत, पारदर्शी और विकासोन्मुख अर्थव्यवस्था की ओर ले जाएगा। जीएसटी सुधार को जनता के लिए एक 'उपहार' कहना गलत नहीं होगा। यह केवल कराधान का बदलाव नहीं, बल्कि जनता के जीवन स्तर को बेहतर बनाने की पहल है। यह निर्णय बताता है कि शासन की नीतियाँ केवल सत्ता चलाने के लिए नहीं, बल्कि जनता को राहत देने और देश को विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ाने के लिए बनाई गई हैं। लेकिन यहां यह देखना ज्यादा जरूरी है कि इस बदलाव से वास्तव में आम उपभोक्ता को कितना फायदा होता है।

यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उद्योग कर कटौती का लाभ उपभोक्ता तक कैसे पहुंचाते हैं। साथ ही नियामक कितनी सतर्कता से अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।

(लेखक, पत्रकार, स्तंभकार ई-253, सरस्वती कुंज अपार्टमेंट 25 आई. पी. एक्सटेंशन, पटपड़गंज, दिल्ली-92)

संस्कार और चरित्र निर्माण की पाठशाला है परिवार

- बाल मुकुन्द ओझा

परिवार के सम्बन्ध में देशभर से मिल रही ख़बरे बेहद चिंताजनक है। परिवार को हमारे समाज में सामाजिक और सार्वभौमिक संस्था के रूप में स्वीकारा गया है। अनुशासन, आपसी स्नेह और भाईचारा तथा मर्यादा, परिवार को एक खुशहाल परिवार बना देता है। बुजुर्गों का कहना है जिस परिवार में एकता की भावना होती है, उसी घर में ही सुख-शांति और सम्पन्नता का निवास होता है। यही सामाजिक संस्था आज खंडित होने की स्थिति में है। परिवार और बिखरते रिश्ते आज समाज की एक जटिल सच्चाई बन गए हैं। परिवार की व्यवस्था आज की नहीं है, बल्कि ऋषि-मुनियों की देन है। लेकिन आज दरकते रिश्तों से परिवार व्यवस्था टूट रही है जो समाज के लिए ठीक नहीं है। आज भी देश और दुनियां, परिवार और संयुक्त परिवार की अहमियत को लेकर विवादों में उलझी है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है। वह भी एक जमाना था जब भरा पूरा परिवार हँसता खेलता और चहकता था और एक दूसरे से जुड़ा रहता था। बच्चों की किलकारियों से मोहल्ला गूंजता था। पैसे कम होते थे पर उसमे भी बहुत बरकत होती थी। घर में कोई हंसी खुशी की बात होती थी तो बाहर वालों को बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। आज परिवार छोटे हो गए हैं और टूटते जा रहे हैं। हमारे रिश्ते बिखरते जा रहे हैं। संयुक्त परिवार की आज के समय में महती आवश्यकता है। संयुक्त परिवारों के अभाव में भाईचारा एवं पारिवारिक वातावरण खत्म होने लगा है। परिवार में रिश्तो की नीरसता और संवादहीनता को दूर करने परस्पर भाईचारे व तालमेल को बैठाने के लिए रिश्तो में सकारात्मक सोच को बढ़ाने की जरुरत है। परिवार के सभी छोटे हुए बड़े सदस्यों की भावनाओ का सम्मान करे तथा दिन भर घटित होने वाली छोटी-छोटी बातों और दुख-सुख को आपस में बांटे करे।

भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली बहुत प्राचीन समय से ही विद्यमान रही है। साधारणत: संयुक्त परिवार वह है जिसमें पति-पत्नी, सन्तान, परिवार की वधुएँ, दादा-दादी, चाचा-चाची, अनके बच्चे आदि सम्मिलित रूप से रहते है। संयुक्त परिवार में माता-पिता, भाई-बहन के अतिरिक्त चाचा, ताऊ की विवाहित संतान, उनके विवाहित पुत्र, पौत्र आदि भी हो सकते हैं। संयुक्त परिवार से घर में खुशहाली होती है। साधारणत पिता के जीवन में उसका पुत्र परिवार से अलग होकर स्वतंत्र गृहस्थी नहीं बसाता है। यह अभेद्य परंपरा नहीं है, कभी-कभी अपवाद भी पाये जाते हैं। ऐसा भी समय आता है, जब रक्त संबंधों की निकटता के आधार पर एक संयुक्त परिवार दो या अनेक संयुक्त अथवा असंयुक्त परिवारों में विभक्त हो जाता है। असंयुक्त परिवार भी कालक्रम में संयुक्त परिवार का ही रूप ले लेता है और संयुक्त परिवार का क्रम बना रहता है। जिस फैमिली में दादा-दादी, माता-पिता, चाचा-चाची और खूब सारे भाई-बहन होते है उसे जॉइंट फैमिली (संयुक्त परिवार) कहां जाता है। ऐसी फैमिली की बुनियाद उनके बीच का प्यार है, जो सबको एस साथ जोड़ कर रखती है। इस में बूढ़ों से लेकर बच्चे कर अपना सुख-दुख एक साथ बाटते है। सास बहू का परस्पर रिश्ता परिवार का मूल आधार होता है। सच तो यह है आज यही रिश्ता दरक रहा है। बहुत से परिवार इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि सास ने बहू को बेटी और बहू ने सास को मां मानने से इंकार कर दिया है। सास को बहू पराये घर से आई लगती है और बहू को ससुराल पराया लगता रहता है। इसी रिश्ते को प्रेम और स्नेह में बदलकर परिवार नामक संस्था को बचाया जा सकता है।

संयुक्त परिवार के सदस्यों के पास आपसी सामंजस्य की समझ होती है। एक बड़े संयुक्त परिवार में, बच्चों को एक अच्छा माहौल और हमेशा के लिये समान आयु वर्ग के मित्र मिलते हैं इस वजह से परिवार की नयी पीढ़ी बिना किसी रुकावट के पढ़ाई, खेल और अन्य दूसरी क्रियाओं में अच्छी सफलता प्राप्त करती हैं। संयुक्त परिवार में विकास कर रहे बच्चों में सोहार्द की भावना होती है अर्थात् मिलनसार तथा किसी भी भेदभाव से मुक्त होते हैं। परिवार के मुखिया की बात मानने के साथ ही संयुक्त परिवार के सदस्य जिम्मेदार और अनुशासित होते हैं। परिवार चाहे संयुक्त हो या एकल, इसकी खुशियां सदस्यों की सोच और व्यवहार पर ही निर्भर करती हैं। हर परिवार के सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष हैं। सुरक्षा की दृष्टि से संयुक्त परिवार की खूबियां है तो सुविधा की दृष्टि से एकल परिवार के भी अपने फायदे हैं। बदलते वक्त और जरूरत के हिसाब से परिवार संयुक्त और एकल परिवार का रूप लेते हैं।सुरक्षा, और सुविधा, दोनों ही दृष्टियों से संयुक्त परिवार के अपने फायदे हैं। संयुक्त परिवार में अगर कभी किसी को कोई दिक्कत होती हैं तो सभी सहायता के लिए पूरा परिवार ही जुट जाता है। बच्चों को छोड़कर ऑफिस या कहीं बाहर जाना है तो भी निश्चिंतता के साथ जा सकते हैं। यहां बच्चों की जिम्मेदारी सिर्फ माता-पिता की नहीं बल्कि पूरे परिवार की होती है। बच्चे परिवार के संस्कार भी सीखते हैं। संयुक्त परिवार का एक मुखिया होता है, जो परिवार के सभी सदस्यों के लिए नीतियाँ और निर्देश देता है। इन परिवारों में पुत्र विवाह के बाद अपने लिए अलग रहने की व्यवस्था नहीं करता।

(वरिष्ठ लेखक एवं पत्रकार, मॉडल टाउन, मालवीय नगर, जयपुर)

कविता: सुंदरतम

जल ने प्रलय मचा
रखी है
आसमाँ की मोहब्बत में
दुनिया तबाह कर रखी
है।

सोचते हो मोहब्बत
बस तुमने ही की है
यहाँ
ओह नहीं नहीं......

हवा ने पानी से
पानी ने हवा से
आंखों से आंखें मिला
रखी है।

सोचते हो खूबसूरत
बस तुम ही हो यहां
ओह नहीं नहीं......

पर्वतों ने अपनी सुंदरता
से
सारी दुनिया अपने
कदमों में झुका रखी है।

डॉ. राजीव डोगरा

(युवा कवि लेखक, हिंदी अध्यापक, गांव जनयानकड़, कांगड़ा हिमाचल प्रदेश)

वैदिक युग में भारत में कोई जाति या वर्ण नहीं थे। कालांतर में जाति का उदय हुआ। जिनकी ज्ञानार्जन और अनुसंधान में रुचि थी, वे ब्राह्मण कहलाए। जिनमें बल था, वे क्षत्रिय और जो व्यापार करने लग गए, वे वैश्य कहलाए। जो मूलत: श्रम और कृषि कार्य से जुड़े रहे, वे शूद्र कहलाए। यही बड़ा उत्पादक समूह रहा है और वर्तमान में भी है। ब्राहमण परशुराम ने क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुन को पराजित कर सत्ता हस्तगत कर ली थी, परंतु उन्हीं के शेष रहे वंशजों को सत्ता सौंप कर ज्ञान की सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी।

ब्राह्मण : तेल की खरीद में जातीय विभाजन की आग

- प्रमोद भार्गव

धर्म और जाति भारत की कमजोर कड़ियां रही हैं। इसकी शुरूआत फिरंगी हुकूमत ने भारत में धर्म के आधार पर बंगाल के विभाजन के साथ की थी, जो कालांतर में अंग्रेजों की कुटिल चाल के परिणाम में भारत विभाजन का मुख्य आधार बनी। अब अमेरिका के भारत विरोधी वाचाल व्यापारी पीटर नवारो एक बार इसी नुस्खे को तूल देकर जातीय वैमन्स्य को चिंगारी भड़काने की कोशिश में हैं। भारत पर लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर अमेरिका से असंतुष्ट देशों में खासतौर से रूस, भारत, चीन अर्थात आरआईसी ट्राइका शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में मजबूती से खड़ा होता दिखा। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो गई। नतीजतन इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रंप के आधिकारिक व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से तेल आयात पर निशाना साधते हुए कहा कि 'ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कमा रहे हैं।' दरअसल एससीओ का तियानजिन में एकत्रीकरण ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दबाव का ऐसा प्रभावी संकेत है, जो न केवल अमेरिका, बल्कि जी-7 और यूरोप की आर्थिक शक्ति को भी संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नवारो ने 'फॉक्स न्यूज संडे' को दिए साक्षात्कार में कहा कि 'देखिए, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के महान नेता हैं, लेकिन वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राश्ट्रपति षी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता समझे कि यह क्या हो रहा है। आपके पास जो ब्राह्मण हैं, वे भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है। यानी पूंजीपति देश का एक उद्योगपति भारत की जनता को बताएगा कि वह क्या करे ? मसलन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता नसमझ है। देश की वह जनता नादान है, जिसने आपातकाल में तानाशाह के रूप में पेश इंदिरा गांधी की सरकार को बदल दिया था ? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारी बहुमत से जीते राजीव गांधी की सत्ता को इसलिए बेदखल कर दिया था, क्योंकि साहबानो प्रकरण को लेकर राजीव गांधी इस्लामी कट्टरवादियों के दबाव में आ गए थे। इसी जनता ने उन मनमोहन सिंह को सत्ताच्युत कर दिया था, जिन्होंने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को सौंप देने की वकालत शुरू की थी और फिर इसी जनता ने देश की कमान उन नरेंद्र मोदी को सौंप दी थी, जो अपने बाल्यकाल में पिता की मदद के लिए रेल के डिब्बों में चाय बेचा करते थे। इन्हीं मोदी को जागरूक मतदाताओं ने फिर से 2019 में जिताया, क्योंकि सुरक्षा सैनिकों को ले जाने वाले एक वाहन को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमलावर, सीआरपीएफ के 46 जवानों की शहादत का कारण बना था। इस जघन्य घटना का बदला लेने के लिए मोदी ने बालाकोट में वायुसेना से सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को जमींदोज कर दिया। 2024 के आम चुनाव में इन्हीं मोदी पर देश देश की जनता ने फिर विश्वास किया और तीसरी बार सत्ता की कुंजी मोदी को सौंप दी। साफ है, जनता उन विदेशी उपदेशकों के बहकावे में आने वाली नहीं है, जो मोदी पर नाजायज दबाव बनाकर अपने अनैतिक हित साधने के फेर में हैं। दोहरे मापदंड वाले ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में जुर्माना लगा रहे हैं, जबकि भारत, चीन और यूरोपीय देशों की तुलना में कम ईंधन खरीदता है। पीटर नवारो इन देशों के ब्राह्मणों, अर्थात कुलीन वर्ग या कारपोरेट घरानों के लिए क्या कहेंगे ?

नवारो भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रलापों के लिए जाने जाते हैं। नवारो ने इसके पहले, यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध आंशिक रूप से नई दिल्ली होकर गुजरता है' का लांछन लगाया था। इसका सटीक उत्तर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहते हुए दिया है कि 'नवारो ने भारत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध-मशीन को वित्तपोशित करने का आरोप लगाया है, जबकि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर किए हमले के बहुत पहले से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। उसी मात्रा में आज भी रूस तेल निर्यात कर रहा है। अर्थात निवारों का बयान भारत, रूस और चीन की एससीओ की बैठक में देखने में आई जुगलबंदी का नतीजा है। चूंकि अब ट्रंप अपने ही देश में बेतुके अड़ियल रुख के कारण घिरते जा रहे हैं। अवाम में नाराजी बढ़ रही है। अमेरिका के अरबपति रे डेलियो ने तो यहां तक कह दिया कि 'ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका 1930 के दशक जैसी तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। निवेशक ट्रंप के डर से चुप हैं। धन एवं मूल्यों की खाई और टूटता भरोसा अमेरिका को चरमपंथी नीतियों की ओर धकेल रहा है।' निवारो का जातिसूचक बयान एक ऐसी साजिश का सूचक है, जो भारत में शहरी नक्सली और वर्णभेदी वामपंथी बीजरूप में आजादी के बाद से ही बोते रहे हैं। जिससे भारत जातीय कुचक्र की आग में जलने लग जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जाति की जड़ें आज भी गहरी हैं। लेकिन बीते 75-80 सालों में जनता बौद्धिक-विवेक के रूप में इतनी परिपक्व हो गई है कि वह अब किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आने वाली नहीं है। वह जानती है कि भारत में तेल का व्यापार करने वाले जो भी चंद उद्योगपति हैं, उनमें ब्राह्मण कोई नहीं है। यह बयान केवल भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में व्यर्थ हस्तक्षेप और जातिगत विद्वेश भड़काने की निर्लज्ज कोशिश है। हालांकि यह संभवत: अपवाद है कि किसी परदेशी उद्योगपति के मुख से जातिगत व्यवस्था को भारत सरकार की विदेश नीति से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। नवारो ने जातिसूचक शब्द ब्राह्मण का जो प्रयोग किया है, उसे अभिजात्य या कुलीन वर्ग को लांछित करने के रूप में भी देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष का कहना है कि बोस्टन ब्रह्माण शब्द अमेरिका में न्यू इंग्लैंड से जाकर बसे धनी वर्ग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस शब्द को एलीट क्लास से जोड़ा है। दरअसल एक समय अमेरिका के बोस्टन में धनी सुशिक्षित प्रोटेस्टेंटों का एक समुदाय था। ये लोग 18वीं और 19वीं सदी में ताकतवर समुदाय थे। ये अमेरिका के उपनिवेशवादियों के वंशज थे। इन लोगों ने व्यापार में अपने को खफा दिया और सफलता के शिखर छू लिए। इन्हें बोस्टन ब्राह्मण या कुलीन कहा गया। ये बोस्टन के आम लोगों से अलग रहते थे और अभिजात्य जीवन-शैली जीते थे।

वैदिक युग में भारत में कोई जाति या वर्ण नहीं थे। कालांतर में जाति का उदय हुआ। जिनकी ज्ञानार्जन और अनुसंधान में रुचि थी, वे ब्राह्मण कहलाए। जिनमें बल था, वे क्षत्रिय और जो व्यापार करने लग गए, वे वैश्य कहलाए। जो मूलत:श्रम और कृषि कार्य से जुड़े रहे, वे शूद्र कहलाए। यही बड़ा उत्पादक समूह रहा है और वर्तमान में भी है। ब्राह्मण परशुराम ने क्षत्रिय सहस्त्रबाहु अर्जुन को पराजित कर सत्ता हस्तगत कर ली थी, परंतु उन्हीं के शेष रहे वंशजों को सत्ता सौंप कर ज्ञान की सर्वोच्चता स्थापित कर दी थी। वे परशुराम ही थे,जिन्होंने गोवा के कोंकण क्षेत्र में समुद्र से भूमि खाली करके हजारों वनवासियों को खेती शुरू कराई। इनका यज्ञोपवीत संस्कार कर इन्हें ब्राह्मण बनाया और अक्षय तृतीया के दिन सामूहिक विवाह कराए। युद्ध में विधवा हुई महिलाओं के भी विवाह कराये। अब भारत में शैक्षिक उन्नति, सह-शिक्षा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेशेवर युवक-युवतियों की बड़ी संख्या में भागीदारी के चलते अन्तर्जातीय व अन्तर्धार्मिक विवाह आम बात हो गई है। बहुत कुछ जातीय कुचक्र टूट गया है। अलबत्ता यह भी देखने में आ रहा है कि जिस किसी भी वर्ग या जाति के लोग राजनीति, नौकरी या व्यापार में सशक्त होते जा रहे हैं, वे उसी ब्रह्मणवादी व्यवस्था के अनुगामी बनते जा रहे हैं, जिसे एक एमय वे कोसते रहे हैं। भारत में निरंतर जातीय समन्वय बढ़ रहा है। अतएव अब वे किसी परदेसी के बचकाने बयान के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, श्रीराम कॉलोनी शिवपुरी म.प्र.)

हो सकता है मैं आपके विचारों से सहमत न हो पाऊं फिर भी विचार प्रकट करने के आपके अधिकारों की रक्षा करूंगा। **–वाल्तेयर**

राजस्थान पत्रिका
संस्थापक
कर्पूर चन्द्र कुलिश

अवसाद में आत्महत्या की बढ़ती घटनाएं चिंताजनक

शारीरिक के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी निरंतर देखभाल और जागरूकता की जरूरत होती है लेकिन चिंता की बात यह है कि दुनिया में एक अरब से ज्यादा लोग मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं से जूझ रहे हैं। इसमें चिंता और अवसाद अब आम बात होने लगी है। बड़ी चिंता यह भी कि समय पर नियंत्रण नहीं करने की वजह से बीमारी गंभीर अवसाद का रूप ले लेती है और पीड़ित व्यक्ति आत्महत्या करने जैसा घातक कदम उठा लेता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट में यह तथ्य चिंताजनक है, जिसमें कहा गया है कि वर्ष 2021 में 7.27 लाख लोगों ने आत्महत्या की जो वैश्विक मृत्यु दर का 1.1 प्रतिशत है। इनमें भी 15 से 29 आयु वर्ग के युवाओं की मृत्यु का तीसरा प्रमुख कारण आत्महत्या है।

भारत में यह स्थिति और भी चिंताजनक है, जहां युवाओं और महिलाओं में आत्महत्या की दुष्प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है। भारत में युवाओं में आत्महत्या की दुष्प्रवृत्ति के पीछे यों तो कई सामाजिक, आर्थिक और मनोवैज्ञानिक कारक हैं। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के अनुसार, भारत में पिछले कुछ वर्षों में आत्महत्या की दर में 27% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है। शैक्षणिक दबाव, बेरोजगारी, प्रेम व विवाह संबंधों में विफलता, सामाजिक अपेक्षाओं का बोझ और नशे की लत इनमें प्रमुख कारण हैं। इन कारणों के अलावा घरेलू हिंसा, जाति-आधारित उत्पीड़न और आर्थिक तंगी भी युवाओं को इस घातक कदम की ओर धकेलती है। देखा जाए तो ये तमाम कारक कहीं न कहीं व्यक्ति को अवसाद में धकेलने का काम करते हैं। बड़ी चिंता यह भी है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर स्थिति कोई खास अच्छी नहीं है। डब्ल्यूएचओ के अनुसार हमारे यहां प्रति एक लाख लोगों पर सिर्फ 0.3 मनोचिकित्सक उपलब्ध हैं और मानसिक स्वास्थ्य पर कुल स्वास्थ्य बजट का मात्र 1 से 2 प्रतिशत खर्च होता है। ग्रामीण और छोटे शहरों में यह सुविधा और भी सीमित है। भारत में मानसिक स्वास्थ्य पर प्रति व्यक्ति खर्च बमुश्किल तीन से चार रुपए तक है जबकि विकसित देशों में यह खर्च प्रति व्यक्ति 65 डॉलर तक है। सामाजिक कारकों जैसे घरेलू हिंसा, पितृसत्तात्मक दबाव और लैंगिक भेदभाव के कारण महिलाएं मानसिक तनाव का अधिक शिकार होती हैं। इसका असर पूरे परिवार पर पड़ता है क्योंकि महिलाएं परिवार की भावनात्मक और सामाजिक धुरी होती हैं।

भारत में बढ़ती आत्महत्याओं और बिगड़ते मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने के लिए समग्र दृष्टिकोण अपनाना होगा। मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल करने के साथ हेल्पलाइन सेवाओं का विस्तार और मनोचिकित्सकों की संख्या भी बढ़ाना जरूरी है। आर्थिक असमानता, बेरोजगारी और घरेलू हिंसा जैसे संरचनात्मक कारणों को संबोधित करना होगा। सरकार, समाज, और परिवारों को मिलकर संकट का समाधान निकालना होगा।

स्त्री-पुरुष दोनों के शरीर पदार्थ हैं, पृथ्वी तत्त्व से बने हैं। स्त्रैण भी हैं और अर्द्धनारीश्वर भी। किन्तु विपरीत स्वभाव के हैं। नश्वर भी हैं, किन्तु भीतर अमृत की प्रतिष्ठा होने से शाश्वत नजर आते हैं।

पूर्णता स्त्रैण भाव से

गुलाब कोठारी
प्रधान संपादक
पत्रिका समूह
@patrika.com

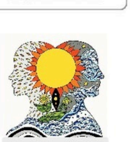

शरीर ही ब्रह्माण्ड

स्त्री: देह से आगे
विषय विवेचन
चेन्नई में आयोजित कार्यक्रम में ***गुलाब कोठारी*** के संबोधन का वीडियो देखने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः।
मनःषष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति।। (गीता 15.7)
अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन्।
प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्ममायया।। (गीता 4.6)

सृष्टि की सभी 84 लाख योनियां मेरा ही अंश लेकर उत्पन्न होती हैं। मैं ही सबका एकमात्र बीज हूं। समस्त प्राणियों का अजन्मा ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योगमाया से प्रकट होता हूं। मैं ही अव्यय हूं। इसका एक ही अर्थ हुआ कि मैं ही अंशी हूं, मैं ही माया का स्वामी हूं, मैं ही प्रकृति रूप में कार्य करता हूं। अव्यय के साथ मैं ही माया हूं, ब्रह्म के साथ बल हूं। अक्षर के साथ महामाया हूं, और पुरुष के साथ प्रकृति हूं। मैं ही अपनी कामना रूप में माया हूं। मैं ही कारण, मैं ही कार्य हूं। मैं अव्यय हूं, परा-अपरा मैं ही हूं।

माया ही मेरा अंश लेकर निर्माण करती है। मेरे ही अंश की चोरी करती है, जीवनभर छिपाकर भी रखती है। इसमें भी ग्रहण-पोषण का भाव जुड़ा रहता है। जीव को गर्भ में छिपाना भी एक अर्थ है। पुरुष शरीर में व्याप्त शुक्र का दोहन करके बलात् खींच लेना, स्वयं में आहुत कर लेना भी एक अर्थ है। पुरुष को कब भान होता है कि जीवात्मा उसके शरीर से निकल गया है! वह भोग मात्र से उल्लासित रहता है। मूलतः माया अपना धर्म-चोरी एवं छिपाना- पूरा करने में सदा ही सिद्धहस्त है।

पुरुषार्थ चतुष्टय में चारों ही धरातलों पर वह अपना यह कर्म निभाती नजर आती है। माया के परोक्ष भावों को, अक्षर सृष्टि स्वरूप को, समझ पाना संभव नहीं है। यह क्षेत्र बुद्धि का नहीं है। बुद्धि को तो माया आसानी से भ्रमित कर देती है। पुरुष के पास देहबल (आसुरी भाव) तथा बुद्धि बल (दिव्य भाव) दोनों होते हैं। स्त्री शुक्राचार्य रूप में आसुरी भाव को तथा बृहस्पति-नीति रूप में दिव्य भाव को अपने आकर्षण से अभिभूत करना जानती है।

पुरुष भीतर सोमप्रधान तो है, किन्तु उसका सोम कुपोषित होने से भी अधिकांशतः अपूर्ण ही रहता है। यह अपूर्णता उसकी बुद्धिमत्ता के अहंकार के अनुपात में बढ़ती जाती है। स्त्री भीतर आग्नेय है, दृढ़ संकल्पवान है। यही उसकी कर्म में निपुणता का कारण है। स्त्री कर्म का ही पर्याय है तथा ब्रह्म कामुकता का- एकोऽहं बहुस्याम्। अपूर्ण होने से स्त्री ही उसका भोग किया करती है। उसे पुरुष को भ्रमित करना आता है—**भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया।।** (गीता 18.61)

माया ही बीज चुराती है, अपने अंग से पोषण करती है, नई आकृति का। पुरुष को छिपाना तत्काल शुरू कर देती है, बुद्बुद् के भीतर। शिशु की देह का उपादान कारण भी माता की देह ही होती है। अतः सभी प्राणियों की देह अपरा प्रकृति रूप ही है। जिस प्रकार सृष्टि का बीज एक है, उसी प्रकार 84 लाख योनियों की देह का उपादान कारण भी माया ही है। पशु-पक्षी-पेड़-जड़ आदि सभी अपरा प्रकृति द्वारा निर्मित हैं। अर्थात् सम्पूर्ण दृश्य जगत स्त्री रूप (माया) ही है। प्रत्येक स्त्री एक ब्रह्माण्ड है। ब्रह्म में वैसे भी कर्ता भाव नहीं होता। कर्ताभाव तो माया में भी नहीं होता। महामाया भी निमित्त कारण ही है। यहां भी हृदय में कामना ही कार्य करती है।

हृदय जीवन का नियन्ता केन्द्र है। मन का निर्माण भी यहीं होता है। अतः जीव की एवं ईश्वर की कामनाएं यहीं पैदा होती हैं। प्रकृति स्त्रैण है, तो कामनाएं भी स्त्रैण हैं। परा प्रकृति चूंकि अव्यय और क्षर सृष्टि के मध्य का सेतु है, अतः कारण शरीर की कामना हृदय में आकर क्षर पुरुष में शुक्र का कार्य करती है। अक्षर में अमृत-मर्त्य दो विभाग होते हैं। मर्त्य भाग ही क्षर ब्रह्म है। अतः स्त्री भी क्षर-अक्षर दोनों स्तर पर कार्य करती है।

कृष्ण प्रकृति की भूमिका को समझने का मार्ग बताते हुए कह रहे हैं कि बाहर के विषयों को बाहर छोड़कर (क्योंकि वे मन की चंचलता के कारण हैं), नेत्रों की दृष्टि को भृकुटी के बीच तथा नासिका के प्राणों को सम करके इच्छा, भय, क्रोध मुक्त होने का प्रयत्न करना चाहिए–

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्यांश्चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः।
प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ।। (गीता 5.27)

हमारे शरीर की प्रत्येक कोशिका एक देह है–जड़ है, चेतन है। स्त्री की भांति पदार्थ और ऊर्जा, दोनों स्तर पर कार्य करती हैं। मन का केन्द्र हृदय है। शब्द ही वहां गतिमान रह सकता है। ध्वनि मातृभूतों की मातृसंस्था है। अतः सबके पार जा सकती है। इन्द्रियों से मुक्त मन प्राणों के माध्यम से मोक्ष साक्षी होने लगता है। भ्रू-मध्य पर मंत्राघात के स्पन्दन इसमें सहायक होते हैं। उधर नासाग्र पर ध्यान-प्रश्वास-श्वास पर दृष्टि से गंध क्षेत्र स्पन्दित होता है, जो कि मूलाधार का स्थान है। इस प्रकार लक्ष्मी को सुप्त करके सरस्वती के सहारे हम मूलाधार (कुण्डलिनी शक्ति) और भ्रू-मध्य (आज्ञा-चक्र) को ऊर्जा प्रवाह से जोड़ देते हैं। पृथ्वी पुनः सूर्य में लीन हो जाती है। यहां से अगली यात्रा अव्यय तक आरम्भ हो जाती है।

स्त्री-पुरुष दोनों के शरीर पदार्थ हैं, पृथ्वी तत्त्व से बने हैं। स्त्रैण भी हैं और अर्द्धनारीश्वर भी। किन्तु विपरीत स्वभाव के हैं। नश्वर भी हैं, किन्तु भीतर अमृत की प्रतिष्ठा होने से शाश्वत नजर आते हैं। स्त्रैण के साथ ईर्ष्या भी जुड़ी रहती है। पुरुष के बीज को इसी कारण चुराने का प्रयास भी करती है। अपनी सफलता पर बागवान की तरह अभिमान भी करती है। शरीर का अपना धर्म होता है, आत्मा का अपना। आज आत्मा का धर्म उजड़ गया है। साम्प्रदायिकता ही शरीर की पहचान हो गई। स्त्री का रहस्यात्मक स्वरूप ही खो गया। शरीर में कुछ नया नहीं होता। समानता के संघर्ष में सम्मान भी छूट गया। ब्रह्म का विवर्त भाव जीवन से विदा हो गया। जीवन की पवित्रता भोग की वस्तु बन गई। क्रय-विक्रय की मुद्रा बन गई। समानता के इस आन्दोलन ने स्त्री को आक्रामक बना दिया। पुरुष को पीछे धकेलने के प्रयास भी तेज होने लगे। न सन्तान की जरूरत है, न ही बीज की।

पुरुष के जीवन में भी नया परिवर्तन आ गया। उसने भी स्वयं को स्त्री शरीर से 'बंध जाना' अस्वीकार कर दिया। जीवन स्थाई स्वरूप खो बैठा। स्त्री की दिव्यता मानो कभी थी नहीं। इसी का परिणाम है कि मानव समाज भी स्वयं में दिव्यता से वंचित होने लगा। शरीर में आसुरी शक्तियां प्रधान भूमिका में आ रही हैं। कभी स्त्री की दिव्यता को ही आसुरी शक्तियों के संहार के निमित्त पूजा जाता था।

-**क्रमशः**

gulabkothari@epatrika.com

बुक इनसाइट

'अमिटी' में 19वीं सदी का अमरीका

नाथन हैरिस की नई किताब अमिटी एक ऐसी कहानी है, जो पाठकों को 19वीं सदी के अमरीका में ले जाती है। यह उपन्यास उनके पूर्व के सफल उपन्यास 'द स्वीटनेस ऑफ वाटर' के बाद आया है। यह एक बार फिर उनकी गहरी लेखनी और भावनात्मक गहराई को दर्शाता है। कहानी 19वीं सदी के उस समय को सामने लाती है, जब अमरीका बदलते दौर से गुजर रहा था। पश्चिम की ओर बढ़ते कारवां, नए बसने वाले लोग और उनके साथ आने वाली उम्मीदें व चुनौतियां इस उपन्यास की पृष्ठभूमि बनाती हैं। हैरिस अपने लेखन में पात्रों के भीतर की बेचैनी, संघर्ष और बेहतर भविष्य की तलाश को बड़े ही जीवंत ढंग से प्रस्तुत करते हैं। इस उपन्यास की सबसे बड़ी ताकत इसकी भाषा और संवेदनशीलता है। लेखक ने इतिहास को सिर्फ घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि इंसानों की भावनाओं और रिश्तों के आईने में दिखाया है।

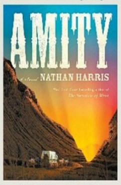

भारत-अमरीका संबंध | एससीओ बैठक का बड़ा फायदा चीन को

टैरिफ, तेल व तंज: क्या गिरती रेटिंग से ट्रंप बैकफुट पर आएंगे?

रजत मिश्रा
स्वतंत्र लेखक एवं शोधार्थी
@patrika.com

क्या ट्रंप अमरीका का एक 'फेज' बस हैं और कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा या फिर ट्रंप का असर दीर्घकालीन होगा? इसका उत्तर वक्त देगा लेकिन भारत को सभी स्थितियों के लिए तैयार होना पड़ेगा।

यह सही है कि ट्रंप टैरिफ से टेक्सटाइल, रत्न-आभूषण, सीफूड और केमिकल जैसे सेक्टरों में 55-65 अरब डॉलर के सालाना शिपमेंट सीधे प्रभावित होंगे। जीडीपी करीब 0.5 से 0.7% घट सकती है। नतीजतन तिरुपुर, सूरत, नोएडा जैसे औद्योगिक हब में कई फैक्ट्रियों पर ताले लगने का खतरा है और अनुमान है कि 20-25 लाख नौकरियां दांव पर लग सकती हैं।

इसके जवाब में सरकार यूरोप, अफ्रीका व लैटिन अमरीका जैसे नए बाजारों की ओर रुख करने की तैयारी कर रही है। साथ ही घरेलू मांग को मजबूत करने के लिए जीएसटी दरों में परिवर्तन ला रही है। अगर इनपुट के लिए प्रयोग में आने वाले माल पर कर कम होगा तो भारतीय निर्यातक भी टैरिफ के असर को कुछ प्रतिशत कम कर सकते हैं। साथ ही सीमेंट, कोयला, कारों आदि से उपकर हटाना भी नए निर्माण और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाने में सहयोगी हो सकता है। ये दांव पर लगी नौकरियों को कुछ हद तक संभालने का एक तरीका है। भारत के समक्ष ट्रंप टैरिफ ने ऐसे विकल्प छोड़े थे, जिनको अपनाने से भारत के लिए परेशानी खड़ी होती। इसलिए मोदी सरकार ने सावधानीपूर्वक चेतावनी देने की सोची और अब तक भुला बैठे शंघाई सहयोग संगठन में पुतिन और जिनपिंग से मिलने चले गए। इसका सबसे बड़ा फायदा चीन को हुआ क्योंकि हर तरह के प्रतिस्पर्धी और विरोधी देश भी उसके बुलाने पर आते दिखे। अब ट्रंप के लिए चीन पर टैरिफ लगाना और मुश्किल हो सकता है लेकिन एक फायदा भारत को जरूर मिला कि अमरीका ने इस बात को संज्ञान में लिया।

एससीओ की बैठक के बाद ट्रंप ने भारत की व्यापार नीतियों को 'एकतरफा तबाही' बताया और अपने 50% टैरिफ को जायज ठहराया। उनके पुराने सलाहकार पीटर नवारो इससे भी आगे निकल गए-नई दिल्ली पर रूस से तेल खरीदकर 'मोदी का युद्ध' कहकर आरोप मढ़ दिया और ऊपर से 'ब्राह्मण' तंज कसकर भारत को खास तबकों का मुनाफाखोर कहा। बयानवीरों की दुनिया में कोई कमी नहीं है, लेकिन ट्रंप के लिए चुनौतियां बढ़ रही हैं. जेफरी एप्सटीन से जुड़ी बदनामी और इजरायल की बातों में फंसकर ईरान पर हमला उनके अंधभक्त समर्थकों को भी बेचैन कर रहा है। 2.7% की मुद्रास्फीति पिछले बाइडन वर्ष से बेहतर नहीं है। ट्रंप की अप्रुवल रेटिंग बहुत ही निचले स्तर पर है। 41% समर्थन और 55% विरोध एक नया रिकॉर्ड है। अमरीका के दक्षिण के कृषि प्रधान राज्य अब भी ट्रंप के साथ हैं और ये टैरिफ उन्हें फायदा देगा। लेकिन आगामी वर्ष मध्यावधि चुनावों का है और अगर रिपब्लिकन पार्टी हारी तो ट्रंप पर दबाव चौतरफा होगा।

ट्रंप कूटनीति समझते नहीं हैं लेकिन धमकी के जरिये जापान से 550, कोरिया से 450, अरब से 1400 बिलियन डॉलर ऐंठ चुके हैं। भारत पर रूस के साथ व्यापार के लिए जुर्माना लगाया और खुद पुतिन के लिए 'लाल कालीन' बिछाने लगे। क्या ट्रंप अमरीका का एक 'फेज' बस हैं और कुछ समय में सब ठीक हो जाएगा या फिर ट्रंप का असर दीर्घकालीन होगा? इसका उत्तर वक्त देगा लेकिन भारत को सभी स्थितियों के लिए आंतरिक रूप से तैयार होना पड़ेगा।

मिस्र की शाही भव्यता की गवाही देतीं टानिस की विशाल मूर्तियां

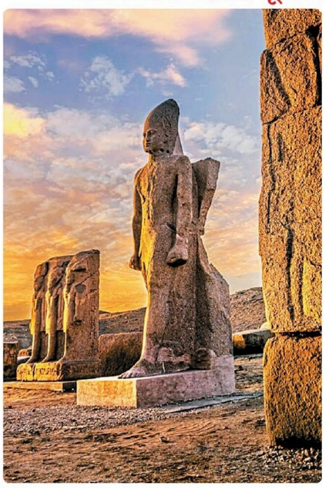

नील *नदी के डेल्टा क्षेत्र का प्राचीन नगर टानिस आज खंडहरों में बदल चुका है, लेकिन इसके अवशेष अब भी मिस्र की शाही भव्यता की गवाही देते हैं। यहां खड़ी विशालकाय मूर्तियां उस दौर की शक्ति, धार्मिक आस्था और स्थापत्य कला की अद्भुत मिसाल हैं। टानिस मिस्र की 21वीं और 22वीं वंशावली के दौरान राजधानी रहा था। इन राजवंशों ने यहां मंदिरों, स्तंभों और देवताओं को समर्पित प्रतिमाओं का निर्माण कराया था।*

आर्ट एंड कल्चर

उपयोगिता व सौंदर्य का मिलन भारतीय शिल्प

चिन्मय मिश्र
वरिष्ठ संस्कृतिकर्मी
@patrika.com

जब किसी शिल्पकार के हाथ किसी शिल्प/कृति की रचना में संलग्न होते हैं तो वह समय काल किसी अनुष्ठान से कम नहीं होता। मनुष्य यह आरंभ से ही समझ चुका था कि स्वस्थ बने रहने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करना जरूरी है। वह यह भी समझ गया था कि उसकी कला में कहां कमी है और इसे किस तरह सुंदर, आकर्षक और उपयोगी बनाया जा सकता है। वह जान गया था कि उसकी कल्पना को परिणित करने के लिए जो पदार्थ उपयोग में लाए गए हैं और जिस विधि का उपयोग निर्माण के लिए किया गया है, दोनों में परस्पर सामंजस्य का अभाव है। यह सामंजस्य ही एक बेहतर शिल्प निर्माण या शिल्पकारिता की मूल शर्त है। हमारे आदिमतम पुरखों (आदिवासियों) की निर्मित प्रत्येक वस्तु उनके दैनिक प्रयोग के लिए होती थी। जब हम अपनी लोकशिल्प और शिल्प परंपरा पर बात करते हैं तब यह जानना बेहद जरूरी है कि इसमें वह क्या था, जिसने करीब 3000 वर्षों तक भारत को दुनिया के व्यापार का सिरमौर बनाए रखा। किसी उपयोग की वस्तु का सौंदर्य से परिपूर्ण होना ही उसे महत्त्वपूर्ण बनाता है।

हमारे शिल्पियों को इसमें महारत हासिल थी। रोम की संसद में ईस्वी संवत् से 500 वर्ष पूर्व यह बहस हुई थी कि 'रोम की नारियां भारतीय वस्त्रों पर जैसे सोना लुटा रहीं हैं। अजीब जरूर लगेगा पर यह सच है कि भारतीय शिल्पों में सभ्यता और मानवता को बचाने का माद्दा है। शताब्दियों पहले एक इतिहासकार ने लिखा था कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनकाल से स्थापित उद्योगों की अपनी विलक्षणता और विशिष्टता है। धातु और हाथी दांत की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन, पच्चीकारी, शाल, मोजेक, मलमल तथा कालीन बनाने में इस समाज का कौशल दिखाई पड़ता है। इतना ही नहीं, भारत में धातु या यंत्रों पर कुशलता पा लेना ही शिल्पकारिता नहीं थी, बल्कि मन की भावनाएं, मस्तिष्क और शरीर सब एक साथ कार्य करते हैं, तभी तो कोई नायाब वस्तु 'प्रकट' होती थी। आदिमानव ने शिल्प गढ़ना हथियारों से शुरू किया था। उसका परिष्कार तो जैसे अवर्णनीय ही है। जीवन की सम्पूर्णता का एक अनिवार्य तत्त्व उपयोगिता है। उपयोगिता में सौंदर्य का समावेश कर अंतरंग जीवन में भी सुंदरता के महत्त्व को प्रतिपादित कर दिया गया। भारतीय शिल्प जिस लंबी परंपरा के संवाहक हैं उसका पहला प्रमाण ऋग्वेद में, बाद में ग्रंथों में और चौथी शताब्दी ईस्वी के आसपास के अग्निपुराण, विष्णु धर्मोत्तर आदि में मिलता है। आज भी भारत वस्त्र बुनाई एवं अन्य लोकशिल्प कलाओं के माध्यम से वैश्विक स्तर पर हस्तक्षेप कर रहा है। एक चीनी यात्री ने सम्राट अशोक का भवन देखकर कहा था कि सम्राट अशोक ने अपने महल के निर्माण के लिए अवश्य ही जिन्न नियुक्त किए होंगे।

आपकी बात

आम आदमी की क्रय शक्ति बढ़ेगी

नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स से रोजमर्रा के सामान सस्ते होंगे, जिससे क्रय शक्ति बढ़ेगी। पैसों की बचत होगी। बीमा और अन्य स्वास्थ्य संबंधी वस्तुओं पर जीएसटी कम होने से राहत मिलेगी। **- गजेंद्र चौहान,** कसौदा

आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा

जीएसटी रिफॉर्म्स से आम जनता को राहत मिलने की उम्मीद है। आवागमन के सस्ते साधन सुगम होंगे। लोगों का आशियाना बनाना सरल होगा। वहीं आर्थिक स्थिति में भी सुधार आएगा। देश आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ेगा।
- आजाद पूरण सिंह राजावत, जयपुर

patrika.com पर पढ़ें

पाठकों की अन्य प्रतिक्रियाएं

पत्रिकायन का सवाल था, 'जीएसटी रिफॉर्म्स से आम आदमी के जीवन में किस तरह का बदलाव आएगा?' अन्य प्रतिक्रियाएं ऑनलाइन भी देखें।

इसे स्कैन करें

https://shorturl.at/i1EeA

नेशनल रीड अ बुक डे | किताबें सिर्फ शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी सभ्यता-संस्कृति की धड़कन हैं

पढ़ने की आदत : सोच को गहराई देने का आसान तरीका

मुनीष भाटिया
स्वतंत्र लेखक एवं स्तंभकार
@patrika.com

नेशनल रीड अ बुक डे, जो कि हर साल छह सितंबर को मनाया जाता है, यह हमें किताबों के महत्त्व और उनके बदलते स्थान की याद दिलाता है। किताबें केवल पन्नों पर लिखे शब्द नहीं होतीं बल्कि सभ्यता, संस्कृति और मानवीय ज्ञान का जीवंत दस्तावेज होती हैं। यदि हम इतिहास पर दृष्टि डालें तो पाएंगे कि हर युग में पुस्तकें समाज को दिशा देने वाली सबसे बड़ी शक्ति रही हैं।

आज के दौर में जब राष्ट्रीय पठन-पुस्तक दिवस मनाया जाता है, तो एक गहरी चिंता मन में उभरती है, क्या वास्तव में लोग अब किताबों से दूर हो रहे हैं? कभी यही किताबें जीवन का अहम हिस्सा हुआ करती थीं। नया उपन्यास प्रकाशित होते ही चर्चा का माहौल बन जाता था। पुस्तक-विमोचन समारोह का इंतजार उतनी ही बेसब्री से होता था, जितना आज किसी फिल्म या वेब-सीरीज का होता है। कभी पुस्तकालयों में बैठकर घंटों पढ़ना युवाओं का शौक हुआ करता था। साहित्यिक गोष्ठियों में चर्चाएं होती थीं लेकिन अफसोस,आज वही किताबें धीरे-धीरे जीवन से ओझल होती जा रही हैं। समय बदलने के साथ पढ़ने की आदतें भी बदल गईं। डिजिटल मनोरंजन और सोशल मीडिया के शोर में किताबों की शांत और गहरी आवाज कहीं दब-सी गई है।

बीते समय में किताबें सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं थीं, बल्कि जीवन को समझने और जीने की कला सिखाती थीं। किसी जमाने में लोग अपने पसंदीदा लेखक की नई कृति का इंतजार करते, लाइब्रेरी से किताबें लेने की होड़ लगती और किताब पढ़ते-पढ़ते रातें जाग जातीं। यह जुनून किताबों की शक्ति को दर्शाता था। आज परिस्थिति उलट है। किताबें बाजार में उपलब्ध हैं, ई-बुक्स और पीडीएफ आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन पाठक कम होते जा रहे हैं। यह बदलाव केवल तकनीक की वजह से नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली में आए असंतुलन का परिणाम है।

सोशल मीडिया और त्वरित सूचना की संस्कृति ने हमें सतही बना दिया है। किताबें पढ़ने का सबसे बड़ा लाभ है मानसिक एकाग्रता। जब कोई पाठक एक उपन्यास या जीवनी पढ़ता है तो वह लगातार कई घंटे एक ही विषय पर केंद्रित रहता है। यही अभ्यास व्यक्ति की सोचने की शक्ति को गहराई और विस्तार देता है। किताबें हमें धैर्य, तर्कशीलता व संवेदनशीलता सिखाती हैं। इसके विपरीत, आज का दौर 'शॉर्टकट' का है। लोग कुछ सेकंड के वीडियो देखकर ज्ञान का भ्रम पाल लेते हैं। लेकिन गहरी समझ केवल किताबों से ही मिलती है। किताबें हमें जीवन के अनुभवों से जोड़ती हैं, कल्पनाशक्ति को उड़ान देती हैं और मनुष्य को सच्चा विवेकशील बनाती हैं। यह मानना गलत होगा कि डिजिटल माध्यम पूरी तरह किताबों के खिलाफ हैं। ई-बुक्स, ऑडियोबुक्स और ऑनलाइन लाइब्रेरी ने किताबों की पहुंच को आसान बनाया है। समस्या माध्यम की नहीं, बल्कि रुझान की है। यदि लोग चाहें तो डिजिटल साधनों का इस्तेमाल कर भी किताबों की दुनिया में डूब सकते हैं लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हम पढ़ने की आदत को पुनर्जीवित करें। राष्ट्रीय पठन-पुस्तक दिवस केवल औपचारिकता भर नहीं होना चाहिए। यह हमें याद दिलाने का अवसर है कि किताबें हमारे जीवन में कितनी जरूरी हैं। इस दिन का संदेश यही होना चाहिए कि घरों में किताबें सजें और पढ़ी जाएं। स्कूल और कॉलेजों में पुस्तक-पठन प्रतियोगिता हो।

किताबें केवल शब्दों का संग्रह नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और सभ्यता की धड़कन हैं। यदि हम इन्हें नजरअंदाज करेंगे तो आने वाली पीढ़ियों को अधूरी सोच और सतही ज्ञान ही मिलेगा। राष्ट्रीय पठन-पुस्तक दिवस केवल एक प्रतीक नहीं होना चाहिए। यह हमें याद दिलाता है कि अगर किताबें जीवन से ओझल हो गई तो ज्ञान की असली धारा भी सूख जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम फिर से पुस्तकों से दोस्ती कर- चाहे वे मुद्रित हों या डिजिटल। नेशनल रीड अ बुक डे हमें यह चेतावनी देता है कि किताबों से दूरी का अर्थ है अपने ही ज्ञान-संसार से दूरी। पढ़ना केवल शौक नहीं, बल्कि जिम्मेदारी है। किताबों से जुड़ना ही हमें संवेदनशील, विवेकशील और रचनात्मक बनाएगा।

आज का सवाल

आमजन की सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाने को आप कितना प्रभावी मानते हैं?

ईमेल करें: edit@epatrika.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

उम्मीदों की चीप से हौसलों की उड़ान भरता भारत

भारत ने तकनीकी आत्मनिर्भरता की दिशा में एक नया इतिहास रचते हुए अपना पहला पूर्णतया स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर तैयार कर एक तकनीकी क्रांति को आकार दिया है। यह उपलब्धि न केवल वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि राष्ट्रीय गौरव का भी प्रतीक है। भारत ने इस तकनीकी क्रांति की तरफ कदम बढ़ते हुए आत्मनिर्भर एवं स्वदेशी तकनीकी प्रगति को नए आयाम दिए हैं। पहला पूर्णतः स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विकसित करने की उल्लेखनीय उपलब्धि के लिये इसरो की सेमीकंडक्टर लैब साक्षी बनी है। पहली मेड इन इंडिया चिप का उत्पादन गुजरात के साणंद स्थित पायलट प्लांट से शुरू होगा। केंद्र की इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत 18 अरब डॉलर से ज्यादा के कुल निवेश वाली दस सेमीकंडक्टर परियोजनाएं देश में चल रही हैं, अब भारत को इस तरह की तकनीक के लिए विदेशों के पराधीन नहीं होना होगा। इस कड़ी प्रतिस्पर्धा वाले चिप क्षेत्र में भारत की यह दस्तक उत्साह जगाने वाली है, निश्चित ही इससे भारत की ताकत बढेगी और तकनीक के साथ-साथ यह आर्थिक विकास को तीव्र गति देगा। फिलहाल आधुनिक समय की इस जादुई चिप के उत्पादन में ताइवान, दक्षिण कोरिया, जापान, चीन और अमेरिका जैसे देशों का वर्चस्व है। विशेषतः भारत की यह जादूई उपलब्धि अमेरिका को आइना दिखाने वाली है, ट्रंप को यह एक बड़ा झटका है।

भारत इस क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनने के लिये उत्सुक है। तभी सेमीकॉन इंडिया-2025 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि वह दिन दूर नहीं है जब भारत की सबसे छोटी चिप दुनिया में बड़े बदलाव की नींव रखेगी। हालांकि, इस राह में अभी कई चुनौतियां हैं, लेकिन उम्मीद है कि छह सौ अरब डॉलर वाले वैश्विक सेमीकंडक्टर उद्योग में भारत की हिस्सेदारी आने वाले वर्षों में 45 से 50 अरब डॉलर की हो सकती है, जिससे भारत अनेक मोर्चें पर सफलता के परचम फहराएगा। इस स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की अर्धचालक प्रयोगशाला ने अभिकल्पित किया है और इसे 'विक्रम' नाम दिया गया है। यह अंतरिक्ष-मानक माइक्रोप्रोसेसर है, जो मुख्यतः अंतरिक्ष अभियानों और रॉकेट प्रणालियों में प्रयोग के लिए तैयार किया गया है। इसरो ने सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला (एससीएल) चंडीगढ़ के साथ मिलकर दो स्वदेशी 32-बिट माइक्रोप्रोसेसर विक्रम 3201 और कल्पना 3201 विकसित किए हैं। यह माइक्रोप्रोसेसर प्रक्षेपण यानों के नेविगेशन और नियंत्रण में मदद करेंगे। विक्रम 3201 पूरी तरह भारत में बना पहला 32-बिट प्रोसेसर है। इस कदम से इसरो को विदेशी प्रोसेसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा जिससे अंतरिक्ष में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ेगी। निश्चित ही इससे भारत ने महाशक्ति बनने की ओर अपनी गति को तीव्रता दी है, जिससे अमेरिका हिला और दुनिया भारत की ताकत से रू-ब-रू हो रही है।

अब तक भारत को अनेक जटिल अंतरिक्ष अभियानों के संचालन हेतु विदेशी सूक्ष्म-प्रक्रमकों और अर्धचालक पट्टिकाओं पर निर्भर रहना पड़ता था। यह विदेशी निर्भरता न केवल आर्थिक दृष्टि से बोझिल थी बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चुनौतीपूर्ण थी। 'विक्रम' माइक्रोप्रोसेसर के निर्माण से भारत ने इस निर्भरता की बेड़ियों को तोड़ा है और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में सशक्त कदम बढ़ाया है। निस्संदेह, भारत को चिप उत्पादन क्षेत्र में एक दिग्गज देश बनने के लिए निरंतर निवेश, अनुसंधान-विकास और विनिर्माण की आवश्यकता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए निरन्तर प्रयासरत है। हाल ही में प्रधानमंत्री की जापान यात्रा से उम्मीद जगी है कि वह वैश्विक सेमीकंडक्टर डिजाइन पारिस्थितिकीय तंत्र विकसित करने में भारत के लिए मददगार साबित हो सकता है। यह सुखद ही है कि भारत में चिप उत्पादन परियोजनाओं में जापानी निवेश बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री मोदी की विदेश यात्राएं भारत को ऐसे ही विकास के नए शिखरों पर आरोहण कराने का सशक्त माध्यम बन रही है।

निश्चित रूप से मोदी सरकार के प्रयासों से भारत चिप उत्पादन के वैश्विक महत्वाकांक्षी अभियान की दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है। दरअसल, डिजिटल डिवाइसों का मस्तिष्क कहा जाने वाला सेमीकंडक्टर कंप्यूटर, मोबाइल, राउटर, कार, सैटलाइट जैसे उन्नत डिजिटल डिवाइस तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उपकरणों की कार्यकुशलता उन्नत चिप की ताकत पर निर्भर करती है। साधारण शब्दों में कहें चिप पतली सिलिकॉन वेफर पर बने लाखों-करोड़ों ट्रांजिस्टरों का संजाल है। जो कंप्यूट करने, मेमोरी प्रबंधन व सिग्नल प्रोसेस करके डिवाइस को उन्नत बनाती है। उम्मीद है कि भारत का स्वदेशी चिप इस साल के आखिर तक बाजार में आ सकेगी। जिसका असर जियोपॉलिटिक्स पर तो होगा ही, नए रोजगार सृजन का वातावरण भी बनेगा, भारत तकनीकी विकास के नए आयाम उद्घाटित करते हुए विश्व को अचंभित भी करेगा। निश्चय ही भारत यदि अनुसंधान-विकास व व्यापार सुगमता की स्थितियां निर्मित कर लेता है तो हमारी सेमीकंडक्टर आयात के लिऐ दूसरे देशों पर निर्भरता कम हो सकती है। इससे हम वैश्विक दबाव से मुक्त होकर अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बना सकते हैं।

32-बिट क्षमता का अर्थ है कि यह माइक्रोप्रोसेसर अधिक व्यापक स्मृति का उपयोग कर सकता है और जटिल संगणकीय कार्यों को तीव्र गति से संपन्न कर सकता है। अंतरिक्ष अभियानों में जहां प्रत्येक क्षण और प्रत्येक संकेत का महत्व होता है, वहां इस प्रकार की क्षमता अत्यंत आवश्यक है। यह केवल गति और कार्यकुशलता नहीं देता बल्कि विकिरण-सहनशीलता और दीर्घकालीन स्थिरता जैसे गुण भी समाहित करता है। अंतरिक्ष में प्रबल विकिरण, तापमान का उतार-चढ़ाव और कठोर परिस्थितियां होती हैं, जिनका सामना सामान्य माइक्रोप्रोसेसर नहीं कर सकते। इसलिए इस प्रकार का अंतरिक्ष-योग्य माइक्रोप्रोसेसर ही मिशनों की सफलता का आधार बन सकता है। इस उपलब्धि का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि इसके लिए आवश्यक रूपांकन, निर्माण और परीक्षण की सम्पूर्ण प्रक्रिया भारत में ही सम्पन्न की गई है। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत अब केवल प्रौद्योगिकी का उपभोक्ता नहीं बल्कि उसका सर्जक भी है। सूक्ष्म-संगणक की यह अभिकल्पना केवल एक चिप का निर्माण नहीं है, यह भारत की वैज्ञानिक प्रतिभा, उसकी दूरदृष्टि और आत्मविश्वास का परिचायक है।

इस संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान पहले ही 'शक्ति' और 'वेगा' जैसे स्वदेशी माइक्रोप्रोसेसर पर काम कर चुके हैं। इन प्रयासों ने आधारभूमि तैयार की और आज ''विक्रम'' के रूप में वह प्रयास मूर्त रूप में सामने आया है। यह न केवल अंतरिक्ष क्षेत्र बल्कि रक्षा, चिकित्सा उपकरणों और संचार प्रणाली में भी क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकता है। निश्चित ही चुनौतियां भी कम नहीं हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन, उपकरण-समूह की उपलब्धता, संगणक-कार्यक्रमों का विकास, अनुप्रयोग-तंत्र का विस्तार और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रमाणन जैसी प्रक्रियाएं अभी पूरी करनी होंगी। किंतु भारत ने जिस आत्मविश्वास के साथ इस दिशा में पहला कदम रखा है, वह आश्वस्त करता है कि भविष्य में हम और भी उन्नत सूक्ष्म-प्रक्रमक तैयार करने में सक्षम होंगे। ''विक्रम'' केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं है, यह भारत की स्वाभिमानी यात्रा का घोष है। यह घोषणा है कि अब भारत केवल विज्ञान का अनुयायी नहीं बल्कि विज्ञान का निर्माता और मार्गदर्शक बनने की ओर अग्रसर है। आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना अब शब्दों में नहीं, ठोस उपलब्धियों में आकार ले रही है।

ललित गर्ग

भारत का जीएसटी सुधार 2025

किशन सनमुखदास भावनानी

वैश्विक स्तरपर भारत की अर्थव्यवस्था ने पिछले एक दशक में अनेकों उतार-चढ़ाव देखे हैं। वैश्वीकरण, अमेरिकी टैरिफ,तेल कीमतों की अनिश्चितता, महामारी के झटके और डिजिटल क्रांति के बीच भारतीय कर प्रणाली को समय- समय पर नए स्वरूप की आवश्यकता महसूस होती रही है। इसी कड़ी में 3-4 सितंबर 2025 को आयोजित जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक ऐतिहासिक साबित हुई,जब इसमें टैक्स स्लैब को पुनर्संरचित कर 12 पर्सेंट और 28 पर्सेंट की दरों को समाप्त कर दिया गया और सैकड़ों उत्पादों को 5 व 18 पर्सेंट टैक्स स्लैब में स्थानांतरित कर दिया गया। साथ ही अनेक आवश्यक वस्तुओं को 0 पर्सेंट टैक्स स्लैब में डाल दिया गया। यह नया ढांचा 22 सितंबर 2025 से लागू होगा।

साथियों बात अगर हम जीएसटी क्या है?और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की करें तो,वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एक ऐसा अप्रत्यक्ष कर है, जिसे 122वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू किया गया। जीएसटी का मूल उद्देश्य देशभर में एक राष्ट्र,एक टैक्स की अवधारणा को साकार करना था। इससे पहले केंद्र और राज्य स्तरपर उत्पाद शुल्क, सेवा कर, वैट, एंट्री टैक्स और लगान जैसी अनेक परतों वाले कर प्रणाली लागू थे, जिससे व्यापारियों और उपभोक्ताओं दोनों को जटिलताओं का सामना करना पड़ता था। जीएसटी ने इन सबको समेटकर एक एकीकृत कर ढांचा दिया। आज की तारीख में दुनियां के 150 से अधिक देशों में इसी तरह का जीएसटी सिस्टम किसी-न-किसी रूप में लागू है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपीय संघ के अधिकांश देश, मलेशिया, सिंगापुर और यहां तक कि ब्राजील जैसे बड़े देश भी जीएसटी आधारित कर व्यवस्था से जुड़े हुए हैं। भारत का नया सुधार इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अब वह वैश्विक मानकों के अनुरूप टैक्स ढांचे को और सरल बना रहा है।

साथियों बात अगर हम नए ढांचे का स्वरूप, नए टैक्स स्लैब की करें तो, नए सुधार के बाद भारत में अब टैक्स ढांचा मुख्यतः तीन बड़े स्लैब पर केंद्रित हो गया है, 0 पर्सेंट 5 पर्सेंट और 18 पर्सेंट- 0 पर्सेंट स्लैब-गरीब और मध्यम वर्ग की जरूरतों से जुड़े खाद्यान्न, दालें, फल, सब्जियां, स्कूल किताबें, प्राथमिक शिक्षा सेवाएं और जीवनरक्षक दवाइयां इसमें शामिल हैं। यह स्लैब सीधे तौर पर समाज के कमजोर तबकों को राहत देने के लिए बनाया गया है। 5 पर्सेंट स्लैब, इसमें रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुएं, कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स, सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और छोटे व्यापार से संबंधित सामान आते हैं। 18 पर्सेंट स्लैब- इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स, बीमा, निर्माण कार्य, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएं, औद्योगिक उत्पादन, लक्जरी सामान और उच्च मूल्य के कंज्यूमर गुड्स शामिल हैं। 12पर्सेंट और 28 पर्सेंट स्लैब हटाने से टैक्स ढांचा सरल हुआ है। पहले जहां चार से अधिक प्रमुख दरें थीं,अब यह तीन स्लैबों में सिमट गया है, जिससे न केवल व्यापारियों के लिए टैक्स अनुपालन आसान होगा बल्कि आम उपभोक्ता को भी स्पष्टता मिलेगी।

साथियों बातें अगर हम किन क्षेत्रों को मिलेगा लाभ? इसको समझने की करें तो,नए ढांचे के सबसे बड़े लाभार्थी वे क्षेत्र हैं जो प्रत्यक्ष रूप से गरीब, मध्यम वर्ग, उद्योग और सामाजिक जरूरतों से जुड़े हैं। (1)डेयरी प्रोडक्ट्स : दूध, पनीर, दही, घी और पोषण संबंधी उत्पादों पर टैक्स संरचना सरल होने से कीमतें स्थिर रहेंगी। इससे किसानों और उपभोक्ताओं दोनों को लाभ होगा। (2)बीमा क्षेत्र- स्वास्थ्य व जीवन बीमा पर बीमा प्रीमियम पर 0पर्सेंट टैक्स लागू होने से उपभोक्ताओं के लिए प्रीमियम लागत कम हो सकती है। इससे जीवन बीमा, स्वास्थ्य बीमा और पेंशन योजनाओं में भागीदारी बढ़ेगी। (3)निर्माण और आवास-घर बनाने के लिए आवश्यक सीमेंट, स्टील, टाइल्स और सेवाओं पर कर भार कम होने से घर की लागत घटेगी। यह मध्यम वर्ग और रियल एस्टेट उद्योग दोनों के लिए लाभकारी है (4) इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र, मोबाइल, लैपटॉप और घरेलू उपकरणों की कीमतें स्थिर होने से डिजिटल इंडिया अभियान को गति मिलेगी। (5) मेडिकल और पोषण क्षेत्र : जीवन रक्षक दवाओं को 0% स्लैब और अन्य चिकित्सा उपकरणों को 5 पर्सेंट-18 पर्सेंट स्लैब में रखने से स्वास्थ्य सेवाएं सस्ती होंगी। (6) एमएसएमई और बड़े उद्योग- सरल टैक्स स्लैब से छोटे और मझोले उद्योगों को अनुपालन लागत कम होगी, जबकि बड़े उद्योगों को उत्पादन और निर्यात बढ़ाने में बहुत विशाल सहूलियत होगी।

साथियों बात अगर हम जीएसटी रिफॉर्म करने का सरकार का मकसद और आम आदमी का फायदा होने की करें तो,जीएसटी सुधार का सबसे बड़ा मकसद है, (1) गरीबों और मध्यम वर्ग को राहत देना। नई दरों से- गरीब तबके को 0 पर्सेंट टैक्स स्लैब से सस्ते में भोजन और दवाइयां मिलेंगी, (2) घर बनाने वालों को कम खर्च आएगा,(3) बीमा सस्ता होगा, (4) स्वास्थ्य सेवाएं किफायती होंगी, (5) छोटे उद्योगों को प्रतिस्पर्धा में मजबूती मिलेगी,(6) और महंगाई का दबाव घटेगासरकार यह संदेश देना चाहती है कि टैक्स नीति सिर्फ राजस्व बढ़ाने का साधन नहीं, बल्कि आर्थिक न्याय और सामाजिक सुरक्षा का भी सशक्त औजार है।

साथियों बात अगर हम टैक्स के स्लैब में परिवर्तन करने से करीब 85000 करोड़ का घाटा और भरपाई के उपायों को समझने की करें तो, सरकार का अनुमान है कि दरें घटाने और कई वस्तुओं को 0 पर्सेंट टैक्स स्लैब में डालने से उसे लगभग 85,000 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान हो सकता है। लेकिन इसकी भरपाई के लिए बड़े उपाय किए गए हैं, 40 पर्सेंट स्लिप से रिकवरी-टैक्स अनुपालन बढ़ने, ई-इनवॉइसिंग और डिजिटल ट्रैकिंग से टैक्स चोरी में कमी आएगी और इससे राजस्व की बड़ी मात्रा में भरपाई होगी। साथियों बात अगर हम अमेरिकी टैरिफ और भारत की रणनीति को समझने की करें तो, हाल के वर्षों में अमेरिका ने भारत सहित कई देशों के खिलाफ टैरिफ हथियार के रूप में इस्तेमाल किए हैं। इस पृष्ठभूमि में जीएसटी सुधार भारत की आंतरिक ताकत को बढ़ाने का जरिया है। (1) सरल टैक्स ढांचा विदेशी निवेशकों को आकर्षित करेगा। (2) घरेलू उद्योग को प्रतिस्पर्धी बनाएगा।(3)निर्यात लागत कम होने से अमेरिका और यूरोप के टैरिफ का दबाव कम महसूस होगा।यह सुधार संकेत देता है कि भारत आत्मनिर्भरता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा के बीच संतुलन बनाना चाहता है।

साथियों बातें अगर हम जीएसटी सुधारो के पीछे संभव होता है राजनीतिक विमर्श,राहत या सियासत? की करें तो, जब 2017 में जीएसटी लागू हुआ था तब सरकार ने इसे 'वन नेशन, वन टैक्स' कहकर ऐतिहासिक बताया था और तर्क दिया था कि उच्च दरें राजस्व जुटाने के लिए जरूरी हैं। अब 2025 में दरें घटाने पर वही सरकार कह रही है कि, इससे उपभोक्ताओं को राहत और उद्योग को प्रोत्साहन मिलेगा। अब सवाल उठता है, क्या यह आर्थिक विवशता है या राजनीतिक रणनीति?दरअसल, यह दोनों का मिश्रण है। वैश्विक मंदी, अमेरिकी दबाव और घरेलू महंगाई ने सरकार को दरें घटाने पर मजबूर किया। साथ ही, यह कदम गरीबों, मध्यम वर्ग और छोटे उद्योगों को चुनावी वर्ष में राहत देने की रणनीति भी हो सकता है।

साथियों बात अगर हम जीएसटी सुधारो को सामाजिक दृष्टिकोण, जैसे घर के बड़े समझाते हैं थ्योरी को समझने की करें तो, अगर इस सुधार को सामाजिक रूप से समझा जाए तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे घर के बड़े सदस्य बच्चों को जीवन जीने का तरीका बताते हैं (1) भोजन और स्वास्थ्य सबसे पहले-इसलिए खाद्यान्न और दवाइयां 0% स्लैब में। (2)स्वास्थ्य का ध्यान रखोह्न- इसलिए मेडिकल और बीमा क्षेत्र सस्ता। (3)घर बनाओह्न -इसलिए कंस्ट्रक्शन सेक्टर को राहत।(4)बच्चों की पढ़ाई जरूरी है-इसलिए शिक्षा सेवाएं किफायती (5)फालतू दिखावा मत करो-इसलिए लक्जरी सामान पर टैक्स ऊंचा रखा गया।यह सुधार दर्शाता है कि सरकार टैक्स नीति को सिर्फ राजस्व का औजार नहीं, बल्कि समाज के कल्याण का ढांचा मानकर आगे बढ़ रही है।

साथियों बात अगर हम इन जीएसटी सुधारो को अंतरराष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य के रूप में समझने की करें तो, विश्व अर्थव्यवस्था आज दो ध्रुवों में बंटी हुई है, अमेरिकी प्रभुत्व और एशियाई उभार। ऐसे समय में भारत का टैक्स सुधार एक सॉफ्ट पावर मॉडल के रूप में सामने आ रहा है।(1) यूरोप ने भी 2008 मंदी के बाद टैक्स स्लैब घटाकर अर्थव्यवस्था को स्थिर किया था। (2) चीन ने निवेश आकर्षित करने के लिए टैक्स दरें लचीली बनाई थीं।(3) भारत अब उसी राह पर चल रहा है। इससे भारत की छवि निवेश के लिए सुरक्षित और आकर्षक गंतव्य के रूप में मजबूत होगी।

अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि भारत का जीएसटी सुधार 2025 सिर्फ एक वित्तीय पहल नहीं बल्कि आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का प्रतीक है। यह सुधार भारत को न केवल घरेलू स्तर पर महंगाई से राहत दिलाएगा बल्कि वैश्विक मंच पर उसे और मजबूती से खड़ा करेगा।

टूर ऑपरेटर में भी है करियर के सुनहरे मौके

अगर आपको घूमने का शौक है तो लोगों को पर्यटन स्थलों पर घुमाने के काम में अपना करियर बना सकते हैं। हालांकि इस काम के लिए मार्केटिंग में दक्ष होना जरूरी है, पर थीम टूरिज्म और विभिन्न भाषाओं की जानकारी भी सफल टूर ऑपरेटर बनने के लिए जरूरी है। ट्रैवल एंड टूरिज्म इंडस्ट्री में टूर ऑपरेटर्स वे पेशेवर होते हैं, जो पर्यटकों को दर्शनीय स्थलों तक घुमाने के लिए होलीडे पैकेज तैयार करते हैं। एक टूर ऑपरेटर के तौर पर यह आपको ही तय करना होता है कि आपके काम करने का दायरा कहां तक होगा। टूर ऑपरेटर के तौर पर आप दुनिया के किसी भी कोने में दिलचस्प और खास जगहों पर पर्यटकों को ले जा सकते हैं, पहाड़ की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं, मोटर-साइकिल या कार से राज्य, देश या विश्व के भ्रमण का कार्यप्रम तय कर सकते हैं।

टूर ऑपरेटर का काम बड़ा दिलचस्प होता है। वह आकर्षक पैकेज तैयार करता है और उन्हें ट्रैवल एजेंट्स के माध्यम से या सीधे ही लोगों तक पहुंचाता है। यह भी ध्यान रखा जाता है कि जो भी पैकेज तैयार किया जाए, वह इतना आकर्षक हो कि पर्यटक ज्यादा से ज्यादा पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकें और जेब पर भी ज्यादा भार न पड़े। इसमें पर्यटकों की सुविधा का इस तरह ध्यान रखना पड़ता है कि उनका हर टूर यादगार बन जाए और एक टूर ऑपरेटर के तौर पर आप हमेशा के लिए उन्हें याद रह जाएं।

वाणिज्य एवं उद्योग मंडल एसोचौम और यस बैंक के संयुक्त अध्ययन में कहा गया है कि जिस तरह से देश-दुनिया में ट्रैवल एवं टूरिज्म का क्षेत्र बढ़ रहा है, उसे देखते हुए लगता है कि 2019 तक यह क्षेत्र रोजगार उपलब्ध कराने के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा क्षेत्र बन जाएगा।

योग्यता : टूर ऑपरेटर के तौर पर करियर बनाने के इच्छुक अभ्यर्थियों को यह बात पता होनी चाहिए कि केवल कोई विशेष कोर्स कर लेने भर से विशेषज्ञता हासिल नहीं हो जाती। हां, डिग्री, डिप्लोमा जैसी योग्यताएं हासिल करने के बाद इस रूप में काम जरूर किया जा सकता है। आप में बेहतर तरीके से चीजों को व्यवस्थित करने की योग्यता होनी चाहिए, घूमने-फिरने का शौक और अधिक से अधिक भाषाओं की जानकारी हो तो और बेहतर। बतौर टूर ऑपरेटर आपको खास राज्य, खास किस्म के थीम में विशेषज्ञता हासिल करनी होगी, मसलन यदि धार्मिक पर्यटन में आपकी महारत है तो बाजार में इस तरह के पर्यटन के लिए तुरंत आपका नाम लोगों के जेहन में आना चाहिए।

कोर्स : आप विभिन्न संस्थानों से डिग्री, डिप्लोमा, पीजी डिप्लोमा व सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। इसके प्रमुख कोर्स में शामिल हैं एडवांस डिप्लोमा इन ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, बेसिक कोर्स इन एयरलाइन ट्रैवल, फेयर्स एंड टिकटिंग मैनेजमेंट, पीजी डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट, बैचलर ऑफ ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट और एयर ट्रैवल फेयर एंड टिकटिंग जैसे कोर्स प्रमुख रूप से किए जा सकते हैं।

अवसर : यहां आप सरकारी, निजी और मल्टीनेशनल कंपनियों में भी रोजगार तलाश सकते हैं। कुछ निजी कंपनियों जैसे कॉक्स एंड किंग्स, एयरलाइंस, ताज ग्रुप ऑफ होटल्स, मेक माई ट्रिप डॉट कॉम में नौकरियां हैं। इसके अलावा पर्यटन विभाग, होटल उद्योग, एयरलाइंस और ट्रैवल एजेंसियों में आपके लिए द्वार खुले हैं।

वेतन : टूर ऑपरेटर के तौर पर सबसे बेहतर बात तो यही है कि आप अपनी ट्रैवल एजेंसी शुरू करें, लेकिन आपके पास निवेश योग्य इतना धन जरूर होना चाहिए कि आप पूरे टूर ऑपरेशन को संभाल सकें। अगर ऐसा नहीं हो पाता तो सरकारी या निजी क्षेत्र में बतौर टूर ऑपरेटर काम कर सकते हैं। शुरूआती सैलरी की बात करें तो 12 हजार से 20 हजार की आमदनी हो सकती है।

चिंतन-मनन

पशुवध निंदनीय-दंडनीय कर्म

सतोगुण में किये गये पुण्यकर्मो का फल शुद्ध होता है, अतएव वे मुनिगण, जो समस्त मोह से मुक्त हैं, सुखी रहते हैं। लेकिन रजोगुण में किये गये कर्म दुख का कारण बनते है। भौतिक सुख के लिए जो भी कार्य किया जाता है, उसका विफल होना निश्चित है। उदाहरणार्थ, यदि कोई गगनचुम्बी प्रासाद बनवाना चाहता है, तो उसके पूर्व अत्यधिक कष्ट उठाना पड़ता है। मालिक को धन-संग्रह के लिए कष्ट उठाना पड़ता है और प्रासाद बनाने वाले श्रमिकों को श्रम करना होता है। अतएव भगवद्गीता का कथन है कि रजोगुण के अधीन होकर जो भी कर्म किया जाता है, उसमें निश्चित रूप से महान कष्ट भोगने होते हैं।

इससे यह मानसिक तृप्ति हो सकती है कि मैंने यह मकान बनवाया या इतना धन कमाया, लेकिन यह वास्तविक सुख नहीं है। जहां तक तमोगुण का सम्बन्ध है, कर्ता को कुछ ज्ञान नहीं रहता, अतएव उसके समस्त कार्य उस समय दुखदायक होते हैं और बाद में उसे पशु जीवन में जाना होता है। पशु जीवन सदैव दुखमय है, यद्यपि माया के वशीभूत होकर वे इसे समझ नहीं पाते। पशुओं का वध भी तमोगुण के कारण है। पशु-बधिक यह नहीं जानते कि भविष्य में इस पशु को ऐसा शरीर प्राप्त होगा, जिससे वह उनका वध करेगा। यही प्रकृति का नियम है। मानव समाज में यदि कोई किसी मनुष्य का वध कर दे तो उसे प्राणदंड मिलता है। यह राज्य का नियम है। अज्ञानवश लोग अनुभव नहीं करते कि संसार परमेश्वर द्वारा नियंत्रित एक पूरा राज्य है। प्रत्येक जीवित प्राणी परमेश्वर की संतान है और उन्हें एक चींटी तक का मारा जाना सह्य नहीं हैं। इसके लिए मनुष्य को दंड भोगना पड़ता है। अतएव स्वाद के लिए पशु-वध में रत रहना घोर अज्ञान मनुष्य को पशुओं के वध की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईश्वर ने अनेक अच्छी वस्तुएं प्रदान की हैं। यदि कोई किसी कारण मांसाहार करता है, तो यह समझना चाहिए कि वह अज्ञानवश ऐसा कर रहा है और अपने भविष्य को अंधकारमय बना रहा है।

लॉफिंग ज़ोन

रमेश (चपरासी से)-मुझे मालिक से मिलना है।

चपरासी (रमेश से)- किस काम से?

रमेश - मेरे पास कुछ नमूने हैं।

चपरासी - सेक्रेटरी से मिलिए।

रमेश - मैं एक बिल भी लाया हूं।

चपरासी - खजांची को दे आइए। साहब पास कर दे तो ले जाइए।

रमेश - वह मेरे अंकल हैं।

चपरासी - घर पर मिलिए उनसे।

रमेश - आप उन्हें खबर तो दीजिए कि रमेश आया है।

चपरासी - साहब बाहर गए हैं।

रमेश - कब तक लौटेंगे?

चपरासी - मैं उनका नौकर हूं, वह मेरे नौकर नहीं हैं कि मुझको बताकर जाएं कि कब आएंगे।

☺ ☺ ☺

पुलिस अधिकारी (सिपाही से)- जब तुम्हें पता था कि चोर भागकर कहां छिपा है, तो तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं?

सिपाही (पुलिस अधिकारी से)- क्या करता साहब, चोर जिस घर में छिपा था, उसके दरवाजे पर लिखा था- अंदर आना मना है।

☺ ☺ ☺

आज का राशिफल

डॉ. पीएल गौतमाचार्य

शुभ संवत 2082, शाके 1947, सौम्य गोष्ठ, भाद्रपद शुक्ल पक्ष, वर्षा ऋतु, गुरु उदय पूर्वे शुक्रोदय पूर्वे तिथी, चतुर्दशी, शनिवासरे, घनिष्ठा नक्षत्रे, आद्र योगे, गरकरणे, सुबह मकर की चंद्रमा, दोपहर बाद कुंभ की चंद्रमा भद्रा 46/26 अनंत चतुर्दशी व्रत, पंचक प्रारंभ दिन के 10/45 रोग स्नान मु. दक्षिण, पश्चिम दिशा की यात्रा शुभ उत्तम होगी।

आज जन्म लिए संतान का फल....

आज जन्म लिया बालक योग्य, बुद्धिमान, चपल, चतुर, चंचल, स्वाभिमानी तथा उत्तमवृत्ति वाला, योगी-भोगी, संत-महात्मा, त्यागी, वक्ता-अधिवक्ता, उत्तमवृत्ति वाला धनीमानी होगा।

मेष — योजनायें फलीभूत हों, सामाजिक कार्यों में प्रतिष्ठा बढ़ेगी तथा धन का लाभ होगा।

कर्क — कार्ययोजना फलीभूत होगी, परिश्रम एवं प्रयत्न पूर्णतः से सफल एवं संतुष्ट होंगे।

तुला — बिगड़े कार्य बनें, कार्य सफलता से संतोष होगा तथा धन का विशेष लाभ होगा।

मकर — सोचे कार्य परिश्रम से पूर्ण होंगे, कार्यवृत्ति में निश्चय ही सुधार होगा, समय का ध्यान रखें।

वृष — तत्परता एवं परिश्रम से धन का लाभ, कार्य पूर्ण सफलता व सहयोग से बिगड़े कार्य बनेंगे।

सिंह — दूसरों के कार्य में व्यर्थ भ्रमण करना होगा, धन का व्यय तथा मानसिक बेचैनी बढ़ेगी।

वृश्चिक — धन का व्यय होगा, थकावट तथा बेचैनी बनी रहेगी, कार्यवृत्ति में सुधार होगा।

कुंभ — कार्य एवं समय बेकार जायेगा किन्तु मेहनत से समय पर कार्य पूर्ण होगा।

मिथुन — कार्य क्षमता के साधन बनें, कार्ययोजना फलीभूत हो, विशेष कार्य समय पर निपटा लें।

कन्या — अशुद्ध गोचर होने से मानसिक बेचैनी बढ़ेगी, विशेष कार्य स्थिगित रखें, हानि होगी।

धनु — योजनाए फलीभूत होंगी, स्त्री-वर्ग से उल्लास होगा तथा भ्रम से बचकर चलें, समय का ध्यान रखें।

मीन — प्रतिष्ठा बाल-बाल बचे, विशेष कार्य से हानि हो सकती है ध्यान रखें।

दैनिक पंचांग

6 सितम्बर 2025 को सूर्योदय के समय की ग्रह स्थिति

ग्रह स्थिति		लग्नारंभ समय	
सूर्य	सिंह में	कन्या	06.33 बजे से
चंद्र	मकर में	तुला	08.44 बजे से
मंगल	कन्या में	वृश्चिक	10.59 ब.से
बुध	सिंह में	धनु	13.15 बजे से
गुरु	मिथुन में	मकर	15.20 बजे से
शुक्र	कर्क में	कुंभ	17.06 बजे से
शनि	मीन में	मीन	18.39 बजे से
राहु	कुंभ में	मेष	20.10 बजे से
केतु	सिंह में	वृष	21.50 बजे से
राहुकाल		मिथुन	23.48 बजे से
9.00 से 10.30 बजे तक		कर्क	02.01 बजे से
		सिंह	04.17 बजे से

शनिवार 2025 वर्ष का 249 वा दिन **दिशाशूल** पूर्व **ऋतु** वर्षा। **विक्रम संवत्** 2082 **शक संवत्** 1947 **मास** भाद्रपद **पक्ष** शुक्ल **तिथि** चतुर्दशी 01.42 बजे रात्र को समाप्त। **नक्षत्र** धनिष्ठा 22.56 बजे को समाप्त। **योग** अतिगण्ड 11.52 बजे को समाप्त। **करण** गर 14.32 बजे तदनन्तर वणिज 01.42 बजे रात्र को समाप्त। **चन्द्रायु** 13.8 घण्टे **रवि क्रान्ति** उत्तर 06° 25' **सूर्य** उत्तरायन **कलि अहर्गण** 1872459 **जूलियन दिन** 2460924.5 **कलियुग संवत्** 5126 **कल्पारंभ संवत्** 1972949123 **सृष्टि ग्रहारंभ संवत्** 1955885123 **वीरनिर्वाण संवत्** 2551 **हिजरी सन्** 1446 **महीना** रवि उलावल **तारीख** 13 **विशेष** अनंत चतुर्दशी, गणेश विसर्जन।

दिन का चौघड़िया			रात का चौघड़िया		
काल	05.55 से	07.23 बजे तक	लाभ	05.37 से	07.10 बजे तक
शुभ	07.23 से	08.51 बजे तक	उद्वेग	07.10 से	08.42 बजे तक
रोग	08.51 से	10.19 बजे तक	शुभ	08.42 से	10.14 बजे तक
उद्वेग	10.19 से	11.46 बजे तक	अमृत	10.14 से	11.47 बजे तक
चर	11.46 से	01.14 बजे तक	चर	11.47 से	01.19 बजे तक
लाभ	01.14 से	02.42 बजे तक	रोग	01.19 से	02.51 बजे तक
अमृत	02.42 से	04.10 बजे तक	काल	02.51 से	04.23 बजे तक
काल	04.10 से	05.37 बजे तक	लाभ	04.23 से	05.56 बजे तक

चौघड़िया शुभाशुभ- शुभत्व श्रेष्ठ शुभ, अमृत व लाभ, **मध्यम** चर, **अशुभ** उद्वेग, रोग व काल। सभी समय भारतीय मानक समय की मध्य रेखा बिन्दु के आधार पर है अतः आप अपने स्थानीय समयानुसार ही देखें। ■Jagrutidaur.com, Bangalore

धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक

आरएसएस प्रमुख डॉ. मोहन भागवत ने स्पष्ट कहा है कि राम मंदिर एकमात्र ऐसा आंदोलन था, जिसका संघ ने समर्थन किया था और अब काशी और मथुरा सहित ऐसे किसी अन्य अभियान का समर्थन नहीं करेगा। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में अपनी तीन दिवसीय व्याख्यान श्रृंखला के अंतिम दिन सवालों के जवाब में भागवत ने यह भी स्पष्ट किया कि आरएसएस के स्वयंसेवक ऐसे आंदोलनों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र हैं। हिन्दू समाज आग्रह करेगा तो संघ के स्वयंसेवक संस्कृति और समाज के हिसाब से इस प्रकार के किसी अभियान में शिरकत कर सकते हैं। यह व्याख्यान श्रृंखला आरएसएस के 100 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित की गई थी। देश में रोजगार परिदृश्य, संस्कृत की विषय के रूप में अनिवार्यता, भारत की अखंडता, हिन्दू-मुस्लिम एकता, जाति-वर्ण व्यवस्था, जातिगत आरक्षण, भाषा विवाद, भाजपा अध्यक्ष के चयन में विलंब, एक तय आयु में संन्यास जैसे तमाम मुद्दों पर भी संघ प्रमुख ने अपनी बात कही। जहां तक काशी-मथुरा में धर्म स्थल का मसला है, तो यह मामला कोई नया नहीं है, लेकिन राम मंदिर आंदोलन के चलते इसे हिन्दुत्ववादियों ने थोड़े समय के लिए विराम दे रखा था। राममंदिर का निर्माण पूरा होते ही वे हरकत में आ गए। न केवल काशी-मथुरा, बल्कि सम्भल में शाही जामा मस्जिद के सर्वे के मुद्दे के साथ ही अन्य अनेक धर्मस्थलों को लेकर मामलों ने भी जोर पकड़ लिया। बीते साल 24 नवम्बर को शाही जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़क उठी थी। हिंसा मामले की जांच के लिए बने आयोग ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंपी है। सूत्रों के मुताबिक, रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे दंगों के बाद तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बड़े पैमाने पर आबादी में बदलाव, धर्म परिवर्तन और समुदाय विशेष के परिवारों का पलायन हुआ। बेशक, संघ प्रमुख पहले भी कह बार स्पष्ट कर चुके हैं कि हर जगह मंदिर नहीं ढूंढ़ा जाना चाहिए। लेकिन लगता नहीं कि धर्मस्थलों में मंदिर ढूंढे जाने की कवायद थम पाएगी। दरअसल, यह मसला बहुत पहले से धार्मिक से ज्यादा राजनीतिक हो चुका है। मंदिर-मस्जिद-चर्च जैसे धर्मस्थलों के मुद्दे गरमाने लगते हैं, तो अलग माहौल बना देते हैं, जिसके बल पर पक्ष-विपक्ष को अपनी राजनीति को धार देने में सहूलियत होती है। इसलिए ऐसे मुद्दे गरमाए रहने हैं।

गृहकलह में उलझे डोनाल्ड ट्रंप

आरती कुमारी

डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापारी हैं और अपनी इस मानसिकता से बाहर नहीं निकल पाए हैं । सिर्फ सात महीनों के कार्यकाल में ही अपने फैसलों से वो न केवल विदेशों में बल्कि अपने ही देश में घिरते जा रहे हैं । बेशक वो एक व्यापारी हैं लेकिन वहां भी कोई बड़ी उपलब्धि उनके नाम नहीं है. वो केवल अपने पारिवारिक व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं । उनकी वर्तमान हालत को देखते हुए कहा जा सकता है कि उन्हें न तो घरेलू राजनीति की समझ है और न ही वो वैश्विक राजनीति को समझ पा रहे हैं । अभी तक सिर्फ उनकी नीतियों को लेकर सवाल उठाया जा रहा था लेकिन अब उनकी नीयत पर भी सवाल उठा दिया गया है । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने डोनाल्ड ट्रंप पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के साथ अपने परिवार के व्यापारिक हितों के कारण भारत के साथ दशकों पुराने रिश्तों को खतरे में डाल दिया है । सुलिवन का कहना है कि ट्रंप ने निजी फायदे के लिए विदेश नीति का दुरुपयोग किया है जो अमेरिका के दीर्घकालिक हितों के लिए नुकसानदेह है । उन्होंने इसे अमेरिका के लिए बड़ा रणनीतिक दुस्साहस बताया है । देखा जाए तो यह एक बहुत ही गंभीर आरोप हैं क्योंकि इससे यह संदेश जाता है कि ट्रंप को केवल अपने निजी हितों की चिंता है । भारत के प्रति उनकी बेरुखी और सख्ती पर यह आरोप सवालिया निशान लगाते हैं । भारत तो पहले ही पूरी दुनिया में यह बता रहा है कि वो अमेरिका के खिलाफ कुछ नहीं कर रहा है, डोनाल्ड ट्रंप ही बेवजह उसे निशाना बना रहे हैं । अभी तक तो यह माना जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी हितों के लिए भारत को झुकाकर समझौता करना चाहते हैं लेकिन जेक सुलिवन के आरोप कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं । ऐसा नहीं है कि यह बात पहले नहीं कही गई है लेकिन इस तरीके से खुलकर किसी प्रतिष्ठित अमेरिकी ने ट्रंप को निशाने पर नहीं लिया है । यह आरोप उस समय लगाया गया है, जब पूरे अमेरिकी मीडिया में एससीओ शिखर सम्मेलन की खबरें चल रही हैं । इस समय पूरा अमेरिकी मीडिया डोनाल्ड ट्रंप को खलनायक साबित करने पर लगा हुआ है और प्रधानमंत्री मोदी को नायक बनाने पर तुला हुआ है । यह तब हो रहा है जब अमेरिकी मीडिया को भारत विरोधी रवैये के लिए जाना जाता है । जेक सुलिवन ने कहा है कि भारत अमेरिका का विश्वसनीय और मजबूत सहयोगी है, विशेष तौर पर तकनीक, प्रतिभा और आर्थिक क्षमता की दृष्टि से भारत महत्वपूर्ण देश है । उनका कहना है कि भारत के साथ मजबूत संबंध चीन और अन्य वैश्विक खतरों से निपटने में मदद कर सकते हैं । उन्होंने कहा है कि ट्रंप की नीतियों का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है बल्कि उनकी नीतियों के कारण अमेरिका के अन्य मित्र देशों में भी यह संदेश चला गया है कि अमेरिका पर भरोसा करना जोखिम भरा कदम हो सकता है । देखा जाए तो उनकी इस बात में सच्चाई है क्योंकि जापान और आस्ट्रेलिया ने डोनाल्ड ट्रंप की परवाह न करते हुए भारत से अपने संबंधों को बढ़ाने की बात कही है । यूरोपीय देश भी भारत से सहयोग बढ़ाने की बात कर रहे हैं जबकि ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय देश भारत पर अमेरिका की तरह टैरिफ लगा दें । सुलिवन का कहना है कि अमेरिका का वचन ही उसकी ताकत है, इसलिए मित्र देशों को यह भरोसा है कि अमेरिका रणनीतिक साझेदारियों में विश्वसनीय है । उन्होंने कहा है कि ट्रंप की नीति अमेरिका की विश्वसनीयता और अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह लगा सकती है । वास्तव में देखा जाए तो सेलिवन जो कह रहे हैं, वो होने का अंदेशा नहीं है बल्कि हो चुका है । अमेरिका की विश्वसनीयता तो सवालों के घेरे में आ चुकी है और उसके ही मित्र देश उससे परेशान हैं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को अपने टैरिफ वॉर से डराकर मनमाना समझौता करना चाहते हैं । यूरोप सहित कई देशों से उन्होंने ऐसे समझौते कर भी लिए हैं । जिन देशों ने ट्रंप के दबाव में आकर समझौते कर लिए हैं, उन देशों में अमेरिका का विरोध बढ़ता जा रहा है । अमेरिका के मशहूर अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर जॉन मियशीर्मर ने ट्रंप प्रशासन की भारत नीति को बड़ी गलती माना है । उनका कहना है कि तेल खरीदने पर लगाए गए टैरिफ काम करने वाले नहीं हैं । उन्होंने कहा है कि अमेरिका के इस कदम से भारत के साथ रिश्तों को बड़ा नुकसान हुआ है और अब भारत अमेरिका से दूर जा रहा है । उन्होंने कहा कि यह हमारी बहुत बड़ी गलती है, यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहां क्या हो रहा है । उन्होंने ट्रंप पर आरोप लगाया है कि उन्होंने भारत के साथ मजबूत रिश्तों को जहरीला बना दिया है । उनका कहना है कि चीन को रोकना अमेरिका की सबसे बड़ी प्राथमिकता है और इसमें भारत अहम साझेदार है । ट्रंप के कारण भारत हमसे बहुत नाराज है, मोदी न सिर्फ रूस बल्कि चीन के भी करीब आ रहे हैं । उन्होंने इसके लिए ट्रेड सलाहकार नवारो को जिम्मेदार बताते हुए कहा है कि उनकी नीतियों का उल्टा असर हो रहा है । उन्होंने कहा है कि भारत को झुकाने की कोशिश की जा रही है लेकिन भारत जो कदम उठा रहा है उससे पता चलता है कि यह रणनीति गलत है । अमेरिका के पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन बोल्टन का कहना है कि सोवियत संघ से नजदीकी और चीन से बढ़ते खतरे के बावजूद पश्चिमी देशों ने भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए थे, लेकिन ट्रंप के टैरिफ ने दशकों पुरानी सारी मेहनत बर्बाद कर दी है । उन्होंने कहा है कि ट्रंप ने आर्थिक दृष्टिकोण अपनाकर रणनीतिक फायदों को खतरे में डाल दिया है । उनका कहना है कि ट्रंप के कारण चीनी राष्ट्रपति शी चिनफिंग को पूर्वी देशों के साथ अपने रिश्ते सुधारने का मौका मिल गया है, ट्रंप की अपनी विनाशकारी टैरिफ नीति के कारण सारे प्रयासों पर पानी फिर गया है। उनका कहना है कि ट्रंप कूटनीति को समझना ही नहीं चाहते है, उन्होंने चिनफिंग को पूर्व के साथ रिश्ते बेहतर करने का मौका दे दिया है। वास्तव में देखा जाए तो इन लोगों द्वारा जो कुछ कहा जा रहा है, वो एससीओ की बैठक से सच साबित होता दिखाई दे रहा है । जिस पाकिस्तान को अमेरिकी राष्ट्रपति गोद में उठाकर घूम रहे हैं, उस पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को उस बैठक में कोई पूछने वाला नहीं था । ट्रंप पाकिस्तान को भारत के बराबर रखकर देख रहे हैं लेकिन चीन और रूस ने दिखा दिया है कि भारत की ताकत क्या है । अमेरिकी मीडिया भारत विरोधी रवैया रखता है और भारत को ज्यादा महत्व नहीं देता लेकिन एससीओ की सफल बैठक के बाद भारत अमेरिकी मीडिया की सुर्खियों में छाया हुआ है । अमेरिकी मीडिया ने डोनाल्ड ट्रंप को भारत-अमेरिकी संबंधों को खराब करने के लिए खलनायक की तरह पेश करना शुरू कर दिया है । कहा जा रहा है कि चीन नई विश्व व्यवस्था का समीकरण तैयार कर रहा है । प्रधानमंत्री मोदी के चीन में हुए भव्य स्वागत और चीन के राष्ट्रपति का उनके साथ व्यवहार अमेरिकी मीडिया की सुर्खियां बना हुआ है । वाशिंगटन पोस्ट ने लिखा है कि राष्ट्रपति शी चिनफिंग एससीओ को सिर्फ सुरक्षा मंच नहीं बल्कि आर्थिक-सहयोगी ब्लाक बनाना चाहते हैं । सीएनएन, न्यूयॉर्क टाइम्स, ब्लूमबर्ग समेत ज्यादातर अखबारों में इस बात का उल्लेख किया गया है कि ट्रंप ने अमेरिका की 25 सालों की मेहनत बर्बाद कर दी है । अमेरिकी मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने एक झटके में भारत को रूस और चीन के खेमे में खड़ा कर दिया है । अमेरिकी मीडिया चिंता जता रहा है कि पीएम मोदी की रूस और चीन से नजदीकी उन्हें धीरे-धीरे अमेरिका से दूर कर रही है । द इकोनॉमिस्ट ने एससीओ शिखर सम्मेलन को भारत और चीन के बीच सुधरते रिश्तों का एक शानदार उदाहरण बताया है । द इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि ट्रंप के बेमतलब फैसलों ने भारत को अमेरिका से दूर कर दिया है । अखबार ने लिखा है कि चिनफिंग ने इस कार्यक्रम का इस्तेमाल चीन की वैश्विक ताकत का प्रदर्शन करने के लिए किया है । न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि रूस और भारत के नेताओं की यात्रा के जरिये चीन ने दिखाया है कि शासन कला, सैन्य शक्ति और इतिहास का उपयोग कैसे किया जा सकता है । अखबार लिखता है कि भारत, अमेरिका के लिए चीन का आर्थिक विकल्प था लेकिन ट्रंप ने उसे खत्म कर दिया है । वॉल स्ट्रीट ने लिखा है कि ट्रंप की नीतियों ने दुनिया को हिला दिया है, चीन इस मौके पर खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश कर रहा है । अमेरिकी मीडिया का ट्रंप के खिलाफ यह अभियान शायद ही उन्हें सोचने के लिए मजबूर करे । उम्मीद की जा रही है कि 2026 के मध्यावधि चुनाव के पहले ट्रंप की नीतियों में कुछ बदलाव हो । हमें उम्मीद करनी चाहिए कि डोनाल्ड ट्रंप को जल्दी समझ आ जाए कि भारत और अमेरिका स्वाभाविक रूप से सहयोगी देश हैं । भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है और सबसे बड़ा लोकतंत्र है । भारत सरकार दोनों देशों के रिश्तों को ज्यादा खराब होने से बचाने के लिए बदले की कार्यवाही नहीं कर रही है । भारत सरकार जानती है कि अमेरिका से रिश्ते भारत के लिए जितने बहुत जरूरी हैं, उतने ही अमेरिका के लिए भारत से रिश्ते जरूरी हैं ।

आरक्षण को लेकर मराठा और ओबीसी के बीच पेच फंसे

कांतिलाल मांडोत

महाराष्ट्र में आरक्षण को लेकर मान्यता दे दी गई है।कई दिनों से चली आ रही चर्चा का अंत हो गया है।लेकिन कैबिनेट मंत्री नेता छगन भुजबल को यह भय है, कि कही मराठा आरक्षण ओबीसी कैटेगरी से नही दे ?ओबीसी कैटेगरी से मराठा को आरक्षण देने की चर्चा भीअगर की है तो राज्यव्यापी आंदोलन करन की चेतावनी भुजबल ने दी है।मराठा आरक्षण को दस प्रतिशत आरक्षण देनेकी घोषणा की गई थी।सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय 50 फीसदी आरक्षण सिमा से अधिक होने के कारण रोक लगा दी थी।2024 मेंभी आरक्षण का मुद्दा उठाया था।तत्कालीन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के आश्वासन से जरांगे ने 2024 में धरना समाप्त कर दिया था।मराठा आरक्षण आंदोलन के मुखिया हजारो समर्थकों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे मनोज जरांगे ने मुख्यमंत्री फड़सवीस के आश्वासन के बाद गत दिन आरक्षण की समस्या का अंत आते देख अनशन खत्म कर दिया।जरांगे मराठा समुदाय को ओबीसी कैटेगरी के लिए आरक्षण की मांग कर रहे थे।ओबीसी समुदाय सख्त तेवर अपनाया है।महाराष्ट्र में मराठा ओबीसी की लड़ाई सख्त हो गई है।सरकार ने आश्वासन दे दिया है,लेकिन अब लड़ाई मराठा और ओबीसी के बीच संघर्ष का कारण बन चुका है।महाराष्ट्र में हैदराबाद गजट में ओबिसी कैटगरी के साथ अन्याय नही होने दिया जाएगा।भाजपा ने स्पष्ट कर दिया है कि ओबिसी कैटेगरी को नुकसान नही होगा।सरकार पर भरोसा किया जाए।जब सुप्रीम कोर्ट ने प्रतिबंध लगा दिया है तो सरकार मराठा समुदाय के लिए कौनसा मार्ग प्रशस्त करेगा?मनोज जोशी ने मराठा समाज को कुनबी समाज का दर्जा देने की मांग और मराठा आरक्षण के लिए अनशन पर बैठे थे।लेकिन मनोज जोशी ने सरकार की स्वीकृति के बाद अनशन खत्म कर दिया है।अब पूरी जवाबदारी सरकार की है।कुनबी समाज का प्रमाणपत्र देने की मांग को लेकर मराठा समाज आश्वस्त है और सरकार ने लड़ाई खत्म करने के लिए मराठा समुदाय की सभी 8 में से 6 बाते स्वीकार कर अनशन खत्म करने का आग्रह किया।आंदोलन को राजनीतिक चश्मे से देखा गया है।सरकार महा टेंशन के दौर से गुजर रही है।महाराष्ट्र देवेंद्र फड़सवीस के लिए मराठा आरक्षण एक चुनौती से कम नही है।फड़सवीस के लिए एक तरफ कुआ तो दूसरी तरफ खाई है।सुप्रीम के प्रतिबंध के बावजूद सरकार ने अपनी जवाबदेही पर मराठा समुदाय को आरक्षण दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने मराठा आरक्षण को असंवैधानिक करार दिया।तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के कार्यालय में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के लिए दिया गया था।लेकिन इनकी मांग गुमराह करने वाली है।महाराष्ट्र में ओबोसी और मराठा के विरोध के बीच सरकार की अग्नि परीक्षा है।क्योंकि भाजपा का महाराष्ट्र में बहुत बड़ा जनाधार है।इन दोनों समुदाय पर महाराष्ट्र की राजनीति का आधार है।इसलिए महाराष्ट्र सरकार इन दोनों समुदाय से किनारा हरगिज नही कर सकता है।2020 में सुप्रीम कोर्ट की पांच जजो की खंडपीठ ने आरक्षण पर रोक लगा दी थी।महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर अमलीजामा पहना दिया है।भाजपा के लिए तलवार की धार है।मराठा समाज को खुश करते ही ओबोसी कैटेगरी नाराज हो गई है।उसी को लेकर सरकार की चिंता में वृद्धि हुई है।जरांगे की बात को हल्के में ले रही सरकार के लिए ओबिसी कैटगरी

को कही न कही नाराज करने की चर्चा है।क्योंकि मराठा के लिए कुनबी समाज का प्रमाणपत्र मिल जाता है तो कुनबी समुदाय के लिए कई फायदे मिल सकते है।क्योकि सरकार की ऐसी कोई धारणा नही है कि इतनी बड़ी समाज को नाराज किया जाए।कुनबी एक कृषि समुदाय है,जो ओबिसी कैटेगरी में आता है।इससे सरकार से आरक्षण का लाभ मिल सकता है।लिहाजा कुनबी प्रमाण पत्र की मांग की जा रही है।मराठा समुदाय के पास जमीन का स्वामित्व प्रमाण नही भी है,वे 1967 के पूर्व उस क्षेत्र में रहते थे और किसी के पास जाति प्रमाणपत्र है तो वो परिवार हलफनामा देकर रिश्तेदारी साबित कर सकते है।इन दोनों समुदाय ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है।मराठा आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के कार्यकाल में भी आंदोलन की चिंगारी पूरे देश मे पहुंच गई थी।देश से आंदोलनकारियों की बडी भीड़ मुम्बई पहुंचने से व्यवस्था भी चरमरा गई थी।यातायात के लिए भी स्थिति गम्भीर बन चुकी थी।लेकिन तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और इस बार महायुति सरकार के आश्वासन के बाद मनोज जरांगे ने अनशन खत्म कर दिया है।कुनबी प्रमाणपत्र और मराठा आरक्षण की दोनो जवाबदेही मुख्यमंत्री के हाथ है।सरकार की एक रूपता पर भरोसा है।दरअसल,भाजपा पर भरोसा किया है।मराठा आरक्षण के लिए आठ मांग रखी गई थी।उसमें सरकार ने छह मांग स्वीकार कर कई वर्षों से आ रही परेशानियों का अंत कर दिया है।महाराष्ट्र सरकार में अपने ही मंत्री छगनलाल भुजबल ने मोर्चा खोल दिया है।महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री छगन भुजबल की नाराजगी के कारण ओबिसी समुदाय की भृकुटि तन गई है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री देवेन्द फड़सवीस और सरकार डैमेज कंट्रोल के लिए जुट गई है। भुजबल ने कहा कि मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि सीएम फडणवीस मराठा समाज को लेकर ऐसा फैसला करेंगे।इस मामले को कोर्ट तक ले जाऊंगा और कानूनी लड़ाई लड़ूंगा। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और कैबिनेट उप-समिति ने मराठा आरक्षण के फैसले से पहले न तो मंत्रिमंडल को विश्वास में लिया और न ही ओबीसी समुदाय से चर्चा की।मैंने सोचा भी नहीं था कि उप-समिति और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ऐसा फैसला लेंगे।अब आगे के समीकरण तय करेंगे कि छगन भुजबल और ओबीसी समाज को नाराज किये बिना महाराष्ट्र सरकार मराठा समाज को दिये भरोसे को कायम रख पाएंगे?

आज का राशिफल

मेष राशि- आज का दिन आपके लिए बेहतर रहेगा। आज आप बिजनेस में अच्छा लाभ कमायेंगें, भौतिक – सुख सुविधाओं की बढ़ोत्तरी होगी। इस राशि के छात्रों का दिन खुशनुमा रहेगा, किसी टेस्ट पेपर में आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगें। आज आप दूसरों की बातों को भी अहमियत देंगें और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगें, इससे आपको लाभ मिलेगा।

वृष राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आप पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करेंगें, भविष्य में आपको बढ़िया लाभ होगा। आज आप अटके हुए कार्यों को पूरा करेंगें, जिससे आप अपने अन्य कार्यों को भी आगे बढ़ा पायें। इस राशि के व्यक्ति आज अपने जीवनसाथी को लेकर कहीं धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं।

मिथुन राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहेगा। आज रोजगार की तलाश ख़त्म होगी, आपको किसी अच्छी कम्पनी से ऑफर मिलने की सम्भावना हैं। आज ऑफिस के कामों में दूसरों की राय लेने से बचें, बेहतर यही होगा की किसी अपने की काम में मदद लें... तो काम आसानी से सफल होंगे। आज पारिवारिक रिश्ते में मधुरता बढ़ेगी, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का मौका मिलेगा।

कर्क राशि- आज का दिन आपके लिए लाभदायक रहेगा। आज आप कारोबार में पैसे के लेन – देन में जल्दबाजी न दिखाएं। आज आप अपने ध्यान को केन्द्रित कर काम को पूरा करने की कोशिश करें। आज आपका दाम्पत्य जीवन खुशहाल रहेगा, बच्चे भी आपको खुश होने की वजह देंगें। इस राशि के स्टूडेंट्स किसी प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म भी भर सकते हैं या इन्टरव्यू में जा सकते हैं।

सिंह राशि- आज का दिन आपके अनुकूल बना रहेगा। आज आप सामाजिक कार्यों में व्यस्त रहेंगें, किसी वरिष्ठ व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी। आज आप जीवनसाथी के लिए उपहार खरीदेगें साथ ही घर की साज-सजावट के लिए घरेलू उपकरणों से जुड़ी ख़रीददारी भी कर सकते हैं। इस राशि की महिलाएं आज किसी काम की शुरुआत कर सकती हैं, जिसमें परिवार का पूरा साथ मिलेगा।

कन्या राशि- आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज के दिन की शुरुआत आप किसी अच्छी आदत के साथ करेंगें, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। आज आपका मन रचनात्मक कार्यों में लगेगा, आप पेंटिंग भी कर सकते हैं। आज आपको मेहनत और अच्छे व्यवहार के कारण वो सब मिलेगा, जिसके आप हक़दार हैं। आज आप अपनी योजनाओं को गुप्त ही रखें अन्यथा विरोधी इसका लाभ उठा सकतें हैं।

तुला राशि- आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है। आज आपको व्यापार में बड़ा धन लाभ होगा, जिससे आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आज आप अपने कार्यक्षेत्र में कामयाबी का परचम लहरायेंगे। आज आप खुद को मेंटली और फिजिकली फिट महसूस करेंगे। अगर आप नया वाहन खरीदने की सोच रहें है तो खरीद सकतें हैं। आज आपको घर की सफाई के दौरान कोई खोई हुई चीज वापस मिल सकती है।

वृश्चिक राशि- आज का दिन आपके लिए फेवरेबल रहेगा। आज आप मेहनत और लगन से किसी काम को करने में सफल रहेंगें, जिससे पेरेंट्स भी गर्व महसूस करेंगें। आज किसी करीबी से आपको खुशखबरी मिलेगी, आपके घर का माहौल भी खुशनुमा बना रहेगा। आज आप जरूरतमंदो की मदद करेंगें, आपको आशीर्वाद की प्राप्ति होगी।

धनु राशि- आज का दिन आपके लिए ठीक – ठाक रहेगा। आज आपको ट्रान्सफर से जुड़ी सूचना प्राप्त हो सकती है, जो आपके काम को आसान बनाएगी। अगर आप किसी नए व्यापार की शुरूआत करना चाह रहें है तो आज शुरूआत कर सकते है। इस राशि के व्यक्तियों को अपने जीवनसाथी से आज बहुत सारा प्यार मिलेगा। जीवनसाथी के साथ आप कहीं धार्मिक स्थलों पर जाने का मन बना सकते है।

मकर राशि- आज का दिन आपके लिए मिला – जुला रहने वाला है। आज आपका काफ़ी समय से रुका हुआ काम पूरा होने से आपको ख़ुशी मिलेगी। आज आप बिज़नेस में परिवर्तन को लेकर विचार – विमर्श कर सकते हैं साथ ही ऑफिस में आपकी क्रिएटिविटी पहले से अच्छी बनेगी। इस राशि के लवमेट के लिए बढ़िया दिन है, आप मूवी देखने का प्लान बना सकतें हैं।

कुम्भ राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। आज आपको कार्यस्थल पर थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन किसी सहकर्मी से मदद भी मिल सकती है। साथ ही किसी विदेशी कम्पनी से जॉब का ऑफर आ सकता है। जिसे ज्वाइन करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज आपका मन रचनात्मक चीजों में अधिक लगेगा, आप बच्चों को ड्राइंग बनाना भी सिखा सकतें हैं।

मीन राशि- आज का दिन आपके लिए अच्छा रहने वाला है। आज आपका ध्यान नयी चीजों के प्रति आकर्षित होगा, आपके मन में कुछ बड़ा करने की प्रेरणा होगी। काफी लम्बे समय बाद आपको घर जाकर आज बच्चों से मिलने का मौका मिलेगा। आज मार्केट में रुका हुआ पैसा आपको मिल जायेगा, जिससे आपका काम आगे बढेगा। इस राशि के स्टूडेंट के लिए आज का दिन शुभ रहने वाला है आज आपको शिक्षकों से प्रशंसा मिलेगी।

कांग्रेस के लिए अभी भी 'दिल्ली' बहुत दूर है

मनोज कुमार मिश्र

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार तेजस्वी यादव के साथ पूरे बिहार का दौरा करने के बाद कांग्रेस के सबसे बड़े नेता माने जाने वाले राहुल गांधी अपने लोगों में यह जताने का प्रयास कर रहे हैं कि उन्होंने बिहार जीत लिया। बिहार विधानसभा का चुनाव आने वाले दिनों में होने वाला है। जिसमें इस बार भी मुख्य रूप से राजद-कांग्रेस की अगुवाई वाले महागठबंधन बनाम भाजपा-जनता दल (एकी) की अगुवाई वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) के बीच चुनावी मुकाबला होना लगभग तय है। जिस कांग्रेस ने आजादी के बाद से बिहार में करीब चालीस साल शासन किया है, उसके नेता बड़े गर्व के साथ एक तरह से राजद का पिछलग्गू बनना स्वीकार लिया। देश में राजग, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पराजित करने का सपना देखने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी दिल्ली समेत उन राज्यों में भी पार्टी को नहीं खड़ी कर पा रहे, जहां अतीत में कांग्रेस सालों तक शासन में रही है। वास्तविकता तो यह है कि कुछ अपवादों को छोड़कर जिन-जिन राज्यों में कांग्रेस एकबार पराजित हुई, वहां उसकी वापसी ही नहीं हो पाई। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष ने भाजपा पर संविधान बदलने के बेबुनियाद आरोप लगा कर मुद्दा बनाने की कोशिश की। उससे कुछ भ्रम की स्थिति बनी लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में लगातार तीसरी बार राजग केन्द्र में सरकार बनाने में कामयाब हुआ और राजग का दायरा बढ़ता गया। लोकसभा चुनाव में दिल्ली की सात सीटों की स्थिति देखें तो आम आदमी पार्टी (आआपा) के साथ सीटों के तालमेल के साथ यहां उतरी कांग्रेस ने 3 और आआपा ने 4 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे। चुनाव में सभी 7 सीटें भाजपा लगातार तीसरी बार जीती। कांग्रेस को 18.50 फीसद वोट मिले। आआपा को लगा कि उसके साथ तालमेल से कांग्रेस मजबूत हो जाएगी और देर-सबेरे आआपा को ही नुकसान पहुंचाएगी। इसलिए उसने दिल्ली विधानसभा चुनाव अकेले लड़ना तय किया। नतीजा यह हुआ कि भाजपा को जीत मिली और 27 साल बाद दिल्ली की सत्ता में उसकी वापसी हुई। दस साल से दिल्ली में सरकार चला रही आआपा को उससे केवल दो फीसदी वोट कम मिले लेकिन सीटों का फासला काफी रहा। 70 सदस्यों वाली दिल्ली विधानसभा में भाजपा 45.86 वोट के साथ 48 और आआपा 43.57 फीसद वोट के साथ 22 सीटों पर जीत पाई। कांग्रेस को करीब 6 फीसदी वोट मिले। खास बात यह है कि चुनाव नतीजों के बाद भाजपा के साथ-साथ कांग्रेस के नेता भी प्रसन्न थे। उन्हें लगता था कि आआपा की पराजय के साथ कांग्रेस की वापसी होगी लेकिन अभी तक एक भी कार्यक्रम ऐसा न हुआ जिससे लगे कि कांग्रेस दिल्ली में वापसी के लिए कोई प्रयास कर रही है। न ही आआपा में कोई भगदड़ मची। साल 2006 के परिसीमन में पूर्वी दिल्ली सीट दो हिस्सों में (पूर्वी दिल्ली और दिल्ली उत्तर पूर्व) बंटी। उससे पहले पूर्वी दिल्ली सीट से दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के पुत्र संदीप दीक्षित सांसद थे जो परिसीमन के बाद 2009 में उसकी एक सीट से सांसद बने और साल 2014 में पराजित हुए। 2019 में पूर्वी दिल्ली की दूसरी सीट दिल्ली उत्तर पूर्व से उनकी मां और दिल्ली की 15 साल मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित चुनाव लड़ी और पराजित हुई। शीला दीक्षित साल 2019 में आआपा से समझौते का विरोध किया तो उन्हें पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के साथ जबरन लोकसभा चुनाव लड़वाया गया। सत्ता सुख भोगने की आदत पड़ जाने के चलते एक ही चुनाव की हार ने कांग्रेस को संकट में ही ला दिया। अपनी चिंता में लगे नेताओं ने पार्टी को हाशिए पर ला दिया। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव की हार के बाद से पार्टी लगातार बिखरती ही गई। साल 2015 के चुनाव के समय पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष थे अरविंद सिंह लवली और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बना दिया गया अजय माकन को। इससे नाराज लवली ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष बने अजय माकन ने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में आआपा से तालमेल की मुहिम चलाई। बताया गया कि कांग्रेस का एक वर्ग सात में से दो सीटों पर भी समझौता करने को तैयार हो गया था। जिस पार्टी ने कांग्रेस को हाशिए पर पहुंचाया उससे समझौता करने का शीला दीक्षित ने कड़ा विरोध किया। समझौता न होने पर भारी मन से अजय माकन नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़कर हारे। उन्होंने भी बिना प्रदेश अध्यक्ष तय हुए बीमारी के बहाने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी छोड़ दी। त्रासदी यह है कि वही अजय माकन आज की तारीख में राहुल गांधी के बेहद करीबी हैं। उन्हें लोकसभा चुनाव हारने के बाद पहले हरियाणा से और वहां से पराजित होने के बाद कर्नाटक से राज्यसभा का सदस्य बनाया गया। वे पार्टी के कोषाध्यक्ष हैं और बिहार चुनाव के सुपर प्रभारी। साल 2013 में दिल्ली विधानसभा चुनाव हारने के बाद से कांग्रेस का दिल्ली में प्रयोग ही चल रहा है। साल 2020 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली और कांग्रेस का वोट औसत घटकर 4.26 हो गया। साल 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में शीला दीक्षित के निधन के बाद चौधरी अनिल कुमार प्रदेश अध्यक्ष बने। लवली थोड़े ही समय भाजपा में रहकर कांग्रेस में लौट आए और 2019 का लोकसभा चुनाव पूर्वी दिल्ली सीट से मजबूती से लड़े। उन्हें 2023 में अनिल कुमार के इस्तीफा देने पर दोबारा अध्यक्ष बनाया गया था लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे में अपनी भूमिका न होने से नाराज होकर उन्होंने फिर कांग्रेस छोड़ कर भाजपा का दामन पकड़ लिया। अब विधायक बनने के बाद भाजपा ने उन्हें यमुना पार विकास बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया है। उसी दौरान बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता भाजपा में शामिल हुए। अब आर्थिक रूप से संपन्न पूर्व विधायक देवेन्द्र यादव दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष हैं। दिल्ली में कांग्रेस वहीं पहुंच गई जहां भाजपा और कांग्रेस के अलावा मजबूत तीसरे दल वाले राज्य में पहुंच गई है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अगुवाई में भाजपा ने गुजरात, मध्य प्रदेश में कांग्रेस को सालों से सत्ता से बेदखल कर दिया। तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, झारखंड उत्तराखंड, बिहार और पंजाब इत्यादि में तो उसकी सत्ता में वापसी संभव नहीं लग रही है। हर राज्य में कांग्रेस क्षेत्रीय दलों की कृपा से कुछ सीटें पा जाती है। देश में भाजपा का विकल्प बनने का सपना देख रही कांग्रेस अपने शासित राज्यों कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश के अलावा शायद ही किसी राज्य में अपने बूते सरकार बना पाएगी- इसकी भविष्यवाणी करना बहुत कठिन नहीं है। राजस्थान या छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के भी समीकरण बदल गए हैं। कांग्रेस के इस कदर बुरे दिन आ गए हैं कि वह उन दलों के साथ उनसे कम सीटों पर चुनाव लड़कर अपने को धन्य मान रही है, जिनके वजूद ने उसे हाशिए पर पहुंचा दिया है। सीधे शब्दों में कहें तो कांग्रेस इन्हीं क्षेत्रीय दलों के बूते भाजपा के मुकाबले बड़ी राष्ट्रीय पार्टी बनी हुई है और इसी के भरोसे देश पर राज करने का सपना देख रही है। पहले ईवीएम (इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन) के खिलाफ कांग्रेस काफी समय से अभियान चला रही है। जबकि ईवीएम से चुनाव कांग्रेस राज में ही शुरू हुआ था। इतना ही नहीं जब कांग्रेस किसी राज्य में जीतती है तब ईवीएम पर कुछ नहीं बोलती। केवल हारने पर ईवीएम मुद्दा होता है।

राहतकारी जीएसटी

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद घोषित जीएसटी की नई दरें 22 सितंबर से लागू करने करने की घोषणा की गई है। जिसमें अब 12 व 28 फीसदी के दो स्लैब को खत्म करके सिर्फ 5 व 18 फीसदी कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि यह सरकार की ओर से आर्थिक सुधारों की कड़ी में एक नई पहल है, जिससे जीएसटी को तार्किक बनाने व आम जनता को महंगाई से राहत देने का प्रयास है। वहीं दूसरी ओर विलासिता आदि वस्तुओं के लिये चालीस फीसदी का एक नया स्लैब जोड़ा गया है। विपक्ष इसे देर से उठाया गया कदम बता रहा है, तो सरकार आर्थिक सुधार की दिशा में बड़ा कदम। वहीं कुछ अर्थशास्त्री इस कदम को ट्रंप के टैरिफ वॉर के परिप्रेक्ष्य में उठाया गया सुरक्षात्मक कदम मानते हैं। जिससे घरेलू खपत को बढ़ाकर निर्यात घाटे को कम किया जा सके। वहीं कुछ लोग इसे नवरात्र में दिवाली से पहले सरकार का तोहफा बता रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार की सोच है कि आर्थिक सुधारों के जरिये घरेलू उपभोग व निवेश को बढ़ाया जाए। निस्संदेह, इससे भारतीय अर्थव्यवस्था का विस्तार होगा। यही वजह है कि कुछ अर्थशास्त्री जीएसटी दरों को घटाने को साहसी व दूरदर्शी कदम बताते हैं, जो उपभोक्ता के उपभोग को बढ़ाएगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने एक जुलाई 2017 को पूरे देश में जीएसटी लागू किया था। उसके बाद समय-समय पर विभिन्न उत्पादों की दरों में परिवर्तन किए जाते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद विपक्षी दलों द्वारा शासित सरकारें कई उत्पादों पर जीएसटी दरें तार्किक बनाने की मांग करती रही हैं। जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी दर घटाने की मांग की थी। इतना ही नहीं, कुछ उद्योगों, विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों व जन-स्वास्थ्य से जुड़ी वस्तुओं के उत्पादकों द्वारा जीएसटी कम करने की मांग की जाती रही है। इसी तरह किसान संगठन भी कृषि उत्पादों पर कर कम करने की मांग करते रहे हैं। वहीं दूसरी ओर जीएसटी दरों में बदलाव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाते रहे हैं। उनका मानना है कि इसकी पृष्ठभूमि में ट्रंप के टैरिफों को कम करने की कवायद भी है ताकि घरेलू उपभोग बढ़ाया जा सके और सस्ते निर्यात को बढ़ावा मिल सके। कालांतर इससे देश की अर्थव्यवस्था को गति मिल सकेगी। इसका संकेत प्रधानमंत्री ने पंद्रह अगस्त को लाल किले से संबोधन में भी दिया था। वहीं आगामी वर्ष मार्च में राज्यों को राहत देने वाले कम्पन्सेशन सेस की समाप्ति से पहले राज्यों को राहत देने के लिये भी यह कदम उठाया गया हो सकता है। निस्संदेह, इस कदम से सरकारी खजाने में जीएसटी कम आएगा, लेकिन आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि विलासिता की वस्तुओं पर चालीस फीसदी का जीएसटी सरकार के घाटे की पूर्ति में किसी हद तक मदद करेगा। फिर भी कहा जा रहा है कि सरकार को अड़तालीस हजार करोड़ का नुकसान हो सकता है, लेकिन चीजें सस्ती होने पर उपभोग वृद्धि से सरकार को राहत मिल सकती है। वहीं कहा जा रहा है कि असंगठित क्षेत्र को जीएसटी कटौती दर का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थशास्त्री लंबे समय से मांग करते रहे हैं कि देश में सबसे ज्यादा रोजगार देने वाले असंगठित क्षेत्र को आर्थिक सुधारों का लाभ दिया जाना चाहिए।

बिहार में इस बार प्रशांत करेंगे बड़ा खेल

राधा रमण

बिहार में सियासी सरगर्मी चरम पर है। राज्य में विधानसभा चुनाव की घोषणा अगले माह होने की संभावना है। ऐसा इसलिए कि चुनाव आयोग ने अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन इस माह 30 सितंबर को करने की घोषणा की है। वैसे भी बिहार विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त हो रहा है। उसके पहले चुनावी गतिविधियां हर हाल में समाप्त करनी होंगी और नई सरकार का गठन करना संवैधानिक मजबूरी है।

इस बार भाजपा बिहार में सरकार बनाने पर आमादा दिखती है। उसके लिए ह्यअभी नहीं तो कभी नहींह्ल की स्थिति है। फिलहाल प्रदेश में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। उसके 80 विधायक हैं। भाजपा के लिए यह संख्या सर्वाधिक है। 243 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के लिए कम से कम 122 विधायक चाहिए। सवाल यह कि बाकी के विधायक कहां से आएंगे ? पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व में प्रवक्ता रहे डॉ विनोद शर्मा कहते हैं कि बिहार में इस बार एनडीए की लहर है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार ने समाज के हर तबके के लोगों को राहत पहुंचाई है। किसानों को 120 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, आंगनबाड़ी कार्यकताओं का मानदेय बढ़ा है। पत्रकारों, बुजुर्गों, विधवाओं और जेपी आंदोलन के मीसाबंदियों के पेंशन में दोगुनी से अधिक की बढ़ोतरी की गई है। यही नहीं, स्वरोजगार के लिए महिलाओं को सस्ते दर पर कर्ज देने के लिए सरकारी खजाना खोल दिया गया है। सड़कें चकाचक हैं और नौकरियों की बहार है। जनता को और क्या चाहिए ?

इसमें दो राय नहीं कि बिहार की महिलाओं पर नीतीश का जादू सिर चढ़कर बोलता रहा है। यह वोट इस बार नीतीश के पक्ष में कितना जाएगा, यह चुनाव परिणाम के बाद पता चलेगा, क्योंकि बिहार के अधिकांश जिले बाढ़ की चपेट में हैं और करीब 17 लाख आबादी सड़कों और राहत केंद्रों में शरण लिये हुए है। इनमें सर्वाधिक संख्या महिलाओं और बच्चों की है। दूसरी तरफ राज्य में अपराधी पुलिस के रसूख को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। विपक्ष इसे एनडीए का जंगलराज बता रहा है। महिलाएं इस अराजकता से भी पीड़ित हैं। ऐसे में महिला वोटरों में बिखराव हो जाए तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। राज्य में नीतीश की बिरादरी कुर्मी जाति का वोट करीब 6 प्रतिशत है, यह वोट भी अभी तक नीतीश के पक्ष में पड़ता रहा है। यही वजह है की नीतीश पिछले 20 वर्षों से अधिक समय से बिहार की सत्ता पर काबिज हैं।

बिहार में महागठबंधन भी इस बार पूरा जोर लगाये हुए है। राज्य में महागठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा को अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली। वोटर अधिकार यात्रा 17 अगस्त को शेरशाह सूरी की धरती सासाराम से शुरू होकर 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान से निकल कर डाकबंगला चौराहे पर समाप्त हो गई। इसमें घटक दलों के तमाम नेता शामिल थे। विपक्ष राज्य से पलायन, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था का मुद्दा जोर-शोर से उठा रहा है। लोगों को नौकरी और डोमिसाइल नीति बनाने की बात कह रहा है। एसआईआर के खतरे के प्रति आगाह कर रहा है। सरकार बनने पर महिलाओं को ढाई हजार रुपये प्रतिमाह देने और सुशासन का ख़्वाब दिखा रहा है।

इस बीच बिहार के माउन्टेन मैन दशरथ मांझी के परिजनों के लिए गयाजी के गहलोर गांव में पक्का घर बनवाकर राहुल गांधी ने अपनी जय-जयकार करा ली है। दशरथ के बेटे भागीरथ मांझी इसके लिए नीतीश कुमार से लेकर जीतनराम मांझी और भाजपा के कई बड़े नेताओं का चक्कर लगाकर थक चुके थे। इससे आसपास के गांवों में भी राहुल के लिए हमदर्दी जगी है। देखने वाली बात होगी कि यह सहानुभूति वोट में कितनी तब्दील हो पाती है।

बिहार की सियासत का तीसरा केंद्र बने प्रशांत किशोर (पीके) की पार्टी जनसुराज पर सबकी निगाहें टिकी हैं। कयास लगाये जा रहे हैं कि प्रशांत इस चुनाव में बड़ा खेल करेंगे। वह अपने दम पर सरकार बनाने से लेकर दोनों बड़े गठबंधनों (एनडीए और महागठबंधन) का खेल बिगाड़ने तक का हो सकता है। एनडीए और महागठबंधन से समान दूरी बनानेवाले लोग आजकल पीके की तरफ खींचे चले आ रहे हैं। कहना न होगा कि ऐसे लोगों की संख्या भी कम नहीं है। इनमें रिटायर्ड आईएएस, आईपीएस और उद्योगपतियों की संख्या काफी है। इसके लिए प्रशांत किशोर बिहार के बाहर रहने वाले प्रवासियों के संपर्क में हैं। उधर, राज्य में जनसुराज की गतिविधियां लगातार जारी हैं। विधानसभा स्तर तक कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किये जा रहे हैं। पीके ने पलायन के मुद्दे को ठीक से पकड़ा है। वह कहते हैं कि बिहार की बदहाली में यहां के नेताओं की बड़ी भूमिका है। जब तक झारखंड राज्य नहीं बना था, बिहार की बदहाली कम दिखती थी। अब सरेआम हो चुकी है। वह मतदाताओं से कहते हैं कि इस बार का मतदान अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए कीजिए। बिहार में रोजी-रोजगार की व्यवस्था के लिए वोट कीजिए। प्रशांत अपनी सभाओं में नीतीश और लालू दोनों को बिहार की बदहाली के लिए बराबर का जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। कहते हैं कि पिछले 35 वर्षों से बिहार में इन्हीं दोनों का शासन रहा है। वह दोनों को नागनाथ और सांपनाथ बताते हैं। कहते हैं कि दोनों विषधर हैं, दोनों डंसते हैं। प्रशांत किशोर जाने-माने चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। वर्ष 2014 के संसदीय चुनाव में नरेंद्र मोदी के चुनावी रणनीतिकार रहे थे। भाजपा को सत्ता में लाने का श्रेय उन्हें दिया जाता है। 2015 के विधानसभा चुनाव में वह जनता दल (यू) की तरफ से महागठबंधन के रणनीतिकार रहे थे। तब नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने में उनकी अहम भूमिका थी। इससे उनकी लोकप्रियता और कमाई दोनों बढ़ी है। इस बार वह जनता दल (यूनाइटेड) और राष्ट्रीय जनता दल दोनों पर बराबर हमलावर हो रहे हैं। आश्चर्य यह कि प्रशांत किशोर पर जवाबी हमला जदयू और राजद कम बल्कि भाजपा ज्यादा कर रही है।

पिछले दिनों चार सीटों के हुए उपचुनाव में जनसुराज तीन सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। उसे 10 प्रतिशत से ज्यादा वोट मिले थे। पीके बताते हैं कि भाजपा को दस प्रतिशत वोट पाने में 20 साल लगे थे। उपचुनाव के समय हमारी तैयारी प्रीमैच्योर थी। तब भी इतने वोट मिले। वह कहते हैं कि ह्यविधानसभा चुनाव में जनसुराज या तो अर्श पर रहेगी या फर्श पर रहेगी। बीच की गुंजाइश काफी कम है। अगर लोगों ने जाति-धर्म से हटकर मतदान किया तो हम अकेले अपने बूते पर सरकार बना सकते हैं।ह्ल लेकिन बिहार में जाति की राजनीति लंबे समय से जड़ जमाये है। वहां के लोग डॉक्टर और मास्टर भी अपनी जाति का ही खोजते हैं। ऐसे में प्रशांत की जनसुराज क्या गुल खिलाती है, यह समय बताएगा।

रोहतास जिले के बगेयां गांव निवासी सामाजिक कार्यकर्ता सूर्यकेश्वर सिंह कहते हैं कि प्रशांत किशोर बिहार के केजरीवाल बनने की जुगत में हैं। वह चुनाव जीतें अथवा नहीं, लेकिन दोनों मुख्य गठबंधनों (एनडीए और महागठबंधन) का खेल जरूर खराब करेंगे।

इस बीच, गंभीर अपराधों में 30 दिन के लिए जेल जाने पर प्रधानमंत्री अथवा मुख्यमंत्रियों को पद से हटाने संबंधी बिल को कैबिनेट की मंजूरी और संसद में पेश कर केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चल दिया है। अगर यह बिल कानून बन जाता है तो इसका देशव्यापी असर पड़ेगा और बिहार भी इससे अछूता नहीं रहेगा। यही कारण है कि विपक्ष इस बिल का पुरजोर विरोध कर रहा है। विपक्ष की यह आशंका निर्मूल नहीं है कि सरकार इसका इस्तेमाल विपक्ष की सरकारों को बर्खास्त करने के लिए करेगी। बिहार में विपक्ष के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी यादव हैं। उन पर पहले से ही कई आपराधिक मुकदमें दर्ज हैं। ऐसे में यह सवाल मौजूं है कि अगर केंद्र सरकार का बिल संसद से पारित होकर कानून बन जाता है और महागठबंधन बिहार में चुनाव जीत भी जाता है तो उसकी सरकार कितनी टिकाऊ होगी। वैसे यह कानून बनाने के लिए संसद के दोनों सदनों में सरकार को दो तिहाई बहुमत की दरकार पड़ेगी जो सरकार के पास फिलहाल नहीं है।

प्रधानमंत्री ने जीएसटी सुधार के वायदे को किया पूरा, कांग्रेस क्रेडिट लेने की जुगाड़ में

अशोक भाटिया

वरिष्ठ स्वतंत्र पत्रकार, लेखक, समीक्षक एवं टिप्पणीकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारत के लोगों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) प्रणाली में सुधार के रूप में दिया गया "दिवाली उपहार", संभवतः तीन स्तंभों - संरचनात्मक सुधार, दरों को युक्तिसंगत बनाना, और जीवन को आसान बनाना - पर आधारित होगा तथा इसमें वर्तमान पांच-दर प्रणाली से दो-दर प्रणाली की ओर बदलाव शामिल हो सकता है। भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली के लाल किले से अपने भाषण में पीएम मोदी ने कहा था कि सरकार अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार लाएगी, जिससे आम आदमी पर कर का बोझ कम होगा। यह आपके लिए दिवाली का तोहफा होगा। पीएम मोदी ने दिवाली के जिस गिफ्ट को आम आदमी को देने का वादा किया था, उसे नवरात्र के पहले दिन ही देने की तैयारी की जा रही है। जीएसटी परिषद ने त्योहारी सीजन पर नए जीएसटी ढांचे को लागू करने की तैयारी पूरी कर ली है। परिषद के फैसले से आम लोगों, किसानों और कारोबारियों को बड़ी राहत मिलेगी। सरकार चाहती है कि जीएसटी परिषद में सहमति बनने के बाद जीएसटी के दो स्लैब लागू करने में ज्यादा देरी न हो।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कर दर में कटौती की घोषणा करते हुए कहा कि अब से जीएसटी के केवल दो चरण होंगे। देश भर में सरकार के विज्ञापन अभियान में भी यही कहा गया है। लेकिन यह सच नहीं है। नवीनतम दर में कटौती से पहले, वस्तु और सेवा कर के छह चरण थे। शून्य प्रतिशत, 5 प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, कर 28 प्रतिशत और 40 प्रतिशत अधिक था। इनमें से 12 प्रतिशत और 28 प्रतिशत को हटा दिया गया। इसका मतलब है कि छह चरणों में से केवल दो चरणों को हटाया जाएगा और अब से चार चरणों में कर लगाया जाएगा। इसमें भी 28 प्रतिशत में से कई 40 प्रतिशत तक चले जाएंगे। केवल एक चरण होना आदर्श वस्तु एवं सेवा कर है। हमारे जैसे देश में, यह असंभव है। हालांकि, सभी घटकों को अधिकतम दो चरणों में विभाजित करना आवश्यक था। इस संदर्भ में, माल और सेवा कर का मूल मसौदा। विजय केलकर की समिति ने भी दो चरणों की सिफारिश की थी और कई विशेषज्ञ अभी भी यही बात कहते हैं। सुधार का दावा करने वाली सरकार ने इससे मुंह मोड़ लिया है। अगर आप इस टैक्स के वास्तविक लाभों का अनुभव करना चाहते हैं, अर्थव्यवस्था के उछाल का अनुभव करना चाहते हैं, तो जी.एस. टैक्स के चरण दो से अधिक नहीं होने चाहिए।

कुछ लोगों का मानना है कि भले ही सरकार दो करने का दावा करती है, लेकिन यह एक धोखा है। वित्त मंत्री के बयान में वस्तु/सेवा कर के तीन महत्वपूर्ण घटकों- पेट्रोल, डीजल और शराब को वस्तु/सेवा कर में शामिल करने का उल्लेख नहीं है। अर्थात, सरकार के पास अभी भी ईंधन की कीमत को छूने की हिम्मत नहीं है, जिस पर परिवहन लागत, जो सभी वस्तुओं/सेवाओं के घटकों की कीमतों को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऐसी स्थिति में, केवल सरकार और विचारक ही जो हुआ उसे 'प्रमुख सुधार' कह पाएंगे। दूसरों ने कहा कि इन कथित सुधारों ने इन कथित सुधारों को जन्म दिया है। यह खुश होना वांछनीय है कि सेवा कर में हास्यास्पद कुछ हद तक कम हो जाएगा।

यानी 'बन-पाव' पर 5 फीसदी, काजल पर 5 फीसदी, लेकिन बन-मास्क पर 18 फीसदी, जो कई लोगों के नाश्ते का एक घटक है। या स्कूल स्तर पर आवश्यक स्नैक्स पर 5 फीसदी, मासिक धर्म के दौरान आवश्यक सैनिटरी पैड पर 12 फीसदी और इसी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल होने वाले टैम्पोन पर 18 फीसदी।नवीनतम तथाकथित सुधारों में चिकित्सा बीमा आदि पर करों में कमी आएगी। बेचारा। अब यह टैक्स फ्री होगा। सबसे बड़ा बदलाव जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर टैक्स में होगा। इन दो आवश्यक सेवाओं पर 18 प्रतिशत का कर लगाना मूल रूप से मूर्खतापूर्ण है। हमारे पास पहले से ही चिकित्सा बीमा चाहने वाले लोगों की एक छोटी संख्या है। इसने इस क्षेत्र की कमर 18 प्रतिशत तक तोड़ दी। यह अब सीधा होना चाहिए। क्योंकि ये बीमा प्रीमियम अब टैक्स फ्री होगा। वही मूर्खतापूर्ण कहर सिनेमाघरों में पॉपकॉर्न-नामित मकई के लट्टे के बारे में था। पहले मक्के के लट्टे साधारण होने पर 5 प्रतिशत, नमकीन लट्ठे पर 12 प्रतिशत और कैरेमलाइज्ड लाठियों पर 18 प्रतिशत कर देना पड़ता था। अब, हम पांच प्रतिशत में सभी लाठियों से छुटकारा पा लेते थे। अब, सभी लाठियां घटाकर पांच प्रतिशत कर दी जाएंगी। बढ़ते तापमान के कारण, एयर कंडीशनर कोई विलासिता नहीं है। रेल मंत्रालय का कहना है कि मुंबई में सभी लोकल ट्रेनें वातानुकूलित होनी चाहिए। उपभोक्ता वस्तुएं 5 फीसदी के दायरे में आएंगी। इसमें आपका स्वागत है। हालांकि, ये तथाकथित सुधार इस स्वागत को एकमुश्त करने की अनुमति नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए, कारों और होटलों के लिए कर संरचना 40 प्रतिशत होगी और 7,500 रुपये से अधिक शुल्क लेने वाली होटल सेवाओं पर भी कर लगेगा। हमारी सरकार को अभी तक पता नहीं है कि ऐसी कार लेने वाले और महंगे होटलों में रहने वाले अमीर नहीं हैं। हमारे पास सड़कों और परिवहन की गुणवत्ता को देखते हुए, बहुत से लोग सुरक्षा कारणों से हाल ही में बड़ी कारें खरीदते हैं। अब लागत बढ़ेगी। एक खामी भी है। इसका मतलब है कि 1200 सीसी इंजन की क्षमता वाली कारों पर ज्यादा टैक्स लगेगा, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि 1150 सीसी क्षमता वाली कारें जल्द ही आएंगी।

दूसरा मुद्दा स्टार होटलों का है। यह सच है कि इसका उपयोग अमीरों द्वारा किया जाता है। लेकिन यह भी सच है कि स्टार होटलों में आम होटलों की तुलना में अधिक रोजगार की क्षमता होती है। एक पांच सितारा होटल सीधे कम से कम 500 लोगों को रोजगार देता है और समान संख्या में अप्रत्यक्ष नौकरियां पैदा करता है। इसलिए अगर हम रोजगार सृजन, खरीदारी और सेवाओं को प्रोत्साहित करना चाहते हैं, तो हमें बड़ी कारों या बड़े होटलों की जरूरत है। ऐसा लगता है कि 'अमीरों को थप्पड़ मारो' मानसिकता के कारण ऐसा नहीं हो रहा है। सरकार का अब तक का सबसे बड़ा आर्थिक सुधार नोटबंदी रहा है। इसके पीछे मकसद अमीरों को सबक सिखाना था। वास्तव में, किसे फायदा हुआ और कौन दिवालिया हो गया, इसका इतिहास ताजा है। इस मानसिकता के दोहराव की संभावना है।

भारत सरकार की तरफ से जीएसटी में किए गए बदलाव को लेकर कांग्रेस भी क्रेडिट लेने की जुगाड़ में है । विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपने कई पुराने ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर कर रहे हैं।कांग्रेस का कहना है कि आठ साल बाद बीजेपी को अपनी गलती का अहसास हुआ है, जबकि कांग्रेस इसका पहले से ही विरोध कर रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने उन पुराने ट्वीट को शेयर किया, जिनमें उन्होंने लिखा था कि कांग्रेस 18 प्रतिशत सीएपी के साथ एक रेट के लिए संघर्ष जारी रखेगी। उन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी ये काम नहीं करेगी, तो कांग्रेस करके दिखाएगी।

राहुल गांधी ने सोशल मीडिया अकाउंट पर ऐसे ट्वीट शेयर किए जिसमें एक ट्वीट 8 साल पुराना है और दूसरा 9 साल पुराना है। 2017 में शेयर किए गए ट्वीट में लिखा था कि भारत को गब्बर सिंह टैक्स नहीं, सरल जीएसटी चाहिए। कांग्रेस और देश की जनता ने लड़कर कई वस्तुओं पर 28 प्रतिशत टैक्स खत्म करवाया है। 18 प्रतिशत सीएपी के साथ एक रेट के लिए हमारा संघर्ष जारी रहेगा। अगर भाजपा ये काम नहीं करेगी, तो कांग्रेस करके दिखाएगी। वहीं 2016 के ट्वीट में लिखा था कि जीएसटी दर पर 18 प्रतिशत की सीमा सभी के हित में है। इस पर पवन खेड़ा ने कहा कि शुरू से राहुल जी 2 स्लैब्स की बात कर रहे हैं। एक सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। हमारी सलाह मानने में 9 साल लग गए। वाकई इनकी समझ कम है या घमंड है। कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने कहा कि मैं आठ साल बाद सरकार को अपनी गलती का एहसास होने पर उसकी सराहना करता हूं। उन्होंने कहा कि आठ साल तक बीजेपी ने मध्यम वर्ग और गरीबों को निचोड़ा है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि उस समय हमने सलाह दी थी कि ऐसा कर नहीं लगाया जाना चाहिए, लेकिन उस समय न तो प्रधानमंत्री और न ही मंत्रियों ने हमारी बात सुनी। उन्होंने कहा कि मैंने संसद में भी आवाज उठाई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। चिदंबरम ने कहा कि जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत से घटाकर घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की वकालत करती रही है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जीएसटी परिषद की बैठक से पहले पीएम मोदी ने 15 अगस्त को जीएसटी की दरों को घटाने की बात कही थी। उन्होंने बीजेपी पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है? उन्होंने कहा कि इसे इसे गुड एंड सिंपल टैक्स कहा गया था, लेकिन यह ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ।अब यह तो धीरे झ धीरे ही पता चलेगा कि आम जनता को दिवाली ला कितना गिफ्ट मिला है ।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अंधेरे को हटाने में समय बर्बाद मत करिए बल्कि दीये को जलाने में समय लगाइए।
- ओशो

मर्यादा की मिसाल

हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक तंज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से सहज आत्मीयता में बदल दिया, वह यही दिखाता है कि व्यक्ति का नजरिया चीजों को किस हद तक बदल सकता है। दरअसल, हुआ यों कि कुछ दिन पहले मैसूर में अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान के एक समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य से पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया, 'क्या आप कन्नड़ जानती हैं?' इस पर राष्ट्रपति के सहज व विनम्र जवाब ने वहां उपस्थित श्रोताओं के दिल को तो छुआ ही, इसने बहुलता में एकता की उस भारतीय भावना को फिर से जीवंत कर दिया, जो हमारी सांविधानिक लोकतांत्रिक परंपरा की आत्मा है। उन्होंने यह कह कर कि-कन्नड़ बेशक मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन यह कर्नाटक की भाषा है और मुझे देश की हर भाषा, संस्कृति व परंपरा से प्यार है-पूछे गए सवाल को तो बौना किया ही, हर चीज को राजनीतिक मोड़ देने या भाषाओं को राजनीतिक हथियार बनाने की प्रवृत्ति पर भी जोरदार, किंतु विनम्र प्रहार किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषा का उद्देश्य तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। हालांकि, सवाल के जवाब में वह भी पूछ सकती थीं कि क्या आपको आदिवासियों की भाषा आती है, लेकिन इसके बजाय उनका यह कहना कि-मैं धीरे-धीरे निश्चित ही कन्नड़ सीखने का प्रयास करूंगी-उनकी शालीनता को ही दिखाता है। यह सभी भारतीयों के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, साथ ही अन्य भाषाओं व बोलियों का भी सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि ऐसे समय में, जब कर्नाटक में भाषा को लेकर बहस गरमाई हुई है, राष्ट्रपति मुर्मू का जवाब इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिद्धरमैया के सवाल को एक सकारात्मक व रचनात्मक दिशा दी, साथ ही यह भी दिखाया कि तंज कसने के बजाय एकता और सम्मान के साथ किसी भी मतभेद को सुलझाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू का जवाब यह भी दर्शाता है कि

किसी भाषा को न जानना उसकी संस्कृति से दूरी का पर्याय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के बीच हुआ यह छोटा-सा संवाद हमें सिखाता है कि भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और एकता की प्रतीक भी हैं। इसमें देश में व्याप्त विविधताओं पर चोट करने वाली बहसों के समाधान का सूत्र भी छिपा है।

टैरिफ के पीछे की वजहें ये तो नहीं

ट्रंप द्वारा भारत पर भारी-भरकम टैरिफ थोपने का कोई वाजिब कारण नहीं है, रूसी तेल तो बस बहाना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की असली वजह मोदी द्वारा उन्हें कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करने देना, संघर्ष विराम का श्रेय न देना, उनसे मुलाकात रद्द करना और बुलावे पर व्हाइट हाउस न जाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उनकी यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत की आलोचना की पृष्ठभूमि में हुई। मोदी की शी के साथ वार्ता जहां भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी मुद्दों के समाधान की उम्मीद जगाती है, वहीं पुतिन के साथ बातचीत दर्शाती है कि भारत और रूस बेहतर साझेदार बने रहेंगे।

एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से भारत को महत्वपूर्ण कूटनीतिक कामयाबी मिली। मोदी, पुतिन और जिनपिंग के एकसाथ आने से ट्रंप की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। उन्हें लग रहा होगा कि ये तीनों देश मिलकर उनकी रणनीति के खिलाफ जमीन तैयार कर रहे हैं। एक तरह से ट्रंप ने ही इन तीनों देशों को अपने संबंधों को फिर से सुधारने का मौका दिया है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

तियानजिन घोषणापत्र मोदी के दृढ़ संदेश 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं हैं' की भी अनुगूंज है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए सदस्य देशों ने जोर देकर कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले अपराधियों, संगठनों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप द्वारा उत्पन्न उथल-पुथल की वजह से भारत ने अपने संबंधों को पुनः दिशा देने के लिए अहम कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन से पहले मोदी जापान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए टोक्यो गए थे।

मोदी-जिनपिंग वार्ता भारत-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण क्षण था। 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद चीनी धरती पर मोदी और जिनपिंग के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक थी। इस घटना के कारण दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इस पृष्ठभूमि में मोदी के दौरे को दोनों देशों के बीच नए कूटनीतिक अध्याय की शुरुआत

के रूप में देखा गया है। क्या मोदी और शी संबंधों को सामान्य बना सकते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा विवाद की छाया रातों-रात दूर नहीं होगी। हालांकि, वर्षों की चुप्पी के बाद हुई आमने-सामने की वार्ता विश्वास बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करती है। विश्लेषक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सफलताओं को तात्कालिक रूप से कम, लेकिन संवाद के रास्ते खोलने के रूप में ज्यादा देखते हैं।

यदि यूक्रेन-रूस युद्ध समाप्त हो जाता है, तो हालात बदल जाएंगे। इससे रूस और चीन भी ट्रंप के साथ फिर संपर्क में आ जाएंगे। इसी तरह, भारत ने भी अमेरिका के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अमेरिका भी व्यापार संबंधी मुद्दों के धीरे-धीरे सुलझ जाने के बाद मोदी के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिश करेगा।

दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ क्यों थोपा। टैरिफ लागू होने के बाद खुद अमेरिकी लोग चिंतित हैं कि भारतीय सामान ज्यादा महंगे हो जाएंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने आग में घी डालने का काम किया है। उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो रूस-यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' तक कह दिया। उनके दूसरे करीबी सलाहकार अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने भारत पर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में 'अड़ियल' रवैया अपनाने का आरोप लगाया। निस्संदेह ट्रंप के पास भारत पर अतिरिक्त टैरिफ थोपने का कोई वाजिब कारण नहीं है। रूसी तेल की खरीद तो एक बहाना है। ट्रंप खुद स्वीकार चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा है।

कुछ विशेषज्ञ मोदी और ट्रंप के बीच हुए मनमुटाव के चार मुख्य कारण गिनाते हैं। पहला कारण, जुलाई 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने उनसे कहा था कि मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए बोला है। ट्रंप की इस टिप्पणी पर मोदी ने नाराजगी जताई और व्हाइट हाउस को साफ कर दिया कि कश्मीर मसले पर भारत किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोदी ने दोनों उम्मीदवारों, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मिलने का समय मांगा था। ट्रंप ने उन्हें समय दिया और अपनी एक रैली में उन्होंने घोषणा कर दी कि मोदी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर कमला हैरिस पीछे हट गईं। मोदी ने सोचा कि एक ही पार्टी के प्रत्याशी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी, जो ट्रंप को बुरा लगा। तीसरा कारण, ट्रंप चालीस से ज्यादा बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया। लेकिन भारत ने बार-बार स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ, पर ट्रंप यह सुनने को तैयार नहीं थे। चौथा कारण, कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप मिलने वाले थे, लेकिन ट्रंप शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने मोदी को फोन कर आमंत्रित किया। ठीक उसी समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप से रात्रिभोज पर मिलने वाले थे। स्वाभाविक है, मोदी ने ट्रंप का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इससे ट्रंप मोदी से नाराज हो गए।

साफ है कि भारत के साथ ट्रंप की समस्या केवल रूसी तेल खरीदने की वजह से ही नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देश अब भी यूक्रेन को भारी समर्थन दे रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत बहुत कम मात्रा में रूसी तेल खरीदता है। ट्रंप की समस्या ने आसिम मुनीर को उनका मित्र बना दिया और उन्होंने टैरिफ विवाद में युद्ध विराम के मुद्दे को शामिल करके मोदी को संकट में डाल दिया। संभवतः इसी वजह से उन्होंने भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया और पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन को राहत प्रदान की, जिसे वह अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे। भारत ने ट्रंप की धमकियों के आगे 'समर्पण' करने से इन्कार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने मोदी को हल्के में ले लिया। ट्रंप के काम करने की अपनी शैली है। वह हर दिन मीडिया से बात कर किसी भी राष्ट्र प्रमुख पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये बड़ी घोषणाएं करते हैं। अन्य किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कभी नहीं किया। अब तो अमेरिकी भी कहने लगे हैं कि ट्रंप सिर्फ एक व्यापारी हैं। इसीलिए भारत को ट्रंप से निपटने के नए तरीके और पद्धतियां तलाशनी होंगी।

आर्थिकी

भारतीय कृषि को मिलेगी नई ऊर्जा

जीएसटी 2.0 केवल कर कटौती भर नहीं है, बल्कि यह किसानों, सहकारी संस्थाओं और छोटे उद्यमों को विकास के केंद्र में रखने का नीति संकेत है।

जुलाई 2017 में जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का शुभारंभ हुआ, तो इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया, पर वर्षों तक बिखरी हुई दरें किसानों के लिए उत्पादन खर्च बढ़ाती रहीं। अब आठ वर्षों बाद जीएसटी परिषद ने कर सुधार के जरिये इन विकृतियों को दूर कर दिया है। कर में राहत किसानों का बोझ घटाएगी, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगी और भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी व टिकाऊ बनाएगी। ट्रैक्टर पर कर घटाकर 12 फीसदी से पांच फीसदी कर दिया गया है, तो टायर, ट्यूब और हाइड्रोलिक पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई उपकरण, थ्रेशर और कंपोस्ट मशीन पर कर घटाकर पांच फीसदी रखा गया है। इससे छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक मशीनें अपना पाएंगे, जिससे श्रम लागत बचेगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

खाद की उपलब्धता किसानों की आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा, दोनों के लिए अहम है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी कर देने से इनपुट की आपूर्ति स्थिर होगी और लागत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार, जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी घटाकर पांच फीसदी किया गया है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, रासायनिक दवाओं का प्रयोग घटेगा और कृषि को स्थिरता व जलवायु अनुकूलन मार्ग पर अग्रसर किया जा सकेगा। छोटे जैविक उत्पादकों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए यह राहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डेयरी केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है, विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए। मक्खन, घी और दूध के डिब्बों पर कर घटाकर पांच फीसदी करने से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और परिवारों को सस्ता पोषण। मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को भी राहत दी गई है। प्राकृतिक शहद पर कर घटने से ग्रामीण और आदिवासी मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ेगी, वहीं मछली उत्पादों पर कर घटाकर पांच फीसदी करने से मत्स्य उद्योग को नई गति मिलेगी। ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वनवासियों की जीवन रेखा तेंदूपत्ता पर भी अब केवल पांच फीसदी कर लगेगा। तैयार-खाद्य और संरक्षित फल, सब्जियों तथा मेवों पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी करने से कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा, फसल की बर्बादी घटेगी, किसानों को उपभोक्ता मूल्य का बड़ा हिस्सा मिलेगा और छोटे प्रोसेसर व एफपीओ-आधारित उद्यम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। दीर्घकाल में यह भारत को मूल्य संवर्धित कृषि-निर्यातों में अहम स्थान दिला सकता है।

नवीन पी. सिंह
प्रधान वैज्ञानिक,
आईसीएआर-एनआईएपी

लॉजिस्टिक्स पर उच्च कर दरों ने माल ढुलाई की लागत बढ़ा दी थी। अब वाणिज्यिक वाहनों पर कर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। माल-वाहन बीमा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इससे परिवहन खर्च घटेगा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होंगे और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसे ग्रामीण कोल्ड चेन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों से जोड़ा जाए, तो यह संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बदल सकता है। जीएसटी 2.0 केवल कर कटौती भर नहीं है, बल्कि यह किसानों, सहकारी संस्थाओं और छोटे उद्यमों को विकास के केंद्र में रखने का नीति संकेत है। खेती की लागत घटाकर, टिकाऊ इनपुट को प्रोत्साहित कर, सहायक गतिविधियों को बल देकर और मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाकर यह जीएसटी को बोझ से समृद्धि के साधन में बदल देता है। जीएसटी 2.0 का लक्ष्य भारतीय कृषि को सशक्त कर विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप आगे बढ़ाना है।

एआई न तो आपसे नफरत करता है और न ही मोहब्बत, लेकिन आप परमाणुओं से बने हैं, जिसका इस्तेमाल वह किसी और काम के लिए कर सकता है।
- एलीजर युडकोव्स्की

अच्छी पुस्तकें स्थायी साथी होती हैं

आइंस्टीन बारह वर्ष की उम्र में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर लिखी किताब पढ़कर समझ पाए कि सर्वमान्य सत्य की खोज बिना किसी महंगी प्रयोगशाला और उपकरण की मदद के भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया को सिर्फ मन की शक्ति से नियंत्रित किया जाता है।

धरती पर विभिन्न कालखंडों में कई महान मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ, किंतु उनमें से कुछ ही सभ्यताएं अस्तित्व में हैं। प्राचीनकाल में दार्शनिक और बाद में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, सभी ने मिलकर विभिन्न सभ्यताओं को संपन्न बनाया।

भारतीय सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने में रचा-बसा लिया। यही कारण है कि करोड़ों की जनसंख्या वाले हमारे समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किंतु मानसिक स्तर पर हम सब एक हैं। इसका श्रेय हमारे चिंतकों को जाता है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

हमारे यहां *महाभारत, तिरुक्कुरल, कबीरवाणी* और *नारायणीयम* जैसे ग्रंथों की परंपरा रही है, जो आज भी कायम है। किसी अच्छी पुस्तक के संपर्क में आने और उसका संग्रह करने से जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल बन जाती है।

अच्छी पुस्तकें हमारी स्थायी साथी बन जाती हैं। कई पुस्तकें काफी पहले लिखी गईं, किंतु वे अब भी हमारा जीवन भर मार्गदर्शन करती हैं और आगे भी कई पीढ़ियों को दिशा दिखाती रहेंगी। कला जिंदगी की खूबसूरती को बड़ी नजाकत से पेश करती है। यह मानव के अस्तित्व को अर्थ देने के साथ-साथ उसे शक्ति भी प्रदान करती है। बारह साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पथ प्रदर्शक मैक्स टालमुड से यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर एक पुस्तक पाकर विस्मय का अनुभव किया था। इस पुस्तक को पढ़ने से आइंस्टीन ने विचार की असली दुनिया में कदम रखा और वह समझ पाए कि सर्वमान्य सत्य की खोज बिना किसी महंगी प्रयोगशाला और उपकरण की मदद के भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया को सिर्फ मन की शक्ति से नियंत्रित किया जाता है।

जीवन धारा

हम अपने चारों ओर दुख और भाग्यवाद पाते हैं, किंतु हमारे अंदर की निष्ठा उन्हें चुनौती देती है। साहित्य इसी तरह हमारे मन को सबल बनाता है। लेखक समाज की चेतना के प्रहरी होते हैं। हमारे चिंतक और लेखकगण युवकों को तेजस्वी मन वाले नेता बना सकते हैं। वे अपने लेखन से युवकों के मन में उदारता और मानवता के भाव भर सकते हैं। वे नई पीढ़ी को अदम्य साहस की याद दिला सकते हैं, जिसके सहारे वे किसी भी प्रकार की दुर्बलता और अभाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

अगर डॉक्टर ही एआई के आदी होने लगें

एआई का उपयोग करना एक बात है, पर इस पर निर्भर होकर डॉक्टर अगर अपनी बुनियादी क्षमताएं खो रहे हैं, तो यह खतरे की घंटी है।

टेडी रोसेनब्लथ
द न्यूयॉर्क टाइम्स

कुछ साल पहले एक अध्ययन में कहा गया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों ने डॉक्टरों को उनके काम में बेहतर बना दिया है। इससे कैंसर जैसे रोगों का पता लगाने और उनका तेजी से निदान करने में मदद मिली है। लेकिन, नए शोध से पता चलता है कि एआई से सहयोग लेना महंगा भी पड़ सकता है। *लैंसेट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी* में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कोलोनोस्कोपी के दौरान कैंसर-पूर्व वृद्धि का पता लगाने में मदद करने के लिए तैयार किए गए एक एआई उपकरण का उपयोग करने के तीन महीने बाद ही यह महसूस किया जाने लगा कि इस वृद्धि को बगैर उपकरण परख लेने की डॉक्टरों की मौलिक प्रवृत्ति में ह्रास हो रहा है। एआई उपकरणों पर डॉक्टरों की निर्भरता का यह पहला साक्ष्य है, जो बताता है कि यह डॉक्टरों के बुनियादी कौशल को खत्म कर रहा है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अध्ययन के साथ एक संपादकीय प्रकाशित करने वाले डॉ. उमर अहमद कहते हैं, 'यह एक दो-तरफा प्रक्रिया है। हम एआई को ऐसे इनपुट देते हैं, जो उसके आउटपुट को प्रभावित करते हैं, पर यह हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है।'

पोलैंड में चार एंडोस्कोपी सेंटरों के डॉक्टरों को कोलोनोस्कोपी करते समय एआई उपकरणों का प्रयोग करने की सुविधा दी गई। इससे परिणाम अच्छे आए और कैंसर का पहले ही पता लगाने में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो कि एक एंडोस्कोपी विशेषज्ञ से बेहतर प्रदर्शन था। शोधकर्ताओं ने मापा कि एआई टूल हटाने पर डॉक्टरों के कौशल पर कितना फर्क पड़ा, पता चला कि तकनीक के प्रयोग से पहले, डॉक्टर कोलोनोस्कोपी में 28 फीसदी वृद्धि का पता लगा रहे थे, पर तीन माह बाद उनकी यह क्षमता गिरकर 22 फीसदी ही रह गई।

हालांकि, अध्ययन से यह जवाब नहीं मिलता कि क्या डॉक्टरों का प्रदर्शन इसी तकनीक के प्रयोग से गिरा है। उदाहरण के लिए, एआई उपकरण के बाद डॉक्टरों ने पहले से लगभग दोगुनी संख्या में कोलोनोस्कोपी कीं, जिससे हो सकता है कि उन्होंने प्रत्येक स्कैन पर कम ध्यान दिया हो। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि एआई के उद्भव से डॉक्टरों की कौशल क्षमता पर असर पड़ना अप्रत्याशित नहीं है। क्या ऑटोपायलट के दौर में पायलटों को अपने कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षणों से नहीं गुजरना पड़ता?

ए जायंट लीप : हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थकेयर एंड व्हाट दैट मीन्स फॉर अवर फ्यूचर के लेखक डॉ. रॉबर्ट वॉचर कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। नई तकनीकों के आने से पुराने कौशलों के लुप्त होने की कई मिसालें दी जा सकती हैं। अब स्टेथोस्कोप को ही लें, जिसके आविष्कार से पहले दिल और फेफड़ों की जांच करने में डॉक्टरों को परेशानी होती थी, और जो 1700 के दशक में बिल्कुल आम बात थी। लेकिन एआई अलग ही चीज है। डॉ. अहमद के अनुसार, इस पर लंबे समय तक मानवीय निगरानी जरूरी है। एल्गोरिदम समय के एक निश्चित बिंदु के लिए तैयार किए जाते हैं, जब उनके चारों ओर की दुनिया बदलती है, तो वे अलग ढंग से पेश आने लगते हैं। डॉक्टर अहमद ठीक ही कहते हैं, 'अगर मैं अपना बुनियादी कौशल गंवा दूंगा, तो मैं एआई की गलतियां कैसे पकड़ सकूंगा?' डॉ. वाचर के अनुसार, आज जब एआई सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है।

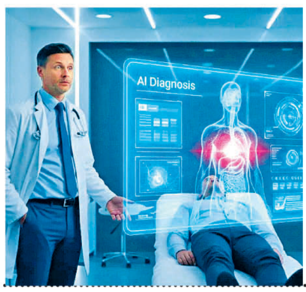

अंडरफिटिंग

यह एआई की खामी है। जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डाटा की अंतर्निहित संरचना को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पाता है, तो उसे अंडरफिटिंग कहते हैं। डाटा विज्ञान में अंडरफिटिंग एक ऐसी स्थिति है, जहां एक डाटा मॉडल इनपुट और आउटपुट चरों के बीच के संबंध को सटीक रूप से समझने में असमर्थ होता है, जिससे प्रशिक्षण सेट और अनदेखे डाटा, दोनों पर उच्च त्रुटि दर उत्पन्न होती है। अंडरफिटिंग तब होती है, जब कोई मॉडल बहुत सरल होता है, जो मॉडल के अधिक प्रशिक्षण समय, अधिक इनपुट फीचर, या कम नियमितीकरण की आवश्यकता के कारण हो सकती है।

Special arrangements by Amar Ujala

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेन्ट्स प्रा.लि. के लिए मुद्रक, प्रकाशक समीर माहेश्वरी द्वारा नवभारत प्रेस, नवभारत भवन, प्रेस कॉम्पलेक्स, जी.ई.रोड, रायपुर से मुद्रित एवं प्रकाशित. प्रधान संपादक : समीर माहेश्वरी, संपादक : राजेश आर. जोशी* (पी.आर.बी. कानून के अनुसार संपूर्ण संपादकीय दायित्व के लिये जिम्मेदार)
■ रायपुर फोन : 0771-4343434, 2535555-66-77, ■ भुवनेश्वर : 0674-2380511/2380518 ■ बिलासपुर : 07752-230591, 407748, 224563 ■ वर्ष 66 ■ अंक 103 (रजि.नं. 13045/59 आरएनआई), पो. रजिस्टर्ड नं. छ.ग./रायपुर संभाग/61/2025-27 ■ भिलाई फोन : (0788) 2294181, 4030655

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 18 अंक 172

मॉनसून और शहरी नियोजन

देश की राजधानी नई दिल्ली, मिलेनियम सिटी गुरुग्राम, वित्तीय राजधानी मुंबई, सिलिकन सिटी बेंगलूरु और उभरते औद्योगिक केंद्र चेन्नई में एक बात साझा है। बीते दशक में हर मॉनसून में देश के ये महानगर जो अहम औद्योगिक गतिविधियों के केंद्र भी हैं, पूरी तरह ठप हो जाते हैं। हाल में आई बाढ़ में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और मुंबई के अनेक हिस्सों में बाढ़ और लोगों के विस्थापन के जो दृश्य नजर आए वे इसी प्रक्रिया का हिस्सा हैं। नगर निगम के अधिकारीगण मौसम की इन अतियों के कारण बड़े पैमाने पर हो रही इस आपदा, लोगों की मौतों और आर्थिक क्षति, सभी से अवगत हैं। परंतु इसका हल उनके पास भी नहीं नजर आ रहा है।

पहली नजर में बढ़ता शहरीकरण इसके लिए दोषी नजर आता है। सच तो यह है कि यह शहरीकरण दुनिया भर में आर्थिक वृद्धि और विकास का अपरिहार्य परिणाम है। भारत भी अलग नहीं है। असली चुनौती है यह सुनिश्चित करना कि बढ़ते शहरी केंद्रों का सही ढंग से नियोजन किया जाए और उनके रखरखाव तथा उन्हें टिकाऊ बनाने के लिए सही वित्तीय मॉडल के साथ-साथ उचित संतुलन कायम किया जाए। भारत के अधिकांश हिस्सों में ऐसा नहीं हो पाया है। खासतौर पर जहां निर्माण लॉबी का प्रभाव नगरीय निकायों पर लगातार बढ़ता जा रहा है। वह भी तब जब ये संस्थाएं वित्तीय संकट से जूझ रही हैं। इसका परिणाम यह है कि पेड़ों को मनमाने ढंग से काटा जा रहा है, या उनकी जड़ों को दमघोंटू कंक्रीट संरचनाओं में बंद कर दिया जाता है। हरियाली लगातार नष्ट हो रही है, और जलाशयों को बिना स्थानीय जल-प्रणाली की समझ के कंक्रीट से ढक दिया जाता है, जबकि मूलभूत जल निकासी प्रणाली और बाढ़ नियंत्रण ढांचे की कमी साफ तौर पर दिखाई देती है। यहां तक कि मानसून से पहले नालियों की सफाई जैसे सरल कदम भी नगर प्रशासन की समझ से बाहर प्रतीत होते हैं।

जलवायु परिवर्तन और अत्यधिक गर्मी के कारण ये समस्याएं हर साल और गंभीर हो रही हैं तथा इनका तत्काल हल तलाश करना जरूरी है। अध्ययन दिखाते हैं कि खासकर उत्तर-मध्य भारत में मॉनसून का असर हालिया दशकों में काफी अधिक रहा है। मॉनसून बहुत असंयमित भी हुआ है। उदाहरण के लिए इस वर्ष मॉनसून जल्दी आ गया। कुछ राज्यों में यह दो सप्ताह से लेकर 18 दिन तक पहले आ गया।

इसके अलावा इसने कई पश्चिमी विक्षोभों को और मजबूत किया जिससे भारी बारिश हुई। जम्मू-कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड तक भारी बारिश के कारण क्षति के शिकार हुए। डाउन टु अर्थ पत्रिका के मुताबिक इस वर्ष अगस्त के अंत तक मॉनसून ने 15 पश्चिमी विक्षोभ झेले। इससे हिमालय के निचले इलाके में, जहां अनियोजित निर्माण कार्य हुए हैं, वहां पहाड़ धसकने और वृक्षों के गिरने की तमाम घटनाओं से भारी नुकसान हुआ। इस वर्ष हरसिल घाटी के पास भूस्खलन से हुई मृत्यु और विनाश की श्रृंखला का मुख्य कारण यह था कि वहां के नाजुक भू-भाग पर आवासीय भवनों और होटलों आदि का निर्माण किया गया। यह निर्माण ऐसी जगह हुआ जहां कायदे से नहीं होना चाहिए था।

भविष्य की बात करें तो भारतीय शहरों को मॉनसून की दृष्टि से बेहतर तैयारी की जरूरत है। पहली बात तो ये कि हमारे शहर मौसमी बारिश के लिए भी तैयार नहीं हैं। शहरी जल निकासी व्यवस्था मॉनसून की विस्तारित अवधि से निपटने के लिए तैयार नहीं है। इसके अलावा अब कम समय में भी तेज बारिश की घटनाएं हो रही हैं जिनसे निपटना मुश्किल है। अगस्त में सामान्य से 5 फीसदी अधिक बारिश के बाद भारत के मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि सितंबर में भी औसत से अधिक बारिश होगी। सितंबर के पहले हफ्ते में ही दिल्ली और गुरुग्राम पानी में डूब गए। यह विकसित भारत के लिए अच्छा उदाहरण नहीं है।

प्रतिस्पर्धा में इजाफे का किफायती मार्ग

विनिर्माण की ऊंची लागत देश के उन लाभों को समाप्त कर सकती है जो उसे कारोबारी सुगमता संबंधी सुधारों और व्यापार समझौतों से हासिल होते हैं। बता रहे हैं लवीश भंडारी

शुल्क वृद्धि की चुनौती से निपटने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यह दिक्कत कहीं अधिक गहरी समस्या के संकेतों को रेखांकित करती हैः हमारे खेत और हमारी कंपनियां पर्याप्त उत्पादक नहीं हैं और कारोबार की लागत भी इतनी कम नहीं है जो वैश्विक बाजारों के लिए उपयुक्त हो। इस समस्या को हल करने से दिक्कतें बहुत हद तक दूर हो जाएंगी।

शुल्क वृद्धि के बाद कई टीकाकारों ने कई सुधारों का प्रस्ताव रखा और यकीनन वे सभी स्वागतयोग्य हैं। कई वैश्विक व्यापार समझौते चाहे वे द्विपक्षीय हों या क्षेत्रीय, उनके भी प्रस्ताव रखे गए और वे भी स्वागतयोग्य हैं। परंतु सरकार कम उत्पादकता और उच्च लागत की समस्या को कैसे हल करेगी? इस दिक्कत के चलते ही सरकार को वैश्विक बातचीत में रक्षात्मक रुख लेना पड़ता है तथा वह हमारी उत्पादक संस्थाओं को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने के बजाय उनका संरक्षण करती है। अगर हम इस समस्या को हल नहीं करते हैं और भारतीय उत्पादकों को प्रतिस्पर्धी नहीं बनाते तो सभी वैश्विक समझौते निरर्थक हो जाएंगे।

नीति निर्माताओं को क्या करना चाहिए? पहली बात, उन्हें यह समझना चाहिए कि हम एक साथ सबकुछ नहीं कर सकते। नीतियों पर ध्यान देने, शुरुआती सफलता हासिल करने, गति तैयार करने और उनके दायरे का विस्तार करने की जरूरत होती है। इसकी शुरुआत उन कंपनियों को मजबूत बनाने से होगी जो अधिक उत्पादक और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी हैं। ये निर्यात करने वाली कंपनियां हैं और यही ट्रंप के शुल्क संबंधी कदमों से सबसे अधिक प्रभावित हैं। दूसरे, बात करते हैं कुछ ऐसे क्षेत्रों की जहां शुरुआती लाभ संभव हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से अधिकांश क्षेत्र अत्यधिक श्रम गहन हैं। आखिर में सुधारों का कठोर हिस्सा अभी भी अंजाम दिया जाना है। वहां भी हमें तभी कामयाबी मिलेगी जब हम व्यवस्थागत ढंग से समग्र सुधारों के बजाय कुछ क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करें।

इसमें कोई संदेह नहीं है कि 50 फीसदी अतिरिक्त शुल्क लगने से कई व्यवसायों को तुरंत ऑर्डर में गिरावट का सामना करना पड़ा है या पड़ेगा। जिन कंपनियों के पास दीर्घकालिक अनुबंध हैं, वे भी इन शुल्कों की शर्तों को पूरा नहीं कर पाएंगी। कई उत्पादन इकाइयों को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ेगा, और कुछ को स्थायी रूप से बंद करने की नौबत आ सकती है। बैंक प्रभावित क्षेत्रों में ऋण वितरण और कार्यशील पूंजी आवंटन को सख्त कर देंगे। सबसे दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जिन कंपनियों को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, वे वही हैं जो अधिक कुशल हैं, ज्यादा निर्यात करती हैं, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हैं।

इन निर्यातक कंपनियों के लिए कुछ सूक्ष्म और व्यापक उपाय उपलब्ध हैं, जैसे कि उनके आयात पर कम या शून्य शुल्क लगाना, और ऋण चुकाने के लिए स्थगन अवधि देना। एक अन्य विकल्प यह हो सकता है कि सरकार सीमित समय के लिए अमेरिकी शुल्कों का भार स्वयं वहन करे, जब तक कि कंपनियां वैकल्पिक बाजार खोजने में सक्षम न हो जाएं। कुल मिलाकर, सरकारी खजाने पर इसका प्रभाव 20 अरब डॉलर से अधिक नहीं होगा।

तत्काल समस्याओं का समाधान करने के बाद, अब मध्यम अवधि के लिए क्षेत्रीय नीतियों पर केंद्रित दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। जो क्षेत्र शुल्कों से सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं, उनमें परिधान, आभूषण, झींगा पालन (मत्स्य पालन क्षेत्र), फुटवियर, हल्की इंजीनियरिंग, फर्नीचर, हस्तशिल्प और कुछ अन्य शामिल हैं।

हम इन क्षेत्रों की मदद कैसे कर सकते हैं? यह सुनिश्चित करना होगा कि निर्यात क्षेत्र के कच्चे माल शुल्क मुक्त हों। यह याद रहे कि ये कंपनियां वैश्विक बाजारों में जिन फर्मों से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं उन्हें यही कच्चे माल कम शुल्क दरों पर और कम सरकारी बाधाओं के साथ मिलते हैं। दूसरे, अमेरिका, रूस, चीन और यूरोपीय संघ के साथ बातचीत में और ब्राजील, इंडोनेशिया जैसे विकासशील देशों के साथ चर्चा में भी भारत के उन बाजारों को खोल दिया जाना चाहिए जहां भारत कम प्रतिस्पर्धी है। यदि भारत को आयात करने की आवश्यकता होती है, तो बेहतर होगा कि ऐसे उत्पादों का आयात किया जाए जिनमें भारतीय कंपनियां अपेक्षाकृत कम उत्पादक हैं। इससे देश की डाउनस्ट्रीम इकाइयों (कच्चे माल का उपयोग करने वाली) को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने में मदद मिलेगी।

तीसरा, भारत में कारोबार की लागत बहुत अधिक है और इसे हल करना होगा। इसका एक तरीका है रुपये का अवमूल्यन। अवमूल्यन के साथ दिक्कत यह है कि इससे होने वाला लाभ क्षणिक होता है। एक अन्य विकल्प है लक्षित सब्सिडी देना वह भी तय अवधि के लिए। कुछ हद तक उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन योजना की तरह। परंतु सरकार इस तरह कितने उत्पादों की मदद कर पाएगी और कब तक?

सबसे बड़ी चुनौती होगी लागत की। बीते दशक में सरकार ने बेहतर कारोबारी माहौल बनाने के लिए कई प्रयास किए हैं। इसके बावजूद विनिर्माण में निवेश की जरूरत है। कारोबारी सुगमता के लिए कई मानक तय किए गए। इसके बावजूद अभी काफी कुछ करना बाकी है। दीर्घावधि में भारत को कारोबारी सुगमता की लागत पर काम करना होगा। इसके लिए प्रत्यक्ष लागत और कारोबारी अनिश्चितता दोनों कम करने होंगे। इसमें क्या-क्या शामिल हो सकता है?

पहला, श्रम के बारे में: भारत को व्यवसायों को सशक्त बनाने के लिए औद्योगिक विकास और विनियमन अधिनियम (आईडीआरए) को समाप्त करना चाहिए, विशेष रूप से वह प्रावधान जो मालिकों को कर्मचारियों की संख्या को तर्कसंगत रूप से समायोजित करने से रोकता है। इसकी जगह बेरोजगारी बीमा की व्यवस्था की जानी चाहिए। उद्देश्य यह होना चाहिए कि कर्मचारियों की उपभोग क्षमता की रक्षा की जाए, न कि उनकी नौकरी की।

दूसरा, जमीन के बारे में: भारत में जमीन महंगी है, जमीन के बड़े टुकड़े जुटाना मुश्किल है, और उपयुक्त अधोसंरचना भी नदारद है। एक औद्योगिक पार्क नीति जरूरी है जहां जमीन की लागत का बोझ सरकार वहन करती है लेकिन औद्योगिक पार्क विभिन्न सेवाएं मुहैया कराने के लिए एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हैं। इस परिसंपत्ति का लाभ लेने की जरूरत है और मांग और सेवा के बड़े केंद्रों के आसपास नए औद्योगिक पार्क बनाने होंगे।

तीसरा, न्यायिक देरी: भारत में अदालती देरी भी कारोबारी सुगमता को बहुत प्रभावित करती है। हमें मौजूदा से तीन गुना अधिक न्यायाधीशों और अदालतों की जरूरत है और अधिक सक्रियता की भी।

चौथा, बिजली की लागत: देश में हर किसी को बिजली की वास्तविक कीमत चुकानी चाहिए बजाय कि विनिर्माताओं से अधिक राशि लेने और आम परिवारों समेत अन्य क्षेत्रों को सब्सिडी देने के।

आखिर में पूंजी की लागत: बैंकों का मार्जिन इतना अधिक क्यों है या फिर कर अधिकारी पुनर्आकलन पर इतना जोर क्यों देते हैं? इससे बढ़ने वाली लागत की जिम्मेदारी कौन लेगा?

कुल मिलाकर, भारत को कुछ प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और उन बाधाओं को दूर करना चाहिए जो कम लागत वाले उत्पादक कृषि और उद्योगों के रास्ते में रुकावट बन रही हैं। यदि हम ऐसा नहीं कर पाए, तो उच्च लागत अंततः उस सारे लाभ को निष्फल कर देगी जो व्यापार सुगमता या अंतरराष्ट्रीय व्यापार समझौतों से संभावित रूप से मिल सकते हैं।

(लेखक सीएसईपी रिसर्च फाउंडेशन के प्रमुख हैं। लेख में उनके निजी विचार हैं)

जीएसटी 2.0 आर्थिक वृद्धि में ला पाएगी तेजी?

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) व्यवस्था में मौजूदा चार मुख्य दरें (5,12,18 और 28 फीसदी) अब दो मुख्य दरों 5 फीसदी और 18 फीसदी में तब्दील हो जाएंगी। तंबाकू जैसी हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसदी जीएसटी के अलावा अतिरिक्त शुल्क भी लगाया जाएगा।

सरकार ने कहा कि इस कदम का मकसद अनुपालन सरल बनाना, जीएसटी व्यवस्था में मौजूद त्रुटियां दूर करना और उपभोक्ताओं के हाथ में अधिक रकम देना है। हालांकि, निवेशकों एवं अर्थशास्त्रियों को यह घोषणा कुछ जानी-पहचानी लगी। छह वर्ष पहले 20 सितंबर, 2019 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कंपनी कर 30 फीसदी से घटाकर 22 फीसदी और नए विनिर्माताओं के लिए इसे 25 फीसदी से घटाकर 15 फीसदी कर भारतीय उद्योग जगत को चौंका दिया था। कई कंपनियों के लिए यह कटौती अचानक बड़े मुनाफे की सौगात लेकर आई। उस दिन बीएसई सेंसेक्स 5.3 फीसदी उछल गया और फिर अगले सोमवार को इसमें 2.8 फीसदी की तेजी दर्ज हुई। मगर निवेशकों एवं कंपनियों का उत्साह कुछ दिनों बाद काफूर हो गया।

आखिर, इसकी क्या वजह थी? कंपनी कर में कटौती एक तत्काल प्रतिक्रिया थी और शिथिल पड़ती अर्थव्यवस्था संभालने के लिए सरकार द्वारा आनन-फानन में उठाया गया कदम था। उस वित्त वर्ष की पहली तिमाही में आर्थिक वृद्धि दर कम होकर 5 फीसदी (पुरानी गणना विधि के अनुसार 3.5 फीसदी) तक सिमट गई। देश से निर्यात कमजोर हो गया था, बेरोजगारी दर तेजी से बढ़ रही थी और वाहनों की बिक्री घट कर दो दशकों के निचले स्तर पर आ गई थी।

वित्तीय क्षेत्र संकट में था और गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी) चरमरा गई थीं। कर घटाने के पीछे यह तर्क था कि इससे कंपनियां अपने पास जमा रकम नई परियोजनाओं में निवेश करेंगी जिससे रोजगार के अवसर सृजित होंगे। मगर वास्तविकता यह है कि कंपनियों के पास जमा नकदी का भंडार धनाढ्य कंपनियों की विस्तार योजनाओं को आगे नहीं बढ़ाती हैं बल्कि अर्थव्यवस्था में वाजिब मांग से ही ऐसा हो पाता है। जिसकी आशंका थी वही हुआ, कंपनी कर में कटौती के बावजूद कंपनियां विस्तार योजनाओं की राह में आगे नहीं बढ़ीं।

इस बार जबकि हमें निजी क्षेत्र की तरफ से पूंजीगत व्यय बढ़ने का इंतजार है छह साल बाद एक बार फिर दरों में बड़ी कटौती हो रही है। हालांकि, 2025 में भारतीय अर्थव्यवस्था की हालत उतनी खराब नहीं है मगर यह मजबूत भी नहीं कहा जा सकती। वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारतीय कंपनियों की मुख्य आय सालाना आधार पर 3.3 फीसदी कम हो गई, जो पिछली चार तिमाहियों में दूसरी गिरावट है। सालाना आधार पर उनका राजस्व 7.3 फीसदी दर से बढ़ा मगर वित्तीय एवं तेल कंपनियों को छोड़कर यह दर महज 5.3 फीसदी ही रही। कर पूर्व मुनाफा भी 7.4 फीसदी कम हो गया।

जुलाई में भारत के प्रमुख क्षेत्रों का उत्पादन सालाना आधार पर केवल 2 फीसदी दर से बढ़ा, जो जून में दर्ज 2.2 फीसदी की तुलना में कम रहा। औद्योगिक उत्पादन भी जून में 10 महीनों के निचले स्तर 1.5 फीसदी पर आ गया। सूक्ष्म वित्त और असुरक्षित खुदरा पोर्टफोलियो में दबाव के कारण बैंकों में फंसे ऋण चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में सालाना आधार पर 26 फीसदी तक बढ़ गए। नए फंसे ऋण एक साल पहले के 39,000 करोड़ रुपये की तुलना में बढ़कर 49,000 करोड़ रुपये हो गए। अब तक उपलब्ध आंकड़े ऋण आवंटन की दर कमजोर पड़ने के संकेत दे रहे हैं।

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (एफपीआई) कंपनियों की कमजोर कमाई और रुपये में गिरावट से सहमे हुए हैं। अगस्त के पहले पखवाड़े में उन्होंने 210 अरब रुपये मूल्य के शेयरों की बिकवाली की जिससे 2025 में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 1.16 लाख करोड़ रुपये रकम बाहर निकल चुकी है। विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफआईआई) ने जुलाई में भारतीय शेयरों में अपना निवेश खासा कम कर लिया।

तो क्या जीएसटी 2.0 इस तस्वीर को बदलने की क्षमता रखता है? उपभोक्ताओं के लिए उपभोग दर कम करना कंपनियों के लिए कंपनी कर घटाने से अलग है। भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) का अनुमान है कि जीएसटी दर तर्कसंगत बनाने से सालाना खपत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये (घरेलू मांग का करीब 8 फीसदी) तक बढ़ सकती है। भारतीय अर्थव्यवस्था में उपभोग का योगदान सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में लगभग 60 फीसदी है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि घरेलू खपत बढ़ने से विनिर्माण एवं सेवाओं में तेजी आएगी जिससे आर्थिक वृद्धि को रफ्तार मिलेगी।

मगर जीएसटी दरों में कमी का तात्कालिक कारण भू-राजनीति से जुड़ा हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच संबंध फिलहाल काफी खराब चल रहे हैं। अमेरिका ने भारत पर यूक्रेन युद्ध में रूस को परोक्ष रूप से मदद पहुंचाने का आरोप थोप दिया है। ट्रंप का कहना है कि भारत रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीद कर उसकी मदद कर रहा है। 27 अगस्त से भारत के लगभग 50 अरब डॉलर (अमेरिका को कुल 80 अरब डॉलर सालाना निर्यात के आधे से अधिक) मूल्य के निर्यात पर 50 फीसदी शुल्क लग चुका है। कुछ गिने-चुने आयातक ही इतना शुल्क चुका कर भारतीय सामान आयात करेंगे। जब तक भारत को निर्यात के वैकल्पिक बाजार नहीं मिल जाते तब तक निर्यात का एक बड़ा हिस्सा प्रभावित हो जाएगा। उपभोग कर में कमी इसी लिहाज से अहम हो जाती है। 'जीएसटी 2.0' के जरिये घरेलू उपभोग बढ़ाने की बढ़ाने की कवायद को अमेरिकी शुल्कों के प्रभाव को कम करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

मगर इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि पल-पल ख्याल बदलने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति यह आर्थिक युद्ध और तेज कर सकते हैं। वह भारत से सॉफ्टवेयर निर्यात, एच1बी वीजा और विदेशी अंतरण यानी अमेरिका से भारत भेजी जाने वाली रकम को निशाना बना सकते हैं। ये सभी भारत के भुगतान संतुलन एवं मुद्रा स्थिरता के लिए अहम समझे जाते हैं। मगर जब तक बात इस स्तर तक पहुंचेगी तब तक क्या 'जीएसटी 2.0' से भारतीय अर्थव्यवस्था को मदद मिल पाएगी।

यहां दिक्कत यह है कि दरों में कमी भारत की कमजोरी को दूर करने में बहुत अधिक योगदान नहीं दे पाती है। उपभोग कर में एकबारगी कमी उपभोक्ताओं को शुल्कों के झटकों से राहत पहुंचा सकती है मगर देश की आर्थिक वृद्धि की राह में बाधाओं को कम करने में नाकाम रहती है।वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने में भारत की विफलता साफ तौर पर दिख रही है। उदाहरण के लिए कपड़ा निर्यात पर विचार करते हैं। वर्ष 2010 में वैश्विक निर्यात में चीन की हिस्सेदारी 36 फीसदी थी मगर बढ़ते पारिश्रमिक के कारण 2018 तक यह कम होकर 31.3 फीसदी रह गई। वियतनाम और बांग्लादेश ने इस अवसर का लाभ उठाया और अपनी हिस्सेदारी दोगुना कर क्रमशः 6.2 फीसदी और 6.4 फीसदी कर ली। दूसरी तरफ, भारत की हिस्सेदारी 3.3 फीसदी से कम होकर 3.2 फीसदी रह गई। उस समय शुल्क कोई मुद्दा नहीं था बल्कि भारत में कारोबार करने में आने वाली बाधाओं (अफसरशाही, भ्रष्टाचार, खराब ढुलाई व्यवस्था और बेतरतीब नीतियां) के कारण कंपनियों को वैश्विक बाजार में हिस्सेदारी बढ़ाने का अवसर नहीं मिला। 2019 में कंपनी कर में कटौती आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने वाली सोच का मुजाहिरा करने के लिए हुई थी। मगर यह एक अस्थायी समाधान से अधिक साबित नहीं हुई। 'जीएसटी 2.0' के साथ भी यही जोखिम जुड़ा हुआ है।

(लेखक डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट मनीलाइफ डॉट इन के संपादक एवं मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं)

https://t.me/AllNewsPaperPaid

आपका पक्ष

जंगल कटे इसलिए बादल फटे, पहाड़ दरके

उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश बीआर गवई और जस्टिस विनोद चंद्रन के पीठ का मानना है कि हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर,उत्तराखंड तथा पंजाब में प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया और भारी तबाही मचाई वह प्राकृतिक आपदा नहीं है बल्कि इंसानों की वजह से ही इतना बड़ा हादसा हुआ है। उन्होंने केंद्र व राज्य सरकारों को इस संबंध में नोटिस भी जारी किए हैं। उच्चतम न्यायालय का इस विषय पर स्वतः संज्ञान उचित है। जंगलों की अवैध कटाई से इंकार नहीं किया जा सकता है क्योंकि बाढ़ के कारण नदियों में लकड़ी के लट्ठे भारी मात्रा में बहकर आए हैं। हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर तथा पहाड़ी राज्यों में कई जगहों पर बादल फटने की घटना हुई है। भारी बारिश के कारण भूस्खलन के कारण पहाड़ भी दरके हैं। इस वजह से पहाड़ी राज्यों में गांव के गांव तबाह हो गए हैं। नदियों में उफान से बाढ़ के कारण शहरी बस्तियां डूब गई हैं। नदियों ने अपना रौद्र रूप दिखाया और पुल ध्वस्त हो गए। बाढ़ के कारण कटान से नदियों के किनारे के मकान-दुकान बह गए। इससे भारी जानमाल का नुकसान हुआ है। इस साल बारिश के कारण हजारों लोग बेघर हुए हैं। राजस्थान जैसे राज्य में भी बारिश ने कहर बरपाया है। इस राज्य के जिन जिलों में लोग पानी को तरसते थे वहां बाढ़ आ गई है। मौसम की मार के कारण बरबादी का सिलसिला अभी भी जारी है। शहरों के विकास के नाम पर हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगलों की हरियाली नष्ट हो रही है। सीमेंट-कंक्रीट के जंगल बसाये जा रहे हैं। पहाड़ों पर बेतरतीब बसाहटें की जा रही हैं। नदी-नालों के किनारे भी रहवासी आशियाने बनाए जा रहे हैं। ऐसे में पानी की निकासी की व्यवस्था कैसे हो सकती है। इस संबंध में पर्यावरणविद तथा समाजसेवक कई बार सरकार से गुहार लगा चुके हैं लेकिन अभी तक उचित कदम नहीं उठाया गया।

शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में भारी बारिश और भूस्खलन के बाद एनडीआरएफ ने शुक्रवार को राहत एवं बचाव अभियान चलाया

बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बने फंड

बुनियादी ढांचे में कमी के कारण शहर प्रगति के वाहक होने के बजाय रोजगार की मजबूरी का केंद्र बनते जा रहे हैं। बारिश में आवासीय क्षेत्रों तथा सड़कों पर जलजमाव, ट्रैफिक जाम, प्रदूषण, कूड़े के ढेर आदि आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण शहरी जीवन की उम्मीदों को ध्वस्त कर लोगों को नारकीय जीवन जीने पर मजबूर कर रहे हैं। इस स्थिति से निपटने के लिए ही सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये का अर्बन चैलेंज फंड बनाया है। लेकिन विकराल शहरी समस्याओं के मद्देनजर ये फंड नाकाफी है। इसलिए राज्यों को भी इस तरह का फंड बनाना चाहिए। साथ ही टोल, रोड टैक्स और रोड सेस से प्राप्त राशि सिर्फ सड़कों के विकास और मरम्मत पर खर्च किया जाए। राज्य और स्थानीय निकाय अनिवार्य रूप से अपनी आय का एक निश्चित भाग बुनियादी ढांचे के विकास पर खर्च करे। बुनियादी ढांचे के रखरखाव को सीएसआर का अंग बनाया जा सकता है। ट्रस्टों का पैसा बैंकों में रखने के बजाय इन्फ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड में निवेश का नियम बनाने पर भी विचार हो।

बृजेश माथुर, गाजियाबाद

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को शिक्षक दिवस के मौके पर विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में देश भर के 81 शिक्षकों को उनकी अनूठी शिक्षण पद्धतियों के लिए इस वर्ष के राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया।

CCI NG 3.7 Product: NBTMumbaiBS PubDate: 06-09-2025 Zone: Mumbai Edition: 1 Page: NBTMP8 User: kamlesh.mestry Time: 09-05-2025 22:45 Color:

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । मुंबई । शनिवार, 6 सितंबर 2025

पीछे क्यों लौटना

बैलेट पेपर से चुनाव कराना हल नहीं

कर्नाटक सरकार ने स्थानीय निकाय चुनाव EVM के बजाय बैलेट पेपर से कराने का फैसला किया है। कांग्रेस की अगुआई में विपक्ष ने जिस तरह से EVM और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है, उसे देखते हुए कर्नाटक सरकार के इस फैसले के राजनीतिक अर्थ निकाले जा सकते हैं।

कर्नाटक निकाय चुनाव

विपक्ष की शिकायत । चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच भरोसा इस समय सबसे निचले स्तर पर है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर विपक्षी दल हमेशा से संदेह जताते रहे हैं, लेकिन अब बात इलेक्शन कमिशन की विश्वसनीयता तक पहुंच गई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने पिछले दिनों आरोप लगाया था कि महाराष्ट्र, हरियाणा और मध्य प्रदेश में हुए विधानसभा चुनावों से लेकर लोकसभा इलेक्शन तक, बड़े स्तर पर धांधली हुई। उन्होंने जिन जगहों पर गड़बड़ी की आशंका जताई थी, उनमें कर्नाटक की बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट के तहत आने वाला महादेवपुरा विधानसभा क्षेत्र भी था।

पारदर्शिता की गारंटी नहीं । कर्नाटक सरकार का कहना है कि EVM की प्रमाणिकता खत्म हो चुकी है। अगर वाकई ऐसा है, तो भी बैलेट पेपर खोए भरोसे को वापस लाने की गारंटी नहीं। भूलना नहीं चाहिए कि देश में जब चुनाव मतपत्रों के जरिये होते थे, तब भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की शिकायतें आती थीं।

टेक्नॉलजी जरूरी । अगर कोई संदेह है, तो उसका हल टेक्नॉलजी से किनारा करके नहीं मिल सकता। इसमें प्रशासनिक मशीनरी के लिए व्यावहारिक चुनौतियां भी हैं। बैलेट पेपर पर लौटने की मांग सुप्रीम कोर्ट भी पिछले साल खारिज कर चुका है। हालांकि शीर्ष अदालत ने दूसरे और तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के लिए यह रास्ता खोला था कि परिणाम से असंतुष्ट रहने की सूरत में वे प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र की 5% EVM की माइक्रोकंट्रोलर चिप का वेरिफिकेशन कर सकते हैं।

संदेह से मुक्त हो । कर्नाटक के निकाय चुनावों को एक प्रयोग मान सकते हैं, जिसके सबक आगे काम आएंगे। लोकतंत्र की बुनियाद निष्पक्ष, स्वतंत्र और विश्वसनीय चुनावों पर टिकी है। अगर कहीं कोई सवाल, कोई शक है, तो उसका उपाय खुली बहस और पारदर्शिता से निकाला जाना चाहिए। EVM के मामले में भी चुनाव आयोग को सोचना चाहिए कि किस तरह इसे आरोप मुक्त किया जा सकता है। इसके लिए सरकार, विपक्ष और आयोग - सभी को मिलकर काम करना होगा।

अंतर्दृष्टि

खुद से ही सवाल पूछें- आप चाहते क्या हैं?

सुंदर चंद ठाकुर

बहुत बार जब हम थके होते हैं, उलझन या भ्रम में होते हैं, तब खुद से यह सवाल नहीं पूछते कि हम वाकई क्या चाहते हैं। हम बस दौड़ते रहते हैं। कभी दौड़ नौकरी की होती है, कभी रिश्तों की, कभी पहचान की और कभी बस एक दिखावे की। लेकिन उस भागदौड़ में क्या आपने कभी रुककर खुद से पूछा है कि मैं सच में चाहता क्या हूं? यह सवाल बहुत सीधा लगता है, मगर इसका उत्तर उतना ही उलझा हुआ होता है। क्योंकि ज्यादातर लोग वही चाहते हैं, जो उन्हें समाज ने सिखाया है - एक अच्छी नौकरी, सम्मान, पैसा, और एक 'सफल' जिंदगी। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जो वे चाहते हैं, वह उनके अपने दिल की पुकार है या समाज की बनाई हुई कोई नकल।

जब हम बचपन में थे, तब हमारी चाहतें सरल थीं। पर जैसे-जैसे हम बड़े हुए, हमारे चाहने की दिशा दूसरों के प्रभाव में बदलती गई। हमें बताया गया कि डॉक्टर बनना अच्छा है, इंजीनियर बनना सम्मानजनक है और सरकारी नौकरी सुरक्षित है। लेकिन कभी आपने सोचा कि 'क्यों' आपको ऐसा करना चाहिए? क्या आप डॉक्टर इसलिए बनना चाहते हैं, क्योंकि आपकी मां चाहती थीं? क्या आप अभिनेता इसलिए बनना चाहते हैं, क्योंकि सबका ध्यान चाहिए? क्या आप शादी इसलिए करना चाहते हैं, क्योंकि सब कर रहे हैं? यदि आपने अपने हर लक्ष्य के पीछे के 'क्यों' को नहीं टटोला है, तो हो सकता है कि आप ऐसी ज़िंदगी बिता रहे हों, जो आपकी अपनी नहीं है। यह 'क्यों' ही है, जो जीवन को अर्थ देता है। अगर किसी पहाड़ पर चढ़ना है और पता नहीं कि क्यों चढ़ना है, तो थकान ही थकान मिलेगी। अगर भीतर कोई आग है, कोई गहरा मकसद, तो वह चढ़ाई तपस्या बन जाती है। अगर एक किसान जमीन पर पसीना बहाता है, तो इसलिए नहीं कि बस मेहनत करनी है, बल्कि इसलिए कि उसे फसल चाहिए और फसल उसके बच्चों का भविष्य है। एक लेखक अगर रात को जागकर शब्दों में जान डालता है, तो इसलिए कि वह अपने भीतर की पीड़ा या प्रेम को दुनिया से बांटना चाहता है।

जब तक हम यह नहीं समझते कि हमारी इच्छाएं कहां से आ रही हैं - हमारे मन की गहराई से या किसी बाहरी दबाव से, तब तक हम भ्रम में हैं। इसलिए अगली बार जब आप कोई सपना देखें, कोई लक्ष्य तय करें, तो खुद से यह दो सवाल जरूर पूछेंः क्या मैं वाकई यही चाहता हूं? और क्यों? ये दो सवाल बहुत कुछ साफ कर देंगे। आपके भीतर अगर कोई ऐसी पुकार है, जो बार-बार लौटकर आती है, तो उसे अनसुना मत कीजिए। शायद वहीं से आपकी असली जिंदगी शुरू होती है। याद रखिए - चाहतें वही मूल्य रखती हैं, जिनका आधार सचाई पर हो। वरना हम बस भीड़ में एक चेहरा बन जाते हैं। जीवन को दिशा देना है, तो उसकी जड़ में उतरिए। जो आप चाहते हैं, वह ही नहीं- क्यों चाहते हैं, यह भी जानिए। वहीं से रोशनी फूटेगी।

ऑफ़ दि ट्रैक

ब्राजील में मच्छर फैक्ट्री

दिलीप लाल

ब्राजील के Curitiba शहर में एक ऐसी फैक्ट्री है, जिसके बारे में सुनकर एक बार लोगों को यकीन नहीं होता। यह फैक्ट्री मच्छर बनाती है, वह भी करोड़ों में। यहां हर हफ्ते मच्छरों के करीब 10 करोड़ अंडे तैयार किए जाते हैं। मच्छर ज्यादा से ज्यादा अंडे दें, इसके लिए घोड़ों का खून भी पिलाया जाता है। इन मच्छरों की इतनी आवभगत इसलिए, क्योंकि ये डेंगू और जीका से लड़ने के हथियार हैं। दरअसल इन मच्छरों में Wolbachia नाम का बैक्टीरिया डाला जाता है। यह बैक्टीरिया मच्छरों की बीमारी फैलाने की क्षमता को कम कर देता है। फैक्ट्री में तैयार मच्छर जब बाहर छोड़े जाते हैं, तो वे दूसरे मच्छरों में भी यही वायरस फैला देते हैं। इन मच्छरों को प्यार से Wolbitos कहा जा रहा है। कोलंबिया, इंडोनेशिया और ब्राजील के ही शहर नितेरोई में यह प्रयोग आजमाया जा चुका है और वहां परिणाम शानदार रहा। प्रयोग में शामिल जगहों में डेंगू के मामलों में 69% तक की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि इस फैक्ट्री को चलाना इतना भी आसान नहीं है। मच्छरों के पनपने के लिए सही तापमान, नमी और खून तो चाहिए ही, आसपास के लोगों को भी समझाना पड़ता है कि ये मच्छर काटने वाले नहीं, बचाने वाले हैं!

रेयर अर्थ मिनरल्स पर चीन का क़ब्ज़ा भारत के लिए ख़तरा

अपना दम दिखाना होगा

उत्तम प्रकाश

अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने जब चीन के रेयर-अर्थ मैग्नेट्स पर 200% का टैरिफ लगाने की धमकी दी, तो इसका मकसद सिर्फ व्यापार की ताकत दिखाना नहीं था। उन्होंने ध्यान दिलाया कि आज की दुनिया में चिप्स, स्मार्टफोन, लड़ाकू विमान और AI सर्वर बनाने के लिए जरूरी कच्चे माल पर नियंत्रण सबसे घातक भू-राजनीतिक ताकत है। रेयर अर्थ की रिफाइनिंग और मैग्नेट बनाने में चीन का लगभग 90% कब्जा है। यहां तक पहुंचने के लिए उसने दशकों मेहनत की है। आज वह चाहे तो एक झटके में अमेरिका से लेकर यूरोप तक की फैक्ट्रियों में काम रोक सकता है।

आर्थिक स्वतंत्रता । रेयर अर्थ पर चीन का दबदबा तुरंत खत्म नहीं किया जा सकता। भारत जैसे देशों के लिए यह चेतावनी है कि आज आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब सिर्फ जमीन या ट्रेड बैलेंस नहीं। आज मायने यह रखता है कि चिप्स, खनिज, एल्गोरिद्म और क्लाउड सर्वर पर किसका कब्जा है।

आधार की सफलता । भारत का तरीका हालांकि अलग है। चीन की तरह खुद को अलग-थलग करने के बजाय वह अपने डिजिटल इनोवेशन का निर्यात कर रहा है। पिछले 10 बरसों में भारत ने बड़े पैमाने पर ओपन डिजिटल प्लैटफॉर्म बनाए हैं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है आधार। यह दुनिया का सबसे बड़ा बायोमीट्रिक आईडी सिस्टम है। दूसरे देशों की तुलना में भारत में इसकी लागत बेहद कम रही। एक कप चाय से भी कम कीमत में देश ने लोगों को उनकी अपनी डिजिटल पहचान दे दी।

लेनदेन आसान हुआ । आधार के बाद आए UPI से पैसों के लेन-देन का तरीका बदल गया। सिर्फ इस साल जुलाई में ही इसके जरिये 19.47 अरब लेन-देन किए गए, जिनकी कुल कीमत 25.08 लाख करोड़ रुपये थी। खास बात यह है कि इस पर कोई शुल्क नहीं लगता, जबकि अमेरिका में 2-3% मर्चेंट फीस ली जाती है। आधार के साथ मिलकर यह नई तरह की डिजिटल संप्रभुता को दर्शाता है।

भारत के सामने चुनौती | ● आर्थिक संप्रभुता के लिए आयात घटाना होगा | ● चिप्स, मिनरल्स में आत्मनिर्भरता जरूरी | ● आधार और UPI ने देश की क्षमता दिखाई

नाजुक तानाबाना । डिजिटल संप्रभुता सिर्फ इस बात पर निर्भर नहीं करती कि ऐप्स का मालिक कौन है या सर्वर कहां रखे गए हैं। यह जुड़ी है चिप्स पर कंट्रोल, रेयर अर्थ मटीरियल्स की सप्लाई चेन और कंप्यूटिंग पावर से। AI के क्षेत्र में भारत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन इसके लिए जरूरी GPUs को अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिजाइन किया जाता है, ताइवान में उनका निर्माण होता है, उनमें चीन का मिनरल्स लगता है और चलाने के लिए अमेरिकी कंपनियों का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। ट्रंप का टैरिफ एक चेतावनी भी है कि डिजिटल दुनिया बहुत ही नाजुक है। इसे किसी भी समय दबाव के हथियार में बदला जा सकता है।

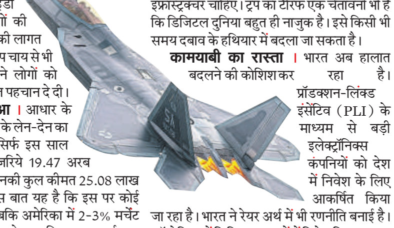

कामयाबी का रास्ता । भारत अब हालात बदलने की कोशिश कर रहा है। प्रॉडक्शन-लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) के माध्यम से बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनियों को देश में निवेश के लिए आकर्षित किया जा रहा है। भारत ने रेयर अर्थ में भी रणनीति बनाई है। ऑस्ट्रेलिया में लिथियम खदानों में निवेश किया जा रहा है। सप्लाई चेन को सुरक्षित बनाए रखने के लिए भारत Quad जैसे मंच का इस्तेमाल कर रहा है।

भारत का व्यावहारिक तरीका । UIDAI अब डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बनाने में दूसरे देशों की भी मदद कर रहा है। UPI से भारतीय विदेशों में भी पैसों का लेनदेन कर सकते हैं। अभी सिंगापुर और फ्रांस समेत सात देशों में यह सुविधा है।

सौदेबाजी का हथियार । भारत की इन उपलब्धियों के बावजूद समय तेजी से बीत रहा है। रेयर अर्थ, चिप्स और AI क्षमता अब वैश्विक कूटनीति में सौदेबाजी के नए हथियार बन गए हैं। यूरोप भी जूझ रहा है। भारत की आर्थिक महत्वाकांक्षाएं इसे और भी असुरक्षित बना देती हैं। हम AI, EV और डिजिटल कॉमर्स में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आयात की चीजों पर निर्भर हैं। अगला भू-राजनीतिक तनाव हमारे भविष्य के सपनों को तोड़ सकता है।

अगला लक्ष्य । डिजिटल संप्रभुता अब राष्ट्रीय सुरक्षा का हिस्सा है। आधार और UPI ने साबित किया है कि भारत बड़े पैमाने पर और कम लागत में तकनीकी ढांचा तैयार कर सकता है। अगली चुनौती है कि अपने विजन को सॉफ्टवेयर और सर्विसेज से आगे बढ़ाकर चिप्स, मिनरल्स और क्लाउड क्षमता तक ले जाया जाए ताकि कोई भी टैरिफ या प्रतिबंध हमें रोक न पाए।

(लेखक कोच्चि में रीजनल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर हैं, ये उनके निजी विचार हैं)

क्यों पढ़ना छूट रहा?

आपने आखिरी किताब कौन-सी पढ़ी थी? शायद याद न आए, क्योंकि हो सकता है कि कुछ पढ़े हुए लंबा अरसा बीत गया हो। जानिए कैसे पूरी दुनिया में पढ़ने की आदत कम हो रही है और इसका असर समाज और राजनीति पर क्या पड़ रहा है।

5 पॉइंट

1 ग्लोबल गिरावट

National Literacy Trust की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 8-18 आयु वर्ग के 34.6% बच्चे ही पढ़ना पसंद करते हैं। US में 20 बरसों में 40% लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया है, ब्रिटेन में 2024 में 40% लोगों ने एक भी किताब नहीं पढ़ी।

2 सरलता पसंद

छोटे और सरल वाक्यों वाली सामग्री ज्यादा पढ़ी जा रही है। न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर्स किताबों का सर्वे बताता है कि 1930 की तुलना में आज वाक्य करीब एक तिहाई रह गए हैं। भाषा आम बोलचाल वाली हो गई है।

3 टेक्नॉलजी को दोष

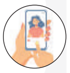

स्मार्टफोन और सोशल मीडिया ने लोगों के समय पर कब्जा कर लिया है। पहले जो खाली वक्त किताबों के हिस्से जाता था, अब स्क्रीन पर जा रहा है। धैर्य कम हुआ है। US के एक सर्वे में स्टूडेंट्स ने किताबों को बोरिंग बताया।

4 पैसा वजह नहीं

लोगों की कमाई के हिसाब से देखें तो पहले की तुलना में किताबें सस्ती हुई हैं। विक्टोरियन दौर में एक किताब औसतन आधे हफ्ते की कमाई के बराबर होती थी। अब कई क्लासिकल बुक ऑनलाइन उपलब्ध हैं।

5 राजनीति पर असर

नेताओं के भाषणों, संसदीय चर्चाओं में गिरावट आई। एक प्रयोग के जरिये इसे मापने का प्रयास किया गया - भूतपूर्व US प्रेजिडेंट जॉर्ज वॉशिंगटन का स्कोर 28.7 और ट्रंप का केवल 9.4 रहा।

प्रस्तुतिः शैलेंद्र पांडेय

इस बार मॉनसून अपनी सही चाल चला है

इस साल साउथ वेस्ट मॉनसून की शुरुआत समय से काफी पहले हो गई। देश के 95% हिस्से में मॉनसून समय से काफी पहले पहुंचा। देश भर में छाने के बाद जब मॉनसून का विकराल रूप दिखा तो लोग दहशत में आ गए। आपदाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। पहाड़ी राज्यों से लेकर पंजाब तक में बहुत नुकसान हुआ है। मॉनसून की इस बिगड़ी चाल पर भारतीय मौसम विभाग के डायरेक्टर जनरल डॉ. मृत्युंजय महापात्रा से NBT की ***पूनम गौड़*** *ने बात की। पेश हैं प्रमुख अंशः*

NBT सप्ताह का इंटरव्यू

मृत्युंजय महापात्रा

■ इस बार का मॉनसून पैटर्न अब तक किस तरह का रहा है?

हम पहले ही पूर्वानुमान में बता चुके थे कि इस बार मॉनसून सामान्य से 108% अधिक रह सकता है। उसी पैटर्न पर यह चल रहा है। यह जरूर है कि बारिश सभी जगह समान नहीं हुई है। इस बार बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर सिस्टम बना। पहाड़ों में भी वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना है। राजस्थान में भी साइक्लोनिक सर्कुलेशन बने हैं। जब ये दोनों-तीनों सिस्टम एक-दूसरे को सपोर्ट करने लगते हैं तो तेज बारिश होती है। यही इस बार भी देखने को मिल रहा है।

■ हिमालय राज्यों में मॉनसून में एक के बाद एक कई बड़ी आपदाएं आई हैं। बादल फटने जैसी घटनाओं में क्या वृद्धि हो रही है?

मॉनसून के दौरान हिमालयन रीजन और पश्चिमी पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं अधिक होती हैं। बादल फटना भी इस क्षेत्र में नया नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यह अधिक हो रहा है। पहाड़ों में ऊपरी इलाकों में जब बारिश होती है तो पानी मलबे के साथ तेजी से बहता हुआ आता है। क्लाइमेट चेंज के असर की वजह से भी बारिश की तीव्रता बढ़ रही है। लेकिन यह समस्या सिर्फ देश की नहीं है। पूरी दुनिया में इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं। ऐसी घटनाओं का दायरा बहुत छोटा होता है। इनमें एक से दो गांव प्रभावित होते हैं। इसलिए इनका पूर्वानुमान भी चुनौती रहता है। अभी हमारे पास वेस्टर्न हिमालयन रीजन में 10 रडार हैं। नॉर्थ-ईस्ट में भी रडार लगाए जा रहे हैं। वेस्ट रीजन में रडार बढ़ाए जा रहे हैं। इससे हम इन घटनाओं से थोड़ा पहले इनकी जानकारी नाउकास्ट में दे सकेंगे। नाउकास्ट हर दो से तीन घंटे में जारी किया जा रहा है। बादल फटने का पूर्वानुमान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है, लेकिन भारी बारिश का पूर्वानुमान हम लगा रहे हैं। हिमालयन रीजन में इतनी सारी पहाड़ी दरारें हैं कि दस रडार भी पर्याप्त नहीं हैं। रडार लगाना भी यहां चुनौतीपूर्ण हैं। हालांकि मिशन मौसम के जरिए रडारों की संख्या बढ़ाई जा रही है।

■ बारिश के पैटर्न में क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या बदलाव आ रहे हैं?

भारी बारिश बढ़ रही है, रिमझिम जैसी लंबे समय तक चलने वाली धीमी बारिश कम हो रही है। अब हमारी प्लानिंग उसी तरह से होनी चाहिए। बहुत छोटे एरिया में बारिश के पैटर्न अलग हो रहे हैं। दिल्ली में ही एक हिस्से में बारिश हो रही है, और उससे दो किमी दूरी पर बारिश नहीं हो रही है।

■ मॉनसून के दौरान प्राकृतिक आपदाओं में जान-माल का नुकसान न हो, इसके लिए IMD क्या प्रयास कर रहा है?

जान बचाना IMD की पहली प्राथमिकता है। बीते सालों के दौरान इसमें काफी सुधार भी हुआ है। साइक्लोन के मामले में हम जीरो कैजुअल्टी हासिल कर चुके हैं। हीट वेव में 2015 में हजारों में मौत थी, अब यह सैकड़ों से भी कम है।

■ जलवायु परिवर्तन के चलते मौसम व बारिश में किस तरह का बदलाव आया है?

वैश्विक तापमान तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों की बात करें तो पिछले दस साल में 1.15 डिग्री तापमान बढ़ा है। भारत में भी तापमान बढ़ रहा है। पिछले 100 साल में 0.6 डिग्री तापमान बढ़ा है। प्री-मॉनसून, सर्दियों और मॉनसून में भी तापमान बढ़ रहा है। इसकी वजह से नमी भी बढ़ रही है। नॉर्थ इंडिया, सेंट्रल इंडिया में तापमान बढ़ रहा है। साउथ इंडिया में पहले हीट नहीं थी, अभी हीट ज्यादा है। एक डिग्री तापमान बढ़ने से नमी का स्तर 7% बढ़ता है। नमी का मतलब वातावरण अधिक पानी सोखता है। उत्तर-पूर्वी भारत में बारिश घट रही है, वहीं उत्तर-पश्चिम भारत में जैसे राजस्थान, गुजरात के कच्छ में बारिश अधिक हो रही है। देश में कुल बारिश को देखें तो न इसमें वृद्धि हो रही है, और न कमी हो रही है। इससे पूर्वानुमान को लेकर चुनौतियां बनी हुई है।

> **मॉनसून साइकल की बात करें तो यह 15-15 दिन का होता है। मतलब पंद्रह दिन यह देश के बाकी हिस्सों में सक्रिय रहता है, फिर पंद्रह दिन पहाड़ों पर। इस बार यह साइकल मॉनसून ने फॉलो किया है। इसकी वजह से हर महीने पहाड़ों में भारी बारिश देखने को मिली है। पहाड़ी क्षेत्रों में बादल फटना भी इस क्षेत्र में नया नहीं है, लेकिन क्लाइमेट चेंज की वजह से यह अधिक हो रहा है**

■ मॉनसून पूर्वानुमान को लेकर IMD कितनी सटीकता हासिल कर चुका है और इसमें आगे क्या सुधार संभव हैं?

मौसम विभाग लगातार प्रयास कर रहा है। हमारे प्रोग्राम लगभग 40 से 50% बढ़े हैं। मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन, कंप्यूटिंग सिस्टम और न्यूमैरिकल मॉडलिंग सिस्टम को हमने मजबूत किया। जलवायु परिवर्तन से भविष्य में कैसे निपटें, इसके लिए भी मौसम जानकारी को ज्यादा एक्यूरेट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इस संदर्भ में प्रधानमंत्री ने देश को 'मिशन मौसम' समर्पित किया है। मिशन मौसम के जरिए अगले दो साल के भीतर लगभग दो हजार करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाएंगे। हमारे पास अभी 40 रडार हैं, उसे 100 करना है। इसके साथ साथ माइक्रो रेडियोमूलर, ऑटोमेटिक सिस्टम में भी सुधार होगा। कम्प्यूटिंग पावर भी बढ़ेगी।

www.nbt.in

बेटियां पीछे क्यों रह गईं

पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी हुई थी। उसी के तुरंत बाद की बात है। भारत सरकार के प्रसारण विभाग में वेकेंसी आई। मैंने फॉर्म भर दिया। परीक्षा दी और संयोग से सिलेक्शन भी हो गया। ट्रेनिंग के लिए मैसूर बुलाया गया। मगर मैं तो इलाहाबाद के रास्ते भी ठीक से नहीं जानती थी, मैसूर कैसे जाती! फिर भी पापा के आते ही मैंने खुशी से विभाग का लेटर पकड़ा दिया। पापा ने लेटर पढ़ा और मुझे पकड़ाते हुए बोले, 'जाओ, रख दो।' जाओगी या नहीं, ऐसी कोई बात नहीं की। मैं भी बेवकूफ थी। मन ही मन सोच लिया इतनी दूर कोई कैसे जा सकता है। इसलिए एक बार भी पापा से जाने की बात नहीं कही। फिर उस पत्र को भूल गई। बाद में प्राइवेट नौकरियों में उलझी रही। परिस्थितियां कुछ ऐसी बनीं कि प्राइवेट नौकरी भी छोड़नी पड़ गई। अब तो बस जिंदगी में धक्के ही धक्के थे। जितनी बार धक्के खाती, उतनी बार उस अकेली सरकारी नौकरी की याद आती। मगर वक्त बीत चुका था।

चंद रोज पहले ही अपने गांव के एक भाई साहब से मिलने उनके घर जाना हुआ। उनकी पत्नी ने बड़ी आत्मीयता से स्वागत किया। उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मैं लिखती हूं। कहने लगीं, 'आप तो इतनी पढ़ी लिखी हैं, नौकरी क्यों नहीं की?' मेरी दुखती रग दबा दी थी उन्होंने। उन्हें संक्षिप्त में अपने साथ घटी घटनाओं को बता दिया। मेरी बात सुनते ही उन्होंने भी एक किस्सा खोल दिया। उनकी बहन ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की थी। उसकी नौकरी बिहार सरकार के राजस्व विभाग में लग गई। घर बनारस में था। एक समय बिहार की कानून व्यवस्था से जुड़ी खौफनाक खबरें अखबारों में रोज ही छपती रही थीं। उनके पिता उन खबरों से सहमे हुए थे। उन्हें अपनी बेटी को बिहार भेजते डर लगा। उन्होंने बेटी को वहां जॉइन करने से मना किया। लेकिन इतनी मेहनत से मिली नौकरी कोई इतनी आसानी से कैसे छोड़ दे। पिता के विरोध के बावजूद उसने जाकर जॉइन कर लिया। महीने भर भी न हुए थे कि लौट आने के लिए पिता का रोज ही फोन आने लगा। हद तो तब हुई जब पिता ने जहर खाकर मरने की धमकी दे डाली।

खुद अपनी आंख से

सरस्वती रमेश

पापा की धमकी से डरकर बेटी लौट आई। आते ही बोली, 'लौट तो आई हूं मगर जब तक दूसरी सरकारी नौकरी नहीं मिलती, शादी नहीं करूंगी।' तब से दस साल बीत चुके हैं। वह अब तक तैयारी कर रही है। मगर नौकरी नहीं लगी। सोच रही हूं, क्या उसके या मेरे पिता को इस बात का कोई पछतावा होगा? ये कैसे पिता हैं जो अपनी बेटियों के सपनों को कब्रों तक पहुंचाने का रास्ता बनाते हैं? क्या मेरे या उसके पिता अपने बेटों के लिए भी वही फैसला करते, जो हमारे लिए किया? बिल्कुल नहीं। बेटों को वे शौक से ले जाते। मगर बेटियों के लिए उनके पास कोई विकल्प नहीं होता, सिवाय उनके सपनों का गला घोंटने के।

चलते-चलते...

कुछ माता-पिता अपने बच्चों को फलों का रस नहीं देते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि इससे दांत खराब हो सकते हैं। लेकिन हालिया अध्ययन में पता चला है कि सलाइवा दांतों की रक्षा करती है और इसकी बाहरी परत को जल्दी सुधारती है। हालांकि शोध में बताया गया है कि सेब के रस का प्रभाव 10 मिनट तक ही रहता है। यह रिसर्च PLOSE One पत्रिका में प्रकाशित हुई है।

रीडर्स मेल

▶ सरकारी स्कूलों की स्थिति

कहा जाता है कि राष्ट्र का भविष्य स्कूल की कक्षाओं में तय होता है। शिक्षक केवल ज्ञान ही नहीं देते, बल्कि जीवन मूल्यों और संस्कारों को गढ़ते हैं। यदि समाज में नैतिकता और मानवीय मूल्यों की स्वीकार्यता चाहिए, तो उसकी शुरुआत अध्यापकों के अनुकरणीय आचरण से ही होगी। आज भी देश के लगभग 56 प्रतिशत बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं। अधिकांश सरकारी स्कूलों की स्थिति संतोषजनक नहीं है। बड़ी विडंबना यह है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों पर इन स्कूलों की जिम्मेदारी है, उनके अपने बच्चे निजी स्कूलों में पढ़ते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान का उदाहरण उल्लेखनीय है। वहां शिक्षकों ने समय-पालन, आत्मसम्मान और उत्तरदायित्व को अपनाकर राष्ट्र का पुनर्निर्माण किया। अध्यापकों का सम्मान केवल समाज से नहीं, बल्कि उनके अपने आचरण और प्रयासों से भी जुड़ा है।

विभूति बुपक्या, ईमेल से

▶ गुरु साधारण नहीं होते

गुरु शब्द का अर्थ ही है- जो अज्ञान के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैलाए। भारतीय संस्कृति में गुरु को देवता के समान स्थान दिया गया है। इसका कारण यही है कि गुरु कभी साधारण नहीं होता। वह केवल एक अध्यापक नहीं, बल्कि जीवन का मार्गदर्शक, चिंतन का निर्माता और संस्कारों का संवाहक होता है। गुरु अपने शिष्य को केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं देता, बल्कि जीवन की गहरी सच्चाइयों से परिचित कराता है। साधारण व्यक्ति भौतिक जगत की बातें बता सकता है, लेकिन गुरु आत्मा को जागृत करता है, सोच को परिष्कृत करता है और शिष्य को समाज के लिए उपयोगी बनाता है। यही कारण है कि गुरु का प्रभाव जीवनभर बना रहता है। इतिहास साक्षी है कि जब भी किसी शिष्य को महान गुरु का मार्गदर्शन मिला, उसने असाधारण उपलब्धियां हासिल कीं।

समराज चौहान, ईमेल से

आर.एन.आई. पंजीयन नंबर 1613/1957 स्वत्वाधिकारी बेनेट, कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड के लिए आर. कृष्णमूर्ति द्वारा टाइम्स ऑफ इंडिया बिल्डिंग, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई 400001 से प्रकाशित और उनके द्वा (1) टाइम्स ऑफ इंडिया सबर्बन प्रेस, आकुर्ली रोड, निकट वेस्टर्न एक्सप्रेस हाइवे, कांदिवली (पू.) मुंबई 400101 एवं (2) टाइम्स ऑफ इंडिया प्रिंट सिटी, प्लॉट नं. 4, टी.टी.सी. इंडस्ट्रियल एरिया, ठाणे बेलापुर रोड, ऐरोली, नवी मुंबई-400708. फोन नं. (022) 2760 9999 ; फैक्सः (022) 2760 5275। फोन मुंबईः (022) 66353535, 22733535 रेस्पांसः (022) 66353636, 22733636 फैक्सः (022) 22731889, 22731144, कांदिवली (022) 28872324 से मुद्रित। स्थानीय संपादक (मुंबई): सुंदर चंद ठाकुर (पी. आर. बी. अधिनियम के अंतर्गत समाचारों के चयन के लिए उत्तरदायी) सर्वाधिकार सुरक्षित। प्रकाशक की लिखित अनुमति के बिना संपूर्ण या आंशिक पुनर्प्रकाशन पूर्णतः प्रतिबंधित। सड़क व रेल परिवहन सेवा शुल्कः मुंबई, ठाणे व रायगड जिलों के बाहर 1.00 रुपया। विमान सेवा शुल्कः रायपुर, नागपुर, गोवा एवं वाया 2.00 रुपये, इंदौर, चेन्नै एवं वाया 3.00 रुपये, अहमदाबाद, बेंगलुरु, कोचीन, कोयम्बतूर, एरनाकुलम, हैदराबाद, कोझीकोड, मंगलूर, त्रिवेंद्रम, उदयपुर, वाइजग एवं वाया 4.00 रुपये, दिल्ली, कोलकाता, एवं वाया 5.00 रुपये।

https://t.me/AllNewsPaperPaid

Machine Translated by Google

चांसलर

विश्वविद्यालयों का नेतृत्व प्रतिष्ठित शिक्षाविदों द्वारा किया जाना चाहिए

टी केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने हाल ही में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें उन्होंने तर्क दिया है कि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के कुलपतियों (वीसी) की नियुक्ति में केरल के मुख्यमंत्री की कोई भूमिका नहीं है।

अब्दुल कलाम प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय और डिजिटल विश्वविद्यालय केरल, एक और उदाहरण है कि कैसे हाल के राज्यपाल एक निर्वाचित राज्य सरकार के राजनीतिक और वैचारिक विरोधी हैं - जैसा कि केरल, तमिलनाडु और कुछ हद तक पश्चिम बंगाल में देखा गया है। श्री आर्लेकर ने खोज-सह-चयन समितियों के गठन और नियमों को निर्धारित करके इन विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्तियों पर लंबे समय से चल रहे गतिरोध को तोड़ने के न्यायालय के प्रयास के खिलाफ अपील की थी। राज्यपाल ने प्रस्तुत किया कि खोज-सह-चयन समितियों के लिए 2018 यूजीसी नियम उच्च शिक्षा में प्रतिष्ठित व्यक्तियों को अनिवार्य करते हैं और उन्हें किसी भी तरह से विश्वविद्यालय या उसके कॉलेजों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। इस प्रकार, उनके प्रस्तुत करने के अनुसार, मुख्यमंत्री, राज्य के सभी ऐसे संस्थानों से घनिष्ठ रूप से जुड़े व्यक्ति के रूप में, की कोई भूमिका नहीं थी। हालांकि न्यायालय श्री आर्लेकर के दृष्टिकोण की योग्यता के आधार पर निर्णय देगा, लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि भाजपा या उसके सहयोगी दलों द्वारा शासित राज्यों के राज्यपालों को उन सरकारों के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं होती है, जिनके वे नाममात्र प्रमुख होते हैं।

राज्यपाल मूल रूप से औपनिवेशिक सत्ता के साधन थे और स्वतंत्र भारत द्वारा बनाए रखे गए थे। हालाँकि, शुरू से ही, उन्होंने अक्सर केंद्र में सत्तारूढ़ दल के राजनीतिक एजेंट के रूप में काम किया है। समय के साथ, केंद्रीय और राज्य विधानों ने राज्यपालों की विवेकाधीन शक्तियों को परिभाषित और प्रतिबंधित किया, जो उन्हें संविधान द्वारा प्रदान की गई थीं। स्वतंत्रता के बाद, राज्य सरकारों ने राज्यपालों को विश्वविद्यालयों के प्रमुख के रूप में रखने की औपनिवेशिक युग की प्रथा को बरकरार रखा - स्वतंत्र उच्च शिक्षा सुनिश्चित करने के राज्य-घोषित इरादे को जारी रखने के साथ-साथ एक "पितामह" या एक बुद्धिमान बुजुर्ग को भी रखने के लिए। राज्य विधानसभाओं द्वारा पारित अधिनियम, जैसे कि एपीजे अब्दुल कलाम विश्वविद्यालय के लिए, विशेष रूप से परिभाषित करते हैं कि कुलाधिपति कौन होगा। राज्यपाल को विश्वविद्यालय के कुलाधिपति के रूप में अपना पद संबंधित राज्य सरकार के लिए ऋणी होता है। जहाँ न्यायालय ने विधेयकों पर हस्ताक्षर करके उन्हें कानून बनाने के संबंध में राज्यपालों के अधिकारों को सीमित कर दिया है, वहीं राज्य सरकारें राज्यपालों को राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बनाने के विरुद्ध निर्णायक रूप से कार्य कर रही हैं — यह उन कुछ अन्य क्षेत्रों में से एक है जहाँ राज्यपालों की सशक्त भूमिका होती है। उदाहरण के लिए, पंजाब और पश्चिम बंगाल ने एक कानून पारित कर मुख्यमंत्री को कुलाधिपति बना दिया है। विश्वविद्यालय प्रमुखों को राज्य या संघ द्वारा नियुक्त राजनीतिक व्यक्तियों के बजाय, व्यावहारिक, प्रतिष्ठित शिक्षाविद, व्यापक कार्यक्षेत्र और दूरदर्शिता वाले, और मज़बूत प्रबंधकीय कौशल वाले होने चाहिए।

एक नया पत्ता

पर्यावरण अनुपालन की सभी स्तरों पर निगरानी की आवश्यकता है

टी पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय जलवायु परिवर्तन ने पर्यावरण लेखा परीक्षा नामक नियमों का एक समूह लागू किया है।
नियम, 2025, जो पर्यावरण निगरानी और लेखा परीक्षा की महत्वपूर्ण गतिविधि को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों के अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने की अनुमति देता है। नियम बड़े पैमाने पर जांच करेंगे कि क्या औद्योगिक इकाइयां पर्यावरण विनियमन का अनुपालन कर रही हैं। मौजूदा पर्यावरणीय ढांचे के भीतर निगरानी और अनुपालन के लिए समग्र रूपरेखा वर्तमान में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, पर्यावरण मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों/प्रदूषण नियंत्रण समितियों द्वारा समर्थित है। हालांकि, उन्हें जनशक्ति, संसाधन, क्षमता और बुनियादी ढांचे के मामले में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। पर्यावरण मंत्रालय के एक प्रेस बयान में कहा गया है, "इन सीमाओं ने देश भर में चल रही बड़ी संख्या में परियोजनाओं और उद्योगों में पर्यावरण अनुपालन की व्यापक निगरानी और लागू करने की उनकी क्षमता में बाधा डाली है।"

नए नियमों के तहत, निजी एजेंसियाँ खुद को लेखा परीक्षक के रूप में मान्यता प्राप्त करा सकती हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट की तरह, पर्यावरण लेखा परीक्षक भी लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं और परियोजनाओं के पर्यावरणीय कानूनों के अनुपालन और प्रदूषण की रोकथाम, नियंत्रण और निवारण में सर्वोत्तम प्रथाओं के पालन का मूल्यांकन करने के लिए अधिकृत हो सकते हैं। हाल के वर्षों में, पर्यावरण विनियमन ने पुलिसिंग और बहीखाता पद्धति को पार कर लिया है। चूँकि मानव-जनित जलवायु परिवर्तन को एक ऐसी समस्या के रूप में देखा जाता है जिसका राष्ट्रों को सामूहिक रूप से समाधान करना चाहिए, पर्यावरण विनियमन के नए आयाम उभरे हैं। इस प्रकार, इन एजेंसियों द्वारा किए गए ऑडिट का उपयोग 'ग्रीन क्रेडिट नियमों' के अनुपालन के लिए भी किया जा सकता है, जिसके तहत व्यक्ति और संगठन वनीकरण, सतत जल प्रबंधन और अपशिष्ट प्रबंधन सहित अन्य गतिविधियों के लिए व्यापार योग्य 'क्रेडिट' प्राप्त कर सकते हैं। औद्योगिक इकाइयों के अलावा, भारत में लगभग हर कंपनी को अपने प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कार्बन उत्सर्जन का हिसाब देना होगा। इसके लिए काफी जटिल लेखांकन पद्धतियाँ आवश्यक होंगी, जिन्हें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी संभाल नहीं सकते। हालाँकि, भविष्य की तैयारी मूल ज़िम्मेदारियों से समझौता करके नहीं की जानी चाहिए। आमतौर पर ज़िला, ब्लॉक और पंचायत स्तर पर ही सबसे ज़्यादा पर्यावरणीय उल्लंघन होते हैं, जो आमतौर पर प्रशिक्षित कर्मचारियों की कमी के कारण नज़रों से बच जाते हैं।

नये शासन को उन्हें भी सशक्त बनाने का प्रयास करना चाहिए।

बहुध्रुवीय विश्व में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता

शशि थरूर

चौथा कार्यकाल है के सदस्य संसद, कांग्रेस (लोकसभा) से तिरुवनंतपुरम, के अध्यक्ष हैं संसदीय बाह्य वायु पर स्थायी समिति के सदस्य और 'पैक्स' के लेखक इंडिका: भारत और 21वीं सदी का विश्व'

अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शब्दकोष में, कुछ ही अवधारणाएँ "रणनीतिक स्वायत्तता" की तरह ही गतिशील रूप से विकसित हुई हैं। कभी अकादमिक बहस से जुड़ा एक शब्द, अब यह

भारत की विदेश नीति के विमर्श का केंद्रबिंदु, तेज़ी से बहुध्रुवीय और अस्थिर होती दुनिया में निर्णयों को आकार दे रहा है। जैसे-जैसे वैश्विक शक्ति परिवर्तन तेज़ हो रहे हैं और पारंपरिक गठबंधन कमज़ोर पड़ रहे हैं, भारत खुद को प्रतिस्पर्धी दिग्गजों: अमेरिका, चीन और रूस: के बीच एक नाजुक रास्ते पर चलता हुआ पा रहा है। सामरिक स्वायत्तता की खोज अब एक सैद्धांतिक आकांक्षा नहीं रही। यह एक दैनिक कूटनीतिक अभ्यास है, जो जटिलताओं और परिणामों से भरा है।

सामरिक स्वायत्तता किसी राष्ट्र की विदेश नीति और रक्षा के क्षेत्र में बाहरी दबावों या गठबंधन संबंधी दायित्वों से विवश हुए बिना संप्रभु निर्णय लेने की क्षमता को संदर्भित करती है। यह अलगाववाद या तटस्थता का पर्याय नहीं है।

बल्कि, इसका तात्पर्य लचीलापन, स्वतंत्रता और अपनी शर्तों पर कई शक्तियों के साथ जुड़ने की क्षमता से है। भारत के लिए, इस अवधारणा की गहरी ऐतिहासिक जड़ें हैं, जो औपनिवेशिक अधीनता और स्वतंत्र भारत के इस दृढ़ संकल्प तक जाती हैं कि वह कभी किसी और को दुनिया में हमारे लिए हमारी जगह तय नहीं करने देगा। शीत युद्ध के दौरान नेहरू के गुटनिरपेक्षता से लेकर वर्तमान युग में मोदी सरकार के "बहु-गठबंधन" तक, लगातार सरकारों ने बदलती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अनुकूल होते हुए भारत की कार्रवाई की स्वतंत्रता को संरक्षित करने की कोशिश की है। सिद्धांत रूप में, रणनीतिक स्वायत्तता कठोर गुट राजनीति और निष्क्रिय विघटन के बीच एक मध्य मार्ग प्रदान करती है। व्यवहार में, यह कुशल कूटनीति, संस्थागत लचीलेपन और राष्ट्रीय हित की स्पष्ट समझ की मांग करती है। यह एक संतुलनकारी कार्य है - कभी-कभी अनिश्चित, अक्सर अपूर्ण, लेकिन भारत जैसे देश के लिए आवश्यक है

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य भारत की सामरिक स्वायत्तता के लिए अवसर और चुनौतियाँ दोनों प्रस्तुत करता है। अमेरिकी प्रभुत्व के एकध्रुवीय दौर ने एक खंडित विश्व व्यवस्था को जन्म दिया है, जहाँ चीन की हठधर्मिता, रूस का संशोधनवाद और पश्चिम के आंतरिक मतभेद, वाशिंगटन की अनिश्चितता से और भी बढ़ गए हैं, एक अस्थिर और अप्रत्याशित वातावरण का निर्माण कर रहे हैं।

भारत के लिए इसका अर्थ है प्रमुख शक्तियों के साथ अपने संबंधों को पुनः संतुलित करना, साथ ही अपने मूल हितों - क्षेत्रीय अखंडता, आर्थिक विकास, तकनीकी उन्नति और क्षेत्रीय स्थिरता - की रक्षा करना।

भारत के संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ संबंध
पिछले दो दशकों में यह साझेदारी नाटकीय रूप से गहरी हुई है। रक्षा सहयोग और ख़ुफ़िया जानकारी साझा करने से लेकर संयुक्त सैन्य अभ्यास और तकनीक हस्तांतरण तक, रणनीतिक साझेदारी परिपक्व हुई है। क्वाड समूह (ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, अमेरिका), हिंद-प्रशांत वार्ता, प्रारंभिक I2U2 (भारत, इज़राइल, संयुक्त अरब अमीरात और अमेरिका) और भारत-मध्य पूर्व-यूरोप आर्थिक गलियारा (IMEC), और चीन के उदय पर साझा चिंताओं ने इसे और मज़बूत किया है।

जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, भारत को कठिन राह पर चलते रहना होगा, तथा दोनों देशों के बीच नाजुक रास्ते पर चलना होगा।

संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और रूस

संबंधों को मज़बूत किया। फिर भी, ये रिश्ते बिना किसी टकराव के नहीं हैं। ट्रंप प्रशासन की अनिश्चित व्यापार नीतियों और उसके बाद उनके दूसरे कार्यकाल में कठोर टैरिफ़ और प्रतिबंधों ने आर्थिक संबंधों को तनावपूर्ण बना दिया है।

रूस के साथ ऊर्जा और रक्षा सौदों को कम करने तथा पश्चिमी रुख के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए भारत पर वाशिंगटन के दबाव ने नई दिल्ली के संकल्प की परीक्षा ली है।

भारत की प्रतिक्रिया नपी-तुली रही है। वह अमेरिका के साथ लगातार संपर्क बनाए रखता है, वैश्विक संघर्षों पर स्वतंत्र रुख अपनाता है, और वैचारिक एकता पर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता देता है। यह कार्रवाई में रणनीतिक स्वायत्तता है, अमेरिका-विरोध नहीं, बल्कि अमेरिकी प्राथमिकताओं के अधीन होने से इनकार।

बीजिंग और मॉस्को के साथ चीन के संबंध एक अधिक जटिल चुनौती प्रस्तुत करते हैं। 2020 में भारत के साथ सीमा पर हुए संघर्षों ने सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के भ्रम को चकनाचूर कर दिया और कूटनीतिक पहल के बावजूद तनाव उच्च बना हुआ है। फिर भी, चीन भारत के सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में से एक है, क्षेत्रीय संस्थानों में एक प्रमुख खिलाड़ी है, और एक ऐसा प्रतिस्पर्धी है जिसके कार्य रणनीतिक वातावरण को आकार देते हैं। भारत का दृष्टिकोण सतर्क जुड़ाव और दृढ़ प्रतिरोध का है। यह सीमावर्ती बुनियादी ढाँचे को मजबूत करता है, हिंद-प्रशांत साझेदारों के साथ संबंधों को गहरा करता है, और स्वदेशी रक्षा क्षमताओं में निवेश करता है। साथ ही, यह ब्रिक्स और शंघाई सहयोग संगठन जैसे बहुपक्षीय मंचों में भाग लेता है, जहाँ चीन एक अग्रणी भूमिका निभाता है - एक कठिन लेकिन आवश्यक संतुलनकारी कार्य।

यहाँ रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है दोनों का विरोध करना टकराव और आत्मसमर्पण। इसका अर्थ है संप्रभुता का दावा करना और उभरते चीन के सामने किसी अन्य देश का प्रतिकार करने से इनकार करना, साथ ही भारतीय अर्थव्यवस्था तक चीन की पहुँच को नियंत्रित करना, और साथ ही संचार के माध्यमों को खुला रखना। इसका अर्थ है यह स्वीकार करना कि प्रतिद्वंद्विता कूटनीति को बाधित नहीं करती है, और यह कि अलगाव हमेशा वांछनीय या व्यवहार्य नहीं होता है।

रूस के साथ भारत के संबंध शीत युद्ध की एकजुटता, रक्षा सहयोग और साझा रणनीतिक हितों पर आधारित हैं। मास्को की बीजिंग के साथ बढ़ती निकटता और यूक्रेन युद्ध के बाद रूस के वैश्विक अलगाव के बावजूद, भारत ने अपने संबंध बनाए रखे हैं—तेल खरीदना, हथियार आयात करना और कूटनीतिक रूप से सक्रिय रहना। पश्चिमी देशों ने इसकी आलोचना की है, लेकिन भारत दृढ़ रहा है। रूस के साथ उसके संबंध ऐतिहासिक, बहुआयामी हैं और किसी बाहरी निषेधाज्ञा के अधीन नहीं हैं। वह अपने सैन्य आयातों में विविधता ला रहा है, स्वदेशी उत्पादन में निवेश कर रहा है और नई साझेदारियों की तलाश कर रहा है, लेकिन पुरानी साझेदारियों को छोड़े बिना। यहाँ रणनीतिक स्वायत्तता का अर्थ है द्विआधारी प्रतिस्पर्धा में पक्ष चुनने से इनकार करना, और इसके बजाय एक ऐसी विदेश नीति तैयार करना जो भारत के अनूठे भूगोल, इतिहास और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करे।

2023 में भारत की जी-20 अध्यक्षता के दौरान, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की कि भारत अब वैश्विक दक्षिण की आवाज है - बिना झुके, बहुलवादी और शक्तिशाली। उन्होंने कहा कि इसका लोकतंत्र महज एक व्यवस्था नहीं, बल्कि एक "आशा का गुलदस्ता" है, जो इसके बहुभाषी, बहुसांस्कृतिक ताने-बाने की ताकत से पोषित है। विदेश मंत्री एस. जयशंकर का तर्क है कि साझेदारियों को हितों से आकार मिलना चाहिए, न कि भावनाओं या विरासत में मिले पूर्वाग्रह से। यह रीढ़ वाली कूटनीति है - मुखर, व्यावहारिक और बेबाक भारतीय, जो "पश्चिम विरोधी" हुए बिना "गैर-पश्चिम" होने की कोशिश करती है। यह रुख पूरे वैश्विक दक्षिण में गूंजता है, जहां कई उभरती और मध्यम शक्तियां, जो अपने क्षेत्रों में शांति और स्थिरता को लेकर चिंतित हैं, महाशक्तियों की प्रतिद्वंद्विता के भंवर में बहने के बजाय अपने भू-राजनीतिक और आर्थिक हितों की रक्षा करना चुन रही हैं। वे एजेंसी चाहते हैं, संरेखण नहीं; आवाज चाहते हैं, गुलामी नहीं।

इससे यह परिकल्पना उभर कर आती है कि भारत एक पुनर्संतुलित विश्व में एक संप्रभु ध्रुव है - एक ऐसा राष्ट्र जो न तो आंख मूंदकर किसी के साथ गठबंधन करता है और न ही खुद को अलग-थलग करता है।
इस प्रकार, भारत का उत्थान सभ्यतागत, बहुलवादी और गहन राजनीतिक है।
हालाँकि भारत की रणनीतिक स्वायत्तता की खोज सैद्धांतिक है, लेकिन प्रमुख शक्तियों के बीच संतुलन बनाते हुए उसे विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। वैश्विक अर्थव्यवस्था तेज़ी से परस्पर निर्भर होती जा रही है, और तकनीकी पारिस्थितिकी तंत्र पर कुछ ही देशों का प्रभुत्व है। रक्षा आधुनिकीकरण के लिए साझेदारी और जलवायु कूटनीति के लिए समन्वय की आवश्यकता है। ऐसी दुनिया में, स्वायत्तता को पुनर्परिभाषित किया जाना चाहिए - अलगाव के रूप में नहीं, बल्कि लचीलेपन और अनुकूलनशीलता के रूप में।

घरेलू कारक भी भूमिका निभाते हैं।
ध्रुवीकरण, आर्थिक कमजोरियां और संस्थागत बाधाएं स्वायत्त निर्णय लेने की प्रभावशीलता को सीमित कर सकती हैं।

सामरिक स्वायत्तता के लिए न केवल कूटनीतिक कौशल, बल्कि आर्थिक मजबूती, तकनीकी क्षमता और राजनीतिक सामंजस्य की भी आवश्यकता होती है। हम कमज़ोर स्थिति से पूरी तरह स्वायत्त नहीं हो सकते।

इसके अलावा, साइबर खतरों की दुनिया में, आर्टिफिशियल खुफिया युद्ध और अंतरिक्ष प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में, स्वायत्तता को पारंपरिक क्षेत्रों से आगे बढ़ना होगा। इसमें डेटा संप्रभुता, डिजिटल बुनियादी ढाँचा और आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा शामिल होनी चाहिए।

स्वदेशी प्लेटफॉर्म बनाने, महत्वपूर्ण खनिजों को सुरक्षित करने और वैश्विक तकनीकी प्रशासन में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए भारत के हालिया प्रयास इस दिशा में उठाए गए कदम हैं।

एक नारे से कहीं बढ़कर: सामरिक
स्वायत्तता सिर्फ़ एक नारा नहीं है। यह एक रणनीति है। यह अपनी दिशा खोए बिना एक अशांत दुनिया में आगे बढ़ने की कला है। जैसे-जैसे वैश्विक व्यवस्था बदल रही है, भारत को लगातार संतुलन बनाए रखना होगा—अमेरिका के साथ बिना किसी जागीरदार के संबंध बनाना होगा, चीन को युद्ध भड़काए बिना रोकना होगा, और रूस के साथ साझेदारी करनी होगी, बिना उसके अलगाव को स्वीकार किए। उसे क्षमताओं में निवेश करना होगा, साझेदारियाँ विकसित करनी होंगी, और स्पष्टता और आत्मविश्वास के साथ अपने हितों का दावा करना होगा।

ऐसा करके, भारत दुनिया को अस्वीकार नहीं करता—वह उसमें अपनी स्वायत्तता पुनः प्राप्त करता है। सामरिक स्वायत्तता का अर्थ अकेले खड़े होना नहीं है; इसका अर्थ है सीधे और ऊँचा खड़ा होना।

समस्याओं का समाधान, भारत की विकास क्षमता का दोहन

Harsha Vardhan अग्रवाल

राष्ट्रपति हैं, भारतीय संघ के चैंबर वाणिज्य और उद्योग (फिक्की)

मैं भारत की आर्थिक यात्रा हमेशा साहसिक सुधारों द्वारा आकार लेती रही है, और नवीनतम सुधारों का एक सेट वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) उपाय
3 सितंबर, 2025 को 56वीं जीएसटी परिषद की बैठक में घोषित, यह अब तक के सबसे महत्वपूर्ण पैकेजों में से एक साबित हो सकता है। वर्षों से, व्यवसाय और नीति निर्माता, दोनों ही भारत की अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था में सरलीकरण, पूर्वानुमान और निष्पक्षता की माँग करते रहे हैं। नवीनतम निर्णयों—दरों को सुव्यवस्थित करना, विसंगतियों को दूर करना, अनुपालन को आसान बनाना और विवाद समाधान को मज़बूत करना—के साथ, सरकार ने एक ऐसा पैकेज पेश किया है जो महत्वाकांक्षा और व्यावहारिकता का संतुलन बनाता है।

इस क्षण को विशेष बनाने वाली बात सिर्फ यह नहीं है कि बदलावों का दायरा ही नहीं, बल्कि उनके पीछे की सहयोगात्मक भावना भी मायने रखती है। इसका नतीजा वही है जिसे कई लोग जीएसटी 2.0 कह रहे हैं—एक ऐसा सुधार जो न सिर्फ़ आज की समस्याओं को दूर करने के लिए, बल्कि आने वाले दशक के लिए भारत की विकास क्षमता को भी उजागर करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

कई आय वर्गों को राहत: साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, शैम्पू, रसोई के बर्तन और पैकेज्ड खाद्य पदार्थ जैसी आवश्यक वस्तुएँ अब कम कर दरों के दायरे में आ गई हैं, जिससे घरेलू बजट में तुरंत सुधार होगा और लाखों लोगों को रोज़गार देने वाले क्षेत्रों में माँग बढ़ेगी। आवास के लिए, सीमेंट और निर्माण सामग्री पर जीएसटी में कमी से ज़्यादा परिवारों की पहुँच में घर आएँगे, जिससे सरकार के 'सभी के लिए आवास' मिशन को बल मिलेगा और साथ ही स्टील, टाइल्स, सैनिटरीवेयर और पेंट जैसे संबद्ध उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा।

बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी इनपुट की कम लागत, परियोजना की व्यवहार्यता में सुधार और विस्तार के लिए पूंजी मुक्त होने से लाभ होगा।

जीवन रक्षक दवाएँ और महत्वपूर्ण चिकित्सा उपकरण जीएसटी को शून्य या 5% कर दिया गया है, जिससे इलाज की लागत कम हुई है और मरीजों के लिए दवाओं तक पहुँच बढ़ी है। एक ऐसे देश में जो सस्ती दवाओं के वैश्विक केंद्र के रूप में उभरा है, यह सामाजिक और आर्थिक दोनों तरह से एक जीत है।

कपड़ा, हस्तशिल्प, चमड़ा, जूते-चप्पल और खिलौने जैसे श्रम-प्रधान उद्योगों को कम दरों का लाभ मिलेगा, जिससे मार्जिन की रक्षा होगी, आजीविका सुरक्षित रहेगी और अर्ध-शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर पैदा होंगे। विकास के प्रमुख चालक, ऑटोमोटिव क्षेत्र में भी वृद्धि देखी जाएगी।

जीएसटी 2.0 एक कर सुधार और विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है

अब अधिक किफायती छोटी कारें, मोटरसाइकिलें, बसें और ट्रक उपलब्ध होने से ऑटो-विनिर्माण केन्द्रों में मांग और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

निर्यातकों और एमएसएमई की मदद: दरों को युक्तिसंगत बनाने से निर्यातकों को भी मदद मिलेगी। कपड़ा, उर्वरक और नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में उल्टे शुल्क ढाँचों के कारण लंबे समय से चली आ रही विकृतियों को अब धीरे-धीरे दूर किया जा रहा है। इससे भारतीय उत्पाद वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे और आयात पर निर्भरता कम होगी।

हस्तशिल्प, चमड़ा और इंजीनियरिंग सामान जैसे निर्यात-प्रधान क्षेत्र — जो मुख्यतः सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) द्वारा संचालित हैं — लाभ प्राप्त करने की अच्छी स्थिति में हैं। पूंजीगत वस्तुओं और मध्यवर्ती वस्तुओं पर कम शुल्क स्थानीय मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा देंगे, जिससे 'मेक इन इंडिया' पहल को सीधे तौर पर समर्थन मिलेगा।

जीएसटी की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक हमेशा से रही है मुकदमेबाजी रही है। व्याख्या संबंधी विवाद, वर्गीकरण संबंधी जटिलताएँ और कर व्यवस्था को लेकर अनिश्चितता ने व्यवसायों पर बोझ डाला है और व्यवस्था को अवरुद्ध कर दिया है। युक्तिकरण स्लैब को सरल बनाकर और समान वस्तुओं के लिए दरों में सामंजस्य स्थापित करके इस समस्या का समाधान करता है। मध्यस्थ सेवाओं और बिक्री के बाद छूट पर स्पष्टीकरण अस्पष्टता को और कम करते हैं, सेवा निर्यातकों को लंबे समय से प्रतीक्षित राहत प्रदान करते हैं और कर नियमों को वाणिज्यिक प्रथाओं के अनुरूप बनाते हैं।

छोटे निर्यातक इस निर्णय का स्वागत करेंगे।
कम मूल्य के माल पर रिफंड की सीमा हटाई जाएगी। इससे कूरियर और ई-कॉमर्स कंपनियों के लिए बेहतर व्यवहार सुनिश्चित होगा, जहाँ नकदी का दबाव बहुत ज़्यादा है। तेज़ और विश्वसनीय रिफंड से कार्यशील पूंजी की चुनौतियाँ कम होंगी और विकास में पुनर्निवेश को बढ़ावा मिलेगा।

शायद सबसे क्रांतिकारी कदम छोटे और कम जोखिम वाले व्यवसायों के लिए सरलीकृत जीएसटी पंजीकरण योजना है। तीन दिनों के भीतर स्वचालित अनुमोदन शुरू करके, सरकार ने प्रवेश बाधाओं को नाटकीय रूप से कम कर दिया है, जिससे अनुपालन लागत में कमी आएगी, औपचारिकता को बढ़ावा मिलेगा और एमएसएमई को नए बाजारों में अधिक आसानी से विस्तार करने में मदद मिलेगी।

यह देखते हुए कि एमएसएमई भारत की रीढ़ हैं अर्थव्यवस्था - नौकरियों, निर्यात और में योगदान नवाचार - इस कदम के महत्व को अतिरंजित नहीं किया जा सकता।

संस्थागत सुधार को भी बढ़ावा मिला है
वस्तु एवं सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) के संचालन के साथ। विवादों के तेज़ और निष्पक्ष समाधान को सक्षम बनाकर, जीएसटीएटी प्रणाली में विश्वास को मज़बूत करेगा और लंबित मामलों को कम करेगा। यह दर्शाता है कि जीएसटी केवल राजस्व संग्रह के बारे में नहीं है, बल्कि एक निष्पक्ष और पूर्वानुमानित कर ढाँचे के निर्माण के बारे में भी है जिस पर व्यवसाय भरोसा कर सकें।

व्यापक संदेश भी उतना ही महत्वपूर्ण है।
सुव्यवस्थित दो-दर वाली जीएसटी संरचना (18% की मानक दर और 5% की मेरिट दर, तथा कुछ चुनिंदा वस्तुओं और सेवाओं के लिए 40% की विशेष डिमेरिट दर) भारत को वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के और अधिक निकट लाती है, और उसे उन्नत अर्थव्यवस्थाओं द्वारा अपनाई जाने वाली कर व्यवस्था की ओर ले जाती है। अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों के लिए, ये सुधार नीतिगत स्थिरता, पूर्वानुमानशीलता और व्यापार में आसानी का एक मज़बूत संकेत देते हैं। ऐसी दुनिया में जहाँ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का पुनर्गठन हो रहा है, भारत न केवल एक विशाल बाज़ार के रूप में, बल्कि एक विश्वसनीय और प्रतिस्पर्धी निवेश गंतव्य के रूप में भी अपनी स्थिति बना रहा है।

आर्थिक विस्तार का मार्ग बेशक, सुधार कभी भी सड़क का अंत नहीं होते हैं।
कार्यान्वयन महत्वपूर्ण होगा, और देरी और प्रक्रियागत जटिलताओं जैसी चुनौतियों पर अभी भी ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो बात सबसे महत्वपूर्ण है, वह है इरादा। सरकार ने दिखाया है कि वह उद्योग जगत की बात सुन रही है, निर्णायक कार्रवाई करने को तैयार है, और एक ऐसी कर प्रणाली बनाने के लिए प्रतिबद्ध है जो विकास को बाधित करने के बजाय उसे बढ़ावा दे।

जीएसटी 2.0 महज एक कर सुधार से कहीं अधिक है। यह एक यह एक ऐसा आर्थिक सुधार है जो उपभोग को बढ़ावा देगा, एमएसएमई को सशक्त बनाएगा, प्रतिस्पर्धात्मकता को मज़बूत करेगा और भारत की विकास गति को सुदृढ़ करेगा। यह भारत के आर्थिक विस्तार के अगले चरण की नींव रखता है।

जीएसटी की कहानी हमेशा से ही एक साहसिक महत्वाकांक्षा की कहानी रही है। इन सुधारों के साथ, भारत ने उस महत्वाकांक्षा को साकार करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाया है। व्यवसायों, उपभोक्ताओं और नीति निर्माताओं, सभी के लिए, यह केवल दरों में समायोजन नहीं है। यह भारत की विकास यात्रा में एक नए अध्याय की शुरुआत है।

द टटर्सटूदएडिटर

जीएसटी स्लैब में रियायतें
इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि चिकित्सा और जीवन बीमा पॉलिसियों के लिए व्यक्तियों द्वारा देय प्रीमियम पर लगाए गए 18% जीएसटी ने कई लोगों, विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों को प्रभावित किया है। नागरिकों और पेंशनभोगियों। उनमें से कई लोगों ने पॉलिसी रिन्यू करना बंद कर दिया क्योंकि वे 18% जीएसटी के भारी बोझ के साथ मूल प्रीमियम का भुगतान करने में असमर्थ थे। उनकी वास्तविक मांगें कम करने की थीं। जीएसटी की दर अनसुनी कर दी गई। उनमें से कई लोगों ने शिकायत की क्योंकि उनके पास अत्यधिक खर्च को कवर करने के लिए कोई वैध चिकित्सा बीमा नहीं बचा था।

बीमार पड़ने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती होने का खर्च उठाना पड़ता था। यह नहीं भूलना चाहिए कि यहाँ तक कि जीवन रक्षक मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन, डायग्नोस्टिक किट, ग्लूकोमीटर और करेक्टिव चश्मों पर भी 12% और थर्मामीटर पर 18% की दर से शुल्क लगाया गया। बेचारी जनता को भारी कीमत चुकाने के बाद अधिकतम जीएसटी दर को कम करने के लिए, सरकार अब जीएसटी स्लैब में संशोधन करने की जल्दी में है। आश्चर्य की बात यह है कि क्या यह बदलाव महत्वपूर्ण राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के कारण है?

बीमा कंपनियां भी जीएसटी छूट का उपयोग अनैतिक रूप से मूल प्रीमियम बढ़ाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए।

शालिनी गेराल्ड,
चेन्नई

letters@thehindu.co.in पर भेजे गए पत्रों में डाक पता अवश्य होना चाहिए।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

राष्ट्रीय सहारा
नई दिल्ली • शनिवार • 6 सितम्बर • 2025
www.rashtriyasahara.com

अनमोल वचन

अगर तुम किसी चीज को पसंद नहीं करते हो तो उसे बदल दो।
अगर बदल नहीं सकते तो अपना रवैया बदल दो।
-माया एंजिलो

तेरी, मेरी, सबकी गलती

देश के चार उत्तरी राज्यों में बाढ़ और भूस्खलन से तबाही को लेकर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने लगता है उस मर्म पर हाथ रख दिया है जिसकी ओर पर्यावरणविद, भूगर्भशास्त्री और स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता अर्से से ध्यान दिलाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार और नीति-निर्धारकों, राजनीतिक नेताओं और प्रशासनिक अमले के कानों पर कोई जूं नहीं रेंगती। स्थानीय सरकारों, मंत्रियों और अफसरों से मिल कर भू माफिया ने इन राज्यों का जो हाल कर दिया है, वह तो अब कभी सुधर नहीं सकता। अदालत ने बाढ़ और भूस्खलन पर गंभीर चिंता जताते हुए इसके लिए पेड़ों की अवैध कटाई को प्रमुख कारण माना है। पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू-कश्मीर सरकारों को नोटिस जारी कर उनसे दो हफ्तों के भीतर जवाब दाखिल करने को कहा गया है।

मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि बड़े पैमाने पर अवैध पेड़ कटाई की गई है, और यही हालिया आपदा का बड़ा कारण हो सकता है। अदालत ने मीडिया रिपोर्टों पर संज्ञान लेते हुए कहा कि हमने हिमाचल प्रदेश के दृश्य देखे, जहां बड़ी संख्या में लकड़ी के कुंदे के कुंदे बाढ़ में बहते हुए नजर आए। यह अनियंत्रित पेड़ कटाई का संकेत है। विकास जरूरी है, लेकिन वह संतुलित होना चाहिए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता क्या कहते, उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि हमने प्रकृति के साथ इतनी छेड़छाड़ की है कि अब प्रकृति हमें उसका जवाब दे रही है। उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि इस मुद्दे पर वे पर्यावरण मंत्रालय के सचिव से बात करेंगे और संबंधित राज्यों के मुख्य सचिवों से भी संवाद स्थापित करेंगे। लेकिन क्या ये बातें कहने से पहले मेहता को सोचना नहीं चाहिए था कि जब-जब पर्यावरणविद, भूगर्भ शास्त्री और सामाजिक कार्यकर्ता सवाल उठाते हैं, या स्थानीय लोग आंदोलन करते हैं, तब सरकारों की गलत नीतियों की पैरवी करने राज्य ओर केंद्र के अटॉर्नी और सालिसिटर जनरल जैसे बड़े अधिकारी क्यों आ जाते हैं। उस समय क्या उन्हें दुष्परिणामों का भान नहीं होता। केदारनाथ त्रासदी, जोशीमठ की दरारें, हिमाचल और उत्तराखंड के भूस्खलन और बाढ़, वैष्णो देवी तथा अमरनाथ यात्रा मार्गों पर हुए हादसों और पंजाब की बर्बादी से हम कभी सबक भी लेंगे या नोटिसों का सिलसिला यूं ही बदस्तूर जारी रहेगा।

जीएसटी में सुधार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी व्यवस्था में किए गए व्यापक सुधारों (जीएसटी 2.0) को राष्ट्र के लिए समर्थन और वृद्धि को 'दोहरी खुराक' करार देते हुए बृहस्पतिवार को कहा कि आत्मनिर्भर भारत के लिए अगली पीढ़ी के सुधारों की शृंखला अब नहीं थमेगी। राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार विजेताओं के साथ संवाद के दौरान कहा कि उन्होंने 15 अगस्त को लाल किले से वादा किया था कि दिवाली और छठ पूजा से पहले देशवासियों को 'दोहरा धमाका' मिलेगा। गौरतलब है कि जीएसटी परिषद की बुधवार को हुई बैठक में अब से सिर्फ पांच और 18 फीसद की दो कर दरें रखने का फैसला किया गया जबकि विलासिता एवं अहितकर उत्पादों को 40 फीसद के दायरे में रखा गया है। जीएसटी में यह राहत 22 सितम्बर से मिलना शुरू हो जाएगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार का लक्ष्य है कि आम लोगों की जेब में अधिक पैसा बचे और उनका जीवन बेहतर बने।

दावा किया जा रहा है कि नये सुधारों से कर प्रणाली सरल होगी, जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा, खपत एवं वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा, कारोबारी सुगमता बढ़ेगी जिससे निवेश और रोजगार सृजन को प्रोत्साहन मिलेगा तथा विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद को मजबूती मिलेगी। हालांकि कांग्रेस और कुछ अन्य विपक्षी दलों ने दावा किया है कि इसे लागू करने में देर हो गई है। हालांकि नये सुधारों का स्वागत किया जा रहा है, लेकिन इस तरफ ध्यान जरूर खींचा जा रहा है कि जीएसटी का मौजूदा डिजाइन और कई दरें होनी ही नहीं चाहिए थीं। कांग्रेस का कहना है कि उसने 2019 और 2024 के लोक सभा चुनावों के अपने घोषणापत्र में तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की मांग की थी, लेकिन मोदी सरकार ने एक राष्ट्र, एक कर को एक राष्ट्र, नौ कर बना दिया। बहरहाल, जीएसटी में नये सुधार के खिलाफ बोलने के लिए विपक्ष के पास कुछ ज्यादा नहीं है। सच तो यह है कि विपक्ष दुविधा में है कि जीएसटी में बदलाव पर क्या कहे। कर सरलीकरण के लिहाज से ही नहीं, बल्कि ट्रंप टैरिफ के असर को कम करने के मद्देनजर भी यह सुधार जरूरी था। निर्यात मोर्चे पर भारतीय उत्पादों को ट्रंप टैरिफ के चलते झटका मिलना तय है। घरेलू मांग को मजबूत बनाए रख कर ट्रंप टैरिफ के असर को कम से कम किया जा सकता है। जीएसटी में यह सुधार यकीनन आर्थिक तकाजों को पूरा करने वाला स्वागतयोग्य कदम कहा जा सकता है।

कटाक्ष/कबीरदास

उनके पास मां है!

फिल्म दीवार का प्रसिद्ध डॉयलाग याद है? मार तमाम चीजें गिना कर हीरो से पूछा गया, तुम्हारे पास क्या है? घनघोर संस्कारी जवाब मिला-मेरे पास मां है। बिहार में उसी फिल्मी मुकाबले का रीप्ले हो गया। राहुल-तेजस्वी-लेफ्ट-वीआइपी सब ने वोटर अधिकार यात्रा निकाली। 'वोट चोर, गद्दी छोड़' के नारे लगाए और जम कर पब्लिक से लगवाए। पर मोदी जी का हीरो स्ट्रोक सब पर भारी पड़ गया। सहयोगियों ने पूछा, वोट चोरी नहीं होने देंगे का क्या जवाब है? मोदी जी ने तसल्ली दी-फिकर नॉट, हमारे पास मां है। फिर क्या था, झटपट बिहार बंद हो गया। मां के सम्मान में, भगवा छाप मैदान में।

नकलची हैं वो लोग जो यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मां उनके पास भी है। हो ही नहीं सकता। मां सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पास है। गैर-पीएम की मां भी कोई मां होती है! और जब दूसरों के पास मां है ही नहीं, तो मां का अपमान कैसे हो सकता है? बोल दिया होगा किसी ने सोनिया गांधी को भी कुछ। किसी ने क्या खुद विश्व गुरु ने ही कह दिया होगा, कभी कुछ। बोल दिया होगा, जर्सी गाय। कह दिया होगा, राहुल को हाइब्रिड बछड़ा। पूछ लिया होगा कि ये पैसा कांग्रेस की किस विधवा के खाते में जाता है? पर इसमें गलत क्या है? यह तो राजनीतिक वाद-विवाद है। राजनीतिक वाद-विवाद ही तो डेमोक्रेसी की जान है। वाद-विवाद है तो डेमोक्रेसी है। इस वाद-विवाद को मां के अपमान से और वह भी पीएम की मां के अपमान से कैसे मिलाया जा सकता है। कोई समानता ही नहीं है। किसी और को सूपनखा कह दिया हो, तब भी नहीं। किसी और को चौसठ करोड़ की गर्ल फ्रेंड कह दिया हो, तब तो बिल्कुल नहीं। कहां गर्ल फ्रेंड और कहां मां और मां का सम्मान। सम्मान भी उस मां का जो राजनीति में भी नहीं थी। जो राजनीति में हो उसका मां होना भी कोई मां होना है, लल्लू! अब प्लीज इस तरह के तकनीकी मुद्दे उठाने की कोशिश कोई नहीं करे कि मोदी जी फिर से बायलॉजीकल कब से हो गए? या मां भी उनके साथ नॉन-बायोलाजीकल हो गईं? गाली मोदी जी को दी गई, तो अपमान मां का कैसे? और मोदी जी की मां के सम्मान में, भगवाई सिर्फ बिहार में मैदान में क्यों? मां के सम्मान के मामले में तर्क को कौन पूछता है, जी!

नफा-नुकसान कितना!

चीन से निकटता

उमाकांत लखेड़ा

प्रधानमंत्री मोदी की हालिया चीन यात्रा को दोस्ती की शुरुआत के तौर पर प्रचारित किया गया। लेकिन असली हालात इतने आसान नहीं हैं, जैसे बताए जा रहे हैं। भारत और चीन की नजदीकी असल में अस्थायी रुकावट जैसी है, न कि भरोसेमंद रिश्ते की नई शुरुआत। कूटनीतिक जानकार इस नई दोस्ती पर फूंक-फूंक कर कदम बढ़ाने की सलाह दे रहे हैं क्योंकि चीन के साथ भारत के आयात-निर्यात में भारी असमानता है। इसलिए जल्दबाजी में जोखिम की अधिक आशंकाएं जताई जा रही हैं।

निःसंदेह प्रधानमंत्री की यात्रा से चीन के साथ रिश्तों की बर्फ पिघली है। दोनों देशों के बीच इस निकटता से कुछ क्षेत्रों में सहयोग के संकेत जरूर मिले। चीन ने कहा कि वह इलेक्ट्रॉनिक्स और गाड़ियों के क्षेत्र में भारत के साथ नये सिरे से काम करेगा। सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियम आसान करने और कुछ निर्यात पाबंदियां हटाने का वादा किया। अमेरिका के भारी टैक्सों के दबाव में फंसे भारत के लिए ये कदम थोड़ी राहत लेकर आए। मोदी और शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन 'साझेदार हैं, दुश्मन नहीं।' इससे दोस्ती का माहौल बना, लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं खड़ी दिखती है। चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है। पाकिस्तान में अरबों डॉलर लगाता है, सैन्य और परमाणु मदद देता है और उसकी ढाल बनता है। इससे भारत के लिए दो तरफ से सुरक्षा का खतरा हमेशा बना रहता है, जिसे कोई भी मुलाकात नहीं बदल सकती।

चीन की बेल्ट एंड रोड योजना भी भारत के लिए चिंता का कारण है। श्रीलंका, मालदीव, नेपाल, बांग्लादेश और म्यांमार तक चीन अपने प्रोजेक्ट्स फैला रहा है। ये सिर्फ विकास के काम नहीं हैं, बल्कि एक तरह का घेरा हैं, जिससे भारत का प्रभाव अपने ही पड़ोस में कम हो रहा है। आर्थिक स्थिति भी भारत के अनुकूल नहीं है। चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 90 अरब डॉलर से ज्यादा हो चुका है। भारत चीन से बहुत ज्यादा सामान खरीदता है, लेकिन चीन भारत से बहुत कम खरीदता है। इससे भारत चीन पर निर्भर हो जाता है, लेकिन उसे उतना फायदा नहीं मिलता। उड़ानों या वीजा में ढील जैसी चीजें इस बड़े घाटे और अमेरिकी टैक्स से हुए नुकसान की भरपाई नहीं कर सकतीं।

भारत-चीन-रूस धुरी की चर्चा ज्यादा नाटकीय कथा जैसी लगती है, इस नई जुगलबंदी में दूरगामी और व्यावहारिक कूटनीतिक संतुलन जैसी नहीं बात नहीं लगती। भारत और चीन एशिया में फिर से अपना प्रभाव बढ़ाने के मामले में अतीत से ही प्रतिद्वंद्वी हैं। जाहिर है इनकी

बुनियादी दृष्टि परस्पर विरोधी है। चीन वर्चस्व स्थापित करना चाहता है, पाकिस्तान को समर्थन देता है और भारत के पड़ोस में प्रभाव बनाना चाहता है। वहीं भारत इसका जवाब अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के साथ क्वाड जैसे बहुपक्षीय गठबंधनों से देता है। रूस, जो यूक्रेन युद्ध के बाद चीन पर और अधिक निर्भर हो गया है, इस धुरी में और भी असंतुलन पैदा करता है। ऐसी स्थिति में भारत के एक 'छोटे खिलाड़ी' की तरह सिमट जाने का खतरा है। इस स्थिति को भारत कभी गवारा नहीं करता।

देश के भीतर कई विदेश मामलों के जानकार मानते हैं कि भारत ने यह जो नया रास्ता पकड़ा है, वह वास्तव में गुटनिरपेक्ष और मुद्दा-आधारित परंपरा से भटकाव है। यह विरोधाभास प्रधानमंत्री की हालिया चीन यात्रा में साफ दिखाई दिया। सात साल बाद मोदी की चीन यात्रा एक अहम पड़ाव रही। मोदी और शी ने सहमति जताई कि मतभेदों को विवादों में नहीं बदलने दिया जाएगा और आपसी भरोसा, सम्मान और संवेदनशीलता भविष्य के रिश्तों की नींव होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा पर शांति को द्विपक्षीय रिश्तों की 'बीमा पॉलिसी' बताया। दोनों पक्षों ने हालिया डिसइंगेजमेंट और स्थिर माहौल को सकारात्मक कदम के रूप में रेखांकित किया। रिश्तों में आई नरमी से जो ठोस कदम उठते दिखे उनमें शामिल रहेः लिपुलेख, शिपकी ला और नाथू ला दर्रों से सीमा व्यापार का पुनःआरंभ। दोनों नेताओं ने कहा कि उनकी अर्थव्यवस्थाएं वैश्विक व्यापार में स्थिरता की भूमिका निभाती हैं। व्यापार असंतुलन दूर करने के लिए रणनीतिक दृष्टि से सहयोग बढ़ाने का वादा किया गया। मोदी ने शी को 2026 में भारत में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया। अच्छी बात है कि प्रधानमंत्री मोदी ने सीमा-पार आतंकवाद का मुद्दा उठाया और सहयोग की जरूरत पर जोर दिया। यह भी दोहराया कि भारत-चीन संबंधों को किसी तीसरे देश के चश्मे से नहीं देखा जाना चाहिए। उन्होंने रणनीतिक स्वायत्तता और बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की वकालत की।

विपक्षी दलों की प्रतिक्रिया तीखी रही। जयराम रमेश ने मोदी पर 'ड्रैगन के आगे झुकने' और आतंकवाद पर दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया। अमेरिका में व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने मोदी की आलोचना करते हुए कहा 'वे दो सबसे बड़े अधिनायकवादी नेताओं' के साथ निकटता बना रहे हैं। कई विश्लेषकों ने एससीओ की सैन्य परेड में मोदी की उपस्थिति को कूटनीतिक सफलता नहीं, बल्कि छवि की समस्या माना-जैसे भारत पश्चिमी लोकतांत्रिक खेमे से दूर हो रहा हो। यात्रा में सद्भावना दिखी, लेकिन कोई ठोस बाध्यकारी समझौते नहीं हुए। मोदी, शी और पुतिन की साझा तस्वीरों को कई लोगों ने वास्तविक उपलब्धि की बजाय केवल संदेश देने वाला प्रतीकवाद माना।

एक ओर चीन से एससीओ और व्यापार के जरिए जुड़ना और दूसरी ओर अमेरिका-झुकाव वाले क्वाड और ब्रिक्स में सक्रिय रहना-आलोचकों को असंगत लगता है। चीन के साथ गहरी प्रतिद्वंद्विता भारत की इस रणनीति पर हमेशा सवाल उठाती है। इस चीन यात्रा का स्वागत करने वालों का मानना है कि मोदी की चीन यात्रा ने एक बार फिर दिखा दिया कि भारत अपने पड़ोसी के साथ संबंधों में शांति और स्थिरता चाहता है, खासकर सीमा और व्यापार के मोर्चे पर। यात्रा से कुछ व्यावहारिक लाभ मिले लेकिन ठोस समझौतों की कमी और घरेलू और अंतरराष्ट्रीय आलोचना ने कूटनीतिक सफलता को सीमित कर दिया। असली सवाल है कि क्या भारत इस बहुस्तरीय कूटनीति को ठोस रणनीति में बदल पाएगा या यह अमेरिकी टैरिफ दबाव से मुक्त होने की प्रतीकात्मक बयानबाजी और पैंतरेबाजी तक सिमट कर रह जाएगी!

(लेख में व्यक्त विचार निजी हैं)

> निःसंदेह प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से चीन के साथ रिश्तों की बर्फ पिघली है। दोनों देशों के बीच इस निकटता से कुछ क्षेत्रों में सहयोग के भी संकेत मिले हैं। सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने, वीजा नियम आसान करने और कुछ निर्यात पाबंदियां हटाने का वादा किया गया है। अमेरिका के भारी टैक्सों के दबाव में फंसे भारत के लिए ये कदम थोड़ी राहत लेकर जरूर आए। लेकिन असली समस्या वहीं की वहीं खड़ी दिखती है-चीन लगातार पाकिस्तान का समर्थन करता है

- तुलसी की कई किस्में होती हैं। भारत में चार पवित्र तुलसी की किस्में पाई जाती हैं-राम, श्याम, कपूर और वन। राम तुलसी अपनी अनूठी सुगंध और औषधीय गुणों के लिए जानी जाती हैं। दक्षिण-पूर्व एशिया की 'देवना' या थाई तुलसी भी अपने स्वाद और औषधीय महत्त्व के लिए लोकप्रिय है
- हरी पत्तियों और मीठी सुगंध वाली राम तुलसी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है। कृष्ण तुलसी, जिसे श्यामा तुलसी भी कहते हैं, बैंगनी पत्तों और तीव्र सुगंध वाली यह तुलसी गले के संक्रमण, त्वचा रोगों और सूजन के इलाज में प्रभावी है
- हिमालयी क्षेत्र में पाई जाने वाली वन तुलसी को जंगली तुलसी भी कहते हैं, जो एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती है। कपूर तुलसी की सुगंध प्राकृतिक मच्छर भगाने का काम करती है

(मीडिया इनपुट्स)

बेचारे उमर खालिद की एक के बाद एक जमानत नामंजूर हो रही है, और उन्हें जेल में सड़ना पड़ रहा है जबकि आरफा खानम शेरवानी पटना में मेहमानवाजी की दावत उड़ा रही हैं, राणा अय्यूब छुट्टियों का लुत्फ उठा रही हैं, और स्वरा भास्कर फिलिस्तीनियों के लिए आंसू गिराने का कोई भी मौका नहीं चूकतीं।

पूर्व जस्टिस मार्कंडेय काटजू
@mkatju

मुस्लिम सियासी दल और मुसलमान

मुद्दा | डॉ. असद रजा

लोकतंत्र में हर नागरिक को वोट देने तथा चुनाव लड़ने और अपनी पार्टी बनाने का अधिकार है। विभिन्न समुदायों, जातियों, जनजातियों, प्रदेशों और धर्मावलंबियों ने अपने-अपने दल बना रखे हैं, जो चुनाव लड़ते हैं। मुस्लिम यद्यपि भारत में अल्पसंख्यक हैं परंतु उनके भी बहुत से राजनीतिक दल हैं-इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तहादुल मुस्लमीन, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट, मुस्लिम मजलिस, पीस पार्टी और उल्मा कौंसिल तथा धर्मनिरपेक्ष मोर्चा आदि आदि।

इन मुस्लिम दलों और सेक्युलर पार्टियों के कारण मुस्लिम वोट लोक सभा, विधानसभा और स्थानीय निकायों आदि के इलेक्शन में दलितों और पिछड़ों के वोटों की भांति विभाजित होकर निष्प्रभावी भी हो जाता है। मुस्लिम दलों के कारण ही संघ परिवार को बहुसंख्यकों को हिन्दू-मुस्लिम के नाम पर एकजुट करने का अवसर मिल जाता है। तथ्य है कि केरल, असम और बिहार के अपवाद के साथ अधिकांश मुस्लिम मतदाता मुस्लिम राजनीतिक दलों को नहीं, बल्कि सेक्युलर दलों यथा समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और टीएमसी आदि को ही वोट देते हैं। यह भी कटु सत्य है कि उत्तर प्रदेश, असम और बिहार में एनडीए की सरकारें हैं, तो उसका प्रमुख कारण मुस्लिम दल भी हैं। इत्तहादुल मुस्लमीन के अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं के उत्तेजक नारों से भी भारतीय मुसलमानों का अहित होता है क्योंकि अकबर के तो नारे ही रहते हैं परंतु संघ परिवार के नारे अमली रूप धारण कर निरीह मुसलमानों को हानि पहुंचाते हैं। यही कारण है कि अधिकांश मुस्लिम मतदाता मुस्लिम दलों को कम वोट देते हैं, और सेक्युलर पार्टियों को ही पसंद करते हैं परंतु सत्य यह भी है कि कुछ अत्यधिक धर्मभीरु और भावुक मुस्लिम उत्तर प्रदेश और बिहार में बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी को वोट देते हैं। परिणामतः उत्तर प्रदेश में अनेक विधानसभा सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार को मिलते तो दो चार हजार वोट ही हैं परंतु वे हिन्दू भाइयों को विशेष रूप से सवर्ण जातियों को भाजपा के पक्ष में लामबंद कर देते हैं, और सपा के उम्मीदवार अनेक सीटों पर भजपा के उम्मीदवार से हजार दो हजार मतों से हार जाते हैं, और योगी जी फिर से मुख्यमंत्री बन जाते हैं। फिर कोई ओवैसी प्रताड़ित मुसलमानों को बचाने नहीं आता, बस

मौखिक निंदा करके बैठ जाते हैं। इस स्थिति के लिए सपा और कांग्रेस जैसी सेक्युलर पार्टियों के नेता भी कुछ हद तक जिम्मेदार होते हैं क्योंकि वे ओवैसी को कम करके आंकते हैं। यदि 'इंडिया' गठबंधन कुछ सीटें बिहार और उत्तर प्रदेश में मजलिस को दे देते तो कदाचित आज इन दोनों बड़े प्रदेशों में एनडीए की सरकारें नहीं होतीं। 'इंडिया' गठबंधन को आशंका है कि ओवैसी को साथ लेने से हिन्दू वोट खिसक सकता है परंतु यदि कांग्रेस केरल में मुस्लिम लीग और असम में मौलाना बदरुद्दीन अजमल के साथ चुनावी गठजोड़ कर सकती है, तो ओवैसी तो मौलाना के मुकाबले अच्छे वक्ता हैं। अतः उनके साथ भी चुनावी गठबंधन किया जा सकता है। यद्यपि मैं भी मुस्लिम दलों द्वारा डेढ़ ईंट की मस्जिद बनाने के विरुद्ध हूं परंतु यदि बिहार विधानसभा से पूर्व कुछ सीटें महागठबंधन मजलिस को दे दे तो निश्चय ही 'इंडिया' को लाभ होगा तथा बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। इसके अतिरिक्त मैं ओवैसी को यह सलाह देना चाहूंगा कि वह आज भारत में बढ़ती सांप्रदायिकता और हिन्दू मुस्लिम वोटों के चुनाव के दौरान ध्रुवी करण को रोकने के लिए अपनी पार्टी के नाम में से मुस्लमीन शब्द हटा कर मुहिब्बान वतन (वतन प्रेमी) लगा दें तो बेहतर होगा और मुस्लिम दुश्मन सरकारों से देश को मुक्ति मिल जाएगी। तब महागठबंधन को भी मजलिस को अपने साथ रखने में कोई आपत्ति नहीं होगी।

यहां यह जिक्र करना भी उचित होगा कि बिहार में वोट अधिकार यात्रा के दौरान मधुबनी में मजलिस के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी, तेजस्वी यादव और दीपांकर भट्टाचार्य के निकट पहुंच कर पोस्टर-बैनर के साथ नारेबाजी की और मांग की कि 'मजलिस को महागठबंधन में शामिल किया जाए अन्यथा हम 'इंडिया' गठबंधन के विरुद्ध अपने उम्मीदवार खड़े करके उसे हरा देंगे। स्पष्ट है कि महागठबंधन धमकियों में तो नहीं आएगा परंतु इसके नेताओं को ऊंच-नीच देख कर निर्णय करना चाहिए। यहां यह जिक्र करना भी उचित होगा कि बिहार के 2020 में विधानसभा चुनाव में मजलिस ने 20 उम्मीदवार खड़े किए थे जिनमें से पांच जीत गए थे और मजलिस को 1.24 प्रतिशत वोट मिले थे तथा 'इंडिया' गठबंधन की बिहार में सरकार न बनने का प्रमुख कारण मजलिस के उम्मीदवार थे। अतः भाजपा भी कोशिश करेगी कि मजलिस अकेले चुनाव लड़ कर मुस्लिम वोट को विभाजित कर भाजपा सरकार बनने में अप्रत्यक्ष रूप से मदद करे। इसलिए बिहार के मुस्लिम मतदाताओं, मजलिस और महागठबंधन के नेताओं को गंभीरतापूर्वक इस बारे में निर्णय लेना होगा।

(लेख में विचार निजी हैं)

अध्यात्म प्रेम | संत राजिन्दर

कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमात्मा के साथ अपना नाता और अपने उद्देश्य का रास्ता खोज रहे हैं। जो लोग परमात्मा को खोज रहे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग भी हैं, जो बहुत उत्साह के साथ खोज रहे हैं। कुछ ऐसे भी हैं, जो बड़े जुनून और बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं, लेकिन उनकी रुचि कम हो जाती है, और वे अपने लक्ष्य को हासिल करने में असफल होते हैं। अगर हमें इस जीवन में अपने आध्यात्मिक सफर को पूरा करना है, तो हमें इस लक्ष्य से दूर नहीं होना चाहिए। इस मानव जन्म का लक्ष्य हमारी आत्मा का परमात्मा से पुनर्मिलन की तड़प को पूरा करना है। अध्यात्म प्रेम का एक मार्ग है, और हमें हमारे वास्तविक स्वरूप से जोड़ता है। जब हम आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हैं, तो अपनी वास्तविक पहचान जरूरी है। क्या हम आध्यात्मिक अनुभव की खोज में भौतिक शरीर हैं, या हम आध्यात्मिक प्राणी हैं, जिसमें भौतिक स्तर पर अनुभव कर रहे हैं? इसी में परमात्मा को पाने का रहस्य छुपा है। हम सब आत्माएं हैं। जैसे हमें यह मनुष्य जन्म मिला है, इसी रूप में ही वास्तव में स्वयं को जानने की सभी सुविधाएं भी मौजूद हैं। यह आत्मा को परमात्मा के प्रेम का अनुभव करने और परमात्मा के पास वापस जाकर अपनी लंबी यात्रा को पूरा करने का मौका है। अभी हम सब इंद्रियों के स्तर पर जी रहे हैं, और सिर्फ वही अनुभव कर रहे हैं, जो जड़ पदार्थ से बना है। प्रभु, जो चेतना के महासागर हैं, के प्रेम का अनुभव करने के लिए हमें आध्यात्मिक रूप से चेतन अवस्था में रहने और अपने सच्चे स्वरूप के प्रति जागृत होने की आवश्यकता है। आत्मा और परमात्मा को खोजने के लिए हमें हमारी खोज पर ही ध्यान देना चाहिए और किसी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम परमात्मा से संवाद करते हैं, तब हमें किसी और चीज की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। हमें परमात्मा को पाने के नशे में मस्ती की गहराई में डुबकी लगा कर ऊपर के मंडल में उड़ान भरनी है। ध्यान-अभ्यास में एकाग्र चित्त होकर बैठना चाहिए। हमें ध्यान-अभ्यास के दौरान किसी और चीज को बीच में नहीं आने देना चाहिए।

रीडर्स मेल

आतंकवाद पर दोहरापन नहीं चलेगा

आतंकवाद के खिलाफ शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) ने अभी तक का सबसे बड़ा बयान देते हुए कहा है कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड अस्वीकार्य है। इसी सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि आतंकवाद के मुद्दे पर भारत कोई भी दोहरा रवैया कतई सहन करने नहीं जा रहा है। पहलगाम हमला भारत पर ही नहीं, बल्कि मानवता में विश्वास करने वाले हर देश, व्यक्ति के लिए खुली चुनौती था। आज कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुला समर्थन हमें कतई बर्दाश्त नहीं है। इस घोषणापत्र में दोहरे मापदंडों को खारिज करते हुए आतंकवाद के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय सहयोग और सीमा पार आतंकियों की आवाजाही पर रोक लगाने की भी मांग की गई। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि भारत पिछले चार दशकों से निर्मम आतंकवाद का दंश झेल रहा है। अतः हमें मिल कर आतंकवाद का हर रंग में, हर रूप में कड़ा विरोध करना होगा। कह सकते हैं कि शंघाई सहयोग संगठन द्वारा पहलगाम आंतकवाद की निंदा करना भारत की एक कूटनीतिक जीत है।

मनमोहन राजावत 'राज', शाजापुर, मप्र

जीएसटी में राहत स्वागतयोग्य

केंद्र सरकार ने कुछ खाद्य पदार्थों जैसे पनीर, रोटी, चपाती, छेना, टेट्रा पैक आदि को करमुक्त कर लोगों को राहत दी है। महंगाई ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ा हुआ था। दैनिक प्रयोग की कुछ खाद्य वस्तुओं और कपड़े पर कर की स्लैब कम करना आम आदमी के लिए बड़ी खुशखबरी है। दुर्लभ बीमारियों और कैंसर की दवाएं भी टैक्स फ्री करने से लोगों की जेब पर अब बोझ कम होगा। व्यक्तिगत स्वास्थ्य बीमा और जीवन बीमा पॉलिसियों को करमुक्त करने से ज्यादा लोग इन्हें लेंगे और स्वास्थ्य क्षेत्र में मजबूती आएगी। हानिकारक वस्तुओं पर 40 फीसद का अतिरिक्त स्लैब लगाना स्वास्थ्य की दृष्टि से सही है। कुल मिला कर सरकार ने लोगों को महंगाई से कुछ राहत देने की कोशिश की है।

अभिलाषा गुप्ता, मोहाली, पंजाब

जीवन में गुरु का बड़ा महत्त्व

शिक्षा अमृत की एक ऐसी बूंद है, जिसके बगैर जीवन की परिकल्पना अपूर्ण है। इसी परिपथ पर जीवन के निर्माण में शिक्षक अपनी भूमिका पथिक के रूप में निभाता है, जिस पथ पर शिष्य चल कर अपने जीवन को संभाल सकता है। शिक्षक के बारे में कहा गया है कि 'असतो मा ज्योतिर्गमय' जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में गुरु का बड़ा महत्त्व होता है जो ताले की चाबी की तरह है। हम सभी को अपने गुरुजनों का सम्मान करना चाहिए। उनके बताए गए रास्ते पर चलना चाहिए। गुरु को अपने शिष्य, मां को अपने बेटे, किसान को ललहाते खेत देख कर जो आनंद आता है, शायद ही इस पृथ्वी पर इससे बड़ा आनंद होता होगा। गुरु की महिमा अपरंपार है। इस समय होता था। ऋग्वैदिक काल में जब शिष्य-गुरु के आश्रम में रह कर शिक्षा ग्रहण करते थे। आज डिजिटलाइजेशन के दौर में शिक्षक हमारे टेलीग्राम, पीएफ, वीडियो में कहीं दूर से शिक्षित कर रहे होते हैं। जो हमारे लिए अनमोल है, हमें उनका सम्मान एवं उनके प्रति आदर रखना चाहिए।

तारामुनी देवी, वैशाली, बिहार
letter.editorsahara@gmail.com

हमें गर्व है हम भारतीय हैं

https://t.me/AllNewsPaperPaid

राष्ट्रीय सहारा • राष्ट्रीयता • कर्तव्य • समर्पण
वर्ष-35, अंक 23
सहारा इण्डिया मास कम्युनिकेशन के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक जिया कादरी द्वारा सहारा इंडिया मास कम्युनिकेशन प्रेस, सी-2,3, 4 सेक्टर-11, नोएडा में मुद्रित तथा तथा 1209-1210, बारहवां तल, नवरंग हाउस, 21 के.जी. मार्ग नई दिल्ली से प्रकाशित। । स्थानीय संपादक - रत्नेश मिश्र* ।
दूरभाष - दिल्ली कार्यालय - 011-23352369, 011-23352372, दूरभाष - नोएडा प्रेस 0120-2444755, 2444756 फैक्स - 2550750
आर.एन.आई. सं. 53469/91, पंजीकरण संख्या UP/BR /GZB- 38/2024-2026
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन तथा कानूनी मामलों के लिए उत्तरदायी

ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत्
भगवान इस जग के कण-कण में विद्यमान हैं।

आदित्य नारायण चोपड़ा
adityachopra@punjabkesari.com

भारत की शिक्षा व्यवस्था !

स्वतन्त्र भारत में शिक्षा व्यवस्था को लेकर समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं। इन संशोधनों में सबसे बड़ा परिवर्तन 1991 में अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के बाद आया जब शिक्षा पूरी तरह बाजार से बंध गई, खासकर उच्च शिक्षा प्रणाली। अर्थव्यवस्था के बाजार मूलक होने का असर शिक्षा प्रणाली पर इस प्रकार पड़ा कि हमारे विद्यालय से लेकर विश्वविद्यालय तक शिक्षा की दुकानों के रूप में विकसित होने लगे। इसका सबसे बुरा असर समाज के गरीब वर्गों पर पड़ा क्योंकि महंगी होती शिक्षा का भार वहन कर पाने में यह वर्ग पूरी तरह असमर्थ साबित हुआ। शिक्षा को 'महादान' समझने वाली भारतीय संस्कृति में धन का प्रभाव जब आया तो शिक्षा मन्दिरों का स्वरूप शिक्षा की दुकानों में तब्दील होने लगा। आजादी मिलने के बाद हमने जो शिक्षा व्यवस्था खड़ी की थी उसमें राज्य या सत्ता की भागीदारी प्रमुख थी। आर्थिक उदारीकरण ने इस क्रम को इस प्रकार पलटा कि शिक्षा का क्षेत्र अच्छा मुनाफा कमाने वाला उद्योग बनता चला गया।

भारतीय संस्कृति में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों को पुण्य कमाने वाला क्षेत्र माना जाता था जिसमें गरीब लोगों को इसे पाने में समाज के धनी वर्गों की बड़ी भागीदारी होती थी जिसे खैरात के रूप में दिया जाता था। परन्तु आर्थिक उदारीकरण ने इस विचार को पूरी तरह उल्टा घुमा दिया और शिक्षा का मोल-तोल होने लगा। राज्य लोगों को शिक्षित करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हुआ परन्तु इसके बावजूद 2009 में मनमोहन सरकार के दौरान तत्कालीन शिक्षामन्त्री श्री कपिल सिब्बल 'शिक्षा का अधिकार' लेकर आये और 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को शिक्षित करने की जिम्मेदारी राज्य पर डाली गई। इससे सरकारी क्षेत्र के स्कूलों पर भार पड़ा मगर इन स्कूलों की हालत देखकर आम गरीब वर्ग भी अपने बच्चों को निजी स्कूलों में पढ़ाने की तरफ लालायित हुआ। आर्थिक उदारीकरण के दौरान शिक्षा के निजीकरण का कुप्रभाव सबसे ज्यादा शिक्षक व विद्यार्थी के रिश्ते पर पड़ा। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था ने विद्यार्थी को एक उपभोक्ता तक बना डाला और शिक्षक को अच्छी तनख्वाह पर काम करने वाला व्यक्ति। स्कूलों की गुणवत्ता इसी आधार पर तय होने लगी जिसकी वजह से गरीब तबके के लोगों की मुसीबतें और बढ़ती चली गईं। यह मुसीबत तब और बढ़ी जब शिक्षकों का ध्यान अधिक से अधिक धनोपार्जन पर केन्द्रित होने लगा। जिस भारत में शिक्षक को देवता की संज्ञा दी जाती थी उसी भारत में शिक्षक का रुतबा एक वेतनभोगी कर्मचारी का बनता चला गया। मगर निजीकरण की वजह से सबसे ज्यादा दीन-हीन भी शिक्षक ही बना और निजी विद्यालय उसका शोषण तक करने से बाज नहीं आये। इसका रास्ता शिक्षकों ने प्राइवेट ट्यूशन के रूप में निकाला। जिस देश के निजी विद्यालयों में शिक्षक का वेतन देते समय दोहरा मापदंड अपनाया जाता हो उस देश की शिक्षा का स्तर कभी ऊपर नहीं उठ सकता। निजी विद्यालय शिक्षकों से ऊंचे वेतनमान पर दस्तखत कराकर उनके हाथ में एक चपरासी से भी कम वेतन की रकम पकड़ा देते हों वहां कभी भी शिक्षक व विद्यार्थी के बीच रिश्ते मीठे नहीं हो सकते।

> **आर्थिक उदारीकरण के दौरान शिक्षा के निजीकरण का कुप्रभाव सबसे ज्यादा शिक्षक व विद्यार्थी के रिश्ते पर पड़ा। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था ने विद्यार्थी को एक उपभोक्ता तक बना डाला और शिक्षक को अच्छी तनख्वाह पर काम करने वाला व्यक्ति। स्कूलों की गुणवत्ता इसी आधार पर तय होने लगी जिसकी वजह से गरीब तबके के लोगों की मुसीबतें और बढ़ती चली गईं। यह मुसीबत तब और बढ़ी जब शिक्षकों का ध्यान अधिक से अधिक धनोपार्जन पर केन्द्रित होने लगा। जिस भारत में शिक्षक को देवता की संज्ञा दी जाती थी उसी भारत में शिक्षक का रुतबा एक वेतनभोगी कर्मचारी का बनता चला गया।**

हमने शिक्षा का निजीकरण करने में पश्चिमी देशों की नकल तो की परन्तु हम उन्हीं देशों की इस परंपरा को भूल गये कि इन देशों में से अधिसंख्य में दसवीं तक की शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी को मुफ्त दी जाती है और यह राज्य की जिम्मेदारी होती है। इसके साथ ही इन देशों के महानगरों से लेकर गांवों तक में हर विद्यार्थी को अपने पड़ोस के स्कूल में दाखिला दिया जाता है। भारत में शिक्षा को राज्यों की सूची में रखा गया है जबकि उच्च शिक्षा समवर्ती सूची में है। राज्य स्तर पर हर राज्य में हमें शिक्षा का स्तर अलग नजर आता है जिसकी वजह से उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कई राज्यों के विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। उनकी प्रतिभा का इससे क्षरण होता है। जबकि भारत एक ऐसा राज्यों का संघ देश है जिसके हर प्रदेश के नागरिक को एक समान अधिकार मिले हुए हैं। इसके लिए जरूरी है कि हर राज्य का शिक्षा स्तर एक समान हो जिससे गरीब वर्ग के लोगों के बच्चों की प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सके।

समाजवादी चिन्तक डॉ. राम मनोहर लोहिया भारत में शिक्षा के स्तर व इसमें गरीबों की भागीदारी को लेकर बहुत चिन्तित रहते थे। उनका मानना था कि पैसे की कमी की वजह से गरीब-पिछड़े वर्ग के विद्यार्थी जीवन की दौड़ में भी बहुत पीछे रह जाते हैं जिसका परिणाम यह होता है कि चपरासी का बेटा चपरासी बनता है और अफसर का बेटा अफसर। स्वतन्त्र होने पर हम लक्ष्य लेकर चले थे कि गरीब चपरासी का बेटा भी शिक्षा पाकर अफसर बने। यह तभी होगा जब चपरासी और अफसर के बेटे की शिक्षा एक समान होगी क्योंकि समान अवसर मिलने पर ही विद्यार्थी की प्रतिभा का सही मूल्यांकन हो सकता है। इसके बिना यह कैसे संभव है कि किसी किसान का बेटा वैज्ञानिक बन सके। अत: पूरे भारत में शिक्षा की एकरूपता बहुत जरूरी है मगर इसका मतलब यह नहीं कि प्रदेश स्तर पर छात्र अपनी क्षेत्रीय संस्कृति से अनभिज्ञ रह जाएं। क्षेत्रीय परिस्थितियों को शिक्षा में समायोजित करने हेतु ही भारत के संविधान में शिक्षा को राज्य सूची में रखा गया था। अत: बहुत स्पष्ट है कि पूरे भारत के हर स्कूल में शिक्षा का एक स्तर बनाये रखने हेतु राज्य ही कारगर कदम उठाये। मगर हर वर्ष 5 सितम्बर आता है और इस दिन को हम शिक्षक दिवस के रूप में मना कर अपने कर्त्तव्य की इतिश्री समझ लेते हैं। यह भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस होता है, जो कि एक महान दार्शनिक थे। डॉ. राधाकृष्णन आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते भी थे। अत: उनके जन्म दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाना शिक्षकों का सम्मान करने जैसा है। मगर हम उस प्राइमरी स्कूल के अध्यापक का क्या करेंगे जो पूरी नई पीढ़ियां तैयार करता है। हम उस शिक्षक को कितना वेतन देते हैं जबकि उसका कार्य सबसे कठिन होता है। डॉ. लोहिया के विचार से किसी कालेज प्रोफेसर और प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक के वेतन में ज्यादा अन्तर नहीं होना चाहिए। शिक्षक का व्यवसाय पकड़ने वाले व्यक्ति का समाज में सम्मान किसी गांव के प्रमुख या शहर के निगम सदस्य से कम नहीं होना चाहिए और इसी के अनुरूप उसका वेतन भी तय होना चाहिए।

पर आपके इस अनूठे मिशन...

सफ़ीना हुसैन सभी भारतीयों को तुम पर नाज है,
''एजुकेट फार गर्ल्स'' इस संगठन ने विश्व में बुलंद की बेटियों की आवाज है,
माना कि 'रैमन मैगसेसे पुरस्कार' एशिया का सबसे बड़ा खिताब है,
पर आपके इस अनूठे मिशन के लिए भविष्य में भी असंख्य-
उपलब्धियों का होगा आपके मस्तक पर ताज है...!!

गीता पाढा

धर्मान्तरण पर रोक लिए सबसे सख्त कानून

राकेश कपूर
संसद से सड़क तक

यह ऐतिहासिक तथ्य है कि भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर पूरे दक्षिण एशिया व मध्य एशिया में ईसा से 300 वर्षों पूर्व तक बौद्ध धर्म का बोलबाला था। सम्राट अशोक का शासन पाटिलीपुत्र से लेकर ईरान तक था और कई मध्य एशियाई (सेंट्रल एशिया) देशों जैसे कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान आदि में बैद्ध धर्म का बोलबाला था। सातवीं सदी में इस्लाम के उदय के बाद इन सभी देशों में इस्लाम फैला और बाद में ये इस्लामी राष्ट्र होते चले गये। जहां तक दक्षिण एशियाई देशों का सवाल है तो थाईलैंड, इंडोनेशिया व मलेशिया से लेकर लाओस, कम्बोडिया व वीयतनाम तक में बौद्ध धर्म का प्रभाव आज भी देखा जा सकता है। भारतीय उपमहाद्वीप के सन्दर्भ में श्रीलंका से लेकर म्यामांर तक बौद्ध धर्म आज भी प्रभावी माना जाता है। मगर अफगानिस्तान में यह पूरी तरह समाप्त हो चुका है। ऐसा ही हाल ईरान आदि देश का भी है। ईरान के सन्दर्भ में यहां बौद्ध संस्कृति के बाद पारसी संस्कृति ने पैर फैलाये मगर इसकी तब्दीली बाद की सदियों में इस्लाम में हो गई।

भारत में धर्म परिवर्तन 712 ई. के बाद सिन्ध में अरब से मुहम्मद बिन कासिम के आने के बाद हुआ। तब सिन्ध के हिन्दू राजा दाहिर को कासिम ने परास्त किया और अफगानिस्तान समेत अन्य इलाकों में इस्लाम धर्म फैला। बौद्धों को मुसलमान बनाना बहुत आसान था क्योंकि यह धर्म पूरी तरह अहिंसा व प्रेम पर टिका हुआ है। साथ ही इसमें मठ संस्कृति के चलते धर्म गुरुओं को समाप्त करने के बाद शेष बौद्धों का धर्म परिवर्तन करना सरल था। इतिहासकार मानते हैं कि दक्षिण एशिया व मध्य एशिया में सर्वाधिक परिवर्तन बौद्धों का ही हुआ है। जबकि भारत में परिस्थितियां दूसरी थी। यहां हिन्दू धर्म फैला हुआ था और सम्राट अशोक ने कभी भी जबरन धर्म परिवर्तन नहीं किया। उसने बौद्ध धर्म का प्रचार-प्रसार पूरे शान्तिमय तरीके से किया। परन्तु आठवीं सदी के बाद भारत में जैसे-जैसे मुस्लिम आक्रान्ताओं के हमले बढ़ते गये वैसे-वैसे ही भारत में इस्लाम धर्म का प्रचार-प्रसार होता गया। 12वीं सदी में जब तैमूरलंग भारत आया तो उसने मेरठ के पास अपनी फौजों का डेरा डाला।

हिन्दू धर्म में जाति प्रथा होने की वजह से भी धर्म परिवर्तन को बढ़ावा मिला। इतिहास के अनुसार मेरठ और आसपास के शूद्र कहे जाने वाले हिन्दू लोगों ने तैमूर लंग से फरियाद की कि वह उन्हें भी वह अपने साथ दिल्ली ले चले क्योंकि दिल्ली और देशी शासक उनसे भारी भेदभाव करते हैं तथा उनका जबर्दस्त शोषण करते हैं। माना जाता है कि दिल्ली पर चढ़ाई करने के बाद जब तैमूर लंग वापस अफगानिस्तान व पंजाब की तरफ लौटा तो वह अपने साथ इन शूद्र कहे जाने वाले लोगों की बड़ी संख्या को भी ले गया और उसने इन्हें पेशावर व आसपास के इलाकों में बसाया तथा इन्हें मुसलमान बनाया। मगर आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं और आज के धर्मनिरपेक्ष भारत में धर्म परिवर्तन किसी भेदभाव की वजह से नहीं हो सकता।

हम जानते हैं कि स्वतन्त्र भारत में सबसे बड़ा धर्म परिवर्तन बाबा साहेब अम्बेडकर ने 1956 में किया जब उनके साथ लाखों अनुसूचित जाति के लोगों ने हिन्दू धर्म छोड़ कर बौद्ध धर्म अपनाया। बाबा साहेब ने धर्मपरिवर्तन तो किया परन्तु भारत की धरती पर ही पनपे बौद्ध धर्म में। इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत की धरती पर जितने भी धर्म उपजे उन सभी में करुणा व दया को प्रमुख माना गया है और इंसानियत को केन्द्र में रखा गया है। चाहे वह सिख धर्म हो या जैन धर्म। इन धर्मों की एक और खासियत है कि इनके सभी प्रतीक व श्रद्धा के केन्द्र वृहद भारतीय भू-भाग में ही हैं। मगर हम 21वीं सदी चलने के बाद भारत के विभिन्न राज्यों में धर्मान्तरण विरोधी कानून बना रहे हैं। इसकी वजह यह मानी जाती है कि कुछ लोगों का धर्म परिवर्तन लालच देकर कराया जाता है जिसकी वजह से उनकी निष्ठाएं भी बदल जाती हैं।

धर्म परिवर्तन करना भारतीय संविधान में वैध है मगर वह किसी लालच या खौफ में नहीं होना चाहिए बल्कि अपनी प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। अक्सर यह सुनने को मिल जाता है कि मुस्लिम समुदाय के युवा अपना नाम बदल कर हिन्दू कन्याओं को अपने प्रेम जाल मे फंसा लेते हैं और फिर शादी करके उनका धर्म परिवर्तन करा देते हैं। इसे भारत में लव जेहाद का नाम दिया गया। मगर धर्म परिवर्तन का यह एकमात्र कारण नहीं है। बहुत से हिन्दू दूसरी शादी करने के लिए भी अपना धर्म परिवर्तन कर लेते हैं और इस्लाम इसलिए कबूल करते हैं कि इसमें चार शादियां करने का विधान है। हालांकि भारत में जिन- जिन राज्यों में भी भाजपा की सरकारें हैं वहां धर्मान्तरण विरोधी कानून बन चुके हैं परन्तु राजस्थान ऐसा अकेला प्रदेश है जहां की भाजपा सरकार अपने द्वारा लाये गये पुराने कानून को नये कानून से बदल रही है।

राज्य विधानसभा में पिछले फरवरी महीने में भाजपा सरकार एक धर्मान्तरण विरोधी विधेयक लाई थी जिसे इस महीने नये विधेयक से बदल दिया गया है। नये विधेयक में बहुत कठोर नियम बनाये गये हैं जिससे कोई भी व्यक्ति केवल निजी नाजायज लाभ के लिए अपना धर्म परिवर्तन न कर सके। इस नये विधेयक को लाने की मंशा यह बताई जा रही है कि पिछले दिनों राज्य में बहुत से लोगों ने दबाव, लालच, झूठे प्रचार में आकर अपना धर्म बदला जिसे देखते हुए नया विधेयक जरूरी था। अब नये विधेयक में यह जिम्मेदारी धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति की होगी कि वह स्वयं को अपराध मुक्त साबित करे। विधेयक में कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति केवल शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन करता है तो उसके विवाह को गैरकानूनी घोषित कर दिया जायेगा। धर्म परिवर्तन यदि किसी दबाव या लालच में किया गया है तो यह अपराध संज्ञेय होगा और गैर जमानती होगा।

नये विधेयक में न केवल शादी के लिए धर्म परिवर्तन अपराध होगा बल्कि शादी के बहाने धर्म परिवर्तन करना भी गंभीर अपराध होगा। अगर किसी धर्म को किसी दूसरे धर्म से बेहतर बताये जाने के उद्देश्य से धर्मान्तरण होता है तो इसे भी अपराध की श्रेणी में डाल दिया गया है और हर अपराध की सजा बहुत कड़ी कर दी गई है। परन्तु यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रेरणा से अपने पुराने धर्म (घर वापसी) में वापस लौटता है तो उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। जाहिर है कि राजस्थान सरकार राज्य के जनजातीय लोगों को धर्म परिवर्तन करने से रोकने के लिए ऐसे उपाय कर रही है क्योंकि राज्य में अनुसूचित जनजातीय लोगों की बहुत बड़ी संख्या रहती है और ये लोग गरीब भी होते हैं। इनमें धर्म परिवर्तन करने में घाघ लोग सफल भी हो जाते हैं। लेकिन नये कानून में 50 लाख रुपए व आजन्म कैद तक के प्रावधान कर दिये गये हैं। ये प्रावधान अपराध को देख कर ही तय किये गये हैं। आगामी 9 सितम्बर को यह नया विधेयक विधानसभा में चर्चा के लिए आयेगा जिस पर विरोधी दलों की प्रतिक्रिया देखने लायक होगी। राज्य में मुख्य विरोधी दल कांग्रेस पार्टी ही है। नये कानून या विधेयक में अपराधी की सम्पत्ति जब्त कर लेने व उसे ढहा देने तक की व्यवस्था है। उम्मीद की जा रही है कि इस विधेयक की चर्चा देश के अन्य राज्यों में भी होगी।

'दिल्ली' का भाग्य निर्माता 'दिल्ली' है, बीजिंग या वाशिंगटन नहीं

अर्जुन चोपड़ा

इतिहास अक्सर राष्ट्रों को उनके द्वारा लड़ी गई लड़ाइयों के लिए नहीं, बल्कि उस संतुलन के लिए याद करता है जो उन्होंने दुनिया के संकट के समय बनाए रखा। आज, जब वैश्विक शक्ति के बड़े भू-आकृतियां बदल रही हैं, भारत ऊंचा उठ खड़ा हुआ है वह न तो वाशिंगटन के जागीरदार के रूप में, न ही बीजिंग के याचक के रूप में, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्थिर हाथों द्वारा निर्देशित एक संप्रभु शक्ति के रूप में उठ खड़ा हुआ है। तिआनजिन में, जब दुनिया देख रही थी, तब मोदी ने चीन के सामने घुटने नहीं टेके और न ही उन्होंने भारत को अमेरिका के खेमे में सिमटने दिया। उन्होंने भारत के लिए अपना रास्ता खुद बनाया और वह रणनीतिक स्वायत्तता का रास्ता। जहां कभी भारत को एक उपेक्षित विचार मानकर खारिज कर दिया जाता था, आज उसे सराहा जाता है, उससे परामर्श किया जाता है और उस पर बारीकी से नज़र रखी जाती है। बीजिंग इसे देखता है, वाशिंगटन इसे जानता है, और दुनिया इसे महसूस करती है।

ट्रेड के दृष्टिकोण से कोई भ्रम में न रहे लेकिन यह सच है कि भारत और चीन कभी भी स्वाभाविक व्यापारिक साझेदार नहीं हो सकते। उनके निर्यात इंजन आश्चर्यजनक रूप से समान तर्ज पर चलते हैं-कपड़ा, रसायन, इस्पात, निम्न-स्तरीय इलेक्ट्रॉनिक्स और इंजीनियरिंग सामान दोनों अर्थव्यवस्थाओं पर हावी हैं। क्योंकि उनका उत्पादन या मैन्युफैक्चरिंग एक जैसे हैं। जब दो देश दुनिया को मोटे तौर पर एक जैसे सामान बेचते हैं, तो पूरकता की गुंजाइश कम हो जाती है और प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है। भारतीय निर्यातकों के लिए, इन मोर्चों पर चीनी बाजारों में सेंध लगाने से नाटकीय लाभ नहीं होगा। फिर भी, इससे यह जुड़ाव निरर्थक नहीं हो जाता। ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत की ताकत चमक सकती है-फार्मास्युटिकल, आईटी-सक्षम सेवाएं, कृषि और यहां तक कि नवीकरणीय ऊर्जा घटक भी। ये क्षेत्र, चीनी विनिर्माण के पैमाने की तुलना में मामूली होने के बावजूद, प्रतीकात्मक और रणनीतिक महत्व रखते हैं।

प्रत्येक सफलता, चाहे कितनी भी छोटी क्यों न हो, इस बात का संकेत देती है कि भारत दुनिया के सबसे प्रतिस्पर्धी बाजारों में अपनी पकड़ बनाए रख सकता है। इसमें मोदी की कूटनीति का शांत तर्क निहित है। व्यापार के आंकड़ों में चीन को पछाड़ना नहीं, बल्कि ऐसे स्थान सुरक्षित करना है, जहां भारतीय उद्यम अपनी

पहचान बना सकें और झंडा गाड़ सकें लेकिन व्यापार इस जुड़ाव का केवल एक स्तर है। गहरी परीक्षा हिमालय की सीमाओं पर है, जहां लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में सैनिक पहरा दे रहे हैं। डोकलाम और गलवान की छाया सिर्फ़ हाथ मिलाने से नहीं मिट सकती। फिर भी मोदी की कूटनीति दर्शाती है कि संवाद और प्रतिरोध साथ-साथ चल सकते हैं। बीजिंग के साथ संवाद के रास्ते खुले रखकर, भारत अपनी सैन्य तैयारियों को मज़बूत करते हुए ग़लतफ़हमी के ख़तरे से बचता है। इस लिहाज़ से, संवाद कमज़ोरी नहीं, बल्कि समझदारी है। इससे समय मिलता है, तनाव कम होता है, और यह सुनिश्चित होता है कि भारत चीन से डर के साथ नहीं, बल्कि दृढ़ता के साथ बात करे और यहीं गहरा बदलाव निहित है।

अभी ज़्यादा समय नहीं बीता, जब वैश्विक शक्तियों की उदासीनता और अहंकार के कारण भारत की संप्रभुता को ख़तरा पैदा हुआ था। निक्सन के दौर में, वाशिंगटन ने खुले तौर पर पाकिस्तान की तरफ़ झुकाव दिखाया और 1971 में बंगलादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय चिंताओं को ख़ारिज कर दिया। उसके बाद के दशकों में, भारत को शीत युद्ध के दौरान तकनीकी इन्कार का सामना करना पड़ा, महत्वपूर्ण उपकरणों तक उसकी पहुंच सीमित रही, और वैश्विक रणनीति में उसे एक हाशिये के खिलाड़ी जैसा समझा गया। 1998 में, पोखरण-II के बाद, संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों ने भारत पर व्यापक प्रतिबंध लगा दिए थे।

नई दिल्ली को अपनी परमाणु संप्रभुता का दावा करने और चीन के प्रसार रिकॉर्ड और पाकिस्तान के गुप्त कार्यक्रमों पर आंखें मूंद लेने के लिए दंडित किया गया था। वर्षों तक, भारत को उपदेश दिए गए, अलग-थलग किया गया और उच्च मंच पर उसके उचित स्थान से वंचित रखा गया। अब वह युग चला गया है। मोदी ने सुनिश्चित किया है कि भारत अब अतीत की उपेक्षित, शक्ति नहीं रहा। आज, वाशिंगटन को दिल्ली के साथ एक समान स्तर पर जुड़ना चाहिए, न कि एक ग्राहक राज्य के रूप में। बीजिंग को यह स्वीकार करना होगा कि भारत को डरा-धमकाकर चुप नहीं कराया जा सकता और यूरोप से लेकर अफ्रीका और हिंद-प्रशांत तक, दुनिया हर परिषद और शिखर सम्मेलन में भारत की आवाज़ का महत्व महसूस करती है।

बहुत लंबे समय से, छोटे देशों को महाशक्तियों के प्रतिद्वंद्वी खेमों में धकेला जाता रहा है। भारत ऐसे बंधनों को अस्वीकार करता है। मोदी ने दिखाया है कि अमेरिका मित्र हो सकता है, लेकिन स्वामी कभी नहीं। वाशिंगटन के साथ संबंधों को गहरा करते हुए, बीजिंग के साथ संवाद स्थापित करते हुए, भारत यह घोषणा करता है कि उसका भाग्य दिल्ली में तय होगा, न कि दूरस्थ राजधानियों में। चीन के साथ पुनर्निर्धारण से लाभ मामूली हो सकते हैं-यहां टैरिफ बाधाओं में कमी, वहां बाज़ार का खुलना, लेकिन बड़ी जीत प्रतीकात्मकता में निहित है कि आज की तारीख में मोदी के नेतृत्व में भार ऐसा बन चुका है, जिसे अलग-थलग नहीं किया जा सकता, जिसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता, और जिसे मजबूर नहीं किया जा सकता। दुनिया को भारत को एक कनिष्ठ भागीदार के रूप में नहीं, बल्कि एशियाई सदी की एक प्रमुख शक्ति के रूप में देखना चाहिए। मोदी की यात्रा एक प्रणाम नहीं, बल्कि एक ध्वज थी-एक ध्वज जो यह घोषणा करता है कि भारत राष्ट्रों के बीच ऊंचा उठेगा, अपने दिशासूचक यंत्र से निर्देशित होगा, अपने चारों ओर उठने वाले तूफ़ानों से बेख़ौफ़।

भाजपा चुनावी मुद्दा तलाशने पर मजबूर

ताक-झांक
आर.आर. जैरथ

राहुल गांधी की बिहार में मतदाता अधिकार यात्रा ने भाजपा को राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनावी मुद्दा तलाशने पर मजबूर कर दिया है। राहुल गांधी द्वारा जुटाई गई भारी भीड़ और मतदाताओं, खासकर दलितों और मुसलमानों के बीच उनके 'वोट चोरी' नारे की गूंज से पार्टी कार्यकर्ता परेशान हैं। उनकी चिंता रणनीति में बदलाव से स्पष्ट है। वे अब घुसपैठ और अवैध प्रवास के ध्रुवीकरण के मुद्दों को कम करके आंक रहे हैं, जिन्हें 'एसआईआर' के ज़रिए उजागर करने की कोशिश की थी। इसके बजाय, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां के 'अपमान' को उजागर करके और इसके लिए गांधी को दोषी ठहराकर मतदाताओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल, यह अपमानजनक टिप्पणी गांधी की एक रैली में एक अज्ञात व्यक्ति ने की थी। उसने यह टिप्पणी गांधी के कार्यक्रम स्थल से जाने के बाद ही की थी, लेकिन भाजपा गांधी को ज़िम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही है।

भाजपा के अभियान का एक और पहलू, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर चुप्पी पर सवाल उठाकर गांधी और राजद नेता तेजस्वी यादव के बीच दरार पैदा करने की कोशिश करना है। जब राजद नेता ने खुद को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित किया, तब गांधी ने यादव के साथ अपनी संयुक्त रैली में कुछ नहीं कहा। हालांकि, बिहार में भाजपा कार्यकर्ता इस दोहरी रणनीति के कारगर होने को लेकर अनिश्चित हैं। वे निजी तौर पर स्वीकार करते हैं कि पार्टी को उम्मीद नहीं थी कि गांधी का वोट चोरी का नारा इस तरह लोकप्रिय होगा।

वे मानते हैं कि दलितों और मुसलमानों के बीच एक महत्वपूर्ण चुनाव से ठीक पहले एसआईआर का विचार एक बुरा विचार था, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं उन्हें मताधिकार से वंचित न कर दिया जाए। वोट चोरी उसी तरह से सामने आ रही है जैसे 2024 के लोकसभा चुनावों में आरक्षण के मुद्दे ने भाजपा के खिलाफ काम किया था, जब विपक्ष कोटा लाभार्थियों के बीच यह चिंता फैलाने में कामयाब रहा कि अगर मोदी सरकार 400 सीटों के साथ सत्ता में आई तो उनके अधिकार छीन लिए जाएंगे।

मोदी क्यों रहे चीन सैन्य परेड से दूर

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास चीन में शंघाई सहयोग संगठन के दो दिवसीय शिखर सम्मेलन के बाद हुई भव्य सैन्य परेड से दूर रहने के दो अच्छे कारण थे। पहला, यह परेड उस दिन के साथ मेल खाती है जिस दिन द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी हार के बाद जापानी सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया था। मोदी द्विपक्षीय संबंधों को मज़बूत करने के लिए शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में जाते हुए जापान गए थे। अगर वे उस परेड में शामिल होते जो उनके देश के लिए अपमान का दिन था, तो जापानियों को गलत संदेश जाता।

इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इस परेड का उद्देश्य उन्नत लड़ाकू विमानों और गैर-परमाणु हथियारों के प्रदर्शन के साथ चीन की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन करना था। इनमें से कुछ का इस्तेमाल पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था। अन्य हथियार निकट भविष्य में पाकिस्तान पहुंच सकते हैं, जो चीन की मदद से अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा रहा है। यह दृश्य भारतीय प्रधानमंत्री के लिए असहज होता, इसलिए उन्होंने समझदारी दिखाते हुए परेड से एक दिन पहले ही स्वदेश वापस लौट आए।

मोदी शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के किसी सदस्य देश के एकमात्र नेता थे जिन्होंने परेड में भाग नहीं लिया। हालांकि उनके चीनी मेज़बान शायद कारणों को समझते होंगे, लेकिन सोशल मीडिया उपयोगकर्ता इतने क्षमाशील नहीं थे। कुछ लोगों ने टिप्पणी की कि इस घटनाक्रम के मद्देनज़र चीन भारत से 'सच्चा दोस्त' होने की उम्मीद नहीं कर सकता। चीनी विदेश मामलों के विश्लेषकों ने भी ऐसी ही राय व्यक्त की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मनमाने टैरिफ लगाकर स्थापित वैश्विक ढांचे को ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे उभरती नई विश्व व्यवस्था में भारत को संतुलन बनाने की चुनौती का सामना करना पड़ेगा।

मोदी के शिष्टमंडल में जयशंकर क्यों नहीं

एससीओ शिखर सम्मेलन में मोदी के प्रतिनिधिमंडल से एक उल्लेखनीय अनुपस्थिति विदेश मंत्री एस. जयशंकर की रही। उनकी अनुपस्थिति का आधिकारिक कारण खराब स्वास्थ्य बताया गया। लेकिन भाजपा में कम ही लोग इस बात से सहमत हैं। विदेश मंत्री हमेशा प्रधानमंत्री के साथ विदेश यात्रा पर जाते हैं, यहां तक कि एससीओ शिखर सम्मेलन जैसी सुरक्षा बैठक के लिए भी। भाजपा के सूत्रों का कहना है कि उनकी अनुपस्थिति के दो संभावित कारण हैं। पहला यह कि जयशंकर अपने अमेरिका समर्थक विचारों के लिए व्यापक रूप से जाने जाते हैं। हो सकता है कि वह उस सम्मेलन में अनुपयुक्त रहे हों जिसका उद्देश्य अमेरिका को यह कड़ा संदेश देना था कि एक वैकल्पिक शक्ति समूह आकार ले रहा है।

जयशंकर हाल ही में अपने बेटे के रिलायंस द्वारा वित्त पोषित ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन से संबंधों को लेकर सोशल मीडिया पर उठे विवाद के केंद्र में रहे हैं, जिसे एक अमेरिका समर्थक थिंक टैंक माना जाता है। जयशंकर के बेटे ध्रुव वाशिंगटन डीसी में ओआरएफ के कार्यालय के प्रमुख हैं। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में डोभाल बेशक बेहद अहम रहे। याद रहे कि हाल ही में जब एनएसए बीजिंग गए थे, तो उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाक़ात का मौक़ा मिला था। किसी विदेशी मेहमान के लिए यह दुर्लभ है और यह दर्शाता है कि उन्होंने चीनियों के साथ कितना अच्छा तालमेल बिठाया है।

दिल्ली आर.एन.आई. नं. 40474/83
पंजाब केसरी
दिल्ली कार्यालय :
फोन आफिस: 011-30712200, 45212200,
प्रसार विभाग: 011-30712224
विज्ञापन विभाग: 011-30712229
सम्पादकीय विभाग: 011-30712292-93
मैगजीन विभाग: 011-30712330
फैक्स : 91-11-30712290, 30712384, 011-45212383, 84
Email: Editorial@punjabkesari.com

स्वत्वाधिकारी दैनिक समाचार लिमिटेड, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, नजदीक वजीरपुर डीटीसी डिपो, दिल्ली-110035 के लिए मुद्रक, प्रकाशक तथा सम्पादक अनिल शारदा द्वारा पंजाब केसरी प्रिंटिंग प्रैस, 2-प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से मुद्रित तथा 2, प्रिंटिंग प्रैस कॉम्पलैक्स, वजीरपुर, दिल्ली से प्रकाशित।

प्रवाह

77 साल बेमिसाल
निर्भीक पत्रकारिता का आठवां दशक
स्थापना : 18 अप्रैल 1948 • आगरा

दुनिया बदल रही है, आपको भी बदलना होगा। भले ही उसी तरह से नहीं, पर उसके समानांतर। -जेनेसिस पी-ऑरिज

मर्यादा की मिसाल

हाल ही में एक सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक तंज को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह से सहज आत्मीयता में बदल दिया, वह यही दिखाता है कि व्यक्ति का नजरिया चीजों को किस हद तक बदल सकता है। दरअसल, हुआ यों कि कुछ दिन पहले मैसूर में अखिल भारतीय वाणी एवं श्रवण संस्थान के एक समारोह में मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य से पहले राष्ट्रपति से पूछ लिया, 'क्या आप कन्नड़ जानती हैं?' इस पर राष्ट्रपति के सहज व विनम्र जवाब ने वहां उपस्थित श्रोताओं के दिल को तो छुआ ही, इसने बहुलता में एकता की उस भारतीय भावना को फिर से जीवंत कर दिया, जो हमारी सांविधानिक लोकतांत्रिक परंपरा की आत्मा है। उन्होंने यह कह कर कि-कन्नड़ बेशक मेरी मातृभाषा नहीं है, लेकिन यह कर्नाटक की भाषा है और मुझे देश की हर भाषा, संस्कृति व परंपरा से प्यार है-पूछे गए सवाल को तो बौना किया ही, हर चीज को राजनीतिक मोड़ देने या भाषाओं को राजनीतिक हथियार बनाने की प्रवृत्ति पर भी जोरदार, किंतु विनम्र प्रहार किया। उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि भाषा का उद्देश्य तोड़ना नहीं, जोड़ना होता है। हालांकि, सवाल के जवाब में वह भी पूछ सकती थीं कि क्या आपको आदिवासियों की भाषा आती है, लेकिन इसके बजाय उनका यह कहना कि-मैं धीरे-धीरे निश्चित ही कन्नड़ सीखने का प्रयास करूंगी-उनकी शालीनता को ही दिखाता है। यह सभी भारतीयों के लिए एक संदेश है कि उन्हें अपनी मातृभाषा पर गर्व करना चाहिए, साथ ही अन्य भाषाओं व बोलियों का भी सम्मान करना चाहिए। गौरतलब है कि ऐसे समय में, जब कर्नाटक में भाषा को लेकर बहस गरमाई हुई है, राष्ट्रपति मुर्मू का जवाब इस मायने में महत्वपूर्ण है कि उन्होंने सिद्धरमैया के सवाल को एक सकारात्मक व रचनात्मक दिशा दी, साथ ही यह भी दिखाया कि तंज कसने के बजाय एकता और सम्मान के साथ किसी भी मतभेद को सुलझाया जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू का जवाब यह भी दर्शाता है कि

किसी भाषा को न जानना उसकी संस्कृति से दूरी का पर्याय नहीं है। एक मुख्यमंत्री और राष्ट्रपति के बीच हुआ यह छोटा-सा संवाद हमें सिखाता है कि भाषाएं केवल संचार का माध्यम नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर और एकता की प्रतीक भी हैं। इसमें देश में व्याप्त विविधताओं पर चोट करने वाली बहसों के समाधान का सूत्र भी छिपा है।

टैरिफ के पीछे की वजहें ये तो नहीं

ट्रंप द्वारा भारत पर भारी-भरकम टैरिफ थोपने का कोई वाजिब कारण नहीं है, रूसी तेल तो बस बहाना है। विशेषज्ञ मानते हैं कि ट्रंप की नाराजगी की असली वजह मोदी द्वारा उन्हें कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप न करने देना, संघर्ष विराम का श्रेय न देना, उनसे मुलाकात रद्द करना और बुलावे पर व्हाइट हाउस न जाना है।

शेखर अय्यर
वरिष्ठ पत्रकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के शिखर सम्मेलन से इतर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। उनकी यह वार्ता अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ लगाने और रूस से तेल खरीदने के कारण भारत की आलोचना की पृष्ठभूमि में हुई। मोदी की शी के साथ वार्ता जहां भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी मुद्दों के समाधान की उम्मीद जगाती है, वहीं पुतिन के साथ बातचीत दर्शाती है कि भारत और रूस बेहतर साझेदार बने रहेंगे।

एससीओ शिखर सम्मेलन में सभी सदस्य देशों द्वारा पहलगाम आतंकी हमले की निंदा से भारत को महत्वपूर्ण कूटनीतिक कामयाबी मिली। मोदी, पुतिन और जिनपिंग के एकसाथ आने से ट्रंप की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है। उन्हें लग रहा होगा कि ये तीनों देश मिलकर उनकी रणनीति के खिलाफ जमीन तैयार कर रहे हैं। एक तरह से ट्रंप ने ही इन तीनों देशों को अपने संबंधों को फिर से सुधारने का मौका दिया है।

तियानजिन घोषणापत्र मोदी के दृढ़ संदेश 'आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मापदंड स्वीकार्य नहीं हैं' की भी अनुगूंज है। पहलगाम आतंकी हमले के पीड़ित परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताते हुए सदस्य देशों ने जोर देकर कहा कि इस तरह के कृत्य करने वाले अपराधियों, संगठनों और प्रायोजकों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ट्रंप द्वारा उत्पन्न उथल-पुथल की वजह से भारत ने अपने संबंधों को पुनः दिशा देने के लिए अहम कूटनीतिक प्रयास शुरू किए हैं। हमें नहीं भूलना चाहिए कि चीन से पहले मोदी जापान के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने के लिए टोक्यो गए थे।

मोदी-जिनपिंग वार्ता भारत-चीन संबंधों में महत्वपूर्ण क्षण था। 2020 में गलवान घाटी में हुए हिंसक संघर्ष के बाद चीनी धरती पर मोदी और जिनपिंग के बीच यह पहली आमने-सामने की बैठक थी। इस घटना के कारण दोनों देशों के रिश्ते ऐतिहासिक रूप से निचले स्तर पर पहुंच गए थे। इस पृष्ठभूमि में मोदी के दौरे को दोनों देशों के बीच नए कूटनीतिक अध्याय की शुरुआत के रूप में देखा गया है। क्या मोदी और शी संबंधों को सामान्य बना सकते हैं? विशेषज्ञ मानते हैं कि सीमा विवाद की छाया रातों-रात दूर नहीं होगी। हालांकि, वर्षों की चुप्पी के बाद हुई आमने-सामने की वार्ता विश्वास बढ़ाने का एक अवसर प्रदान करती है। विश्लेषक प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा की सफलताओं को तात्कालिक रूप से कम, लेकिन संवाद के रास्ते खोलने के रूप में ज्यादा देखते हैं।

यदि यूक्रेन-रूस युद्ध समाप्त हो जाता है, तो हालात बदल जाएंगे। इससे रूस और चीन भी ट्रंप के साथ फिर संपर्क में आ जाएंगे। इसी तरह, भारत ने भी अमेरिका के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं किए हैं। अमेरिका भी व्यापार संबंधी मुद्दों के धीरे-धीरे सुलझ जाने के बाद मोदी के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने की कोशिश करेगा।

दुनिया भर में चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने भारत पर भारी टैरिफ क्यों थोपा। टैरिफ लागू होने के बाद खुद अमेरिकी लोग चिंतित हैं कि भारतीय सामान ज्यादा महंगे हो जाएंगे। ट्रंप के सलाहकारों ने आग में घी डालने का काम किया है। उनके व्यापार सलाहकार पीटर नवारो ने तो रूस-यूक्रेन युद्ध को 'मोदी का युद्ध' तक कह दिया। उनके दूसरे करीबी सलाहकार अमेरिकी राष्ट्रीय आर्थिक परिषद के निदेशक केविन हेसेट ने भारत पर अमेरिकी उत्पादों के लिए अपने बाजार खोलने में 'अड़ियल' रवैया अपनाने का आरोप लगाया। निस्संदेह ट्रंप के पास भारत पर अतिरिक्त टैरिफ थोपने का कोई वाजिब कारण नहीं है। रूसी तेल की खरीद तो एक बहाना है। ट्रंप खुद स्वीकार चुके हैं कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार बेचकर मुनाफा कमा रहा है।

कुछ विशेषज्ञ मोदी और ट्रंप के बीच हुए मनमुटाव के चार मुख्य कारण गिनाते हैं। पहला कारण, जुलाई 2019 में पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान की अमेरिका यात्रा के दौरान ट्रंप ने उनसे कहा था कि मोदी ने उनसे कश्मीर मसले पर मध्यस्थता करने के लिए बोला है। ट्रंप की इस टिप्पणी पर मोदी ने नाराजगी जताई और व्हाइट हाउस को साफ कर दिया कि कश्मीर मसले पर भारत किसी तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप स्वीकार नहीं करेगा। दूसरा कारण, अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के दौरान मोदी ने दोनों उम्मीदवारों, डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस से मिलने का समय मांगा था। ट्रंप ने उन्हें समय दिया और अपनी एक रैली में उन्होंने घोषणा कर दी कि मोदी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, लेकिन ऐन मौके पर कमला हैरिस पीछे हट गईं। मोदी ने सोचा कि एक ही पार्टी के प्रत्याशी से मिलना ठीक नहीं रहेगा। उन्होंने ट्रंप के साथ अपनी मुलाकात रद्द कर दी, जो ट्रंप को बुरा लगा। तीसरा कारण, ट्रंप चालीस से ज्यादा बार दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत-पाकिस्तान संघर्ष रुकवाया। लेकिन भारत ने बार-बार स्पष्ट किया कि संघर्ष विराम पाकिस्तान के अनुरोध पर हुआ, पर ट्रंप यह सुनने को तैयार नहीं थे। चौथा कारण, कनाडा में जी-7 शिखर सम्मेलन से इतर मोदी और ट्रंप मिलने वाले थे, लेकिन ट्रंप शिखर सम्मेलन को बीच में ही छोड़कर अमेरिका चले गए। उन्होंने मोदी को फोन कर आमंत्रित किया। ठीक उसी समय पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर व्हाइट हाउस में ट्रंप से रात्रिभोज पर मिलने वाले थे। स्वाभाविक है, मोदी ने ट्रंप का आमंत्रण स्वीकार नहीं किया। इससे ट्रंप मोदी से नाराज हो गए।

साफ है कि भारत के साथ ट्रंप की समस्या केवल रूसी तेल खरीदने की वजह से ही नहीं है। अमेरिका और यूरोपीय देश अब भी यूक्रेन को भारी समर्थन दे रहे हैं। अन्य देशों की तुलना में भारत बहुत कम मात्रा में रूसी तेल खरीदता है। ट्रंप की समस्या ने आसिम मुनीर को उनका मित्र बना दिया और उन्होंने टैरिफ विवाद में युद्ध विराम के मुद्दे को शामिल करके मोदी को संकट में डाल दिया। संभवतः इसी वजह से उन्होंने भारत पर सबसे अधिक टैरिफ लगाया और पुरानी दोस्ती का भी ख्याल नहीं रखा। दूसरी तरफ ट्रंप ने चीन को राहत प्रदान की, जिसे वह अमेरिका का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानते थे। भारत ने ट्रंप की धमकियों के आगे 'समर्पण' करने से इन्कार कर दिया। अधिकारियों का कहना है कि ट्रंप ने मोदी को हल्के में ले लिया। ट्रंप के काम करने की अपनी शैली है। वह हर दिन मीडिया से बात कर किसी भी राष्ट्र प्रमुख पर अपने विचार व्यक्त करते हैं और सोशल मीडिया पोस्टों के जरिये बड़ी घोषणाएं करते हैं। अन्य किसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऐसा कभी नहीं किया। अब तो अमेरिकी भी कहने लगे हैं कि ट्रंप सिर्फ एक व्यापारी हैं। इसीलिए भारत को ट्रंप से निपटने के नए तरीके और पद्धतियां तलाशनी होंगी। edit@amarujala.com

आर्थिकी

भारतीय कृषि को मिलेगी नई ऊर्जा

जीएसटी 2.0 केवल कर कटौती भर नहीं है, बल्कि यह किसानों, सहकारी संस्थाओं और छोटे उद्यमों को विकास के केंद्र में रखने का नीति संकेत है।

नवीन पी. सिंह
प्रधान वैज्ञानिक, आईसीएआर-एनआईएपी

जुलाई 2017 में जब वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) का शुभारंभ हुआ, तो इसे स्वतंत्र भारत का सबसे बड़ा कर सुधार माना गया, पर वर्षों तक बिखरी हुई दरें किसानों के लिए उत्पादन खर्च बढ़ाती रहीं। अब आठ वर्षों बाद जीएसटी परिषद ने कर सुधार के जरिये इन विकृतियों को दूर कर दिया है। कर में राहत किसानों का बोझ घटाएगी, सहकारी संस्थाओं को सशक्त बनाएगी और भारतीय कृषि को अधिक प्रतिस्पर्धी व टिकाऊ बनाएगी। ट्रैक्टर पर कर घटाकर 12 फीसदी से पांच फीसदी कर दिया गया है, तो टायर, ट्यूब और हाइड्रोलिक पंप, स्प्रिंकलर, ड्रिप सिंचाई उपकरण, थ्रेशर और कंपोस्ट मशीन पर कर घटाकर पांच फीसदी रखा गया है। इससे छोटे और सीमांत किसान भी आधुनिक मशीनें अपना पाएंगे, जिससे श्रम लागत बचेगी और उत्पादकता बढ़ेगी।

खाद की उपलब्धता किसानों की आर्थिक स्थिति और खाद्य सुरक्षा, दोनों के लिए अहम है। अमोनिया, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जैसे कच्चे माल पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी कर देने से इनपुट की आपूर्ति स्थिर होगी और लागत का बोझ किसानों पर नहीं पड़ेगा। इसी प्रकार, जैव कीटनाशकों और सूक्ष्म पोषक तत्वों पर भी जीएसटी घटाकर पांच फीसदी किया गया है। इससे प्राकृतिक खेती को बढ़ावा मिलेगा, रासायनिक दवाओं का प्रयोग घटेगा और कृषि को स्थिरता व जलवायु अनुकूलन मार्ग पर अग्रसर किया जा सकेगा। छोटे जैविक उत्पादकों और किसान उत्पादक संगठनों के लिए यह राहत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। डेयरी केवल एक उद्योग नहीं, बल्कि ग्रामीण आजीविका की रीढ़ है, विशेषकर महिलाओं और स्वयं सहायता समूहों के लिए। मक्खन, घी और दूध के डिब्बों पर कर घटाकर पांच फीसदी करने से प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी, किसानों को बेहतर मूल्य मिलेगा और परिवारों को सस्ता पोषण। मधुमक्खी पालन और मत्स्य पालन को भी राहत दी गई है। प्राकृतिक शहद पर कर घटने से ग्रामीण और आदिवासी मधुमक्खी पालकों की आय बढ़ेगी, वहीं मछली उत्पादों पर कर घटाकर पांच फीसदी करने से मत्स्य उद्योग को नई गति मिलेगी। ओडिशा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के वनवासियों की जीवन रेखा तेंदूपत्ता पर भी अब केवल पांच फीसदी कर लगेगा। तैयार-खाद्य और संरक्षित फल, सब्जियों तथा मेवों पर जीएसटी घटाकर पांच फीसदी करने से कोल्ड स्टोरेज में निवेश बढ़ेगा, फसल की बर्बादी घटेगी, किसानों को उपभोक्ता मूल्य का बड़ा हिस्सा मिलेगा और छोटे प्रोसेसर व एफपीओ-आधारित उद्यम अधिक प्रतिस्पर्धी बनेंगे। दीर्घकाल में यह भारत को मूल्य संवर्धित कृषि-निर्यातों में अहम स्थान दिला सकता है।

लॉजिस्टिक्स पर उच्च कर दरों ने माल ढुलाई की लागत बढ़ा दी थी। अब वाणिज्यिक वाहनों पर कर 28 से घटाकर 18 फीसदी कर दिया गया है। माल-वाहन बीमा पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति दी गई है। इससे परिवहन खर्च घटेगा, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान कम होंगे और निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी। इसे ग्रामीण कोल्ड चेन और डिजिटल लॉजिस्टिक्स प्लेटफार्मों से जोड़ा जाए, तो यह संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला को बदल सकता है। जीएसटी 2.0 केवल कर कटौती भर नहीं है, बल्कि यह किसानों, सहकारी संस्थाओं और छोटे उद्यमों को विकास के केंद्र में रखने का नीति संकेत है। खेती की लागत घटाकर, टिकाऊ इनपुट को प्रोत्साहित कर, सहायक गतिविधियों को बल देकर और मूल्य श्रृंखलाओं को सशक्त बनाकर यह जीएसटी को बोझ से समृद्धि के साधन में बदल देता है। जीएसटी 2.0 का लक्ष्य भारतीय कृषि को सशक्त कर विकसित भारत की परिकल्पना के अनुरूप आगे बढ़ाना है।

एआई न तो आपसे नफरत करता है और न ही मोहब्बत, लेकिन आप परमाणुओं से बने हैं, जिसका इस्तेमाल वह किसी और काम के लिए कर सकता है।
- एलीजर युडकोव्स्की

अच्छी पुस्तकें स्थायी साथी होती हैं

आइंस्टीन बारह वर्ष की उम्र में यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर लिखी किताब पढ़कर समझ पाए कि सर्वमान्य सत्य की खोज बिना किसी महंगी प्रयोगशाला और उपकरण की मदद के भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया को सिर्फ मन की शक्ति से नियंत्रित किया जाता है।

डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम

जीवन धारा

धरती पर विभिन्न कालखंडों में कई महान मानव सभ्यताओं का जन्म हुआ, किंतु उनमें से कुछ ही सभ्यताएं अस्तित्व में हैं। प्राचीनकाल में दार्शनिक और बाद में वैज्ञानिक, प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ, अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री, सभी ने मिलकर विभिन्न सभ्यताओं को संपन्न बनाया।

भारतीय सभ्यता ने विभिन्न संस्कृतियों के संपर्क से होने वाले परिवर्तनों को स्वीकार करते हुए उन्हें अपने में रचा-बसा लिया। यही कारण है कि करोड़ों की जनसंख्या वाले हमारे समाज में विभिन्न संस्कृतियों, भाषाओं और धर्मों को मानने वाले लोग हैं, किंतु मानसिक स्तर पर हम सब एक हैं। इसका श्रेय हमारे चिंतकों को जाता है।

हमारे यहां *महाभारत, तिरुक्कुरल, कबीरवाणी* और *नारायणीयम* जैसे ग्रंथों की परंपरा रही है, जो आज भी कायम है। किसी अच्छी पुस्तक के संपर्क में आने और उसका संग्रह करने से जिंदगी हमेशा के लिए खुशहाल बन जाती है।

अच्छी पुस्तकें हमारी स्थायी साथी बन जाती हैं। कई पुस्तकें काफी पहले लिखी गईं, किंतु वे अब भी हमारा जीवन भर मार्गदर्शन करती हैं और आगे भी कई पीढ़ियों को दिशा दिखाती रहेंगी। कला जिंदगी की खूबसूरती को बड़ी नजाकत से पेश करती है। यह मानव के अस्तित्व को अर्थ देने के साथ-साथ उसे शक्ति भी प्रदान करती है। बारह साल की उम्र में अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपने पथ प्रदर्शक मैक्स टालमुड से यूक्लिडियन ज्योमेट्री पर एक पुस्तक पाकर विस्मय का अनुभव किया था। इस पुस्तक को पढ़ने से आइंस्टीन ने विचार की असली दुनिया में कदम रखा और वह समझ पाए कि सर्वमान्य सत्य की खोज बिना किसी महंगी प्रयोगशाला और उपकरण की मदद के भी की जा सकती है। इस प्रक्रिया को सिर्फ मन की शक्ति से नियंत्रित किया जाता है।

हम अपने चारों ओर दुख और भाग्यवाद पाते हैं, किंतु हमारे अंदर की निष्ठा उन्हें चुनौती देती है। साहित्य इसी तरह हमारे मन को सबल बनाता है। लेखक समाज की चेतना के प्रहरी होते हैं। हमारे चिंतक और लेखकगण युवकों को तेजस्वी मन वाले नेता बना सकते हैं। वे अपने लेखन से युवकों के मन में उदारता और मानवता के भाव भर सकते हैं। वे नई पीढ़ी को अदम्य साहस की याद दिला सकते हैं, जिसके सहारे वे किसी भी प्रकार की दुर्बलता और अभाव पर विजय प्राप्त कर सकते हैं।

अगर डॉक्टर ही एआई के आदी होने लगें

एआई का उपयोग करना एक बात है, पर इस पर निर्भर होकर डॉक्टर अगर अपनी बुनियादी क्षमताएं खो रहे हैं, तो यह खतरे की घंटी है।

टेडी रोसेनब्लथ
द न्यूयॉर्क टाइम्स

एआई समय

कुछ साल पहले एक अध्ययन में कहा गया था कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) उपकरणों ने डॉक्टरों को उनके काम में बेहतर बना दिया है। इससे कैंसर जैसे रोगों का पता लगाने और उनका तेजी से निदान करने में मदद मिली है। लेकिन, नए शोध से पता चलता है कि एआई से सहयोग लेना महंगा भी पड़ सकता है। *लैंसेट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड हेपेटोलॉजी* में प्रकाशित अध्ययन के अनुसार, कोलोनोस्कोपी के दौरान कैंसर-पूर्व वृद्धि का पता लगाने में मदद करने के लिए तैयार किए गए एक एआई उपकरण का उपयोग करने के तीन महीने बाद ही यह महसूस किया जाने लगा कि इस वृद्धि को बगैर उपकरण परख लेने की डॉक्टरों की मौलिक प्रवृत्ति में ह्रास हो रहा है। एआई उपकरणों पर डॉक्टरों की निर्भरता का यह पहला साक्ष्य है, जो बताता है कि यह डॉक्टरों के बुनियादी कौशल को खत्म कर रहा है।

यूनिवर्सिटी कॉलेज हॉस्पिटल लंदन में गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और अध्ययन के साथ एक संपादकीय प्रकाशित करने वाले डॉ. उमर अहमद कहते हैं, 'यह एक दो-तरफा प्रक्रिया है। हम एआई को ऐसे इनपुट देते हैं, जो उसके आउटपुट को प्रभावित करते हैं, पर यह हमारे व्यवहार को भी प्रभावित करता है।'

पोलैंड में चार एंडोस्कोपी सेंटरों के डॉक्टरों को कोलोनोस्कोपी करते समय एआई उपकरणों का प्रयोग करने की सुविधा दी गई। इससे परिणाम अच्छे आए और कैंसर का पहले ही पता लगाने में भी उल्लेखनीय सुधार देखा गया, जो कि एक एंडोस्कोपी विशेषज्ञ से बेहतर प्रदर्शन था। शोधकर्ताओं ने मापा कि एआई टूल हटाने पर डॉक्टरों के कौशल पर कितना फर्क पड़ा, पता चला कि तकनीक के प्रयोग से पहले, डॉक्टर कोलोनोस्कोपी में 28 फीसदी वृद्धि का पता लगा रहे थे, पर तीन माह बाद उनकी यह क्षमता गिरकर 22 फीसदी ही रह गई।

हालांकि, अध्ययन से यह जवाब नहीं मिलता कि क्या डॉक्टरों का प्रदर्शन इसी तकनीक के प्रयोग से गिरा है। उदाहरण के लिए, एआई उपकरण के बाद डॉक्टरों ने पहले से लगभग दोगुनी संख्या में कोलोनोस्कोपी कीं, जिससे हो सकता है कि उन्होंने प्रत्येक स्कैन पर कम ध्यान दिया हो। हालांकि, विशेषज्ञ यह भी कहते हैं कि एआई के उद्भव से डॉक्टरों की कौशल क्षमता पर असर पड़ना अप्रत्याशित नहीं है। क्या ऑटोपायलट के दौर में पायलटों को अपने कौशल विकास के लिए विशेष प्रशिक्षणों से नहीं गुजरना पड़ता?

ए जायंट लीप : हाउ एआई इज ट्रांसफॉर्मिंग हेल्थकेयर एंड व्हाट दैट मीन्स फॉर अवर फ्यूचर के लेखक डॉ. रॉबर्ट वॉचर कहते हैं कि सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब किया क्या जाए। नई तकनीकों के आने से पुराने कौशलों के लुप्त होने की कई मिसालें दी जा सकती हैं। अब स्टेथोस्कोप को ही लें, जिसके आविष्कार से पहले दिल और फेफड़ों की जांच करने में डॉक्टरों को परेशानी होती थी, और जो 1700 के दशक में बिल्कुल आम बात थी। लेकिन एआई अलग ही चीज है। डॉ. अहमद के अनुसार, इस पर लंबे समय तक मानवीय निगरानी जरूरी है। एल्गोरिदम समय के एक निश्चित बिंदु के लिए तैयार किए जाते हैं, जब उनके चारों ओर की दुनिया बदलती है, तो वे अलग ढंग से पेश आने लगते हैं।

डॉक्टर अहमद ठीक ही कहते हैं, 'अगर मैं अपना बुनियादी कौशल गंवा दूंगा, तो मैं एआई की गलतियां कैसे पकड़ सकूंगा?' डॉ. वाचर के अनुसार, आज जब एआई सभी स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों पर उपलब्ध नहीं है, डॉक्टरों का बुनियादी कौशल खोना चिंताजनक है। एआई के आदी डॉक्टर को अगर इसके बगैर काम करना पड़े, तो उसे मुश्किल होगी। हालांकि, अभी यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है कि एआई से डॉक्टरों की क्षमता में इतनी जल्दी गिरावट क्यों आ जाती है। डॉ. अहमद कहते हैं कि इसका एक कारण लंबे समय तक किसी सहयोगी पर निर्भर होने से स्कैन छवियों के मूल्यांकन पर ठीक से ध्यान न देना भी हो सकता है। बोस्टन स्थित बेथ इस्राइल डियाकोनेस मेडिकल सेंटर के एआई कार्यक्रम निदेशक डॉ. एडम रोडमैन कहते हैं कि 'यदि सिर्फ तीन महीने तक एआई उपकरण का उपयोग करने से अध्ययन में शामिल अनुभवी चिकित्सकों (सभी के पास करीब 27 वर्ष की प्रैक्टिस का अनुभव था) की क्षमता में कमी आ जाती है, तो फिर उन विद्यार्थियों का क्या होगा, जिन्होंने अभी मेडिकल की पढ़ाई शुरू ही की है।'

अंडरफिटिंग

यह एआई की खामी है। जब मशीन लर्निंग एल्गोरिदम डाटा की अंतर्निहित संरचना को पर्याप्त रूप से नहीं पकड़ पाता है, तो उसे अंडरफिटिंग कहते हैं। डाटा विज्ञान में अंडरफिटिंग एक ऐसी स्थिति है, जहां एक डाटा मॉडल इनपुट और आउटपुट चरों के बीच के संबंध को सटीक रूप से समझने में असमर्थ होता है, जिससे प्रशिक्षण सेट और अनदेखे डाटा, दोनों पर उच्च त्रुटि दर उत्पन्न होती है। अंडरफिटिंग तब होती है, जब कोई मॉडल बहुत सरल होता है, जो मॉडल के अधिक प्रशिक्षण समय, अधिक इनपुट फीचर, या कम नियमितीकरण की आवश्यकता के कारण हो सकती है।

©The New York Times 2025

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

हिन्दुस्तान
1936 सत्य • सार्थक • सदैव

दागदार मंत्री

यह सूचना न केवल चौंकाती है, हमें सोचने पर भी विवश करती है कि भारत के लगभग 47 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। आपराधिक मामलों में भी हत्या, अपहरण और महिलाओं के खिलाफ अपराध के गंभीर मामले शामिल हैं। 'एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स' अर्थात एडीआर का यह अध्ययन खास मायने रखता है। अभी हाल ही में तीन विधेयक संसद में पेश किए गए थे, ताकि गंभीर आपराधिक मामलों में अगर किसी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री को 30 दिन भी जेल में रहना पड़े, तो उसे स्वतः पदमुक्त मान लिया जाए। इस संशोधन का अनेक दलों और नेताओं ने विरोध किया है। आशंका जताई गई कि अगर ये कानून बन गए, तो उनका दुरुपयोग होगा, जिससे विपक्षियों को निशाना बनाया जाएगा। जिस देश में 47 प्रतिशत के करीब मंत्रियों के दामन पर आपराधिक दाग हों, वहां कड़े कानून के विरोध को समझा जा सकता है। जैसी चालू परिपाटी रही है, उसमें किसी भी कानून के दुरुपयोग को पूरी तरह रोका नहीं जा सकता। संभव है कि कुछ मंत्रियों के खिलाफ मामले दर्ज करने में कानून का दुरुपयोग हुआ हो, फिर भी समग्रता में चिंता वाजिब है।

गौर करने की बात है कि 27 राज्यों, तीन केंद्रशासित प्रदेशों और केंद्रीय मंत्रिपरिषद के कुल 643 मंत्रियों के स्व-शपथ पत्रों की जांच की गई है। चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली प्रसिद्ध संस्था एडीआर ने पाया है कि 302 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं। भाजपा के 40 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ, तो कांग्रेस के 74 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक के लगभग 87 प्रतिशत मंत्रियों पर आपराधिक आरोप हैं। वास्तव में, देश में कोई ऐसी पार्टी नहीं है, जिसमें आपराधिक दाग वाले नेता न हों। हालांकि, यह दाग तेलुगु देशम पार्टी पर सबसे गाढ़ा है, उसके 96 प्रतिशत मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले बताते हैं कि कथित साफ छवि वाले राजनीतिक दल भी अपने नेताओं पर लगने वाले दाग को गंभीरता से नहीं लेते हैं। पहले यह उम्मीद जताई गई थी कि राजनीतिक दल स्वयं दागदार नेताओं को किनारे कर देंगे, मगर इसमें कामयाबी नहीं मिल रही है। यह उम्मीद भी रहती है कि राजनेताओं के मामले में जल्दी सुनवाई और फैसला होना चाहिए, लेकिन इसमें भी सफलता नहीं मिल पा रही है। ऐसे में, न तो हम दागदार विधायकों, सांसदों से बच सकते हैं और न दागदार मंत्रियों से।

चुनाव सुधार के लिए काम करने वाली संस्था एडीआर ने पाया है कि 302 मंत्रियों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 174 पर गंभीर आपराधिक मामले हैं।

जैसे हालात हैं, उसमें यह आश्चर्य की बात नहीं कि 72 केंद्रीय मंत्रियों में से 29 अर्थात 40 प्रतिशत ने खुद पर आपराधिक मामले को स्वीकार किया है। वैसे, बहुत निराश होने की भी जरूरत नहीं है। हरियाणा, जम्मू-कश्मीर, नगालैंड और उत्तराखंड के मंत्रियों ने अपने खिलाफ कोई आपराधिक मामला दर्ज न होने की सूचना दी है। बहरहाल, एडीआर ने मंत्रियों की औसत संपत्ति के भी दिलचस्प आंकड़े पेश किए हैं। अपने देश में मंत्रियों की औसत संपत्ति 37.21 करोड़ रुपये है। दर्ज करने वाली बात है कि 30 विधानसभाओं में से 11 में अरबपति मंत्री हैं। कर्नाटक में सबसे ज्यादा आठ अरबपति मंत्री हैं। इसमें कोई दोराय नहीं कि देश में अमीर नेताओं की तादाद समय के साथ बढ़ती चली जाएगी। जहां अरबपति बढ़ रहे हैं, वहीं दो या तीन लाख संपत्ति वाले मंत्री भी आम लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। अतः विविधताओं से भरा यह देश सुधार और समानता की उम्मीद बनाए रखेगा।

हिन्दुस्तान Hindustan | 75 साल पहले
06 सितम्बर, 1950

एक और रेल दुर्घटना

देश में रेल दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ती जाती है। एक और रेल-दुर्घटना का हाल ही में समाचार प्राप्त हुआ है। काश्मीर मेल एक बार फिर दुर्घटना का शिकार हो गई है। यह दुर्घटना 3 सितम्बर की शाम को 4 बजकर 5 मिनिट पर दीनानगर और गुरुदासपुर स्टेशनों के बीच हुई और उसमें अब तक 11 व्यक्ति मर चुके हैं और घायलों की संख्या 54 तक पहुंच चुकी है। शुरू में 20 व्यक्तियों के मरने की खबर आई थी, किन्तु रेल-अधिकारियों द्वारा इसका खंडन किया गया है। प्राण-हानि इसलिए अधिक नहीं बताई जाती कि दुर्घटना रविवार के दिन हुई और रविवार छुट्टी का दिन होने के कारण रेल पर अधिक यात्री सफर नहीं कर रहे थे। मृतकों में कुछ ऐसे लोग होंगे, जो अपने परिवारों के एक मात्र भरण-पोषण कर्त्ता रहे होंगे। थोड़ा-बहुत मुआवजा यदि रेलवे ने दिया भी, तो उससे शोक सन्तप्त परिवारों की कोई क्षति पूर्ति नहीं हो सकती। ऐसी दुर्घटनाओं के अवसर पर उच्च अधिकारियों की ओर से समवेदना के जो संदेश भेजे जाते हैं, उनसे भी पीड़ितों को कोई खास सान्तवना मिलने वाली नहीं है।

इस दुर्घटना के लिए तोड़-फोड़ की कार्रवाई को उत्तरदायी नहीं ठहराया गया। खतरे की सूचना भी पहले से दे दी गई थी। रेलगाड़ी ज्यादा तेज रफ्तार से भी नहीं जा रही थी। गाड़ी जब दीनानगर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई, तब गाड़ी के गार्ड को यह चेतावनी दे दी गई थी कि 48वें मील पर रेल पटरी पानी के अंदर डूबी हुई है। खतरे का खयाल करके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और स्थायी वे इंसपेक्टर इंजन पर ही सफर कर रहे थे। फिर भी दुर्घटना को नहीं बचाया जा सका। इससे बढ़कर अफसोस की बात और क्या हो सकती है? अगर हम भाग्यवादी होते, जैसे कि इस देश के अधिकांश लोग हैं, तो यह संतोष कर लेते कि होनहार को कौन टाल सकता है। दुर्घटना में मरने वालों की मृत्य इस निमित्त होने वाली थी, वह होकर रही। विधाता की इच्छा के आगे किसका वश चल सकता है। किन्तु बुद्धि इस भाग्यवाद के आगे जाकर विचार करना चाहती है। प्रश्न उठता है कि दुर्घटना को टालने के लिए उन लोगों ने आवश्यक सावधानी बरती या नही, जिन पर ऐसा करने की जिम्मेदारी थी। काश्मीर मेल 48वां मील पार कर चुकने के बाद एक नाले पर होकर गुजर रही थी, तो दुर्घटना का शिकार हुई।

एक दौर था, जब चुनाव प्रचार के दौरान नेता विरोधियों के लिए कुछ कटु शब्द बोलते थे, मगर उस पर ज्यादा चर्चा की नौबत नहीं आती थी। कटुता को भूलकर लोग आगे बढ़ते थे, लेकिन अब नेताओं के सामान्य अभियान भी सार्थक संवाद व जन-जागरण के बजाय अशोभनीय टिप्पणियों से सुर्खियां बटोरने लगे हैं। दरभंगा में प्रधानमंत्री की मां के विरुद्ध अभद्रता एक नई गिरावट है। पेश हैं, इस अप-संस्कृति पर दो पक्ष :

आमने-सामने

मां का अपमान हमारी सभ्यता पर सीधा वार

यहां स्कैन करें

शाजिया इल्मी | राष्ट्रीय प्रवक्ता, भाजपा

- कांग्रेस-राजद के मंच से अभद्रता ने करोड़ों माओं की भावना आहत की।
- विपक्ष झूठ और दुष्प्रचार का सैलाब बहाने की कोशिश कर रहा है।
- जनता अब तय कर चुकी है कि सत्ता नामदारों की बपौती नहीं रहेगी।

हिन्दुस्तानी तहजीब में मां और संतान का रिश्ता जीवन का सबसे पवित्र, सर्वाधिक अनमोल रिश्ता है। मां ही उसकी पहली गुरु हैं, मां ही पहला देवता हैं। यहां के हरेक बच्चे को *मातृदेवो भव* का संस्कार दिया जाता है। इसीलिए जब बिहार के दरभंगा में वोटर अधिकार यात्रा के दरमियान कांग्रेस-राजद गठबंधन के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दिवंगत माता को लेकर अभद्र टिप्पणी की गई, तो देश भर के लोग हैरान रह गए। यह एक बेटे का नहीं, बल्कि पूरे भारतवर्ष का अपमान था। मां भारती का निरादर था!

ऐसे प्रकरण से स्वाभाविक ही कोई पुत्र आहत होगा। मगर प्रधानमंत्री की आंखों से निकले आंसू कतई व्यर्थ नहीं जाएंगे। ये आंसू केवल निजी वेदना नहीं हैं, बल्कि ये देश की करोड़ों माताओं की पीड़ा हैं। आज का विपक्ष झूठ और दुष्प्रचार का सैलाब बहाने की कोशिश कर रहा है। आरोप लगाना, अफवाहें फैलाना और कीचड़ उछालना, यही उसकी राजनीति के आधार हैं। मगर उसका सैलाब प्रधानमंत्री की पीड़ा के आगे टिक नहीं सकता। उनकी आंखों से झरे आंसू झूठ की सारी दीवारें ढहा देते हैं।

सारा देश जानता है कि प्रधानमंत्री की माता जी ने अत्यंत गरीबी और कठिन परिस्थितियों में अपने बच्चों की परवरिश की, उन्हें संस्कार दिए और ईमानदारी व मेहनत के मूल्य सिखाए। उनके जीवन में देश की हर उस मां की झलक मिल जाती है, चाहे वे खेतों में काम करने वाली माएं हों, मजदूर बस्तियों की माएं हों या गृहिणी की भूमिका निभाती हों। ऐसे में, किसी राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी द्वारा उनके बारे में अपशब्द कहना न केवल प्रधानमंत्री का, बल्कि देश की हर मां का अपमान है।

हमें यहां यह भी समझने की जरूरत है कि यह अपमान किसी एक धर्म या जाति की मां का नहीं है। चाहे उनको अम्मा कहें, अम्मी, माता या मम्मी पुकारें, सबका सम्मान एक समान है और हरेक मां का लाल इस कसम के साथ खड़ा है कि इस अपमान का बदला अवश्य लिया जाएगा। सबसे शर्मनाक बात यह है कि अपने मंच से हुए इस अपराध के लिए अब तक न तो राहुल गांधी ने और न ही तेजस्वी यादव ने क्षमा मांगी है। यह अहंकार है। यह वही सोच है, जिसमें वोटबैंक के लिए किसी मां और महिला की गरिमा को रौंदा जा सकता है। किसी भी सभ्य समाज में राजनीति का मूल धर्म विचारों की लड़ाई, नीतियों पर बहस है। इसलिए यह केवल देश के शीर्ष पद पर आरूढ़ व्यक्ति की माताजी पर हमला नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की मर्यादा को तार-तार करने की चेष्टा है।

इस घटना ने एक और सच्चाई उजागर की है। हमारे देश का विपक्ष लोकतंत्र की लड़ाई को वोट के अधिकार तक सीमित समझ रहा है। लेकिन भारत की जनता का संघर्ष इससे कहीं बड़ा है। यह संघर्ष केवल चुनाव जीतने का नहीं है, बल्कि उस सत्ता को बचाने का भी है, जो जनसेवा के लिए है, जन-भावनाओं का सम्मान करने के लिए है और देश की दुखियारी माओं के आंसू पोंछने के लिए है।

भारतवर्ष में मां भारती, गौ माता और जननी- तीनों की पूजा हमारे संस्कार का हिस्सा हैं। इसीलिए एक मां पर कीचड़ उछालना हमारी सभ्यता पर सीधा वार है। प्रधानमंत्री की माता पर की गई अभद्र टिप्पणी ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया है कि हमारी राजनीति आखिर किस दिशा में जा रही है? जब जनता को बरगलाना मुमकिन नहीं हो पा रहा, तो अब गाली-गलौज के स्तर पर उतरकर विरोध किया जाने लगा है? मगर, ऐसा करने वाली विरोधी पार्टियां भारी गलतफहमी की शिकार हैं। यहां का अवाम कभी बदजुबानी को पसंद नहीं करता है और चंद महीनों में ही बिहार की जनता यह बताएगी भी।

गौर कीजिए, वोट अधिकार यात्रा के नाम पर बिहार या देश के दूसरे इलाकों में फरेब कौन रच रहा है? इतिहास साक्षी है कि किस कदर का फर्जीवाड़ा होता था। लोगों को डरा-धमकाकर उनके लोकतांत्रिक हक पर डाके डाले जाते थे। गरीबों-वंचितों-औरतों के वोटों के पुराने डकैत आज चुनावों में धांधली की बातें कर रहे हैं और सबसे शर्मनाक बात यह है कि अपनी हताशा में वे किसी की स्वर्गवासी मां को भी राजनीति की दलदल में घसीट रहे हैं! मगर यह राजनीति नहीं, बल्कि ओछेपन की पराकाष्ठा है। इससे विपक्षी पार्टियों ने अपना बौनापन ही उजागर किया है।

फिर यह सिर्फ एक मां की बात नहीं है, यह उन करोड़ों भारतीय माताओं और बहनों की बात है, जिन्होंने अनथक संघर्ष करके, तरह-तरह की कठिनाइयां झेलकर अपने बच्चों को पाला-पोसा, उन्हें सभ्य नागरिक बनाया। राहुल गांधी और उनके जैसे नामदार कभी यह समझ ही नहीं सकते कि गरीबी में पले-बढ़े बच्चे और उसकी मां ने कैसे हालात का सामना किया होगा? उनके लिए तो सत्ता परिवार की जागीर है और वंश परंपरा से मिलने वाला 'हक।' मगर जनता यह तय कर चुकी है कि सत्ता अब नामदारों की बपौती नहीं रहेगी।

यहीं पर दो माओं के योगदान की कहानी सामने आती है। एक तरफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हैं, जिन्होंने अपने बच्चों की परवरिश के लिए दूसरों के बर्तन मांजे, अथक मेहनत की और अपनी संतान को ईमानदारी व परिश्रम के संस्कार दिए। इस मां ने बेहद विपरीत परिस्थिति में भी अपने बेटे को जनसेवक बनने का हौसला दिया। दूसरी तरफ, राहुल गांधी की मां हैं, जिनके बेटे को जन्म के साथ ही दुनिया की हर सुख-सुविधा या ऐशो-आराम प्राप्त रहा और जिन्होंने राजनीतिक विरासत भी तैयार थाली में पाया। उनके लिए संघर्ष का मतलब केवल किताबों और भाषणों तक सीमित है।

यही है, दो तरह के भारत का फर्क। एक भारत, जिसमें पैदा हुए नरेंद्र मोदी अपनी मां की मेहनत और त्याग की बदौलत प्रधान सेवक बनते हैं। दूसरा वह भारत है, जिसमें बेटे सिर्फ राजवंश के वारिस बनते हैं। इसलिए कोई यह मुगालता न पाले कि सामने वाले को नीचा दिखाने की चेष्टा करके या अमर्यादित आचरण करके जनता में लोकप्रिय हो जाएगा। भारत की जनता अपने सपूत को पहचानने में कभी चूक नहीं करती।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

बिहार में असली मुद्दों से ध्यान हटाना मकसद

यहां स्कैन करें

अलका लांबा | अध्यक्ष, अखिल भारतीय महिला कांग्रेस

- भाजपा बिहार में वोटों की फसल काटने के लिए यह विवाद खड़ा कर रही है।
- अपने वादे निभाने में वह विफल रही है, उसके नारे जुमले साबित हो रहे हैं।
- राहुल गांधी की यात्रा की सफलता से भाजपा की नींद उड़ चुकी है।

क्या सचमुच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय मां के खिलाफ किसी ने अशोभनीय टिप्पणी की या फिर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में राजनीतिक लाभ उठाने के लिए जान-बूझकर यह विवाद खड़ा किया जा रहा है?

बिहार में पिछले 20 सालों से एनडीए (जेडीयू-भाजपा) की सरकार है। डबल इंजन की यह सरकार बिहार से पलायन रोकने और युवाओं को रोजगार देने में बुरी तरह से विफल साबित हुई। परीक्षाओं में धांधली और आंदोलनकारी छात्रों पर बर्बर लाठीचार्ज की घटनाओं के अलावा 'बेटी बचाओ' का नारा भी बाकी भाजपा शासित राज्यों की तरह बिहार में एक जुमला ही साबित हुआ और महिलाओं, खासकर नाबालिग दलित बच्चियों की असुरक्षा बढ़ी। सूबे के लोगों को महंगाई से कोई बड़ी राहत नहीं मिली, मगर पटना अपराध की राजधानी बन गया। अपराधियों द्वारा सरेआम व्यापारियों को कत्ल करते देखा गया, राज्य में शिक्षा का स्तर पहले से ही लचर है, स्वास्थ्य केंद्रों में चूहे और आवारा कुत्ते देखे गए। इन सब मुद्दों पर विपक्ष, खासकर कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी अग्रिम पंक्ति में खड़े और लड़ते दिखे।

ऐसे में, मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के मुद्दे ने आग में घी डालने का काम किया। जल्दबाजी में हो रही इस प्रक्रिया में 65 लाख मतदाताओं को वोट के अधिकार से वंचित कर दिया गया। सीसीटीवी फुटेज, जिसमें वोटों से छेड़छाड़ के सारे सुबूत दर्ज हैं, उन्हें 45 दिनों में नष्ट करके सत्ताधारियों को बचाने की चुनाव आयोग की कोशिश को देखते हुए और ऐसी किसी भी आशंका को रोकने के लिए कांग्रेस और 'इंडिया' ब्लॉक के नेताओं ने मिलकर बिहार में 'वोटर अधिकार यात्रा' निकालने का फैसला किया और यात्रा निकाली भी। 16 दिनों की इस यात्रा ने बिहार का राजनीतिक माहौल बदलकर रख दिया है। इसी से बौखलाकर बीजेपी ने एक साजिश रची और स्थानीय लोगों के मुताबिक, एक व्यक्ति को प्लांट किया गया। उसे यात्रा के मंच पर भेज यह सब करवाया गया। आरोपी व्यक्ति को बीजेपी नेताओं के साथ बहुत बार देखा भी गया है। अब वह पुलिस की हिरासत में है। उसे कानून के अनुसार सख्त सजा मिलनी चाहिए।

भाजपा ने यह आरोप लगाया कि 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान एक व्यक्ति ने सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को अपशब्द कहे हैं। जिस व्यक्ति पर आरोप लगे, उसका कांग्रेस से कोई संबंध नहीं रहा, फिर भी प्रधानमंत्री ने स्वयं आगे बढ़कर इसे कांग्रेस-राजद के विरोध में देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश की। उन्होंने 'मेरी मां का अपमान हुआ' कहते हुए भाषण दिए। पहले वीडियो और ट्वीट सोशल मीडिया पर शेयर करके कांग्रेस-राजद के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई और फिर भाजपा ने 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान कर डाला। मगर बंद पूरी तरह से विफल साबित हुआ।

इस बंद के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी पर अभद्र टिप्पणी की गई, महिला अध्यापक को भाजपा महिला मोर्चा की कार्यकर्ताओं द्वारा सरेआम पीटा गया, एक गर्भवती महिला को अस्पताल जाने से रोके जाने का जनता ने ही विरोध किया, एक गरीब मजदूर जो साइकिल से जा रहा था, उसे पीटा गया। कुल मिलाकर भाजपा के बिहार बंद का जनता ने समर्थन नहीं, बल्कि विरोध और बहिष्कार किया। इसका साफ मतलब है, बिहार के लोग भाजपा के इस आरोप को कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री की मां को दुर्वचन कहे गए, सिरे से खारिज कर रहे हैं और इसको मुद्दा नहीं भी नहीं बनने देना चाहते।

वास्तव में, लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी की यात्रा की सफलता ने पूरी भाजपा की नींद उड़ाकर रख दी है। राहुल गांधी द्वारा यह कहा जाना कि वोट चोरी के मामले में एटम बम के बाद अब हाइड्रोजन बम फटने वाला है, तो अटकलें लगाई जाने लगीं कि क्या यह हाइड्रोजन बम वाराणसी में तो नहीं फटने वाला? बस, तभी से पूरी बीजेपी मुद्दा खोजने लगी है, ताकि वोट चोरी और वोटर अधिकार यात्रा की सफलता से ध्यान हटाया जाए।

भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय मां को देश का सबसे बड़ा मुद्दा बनाने और विपक्ष को घेरने की कोशिश की, मगर यह उसी पर उल्टी आ पड़ी। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री सहित भाजपा के उन तमाम नेताओं के बयान वायरल होने लगे, जिनमें उन्होंने विपक्ष की महिला नेताओं पर अभद्र टिप्पणी करने में बार-बार सीमाओं का उल्लंघन किया।

मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी (गुजरात चुनाव 2007) ने सोनिया गांधी के लिए अप्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया था। अपने बिहार दौरे के समय प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जिस भाजपाई शख्स को बुलाया गया, उसने सरेआम राजद की एक दलित महिला प्रवक्ता के बारे में अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया और उन्हें धमकी दी थी। उसके खिलाफ बाकायदा मुकदमा दर्ज है।

मां के अपमान की बात करने वालों से पूछा जाना चाहिए कि किसी के डीएनए पर प्रश्नचिह्न लगाने का अर्थ क्या उसकी मां का सम्मान करना होता है? कभी किसी को मिक्स ब्रीड बोलना, किसी की पत्नी को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बताना, किसी के लिए जर्सी गाय, हाइब्रिड बछड़ा, शूर्पणखा, कांग्रेस की विधवा जैसे शब्दों का इस्तेमाल किस राजनीतिक शुचिता की शब्दावली है? सोचिए, 'विधवा' जैसा संवेदनशील शब्द, जो समाज में पीड़ा का प्रतीक है, उसको भी उन्होंने राजनीति और वोट की खातिर इस्तेमाल किया गया।

प्रज्वल रेवन्ना के लिए वोट मांगकर, उसके साथ मंच पर खड़े होकर किसने मान-मर्यादा को तोड़ा है? कांग्रेस मानती है कि गाली देना गलत है और उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों और भाजपा नेताओं को राजनीति में मर्यादा का पहला पाठ खुद पढ़ना होगा, क्योंकि उन्होंने ही इस गंदी राजनीति की शुरुआत की है।

(ये लेखिका के अपने विचार हैं)

मनसा वाचा कर्मणा
मंत्रों की शक्ति

वैदिक ऋषियों ने चाहे विद्युत को अपने रथों में न जोता हो, न सूर्य और सितारों को तौला हो, न कत्लेआम और आधिपत्य जमाने में अपनी सहायता के लिए प्रकृति की विनाशकारी शक्तियों को भौतिक बनाया हो, किंतु उन्होंने हमारे भीतर के सभी स्वर्गों और भूतलों को नाप और थाह लिया था, उन्होंने मौत की पहेली को बूझ लिया था और अमरता के रहस्य को पा लिया था; उन्होंने उस एक (ईश्वर) का पता लगाना चाहा था और उसे खोज लिया था। वे उसे जान गए थे और उसके प्रकाश और पवित्रता, बुद्धिमत्ता और शक्ति की स्तुतियों में उसकी पूजा की थी।

संपूर्ण ऋग्वेद अपने आप को गूढ़, गोपनीय और आध्यात्मिक सिद्धांत व व्यवहार के तत्व के रूप में प्रकट करता है, जैसा किसी भी प्राचीन देश में रहस्यवादियों द्वारा किया गया होता, पर जो वस्तुतः हमारे लिए केवल वेद में बच रहा है। वहां वह जान-बूझकर एक परदे में छिपा हुआ है, किंतु परदा उतना मोटा नहीं है, जितना पहले हम सोचते थे; हमें बस अपनी आंखों का प्रयोग करना है कि परदा खुल जाता है; हमारे सामने शब्द और सत्य सशरीर साकार होकर खड़े हो जाते हैं।

हमारा जीवन प्रकाश व सत्य की शक्तियों और अंधकार की शक्तियों के बीच एक लड़ाई है। इनको अनेक नामों से बताया गया है, जैसे, वृत्र और वृत्राः, वल और पनि, दस्यु और उनके राजा। हमें अंधकार की इन शक्तियों के विरोध को नष्ट करने के लिए देवताओं की सहायता का आह्वान करना पड़ता है। हमें आंतरिक त्याग द्वारा देवताओं का उद्बोधन करना होता है और शब्द द्वारा अपने भीतर उनका आह्वान करना होता है- यही मंत्र की विशेष शक्ति है।

श्री अरविंद

आशुतोष राणा | अभिनेता

गुरु आकाश के जैसे विशाल और समुद्र की तरह गहरे होते हैं। स्मरण रखिए, इन दोनों स्थानों पर पदचिह्न नहीं पाए जाते। इसलिए गुरु जहां देख रहे हैं, वह नहीं, गुरु जहां दिखा रहे हैं, वह धारण करने योग्य होता है।

शहरी प्रबंधन की नाकामी से लगते जाम

भारत के प्रमुख शहर दुनिया के सबसे धीमे शहरों में शुमार किए जाने लगे हैं। यहां शहरी लोग ट्रैफिक जाम में ही सालाना सैकड़ों घंटे गंवा देते हैं। अगर जाम की समस्या न होती, तो वे इस समय का उपयोग दूसरे काम करने, आराम करने या परिवार के साथ बिताने में इस्तेमाल कर सकते थे। अधिक से अधिक सड़कें बनने के बावजूद, ट्रैफिक जाम लंबा और जानलेवा होता जा रहा है। इसका प्रमुख कारण यह है कि देश में कार रखने वाले अभिजात वर्ग की संख्या तेजी से बढ़ी है। भारत में प्रति 1000 लोगों पर 34 कारें हैं, जो वैश्विक स्तर पर तो कम है, लेकिन तेजी से बढ़ रही है। शहरी सड़कों पर कुछ खास लोगों का दबदबा बढ़ता जा रहा है, जबकि सार्वजनिक परिवहन पिछड़ रहे हैं।

सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि भारतीय शहरों में यात्रा के समय में जरा भी सुधार नहीं हुआ है। कोलकाता में अब भी पिछले पांच सालों से सबसे लंबा औसत यात्रा समय है। दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु में भी ज्यादा बदलाव नहीं आया है। आंकड़े भी यही कहते हैं। टॉमटॉम के '2024 के ट्रैफिक इंडेक्स' में कोलकाता और बेंगलुरु को दुनिया के सबसे खराब यातायात वाले शहरों में शामिल किया गया है। दिल्ली, मुंबई और चेन्नई भी पीछे नहीं हैं। हैदराबाद जैसी जगहों पर भी, जिन्हें लंबे समय से अपेक्षाकृत कम यातायात वाला माना जाता था, हालात बिगड़ रहे हैं। बेंगलुरु के लोग सालाना दो कार्य सप्ताह का वक्त भीड़भाड़ के कारण गंवा देते हैं, तो मुंबई वाले करीब 13 कार्य दिवस।

ट्रैफिक संकट स्वास्थ्य आपातकाल जैसा भी है। यहां तक कि जिन शहरों की हवा कभी साफ मानी जाती थी, वहां भी अब प्रदूषण से होने वाली मौतों की संख्या बढ़ गई है। द *लैंसेट प्लैनेटरी हेल्थ* में प्रकाशित पहले बहु-शहरी अध्ययन से वायु प्रदूषण के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले घातक प्रभावों का पता चलता है। जहां ज्यादा प्रदूषण है, वहां होनेवाली मौतों का अनुपात भी ज्यादा है। दिल्ली में सालाना कुल मौतों का लगभग 12 प्रतिशत मौतें वायु प्रदूषण से होती हैं। बेंगलुरु में प्रदूषण का स्तर हालांकि कम मापा गया, फिर भी इससे होनेवाली मौतों का प्रतिशत 4.8 रहा। जबकि बेंगलुरु के निवासियों को दिल्ली वालों द्वारा झेले जा रहे वायु प्रदूषण का केवल 30 प्रतिशत ही झेलना पड़ता है। यहां यह भी बता दें कि यह सिर्फ मेट्रो की समस्या नहीं है। छोटे शहर भी तेजी से इस राह पर चल रहे हैं। जयपुर के यात्रियों को 2024 में यातायात जाम के कारण 82 घंटे का नुकसान हुआ। हालांकि, लोगों को इसका असली नुकसान दिखाई नहीं देता। वह है- समय की बर्बादी, जहरीली हवा और बढ़ता तनाव।

श्रुति कुमारी, छात्रा

अनुलोम-विलोम
जानलेवा जाम

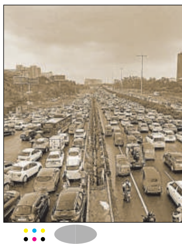

नागरिक अनुशासन की कमी जिम्मेदार

अपने यहां शहरों में जिस तरह से जाम की समस्या विकराल होती जा रही है, उसका तुरंत समाधान नहीं हुआ, तो ये शहर ही ठप पड़ सकते हैं। दुर्भाग्य से इस समस्या को बढ़ाने में कुछ हद तक हम आम लोगों का भी योगदान है। दरअसल, जाम से बचने के लिए जो सुझाव दिए जाते रहे हैं, उनमें सबसे प्रमुख है कि लोग बड़े निजी वाहन रखें ही नहीं, बल्कि इसकी जगह वे सार्वजनिक वाहनों का उपयोग करें। यह बताता है कि सड़कों पर गाड़ियों का बोझ हमने कितना बढ़ा दिया है। नागरिक अनुशासन की कमी का आलम यह है कि फुटपाथों पर मोटरसाइकिल चलाने तक से हम बाज नहीं आते। एक अध्ययन के मुताबिक, शहरों में सड़कों का लगभग 80 प्रतिशत हिस्से पर निजी वाहन काबिज हैं, जिनमें मुश्किल से 20 प्रतिशत यात्री ही सफर कर पाते हैं। दूसरी ओर 20 प्रतिशत सड़क पर 70 प्रतिशत से अधिक यात्रियों को चलना पड़ता है। समाधान के तौर पर कहा जा रहा है कि शहरों में निजी वाहनों का प्रवेश ही प्रतिबंधित कर दिया जाना चाहिए। दुनिया के कई अहम शहरों में यह व्यवस्था लागू है। लेकिन भारत समेत अनेक देशों में इस पर कोई सीमा नहीं है।

एक अहम उपाय के तौर पर पुराने जमाने के क्रांतिकारी विचार सुझाए जा रहे हैं। यह है, यातायात पर शुल्क लगाना। स्थानीय सरकारों ने सड़कें चौड़ी करने, फ्लाईओवर बनाने और रास्ते बदलने की कोशिशें की हैं, पर ये सब कारगर नहीं रहे। शहरों को ठप होने से बचाने के लिए भीड़भाड़ शुल्क जैसे बुनियादी उपाय कारगर हो सकते हैं। कुछ शहर भीड़भाड़ के मूल्य निर्धारण पर विचार भी करने लगे हैं। भारत के आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने 2013 में ही यह विचार प्रस्तुत किया था। लेकिन किसी भी शहर ने इसे लागू नहीं किया। इसके बजाय, ज्यादातर शहरों ने ज्यादा सड़कें, ज्यादा फ्लाईओवर और ज्यादा भीड़भाड़ को प्राथमिकता दी है। इसका नतीजा यह निकला है कि सड़कों पर गाड़ियों की बेहिसाब संख्या दिखने लगी है। हमें यह समझना होगा कि अगर सड़क पर जगह सीमित है, तो उसका सही व सुसंगत इस्तेमाल किया जाना चाहिए। सार्वजनिक परिवहन पर हमें भरोसा करना ही चाहिए, क्योंकि इससे न सिर्फ सड़कों का बोझ कम होता है, बल्कि पर्यावरण की रक्षा भी होती है।

कुल मिलाकर, हाल में दिखी जाम का यही संदेश है कि हमारा समय और हमारे शहर की हवा, दोनों कीमती हैं। इसका हमें हर हाल में ध्यान रखना भी चाहिए। वैसे भी, जब हम विकसित भारत की सपना देख रहे हैं, तो यह जरूरी है कि हमारा देश स्वस्थ हो, और सेहत की सुरक्षा तभी हो सकेगी, जब सड़कों पर उत्सर्जन कम हो।

दिव्या, गृहिणी

संपादकीय जागरण
(8) शनिवार, 6 सितंबर, 2025 : भाद्रपद शुक्ल - 14 वि. 2082

खुशी का सबसे बड़ा रहस्य त्याग है

क्या चाहते हैं ट्रंप

अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप अपनी इस पोस्ट के जरिये क्या कहना चाहते हैं, इसका अनुमान लगाना कठिन है कि लगता है हमने भारत और रूस को चीन के गहरे अंधकार में खो दिया है। चूंकि इसके साथ ही उन्होंने इन तीनों देशों के समृद्ध भविष्य की भी कामना की, इसलिए यह पता नहीं चल रहा कि वे कटाक्ष कर रहे हैं या अपने विचित्र स्वभाव के अनुरूप एक और बचकानी टिप्पणी कर रहे हैं? शायद उन्हें इसका भान नहीं कि वे एक बड़ी आर्थिक एवं सैन्य शक्ति समझे जाने वाले देश के राष्ट्रपति हैं। लगता है उन्हें यह समझ नहीं आ रहा है कि वे विश्व के थानेदार नहीं हैं और वह जमाना चला गया, जब अमेरिका जैसा चाहता था, दुनिया में वैसा ही होता था। यदि उन्होंने अपना रवैया नहीं बदला तो आने वाले समय में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका का प्रभाव और घटेगा। हाल में चीन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन के जिस शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रधानमंत्री ने भागीदारी की, उसे अमेरिका को दी जाने वाली चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री ने चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात कर ट्रंप को यही संदेश देने की कोशिश की कि यदि वे मनमानी करेंगे तो भारत चीन से संबंध सुधारने के अपने विकल्प का उपयोग करेगा। चूंकि अमेरिका से त्रस्त चीन भी भारत से संबंध सुधारने के लिए इच्छुक है, इसलिए दोनों देशों के बीच अविश्वास की खाई कम हो सकती है। पता नहीं ऐसा होगा या नहीं, लेकिन शंघाई सहयोग संगठन के जरिये भारत, रूस और चीन ने ट्रंप को यही संदेश दिया कि वे अपनी ही नहीं चला सकते। पिछले दिनों इस संदेश को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने यह कहकर और स्पष्ट किया कि अमेरिका भारत और चीन सरीखी बड़ी ताकतों से वैसे बात नहीं कर सकता, जैसे वे उसके उपनिवेश हों। अच्छा यह होगा कि ट्रंप और उनके सहयोगी बदलती वैश्विक राजनीति को समझें। भारत के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति से अधिक बड़बोलापन जिस तरह आर्थिक मामलों में उनके सलाहकार पीटर नवारो दिखा रहे हैं, उससे यही प्रतीति होती है कि वे उन्हें भारत के खिलाफ उकसा रहे हैं और अपने उन सहयोगियों की नहीं सुन रहे हैं, जो इस पक्ष में हैं कि भारत से मित्रता बनाकर रखी जाए। उन्हें यह पता हो तो अच्छा कि यदि भारत को अमेरिका की आवश्यकता है तो उसे भी भारत का साथ चाहिए। भारत का साथ लिए बगैर अमेरिका न तो आगे बढ़ सकता है और न ही अपने अंतरराष्ट्रीय प्रभाव को कायम रख सकता है। ट्रंप जब तक इस हकीकत को नहीं समझते, तब तक भारत के लिए यही उचित है कि वह उनसे सावधान रहे और उन चुनौतियों का सामना करने के लिए और अच्छे से कमर कसे, जो उनकी ओर से भारत पर 50 प्रतिशत टैरिफ थोपने के कारण उठ खड़ी हुई हैं।

जान बचाएं या गंवा दें

राज्य सरकार का आंकड़ा बता रहा है कि करीब 72 प्रतिशत सड़क दुर्घटनाएं तेज रफ्तार के कारण होती हैं। सड़क से जुड़े कानून में गति सीमा के उल्लंघन को अपराध माना गया है। इसके लिए जुर्माने का प्रविधान भी किया गया है। सरकार इससे अधिक कुछ कर भी नहीं सकती है। क्योंकि इस कानून का उल्लंघन करने वाले ढेर सारे लोग स्वयं मृत्यु दंड को प्राप्त कर लेते हैं। हां, दूसरे लोग भी इसके शिकार होते हैं, जिसमें अंग भंग से लेकर मौत तक होती है। लापरवाही से गाड़ी चलाने के कारण अगर किसी की मौत होती है तो वाहन चालक के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई का प्रविधान है। लेकिन, इन सबसे सड़क दुर्घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण हो पाएगा, इसमें संदेह है। क्योंकि कुल मिलाकर यह मामला आदमी के विवेक से जुड़ा हुआ है। गति सीमा का उल्लंघन आत्म हत्या से भी अधिक घातक है। इसमें दूसरों की भी जान जाती है। अभी पटना के पांच युवक परसा के निकट एक सड़क दुर्घटना में मारे गए। उनकी कार ही ट्रक में घुस गई। इस तरह की दुर्घटना को दुनिया का कोई कानून नहीं रोक सकता है। वाहनों पर निर्धारित से अधिक संख्या में बैठने का मुद्दा है। आसानी से कह दिया जाता है कि वाहन चालक बिठाते हैं। कोई इनसे पूछे कि जगह नहीं रहने पर आप लदते क्यों हैं? बचाव का एक ही रास्ता है-जीवन आपका है। इसे बचाएं या गंवा दें।

वाहन चालन में गति सीमा का उल्लंघन आत्महत्या से भी अधिक घातक है।

कह के रहेंगे — माधव जोशी

जागरण जनमत — कल का परिणाम

क्या जीएसटी सुधार से टैरिफ की चुनौती का भी सामना करना आसान होगा?

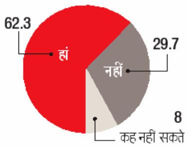

आज का सवाल
क्या आपको लगता है कि जीएसटी कटौती का लाभ कंपनियां आमजन को देंगी?

परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों का मत है। सभी आंकड़े प्रतिशत में।

कौशल वाली शिक्षा ही बनाएगी देश को अग्रणी

राजीव शुक्ला

तमाम देशों की सफलता का आधार यही रहा है कि उन्होंने युवाओं को केवल किताबों तक सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें वास्तविक काम का अनुभव दिलाया

भारत विश्व की सबसे युवा जनसंख्या वाला देश है, जहां 65 प्रतिशत से अधिक नागरिक 35 वर्ष से कम आयु के हैं। यह जनसांख्यिकीय लाभांश भारत की आर्थिक प्रगति को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखता है। हमारे युवा तेज तर्रार हैं, लेकिन उनका आत्मविश्वास अक्सर नौकरी के मैदान में ठहर जाता है, क्योंकि उन्हें व्यावहारिक कौशल की कमी महसूस होती है। असल सवाल यही है कि क्या केवल डिग्री लेकर हम इस अवसर को भुना पाएंगे या फिर हमें दक्षता और व्यावसायिक योग्यता की ओर गंभीरता से बढ़ना होगा। दुर्भाग्य से 2025 तक की तस्वीर बताती है कि देश के केवल सात प्रतिशत युवा ही औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त कर पाते हैं। जबकि जर्मनी, जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देशों में यह अनुपात 70 से 90 प्रतिशत तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि वहां के युवाओं की रोजगार क्षमता और उत्पादकता भारत की तुलना में कहीं अधिक है। यह अंतर भारत के लिए गंभीर संकट का संकेत है। डिग्रियों से लैस युवाओं की बेरोजगारी इस खाई को साफ दिखाती है।

हमारे विश्वविद्यालयों से हर साल लाखों छात्र निकलते हैं, लेकिन उनमें से बड़ी संख्या ऐसी होती है जिनके पास न तो उद्योगों की अपेक्षाओं के अनुरूप तकनीकी दक्षता होती है और न ही आधुनिक कार्यस्थल के अनुकूल साफ्ट स्किल्स। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और श्रम मंत्रालय के अनुसार लगभग 40 प्रतिशत स्नातक युवाओं के पास रोजगार पाने के लिए आवश्यक व्यावहारिक कौशल ही नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि डिग्री और नौकरी के बीच जो सेतु होना चाहिए था, उसे हमारी शिक्षा और प्रशिक्षण व्यवस्था ने खड़ा ही नहीं किया। 2024 में एक औद्योगिक शहर में किए गए सर्वेक्षण ने इस तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया। 10 हजार युवाओं में से केवल 12 प्रतिशत ने औपचारिक प्रशिक्षण लिया था और उनमें से भी अधिकांश को उम्मीद के अनुसार रोजगार नहीं मिला। यह केवल बेरोजगारी की कहानी नहीं है, बल्कि प्रशिक्षण तंत्र की कमजोरी का आईना है। हमारे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रशिक्षकों की भारी कमी से जूझ रहे हैं। मशीनें पुरानी हैं, पाठ्यक्रम दशकों पुराने हैं और प्रशिक्षण पद्धति में न तो आधुनिक तकनीकी संसाधनों का इस्तेमाल है और न ही उद्योगों की मांग का ध्यान रखा जाता है। ऊपर से समाज में व्यावसायिक शिक्षा को अब भी 'दूसरे दर्जे' की पढ़ाई माना जाता है। परिणाम यह होता है कि डिग्रीधारी छात्र भी नौकरी की कसौटी पर खरे नहीं उतर पाते। सरकार ने इस संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन जैसी पहल की हैं। कागज पर ये योजनाएं बहुत आकर्षक दिखती हैं। इनका मकसद युवाओं को उद्योग-अनुकूल प्रशिक्षण देना और स्वरोजगार के लिए तैयार करना है। हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही कहानी कहती है।

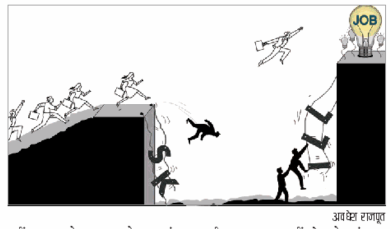

अवधेश राजपूत

विभिन्न रिपोर्टों के अनुसार लगभग 30 प्रतिशत प्रशिक्षित युवाओं को प्रशिक्षण के बाद भी रोजगार नहीं मिला और जिन्हें मिला वे अधिकतर अस्थायी और कम वेतन वाली नौकरियों में सिमट गए। यह इस बात का सुबूत है कि केवल प्रमाणपत्र थमा देना समाधान नहीं है। प्रशिक्षण की गुणवत्ता और उसका उद्योगों से जुड़ाव ही असली सफलता तय करेगा। ग्रामीण भारत में यह समस्या और गहरी है। अधिकांश योजनाएं शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों तक ही सीमित हैं। गांवों में प्रशिक्षण केंद्रों की संख्या बहुत कम है। डिजिटल प्रशिक्षण कार्यक्रम इंटरनेट कनेक्टिविटी की कमी और तकनीकी साक्षरता की खाई के कारण पूरी तरह कारगर नहीं हो पाते। गांव का युवा चाहकर भी शहर जाकर प्रशिक्षण नहीं ले पाता, क्योंकि वहां पहुंचने के लिए न साधन होते हैं न संसाधन। इस असमानता को मिटाए बिना भारत का कौशल संकट दूर नहीं होगा। दुनिया के सफल अनुभव बताते हैं कि यह स्थिति बदली जा सकती है। जर्मनी का डुअल एजुकेशन सिस्टम इसका उत्कृष्ट उदाहरण है। वहां छात्र पढ़ाई के साथ-साथ उद्योगों में व्यावहारिक प्रशिक्षण लेते हैं।

जापान की अप्रेंटिसशिप प्रणाली और चीन के ग्रामीण प्रशिक्षण केंद्रों ने भी यह साबित किया है कि यदि उद्योग और शिक्षा मिलकर चलें तो कौशल विकास स्वतः सशक्त हो सकता है। इन देशों की सफलता का आधार यही रहा है कि उन्होंने युवाओं को केवल किताबों तक सीमित नहीं किया, बल्कि उन्हें वास्तविक काम का अनुभव दिलाया। भारत को भी इसी राह पर चलना होगा। समय की आवश्यकता है कि कौशल योजनाओं को एक केंद्रीकृत मंच पर लाना होगा, ताकि पारदर्शिता और समन्वय सुनिश्चित हो। प्रशिक्षकों को मानकीकृत प्रशिक्षण दिया जाए और उन्हें समय-समय पर अद्यतन किया जाए। पाठ्यक्रमों को उद्योग की जरूरत के अनुसार बदलना होगा और ग्रामीण क्षेत्रों को प्रशिक्षण केंद्रों के साथ जोड़ना होगा। मोबाइल प्रशिक्षण वैन, डिजिटल क्लास और स्थानीय उद्योगों के साथ साझेदारी इस दिशा में अहम कदम हो सकते हैं। साथ ही उद्योगों को भी पाठ्यक्रम निर्माण और इंटर्नशिप अवसर उपलब्ध कराने में सक्रिय भागीदार बनना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कौशल विकास को केवल नौकरी पाने तक सीमित न रखा जाए। आजीवन सीखने की संस्कृति युवाओं में विकसित करनी होगी। तकनीक इतनी तेजी से बदल रही है कि एक बार सीखा गया कौशल कुछ ही वर्षों में अप्रासंगिक हो जाता है। ऐसे में युवाओं को लगातार नए कौशल सीखते रहना होगा। आनलाइन प्लेटफार्म और माइक्रो-कोर्स इसमें सहायक बन सकते हैं।

भारत की युवा शक्ति तभी वास्तविक संपत्ति बनेगी, जब उसे केवल डिग्रियां नहीं, बल्कि दक्षता भी दी जाएगी। बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण सिर्फ नौकरियों की कमी नहीं, बल्कि युवाओं में उपयुक्त कौशल का अभाव है। यदि नीति-निर्माण और क्रियान्वयन में सुधार किए जाएं, प्रशिक्षण की गुणवत्ता बढ़ाई जाए और उद्योग-शिक्षा के बीच पुल बनाया जाए, तो भारत न केवल अपने युवाओं के लिए रोजगार सुनिश्चित कर सकेगा, बल्कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी भी बन सकेगा।

(लेखक कांग्रेस सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं)
response@jagran.com

राष्ट्र निर्माण के प्रति संकल्पित संघ

प्रो. रसाल सिंह

आरएसएस की शताब्दी यात्रा संघर्ष, सेवा से परिपूर्ण रही है, जिसका व्यापक प्रभाव भारतीय समाज में देखा जा सकता है

वर्ष 1925 में विजयादशमी के दिन नागपुर में आद्य सरसंघचालक डा. केशव बलिराम हेडगेवार द्वारा स्थापित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ-आरएसएस अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ की स्थापना का मुख्य ध्येय हिंदू समाज को जागृत और संगठित करते हुए राष्ट्रीय एकता और सांस्कृतिक गौरव का विकास करना था। दैनंदिन शाखाओं के माध्यम से अनुशासन और चरित्र-निर्माण पर बल देते हुए व्यक्तित्व विकास और सामाजिक संगठन को समर्पित संघ आज विश्व का सबसे बड़ा और प्रभावशाली सामाजिक-सांस्कृतिक संगठन बन गया है। संघ की शताब्दी यात्रा संघर्ष, सेवा, समर्पण, संगठन और संस्कारों से परिपूर्ण रही है, जिसका व्यापक प्रभाव भारतीय समाज में देखा जा सकता है। इस संगठन ने समाज सेवा, स्वदेशी, शिक्षा, ग्राम-विकास, आपदा-राहत, वनवासी कल्याण और सामाजिक समरसता आदि अनेक क्षेत्रों में निरंतर काम करते हुए सकारात्मक बदलाव लाने का सराहनीय प्रयास किया है। संघ की विचारधारा सभी को साथ लेकर चलने एवं समरसता पर केंद्रित रही है। इसका उद्देश्य व्यक्तियों में नैतिकता, कर्तव्यबोध और नेतृत्वक्षमता विकसित करना है। संघ अपने स्वयंसेवकों को एक राष्ट्रीय दृष्टि देता है। संघ का मानना है कि व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि वह अपने राष्ट्र को किस दिशा में ले जाना चाहता है और उसमें उस व्यक्ति का क्या योगदान हो सकता है। संघ अपने स्वयंसेवकों को भारत-बोध से अनुप्राणित करते हुए निष्काम कर्म और निस्वार्थ सेवा करने की प्रेरणा देता है। यह जीवन में अध्यात्म के समावेश से ही संभव है।

आरएसएस के अनुसार, हिंदुत्व एक मत/पंथ नहीं, बल्कि एक सभ्यता, संस्कृति और मातृभूमि के प्रति समर्पण की भावना है। डा. हेडगेवार ने हिंदू को उस व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया, जो भारत को अपनी मातृभूमि और संस्कृति के रूप में स्वीकार करता है। संघ विविधताओं का सम्मान करते हुए उनमें एकता के सूत्र ढूंढने के लिए समर्पित और संकल्पित है। इस सबसे बड़े सामाजिक संगठन ने हिंदुत्व को

समाज में पंच-परिवर्तन लाने की पहल ● फाइल

एक समावेशी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के रूप में देखा है, जिसमें सारे भेदभाव से ऊपर उठकर भारत की सांस्कृतिक एकता और अखंडता को महत्व दिया गया है। इसका यह भी मानना है कि हिंदू राष्ट्रवाद भारत की बहुसंख्यक हिंदू संस्कृति और मूल्यों पर आधारित है, लेकिन इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की उपेक्षा या अवहेलना करना नहीं, बल्कि सभी को भारतवासियों के रूप में संगठित करना है। पिछले दिनों दिल्ली में सरसंघचालक डा. मोहन भागवत ने हिंदुत्व के समावेशी स्वरूप पर जोर देते हुए कहा कि संघ के हिंदुत्व का मतलब स्वीकार और समावेशिता है, न कि बहिष्कार और विरोध। समरसता, सद्भाव और सहअस्तित्व हिंदू जीवन पद्धति की मूल पहचान है। इसमें मुस्लिम तथा अन्य मतावलंबियों के प्रति भी सहज स्वीकार्यता का भाव है।

शताब्दी वर्ष में संघ का समाज में 'पंच परिवर्तन'' लाने पर विशेष ध्यान है। इसमें सामाजिक समरसता, पर्यावरण संरक्षण, कुटुंब प्रबोधन, स्वदेशी जीवनशैली और नागरिक कर्तव्य शामिल हैं। सामाजिक समरसता का आधार संघ की समावेशी राष्ट्र और समाज की अवधारणा है। यह अवधारणा जातीय भेदभाव से मुक्त समानता पर आधारित समरस समाज के निर्माण की है। स्वदेशी के अंतर्गत अपनी चेतना को भारतीय मनीषा के अनुरूप ढालने पर बल है। आर्थिक रूप से अपने राष्ट्र को सुदृढ़ करने के लिए स्वदेशी सामानों का ही उपभोग करना चाहिए। स्व का बोध और स्व के प्रति गौरव का भाव ही हमें औपनिवेशिक दासता से सच्ची और पूरी मुक्ति दिला सकता है। अपने भाषाई स्वबोध को जागृत करके ही एक आत्मनिर्भर और स्वतंत्रचेता राष्ट्र बना जा सकता है।

आज पर्यावरण संबंधी समस्याओं और आपदाओं से दुनिया के देश भी पीड़ित हैं। भारत भी इस संकट से अछूता नहीं है। आज हमें विकास के ऐसे माडल को विकसित करना है, जो प्रकृति का सहगामी और सहकारी हो। इसीलिए संघ पर्यावरण संरक्षण पर जोर दे रहा है। कुटुंब प्रबोधन का उद्देश्य संकटग्रस्त पारिवारिक-सामाजिक जीवन को बचाना है। परिवार भारत की सबसे बड़ी विशेषता और उपलब्धि रही है। व्यक्तिवाद और उपभोक्तावाद की पश्चिमी आंधी ने इसकी नींव को हिला दिया है। इस विकराल होती चुनौती को पहचानकर संघ प्राथमिकता के आधार पर इससे निपटने के लिए कृतसंकल्प है।

हम कर्तव्य-सचेत समाज की जगह अधिकार सचेत और आत्मकेंद्रित समाज बनते जा रहे हैं। हमारे समाज में हम सारे काम सरकार के ऊपर छोड़ देते हैं। जबकि बिना नागरिक सहभागिता के सरकार भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं कर सकती। बिजली-पानी आदि संसाधनों की बचत करना, राष्ट्रीय संपत्ति को क्षति न पहुंचाना, राष्ट्रीय पर्वों, प्रतीकों और संस्थाओं का सम्मान करना आदि कार्य दैनिक जीवन की देशभक्ति है। इन पंच-परिवर्तन से सामाजिक जीवन में अनुशासन, देशभक्ति और नागरिक सहभागिता बढ़ेगी। इससे राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और राष्ट्रोन्नयन की आधारभूमि तैयार होगी।

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय के रामानुजन कालेज में प्राचार्य हैं)
response@jagran.com

ऊर्जा

यज्ञीय संस्कृति

मानवतामूलक होने से भारतीय संस्कृति यज्ञीय संस्कृति है। जन्म से मृत्यु तक सभी मानवीय संस्कार यज्ञ आधारित हैं, किंतु धार्मिक अनुष्ठान के समय पवित्र वेदिका बनाकर वैदिक मंत्रों से देवों को समर्पित आहुतियां ही यज्ञ नहीं हैं। जगत का कल्याण करने वाली वे सभी क्रियाएं यज्ञ हैं, जो परार्थ के लिए होती हैं और मानवता की विस्तारक हैं। 'यज्ञो भुवनस्य नाभिः' इस कथन से वेदों ने यज्ञ को विश्व का नाभिकीय केंद्र स्वीकार किया है। इसलिए यज्ञ का स्वरूप व्यापक है। सृष्टि से प्रलय पर्यंत प्रकृति का हर विधान यज्ञ है। जिसकी परिणति सृजन, पालन और संहार रूप में देखी जाती है। जीवनदायी मेघों का जलवर्षण, वनस्पतियों का प्राणवायु निष्पादन और परहित भाव से फल-पुष्पादि का समर्पण यज्ञ के उत्कृष्टतम रूप हैं। गीता में मनुष्य द्वारा निष्काम भाव से किए गए सभी कर्मों को यज्ञ कहा गया है। इसलिए सभी कार्य यज्ञ समझकर पवित्र भाव से करने चाहिए।

पर्यावरण शुद्धि की प्रयोगशाला होने से यज्ञ स्वस्थ प्राकृतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के आधार हैं। इनकी सिद्धि के लिए पंच महायज्ञों का विधान यज्ञीय संस्कृति का सुखद विस्तार है। यही गृहस्थ धर्म की आधारशिला हैं। समाज का सर्वांगीण विकास इन्हीं से संभव है; जैसे-मानव जीवन की सार्थकता के लिए किया जाने वाला अध्ययन-अध्यापन ब्रह्मयज्ञ है, विविध प्रकार से उपकार करने वाले देवों के निमित्त दी गईं आहुतियां देवयज्ञ हैं, अष्ट दरिद्रों से ग्रस्त मानव समाज की सेवा नृयज्ञ है। यदि जीव जगत के लिए भोज्यादि का समर्पण भूतयज्ञ है, तो पूर्वजों के निमित्त किया जाने वाला तर्पण और दानादि क्रियाएं पितृयज्ञ हैं। मातृभूमि की रक्षा का संकल्प यज्ञ का ही स्वरूप है। यज्ञ के ये सभी रूप एकता के आधार हैं। आइए, श्रेष्ठ कर्मों की आहुति देकर यज्ञीय संस्कृति को संपोषित करें तथा राष्ट्र निर्माण में रचनात्मक योगदान दें।

डा. सत्यप्रकाश मिश्र

पाठकनामा
pathaknama@pat.jagran.com

विकास को गति दे जीएसटी

'समय के अनुरूप जीएसटी में सुधार' से प्रकाशित आलेख में आदित्य सिन्हा की बात विचार करने योग्य है, क्योंकि जीएसटी में हाल में किए गए सुधार समय की बड़ी जरूरत थे। इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जैसी जटिलताओं से उद्यमों को तरलता की कमी, अनुपयोगी क्रेडिट और प्रतिस्पर्धा में नुकसान झेलना पड़ रहा था। इससे निवेश का माहौल भी प्रभावित हो रहा था। अब जीएसटी अपीलीय न्यायाधीकरण (जीएसटैट) का गठन इस दिशा में एक अहम कदम है, क्योंकि इससे कारोबारियों को भरोसा मिलेगा कि उनके विवादों का जल्दी और निष्पक्ष समाधान होगा। इससे न्यायिक प्रक्रिया पर बोझ कम होगा और उद्योगों को स्थिरता मिलेगी। आगे सरकार को चाहिए कि कर ढांचे को और सरल बनाए, खासकर छोटे और मध्यम उद्यमों के लिए अनुपालन आसान करे। डिजिटल व्यवस्था को और मजबूत बनाकर कर संग्रह पारदर्शी और सहज किया जा सकता है। साथ ही उद्योगों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखना जरूरी है, ताकि नीतियां व्यावहारिक हों और कारोबारियों का विश्वास बढ़े। अगर ये कदम उठाए जाते हैं तो जीएसटी सिर्फ टैक्स वसूली का माध्यम नहीं रहेगा, बल्कि रोजगार, निवेश और आर्थिक विकास को गति देने वाला सशक्त इंजन बन जाएगा। देश के विकास की गति भी बढ़ती रहेगी।

आयुष्मान पांडेय, लखनऊ विश्वविद्यालय

तय मानकों के अनुसार व्यवहार

राष्ट्र के निर्माण में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पिछले कुछ वर्षों में शिक्षकों के प्रति सम्मान में कमी आई है, जिसका मुख्य कारण शिक्षकों का स्वयं का व्यवहार है। समाज में सम्मान प्राप्त करने के लिए शिक्षकों को समाज के मानकों के अनुसार व्यवहार करना आवश्यक है। अपने प्रति सम्मान अर्जित करने के लिए शिक्षकों को अनुकरणीय आचरण अपनाना होगा, चाहे वह ज्ञानार्जन का क्षेत्र हो या सामाजिक मानकों के अनुरूप व्यवहार। सरकार को भी शिक्षकों के सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षकों को गैर शैक्षणिक कार्यों से अलग रखना, सरकारी महकमे में शिक्षकों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार का स्पष्ट आदेश जारी करना, और शिक्षकों से संबंधित विषयों जैसे स्थानांतरण और पदस्थापन के निष्पादन हेतु गठित समितियों में वरिष्ठ शिक्षकों को शामिल करना आवश्यक है। यद्यपि इन उपायों को लागू करना कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति की आवश्यकता है। सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता शिक्षकों पर निर्भर करती है। यदि शिक्षक पूरी तरह से शिक्षण कार्य में संलग्न नहीं होंगे, तो शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रभावित होना स्वाभाविक है। इसलिए, शिक्षकों को अपने आचरण में सुधार लाना होगा और सरकार को भी उनके सम्मान की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने होंगे। इस प्रकार, शिक्षकों का सम्मान और उनकी भूमिका को पुनर्स्थापित करना आवश्यक है ताकि राष्ट्र निर्माण में उनकी योगदान को सही मायने में मान्यता मिल सके।

सुब्रत कुमार, राजपुर पुल, पटना

शिक्षकों का सम्मान

विद्वान लेखक जगमोहन सिंह राजपूत ने अपने एक लेख में चार सितंबर को शैक्षणिक व्यवस्था में सुधार एवं शिक्षक सम्मान में वृद्धि के लिए एक बड़े प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक साधारण सा परामर्श दिया था। उन्होने कहा था कि जब भी किसी कार्यालय में कोई भी शिक्षक अपने किसी कार्य के लिए या अन्य कारण से आए तो वहां के अधिकारी व कर्मचारी अपनी सीट से उठकर उनका स्वागत करें। उनकी शिकायतों का निवारण करें एवं लौटने के समय उनको गेट तक छोड़ने जाएं। यह सब कार्यालय के अन्य कर्मचारियों के समक्ष हो। इससे सभी के मध्य यह संदेश जाएगा कि शिक्षक आदरणीय होते हैं। यही संदेश समाज में भी जाएगा, जिससे स्वाभाविक रूप से समाज में उनकी ग्राह्यता बढती। इस परामर्श के अनुसार कार्य करने में कुछ भी व्यय नहीं होता। यह भी अनिवार्य कर दिया जाए कि प्रत्येक सरकारी अधिकारी एवं कर्मचारी के बच्चे केवल परिषदीय स्कूलों में ही पढ़ेंगे। मात्र इस निर्णय से शैक्षणिक जगत का कायापलट हो जायेगा। सभी स्कूलों के भवनों की देखभाल बढ़िया हो जाएगी। वहां के बच्चों को लंच में उत्तम कोटि का भोजन मिलने लगेगा। वहां के बच्चों को कोचिंग की आवश्यकता नहीं रहेगी। अध्यापकों के स्थान पर नकली अध्यापक पढ़ाने की धृष्टता नहीं करेंगे। शिक्षा का स्तर और बेहतर होगा।

धर्मेन्द्र नाथ रस्तोगी, दुर्गादेवी मंदिर मार्ग चौक पटना

X पोस्ट

अमेरिकी लोग अति-प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से होने वाले नुकसान के प्रति जागरूक हो रहे हैं। इस बीच भारत में हम खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को विकसित करने पर विचार कर रहे हैं। — श्रीधर वेम्बू@svembu

जीएसटी की दर घटाना अगर बड़ा कदम है, तो उससे भी बड़ा कदम कटौती का फायदा ग्राहकों तक पहुंचाना है, लेकिन जीएसटी में मुनाफाखोरी पर लगाम की व्यवस्था नहीं होना खटक रहा है। कंपनियां मोटा माल कमाने के लिए हरसंभव बहाना बनाने से नहीं चूकेंगी। — शिशिर@shishirs2

केरल सरकार ने शानदार पहल की है। राज्य में वरिष्ठ नागरिकों की चिंताओं का समाधान करने के लिए वरिष्ठ नागरिक आयोग बनाया गया है। यह बुजुर्गों के अधिकारों की रक्षा, उनकी उपेक्षा और दुर्व्यवहार जैसे मुद्दों का समाधान करेगा। — अखिलेश शर्मा@akhileshsharma1

ट्रंप कह रहे हैं, लगता है कि हमने भारत को चीन के हाथों खो दिया। अच्छी बात यह है कि उनको पाकिस्तान मिल गया है... दुनिया में आतंकवाद फैलाने वाला देश। — सुशांत सरीन@sushantsareen

जनपथ

बनें नागरिक बाद में, पहले डालें वोट,
लेकिन इसमें तनिक भी उन्हें न दिखती खोट।
उन्हें न दिखती खोट चोर है घर में बैठा,
औरों पर आरोप गढ़ रहा उनका बेटा!
बेटा घूम बिहार बेवजह करता झिक झिक,
मां जी पहले वोट डाल फिर बनें नागरिक!!
– ओमप्रकाश तिवारी

संस्थापक-स्व.पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान सम्पादक- स्व. नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन- महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान सम्पादक -संजय गुप्त
जागरण प्रकाशन लिमिटेड के लिये आनन्द त्रिपाठी द्वारा दैनिक जागरण प्रेस C-5, C-6 & 15 इंडस्ट्रियल एरिया, पाटलिपुत्रा, पटना - 800013 से प्रकाशित एवं मुद्रित, सम्पादक (बिहार/प. बंगाल)-विष्णु प्रकाश त्रिपाठी, स्थानीय सम्पादक - आलोक मिश्रा * दूरभाष : 0612-2277071, 2277072, 2277073
E.mail : patna@pat.jagran.com, R.N.I. NO. BIHHIN/2000/03097* इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं सम्पादन हेतु पी.आर. बी.एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी पटना जीपीओ रजि.नं. R-10/NP-18/14-16 समस्त विवाद पटना न्यायालय के अधीन ही होंगे। वर्ष 26 अंक 146

****

कल्पमेधा

लोग तुम्हारी स्तुति करें या निंदा, लक्ष्मी तुम्हारे ऊपर कृपालु हो या न हो, तुम्हारा देहांत आज हो या एक युग में, तुम न्यायपथ से कभी भ्रष्ट न हो।

- स्वामी विवेकानंद

शांति की राह

करीब सवा दो साल के बीच मणिपुर में यह अहम मौका है जब सरकार और कुकी समुदाय के बीच स्थायी समाधान की खोज के लिए एक सहमति बनी है और राज्य में शांति की उम्मीद जगी है। इससे पहले राज्य में जारी संघर्ष के बीच संबंधित पक्षों की अपनी शर्तों की वजह से किसी समझौते तक पहुंचना मुश्किल बना रहा और यही वजह है कि जब कुकी-जो के दो प्रमुख संगठनों और सरकार के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, तब भी इसके जमीन पर उतरने और स्थायी हल को लेकर एक आशंका बनी हुई है। हालांकि अब तक सबसे बड़ी समस्या यही रही कि संघर्षरत समूहों के बीच संवाद कायम होना ही एक बड़ी चुनौती थी और इसी वजह से समाधान के किसी प्रारूप पर आगे बढ़ना संभव नहीं हो सका। अब गुरुवार को केंद्र और मणिपुर की सरकार के साथ कुकी-जो के दो समूहों के बीच एक नए समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं, जिसके तहत राज्य की क्षेत्रीय अखंडता को बनाए रखने, राष्ट्रीय राजमार्ग-2 को मुक्त आवाजाही के लिए खोलने और उग्रवादी शिविरों को स्थानांतरित करने पर सहमति बनी है।

इसमें कोई दोराय नहीं कि मई 2023 में शुरू हुए टकराव और हिंसा के जटिल हो चुके स्वरूप के बाद अब कुछ अहम बिंदुओं पर हुए समझौते को अंतिम और सबके लिए स्वीकार्य समाधान के तौर पर देखना जल्दबाजी होगी, लेकिन इस बातचीत में सबसे महत्त्वपूर्ण यह है कि राज्य में हिंसा और संघर्ष से प्रभावित एक मुख्य समूह की नुमाइंगी कर रहे कुकी-जो संगठनों ने भागीदारी की और फिलहाल मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने पर सहमति बनी है। इससे पहले कुकी संगठनों की ओर से यह कई बार कहा गया कि जब तक 'अलग पहाड़ी राज्य' या संघ राज्य क्षेत्र की उनकी मांग पूरी नहीं होगी, तब तक वे किसी समझौते को स्वीकार नहीं करेंगे। यही स्थिति सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती बनी हुई थी। इस लिहाज से देखें, तो अगर कुकी-जो के दो समूहों और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच क्षेत्रीय अखंडता बरकरार रखने पर सहमति बनी है, तो इसे मणिपुर में जारी टकराव या संघर्ष की स्थिति को खत्म करके स्थायी समाधान की ओर बढ़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा सकता है।

हालांकि इस समझौते के समांतर एक बाधा यह खड़ी हुई है कि मणिपुर में नगाओं की शीर्ष संस्था ने मुक्त आवागमन व्यवस्था को समाप्त करने और भारत-म्यांमा सीमा पर बाड़ लगाने के विरोध में 'व्यापार प्रतिबंध' लागू करने की घोषणा कर दी है। वहीं कुकी-जो परिषद ने कहा कि समझौते को मैतेई आबादी और कुकी जो के इलाकों के बीच के 'बफर जोन' में किसी तरह की आवाजाही के रूप में नहीं समझा जाए; लोगों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। जाहिर है, कुकी-जो समूहों के साथ बनी सहमति के बावजूद राज्य में स्थायी समाधान और पूर्ण शांति की फिलहाल सिर्फ उम्मीद की जा सकती है। गौरतलब है कि राज्य में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के सवाल पर उभरा संघर्ष वहां कुकी और मैतेई समुदायों के बीच ऐसी दूरी पैदा कर चुका है, जिसका हल निकालना अब तक संभव नहीं हो सका है। वहां जातीय हिंसा के क्रम में कई महिलाओं पर बर्बर अत्याचार किए गए और अब तक ढाई सौ से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। यह समझना मुश्किल है कि अब जाकर केंद्र और राज्य सरकार ने कुकी-जो संगठनों के साथ संवाद कायम करके शांति की राह में जो कदम बढ़ाए हैं, इस तरह की पहल पहले क्यों नहीं हो सकती थी।

सकारात्मक संकेत

देश में स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम कमियों और चुनौतियों के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। भारत के महापंजीयक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, सतत विकास लक्ष्यों की ओर देश कदम जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती शिशु मृत्यु दर को कम करने की रही है। लंबे समय से मातृ-शिशु देखभाल के लिए नीतियां और योजनाएं भी बनाई जाती रहीं। इस क्रम में प्रसव के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने से लेकर टीकाकरण आदि के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए गए। इसी का परिणाम है कि शिशु मृत्यु दर कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बुधवार को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के मुताबिक, देश में शिशु मृत्यु दर प्रति एक हजार पर पच्चीस के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। एक दशक पहले यह संख्या चालीस थी। इस लिहाज से देखें तो मृत्यु दर में 37.5 फीसद गिरावट बताती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों और खासकर महिलाओं की पहुंच की स्थिति में सुधार हुआ है।

हालांकि, स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच के मामले में कई स्तर पर असमानता अब भी बनी हुई है और इस तस्वीर में अभी काफी सुधार होना बाकी है, इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिशु मृत्यु दर कम होना महत्त्वपूर्ण है। यहां एक हजार शिशुओं पर यह दर चौवालीस से घट कर अट्ठाईस रह गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह दर सत्ताईस से अठारह पर आ गई। इससे स्पष्ट है कि एक ओर जहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, वहीं लोगों के बीच गर्भवती महिलाओं की सेहत और सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके नतीजे भी सामने हैं। मगर आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच प्रसव के बाद महिलाओं और उनके शिशुओं को निरंतर और पर्याप्त पोषक आहार न मिलने की समस्या बनी हुई है। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। बहरहाल, कई चुनौतियों के बीच वर्ष 1971 के मुकाबले शिशु मृत्यु दर में अस्सी फीसद की गिरावट भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगाती है।

बिगड़ता पर्यावरण, बढ़ती आपदाएं

यह शायद पहली बार है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस बात का अध्ययन करेगा कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में प्राकृतिक आपदाएं क्यों लगातार बढ़ती जा रही हैं? यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जलप्रलय की घटनाओं ने विकास के माडल पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं।

अखिलेश आर्येंदु

उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में हर वर्ष बरसात के दिनों में तबाही देखने को मिलती हैं। भूस्खलन, बादल फटना और हिमनदों के पिघलने का सिलसिला लगातार जारी है। यह शायद पहली बार है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण इस बात का अध्ययन करेगा कि दोनों प्रदेशों में इस तरह की घटनाएं क्यों लगातार बढ़ रही हैं? यह इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि जलप्रलय की इन घटनाओं ने आधुनिक विकास के माडल पर फिर एक बार सवाल खड़े कर दिए हैं। अचानक बाढ़ या भूस्खलन कुछ ही मिनटों में ऐसी तबाही मचाते हैं कि बड़े पैमाने पर ढांचागत संपत्तियों और जान-माल का नुकसान हो जाता है। उत्तराखंड के धराली में पिछले दिनों ऐसी ही त्रासदी देखने को मिली थी। किसी को समझ में नहीं आया कि कैसे इस खौफनाक मंजर से खुद को बचाया जाए। अब यह भी कहा जा रहा है कि धराली की घटना बादल फटने से नहीं, बल्कि नदी के स्वभाविक जल प्रवाह में बाधाएं खड़ी करने की वजह से हुई थी। जो भी हो, मगर एक बड़ा सवाल यह खड़ा हो गया है कि क्या विकास के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ की जा रही है? एक बात स्पष्ट है कि नदियों, झीलों और सरोवरों के किनारे अतिक्रमण करना आपदाओं को न्योता देने के समान है।

वैज्ञानिकों के मुताबिक, इस तरह की प्राकृतिक आपदाओं की मूल वजह वनों की कटाई, नदी के मार्ग में अतिक्रमण तथा बंजर भूमि और पर्वतों का कटान है। जलवायु परिवर्तन के कारण किस तरह की आपदाएं आ सकती हैं, इसे हाल की घटनाओं से समझा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने वर्ष 1991 में निर्देश दिया था कि लोगों को खासकर नई पीढ़ी को पर्यावरण के प्रति जागरूक बनाने के लिए राज्य सरकारों को शिक्षा संस्थानों के पाठ्यक्रम में नया विषय जोड़ना चाहिए। हालांकि, पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण का विषय जोड़ा गया, लेकिन इससे समाज में पर्यावरण के प्रति कितनी जागरूकता बढ़ी, यह कहना मुश्किल है। गौरतलब है कि शीर्ष अदालत ने पर्यावरण की रक्षा के लिए राज्य सरकारों को स्पष्ट निर्देश दिया था कि जन जागरण के जरिए लोगों में नई चेतना जगाई जाए। लेकिन जब इन निर्देशों से राज्य सरकारें ही नहीं जगीं, तो फिर जनता को जगाने की बात ही बेमानी है।

जानकारों का मानना है कि बढ़ते शहरीकरण से पर्यावरण को ज्यादा खतरा है। जाहिर है, भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में औद्योगीकरण बढ़ रहा है। नदियों के स्वाभाविक रास्ते को अवरुद्ध कर वहां ढांचागत निर्माण किए जा रहे हैं। गांव और जंगल उजड़ रहे हैं। लोग रोजगार एवं सुख-सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ कर शहर आ रहे हैं। लेकिन जो नई बस्तियां बसाई जा रही हैं, वहां न तो पर्यावरण के मानकों का पालन हो रहा है और न ही वहां के लोगों को यह बताया जा रहा है कि वे किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करने में सहयोगी बन सकते हैं। सारी व्यवस्था एक तरफ और पर्यावरण की हिफाजत का सवाल दूसरी तरफ। ऐसे में पर्यावरण की

रक्षा कैसे हो, यह सवाल और गंभीर हो गया है। इतना जरूर हो रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं। इससे कुछ लोग अपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में लगे हुए हैं और पर्यावरण की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। जो संस्थाएं या

भारत सहित दुनिया के तमाम देशों में औद्योगीकरण बढ़ रहा है। नदियों के स्वाभाविक रास्ते को अवरुद्ध कर वहां ढांचागत निर्माण किए जा रहे हैं। गांव और जंगल उजड़ रहे हैं। लोग रोजगार और सुख-सुविधाओं की तलाश में गांव छोड़ कर शहर आ रहे हैं, लेकिन जो नई बस्तियां बसाई जा रही हैं, वहां न तो पर्यावरण के मानकों का पालन हो रहा है और न ही वहां के लोगों को यह बताया जा रहा है कि वे किस तरह से पर्यावरण की रक्षा करने में सहयोगी बन सकते हैं। ऐसे में पर्यावरण की रक्षा कैसे हो, यह सवाल और गंभीर हो गया है। इतना जरूर हो रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के नाम पर अरबों रुपए बहाए जा रहे हैं।

पर्यावरणवादी पर्यावरण संरक्षण की बात कर रहे हैं, उन्हें विकास विरोधी बता कर हताश किया जा रहा है।

देखा जाए तो विकसित देश पर्यावरण को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों के लिए धरती के संसाधनों का बेतहाशा दोहन बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए वे विकास के उस माडल के पैरोकार बने हुए हैं, जो पर्यावरण के साथ-साथ संस्कृति, धर्म और मानवता के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है। विकसित देशों की बहुराष्ट्रीय कंपनियां पूरे समाज को एक बाजार में तब्दील करती जा रही हैं। इसका असर यह हो रहा है कि ज्यादातर लोग धरती की हिफाजत के बजाय, उसको उजाड़ने में लगे हैं। इंसान से लेकर संस्कृति, पर्व और चिकित्सा यानी सब कुछ एक बाजार में तबदील हो चुका है। समाज का हर छोटा-बड़ा तबका इस कथित विकास की दौड़ में शामिल हो चुका है, मगर किसी का पर्यावरण की रक्षा की तरफ ध्यान नहीं है। जो पर्यावरण की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, उन्हें विकास विरोधी या गरीब विरोधी बता कर हाशिये पर धकेलने की मुहिम चलाई जा रही है। ऐसे में सोचा जा सकता है कि आने वाला वक्त कितना चुनौतीपूर्ण होगा?

वर्तमान में पर्यावरणीय मापदंडों और विकास के मानकों को संतुलित करने की बहुत जरूरत है। बिना संतुलन बनाए और इस दिशा में जनजागृति फैलाए, न तो हम आने वाले तमाम खतरों से बच पाएंगे और न ही निरापद विकास कर पाएंगे। दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान में अधिक धूम्रपान से ऐसे लोग भी श्वास और आंख की बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, जो इस लत से दूर हैं। धूम्रपान अनपढ़ या कम पढ़े-लिखे ही नहीं कर रहे, बल्कि पढ़े-लिखे लोग भी इस लत के आदी हैं। पर्यावरणीय जागरूकता का यह हाल है। जो लोग इस दिशा में कुछ सार्थक कार्य जैसे जागरूकता और शिक्षण कर रहे हैं, उन्हें प्रोत्साहन देने के बजाय हतोत्साहित किया जाता है। इसलिए यह समस्या दिनोंदिन गंभीर होती जा रही है।

सरकार वर्षों से पर्यावरण सुधार की दिशा में संयुक्त राष्ट्र के साथ मिल कर कई स्तरों पर कार्य कर रही है। अरबों रुपए अब तक इस मद में खर्च किए जा चुके हैं, लेकिन जन सहयोग न मिलने और पैसे का दुरुपयोग होने के कारण इस दिशा में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं हो सका है, जिससे सुरक्षित जीवन को लेकर भरोसा कायम हो सके। भारत सहित पूरी दुनिया में विकास के नाम पर विस्थापन, उजाड़ और पर्यावरण विध्वंस का दौर चल रहा है। जो इस दौर में शामिल हैं, वे 'बुद्धिमान' और 'चतुर' माने जा रहे हैं और जो इस विनाश लीला का विरोध कर आंदोलन के जरिए लोगों को जागरूक करना चाहते हैं, उन्हें विकास विरोधी घोषित कर उनकी पहल पर ही सवाल उठाया जा रहा है। मतलब एक तरफ बाजारवादी शक्तियां हैं, जिनके पास अकूत धन है। वे पर्यावरण का विनाश करने में लगीं हैं। दूसरी ओर कुदरत की हिफाजत करने वाले लोग भी हैं, जो इस विनाश को रोकने की कोशिश में लगे हैं। देखना यह है कि विनाशकारी जीतता है या विनाश को रोकने वाला। यदि आपदाओं से सबक लेकर अतिक्रमण और वनों के कटान जैसी कवायदों को बंद कर दिया जाए, तो जलवायु परिवर्तन के प्रकोप से धीरे-धीरे निजात मिल सकती है।

चुनौतियों के बीच शिक्षक

नवनीत शर्मा

'भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है'। सार्वभौमिक प्रतीत होती इस पंक्ति के साथ कोठारी आयोग ने अपनी विस्तृत रपट 1964 में लिखी और शायद ही सोचा होगा कि इसके छह दशक बाद भी यह भविष्य उन कक्षाओं में रचा जा रहा होगा, जहां मार्गदर्शन के लिए अध्यापक की बाट देखी जा रही है। आज बढ़ती संख्या वाली कक्षाएं अपनी और राष्ट्र की तकदीर लिखने को तैयार बैठी हैं, लेकिन उनमें वह अभिप्रेरणा नहीं है, जो शिक्षक की उपस्थिति से आती है। शिक्षक, जिसे भविष्य गढ़ने का शिल्पी कहा गया, इन कक्षाओं में कम होते जा रहे हैं। परिणाम यह है कि लाखों बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी किस्मत और देश का भविष्य अंधेरे में गढ़ने को विवश हैं।

हाल ही में आई एक खबर में यह दावा किया गया कि भारत में एक करोड़ शिक्षक चौबीस करोड़ बच्चों को स्कूलों में पढ़ा रहे हैं। यह अनुपात शिक्षा की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिहाज से आदर्श है, लेकिन जमीनी हकीकत उतनी अच्छी नहीं दिखती। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश- ये दस राज्य देश की कुल आबादी का लगभग सत्तर फीसद हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा की स्थिति पर राज्य की आधिकारिक वेबसाइट पर दर्ज आंकड़े दर्शाते हैं कि पूरे प्रदेश में 1,32,855 सरकारी स्कूलों को 6,03,441 शिक्षक संभाल रहे हैं। औसतन देखें तो हर स्कूल में 4.5 शिक्षक नियुक्त हैं। यहीं से असमानता की असली तस्वीर सामने आती है। इन्हीं आंकड़ों में यह भी दर्ज है कि 8,866 स्कूल ऐसे हैं, जहां सिर्फ एक शिक्षक तैनात है और इन स्कूलों में 6,11,950 बच्चे पढ़ते हैं। यानी एक शिक्षक को औसतन उनहत्तर बच्चों को 'पढ़ाने' की जिम्मेदारी उठानी पड़ रही है। उत्तर प्रदेश की तरह ही अन्य नौ सबसे अधिक आबादी वाले राज्यों की स्थिति भी चिंताजनक है। आधिकारिक आंकड़े बताते हैं कि कुल 10,17,660 सरकारी स्कूलों में से 1,10,971 स्कूल ऐसे हैं, जहां पूरे विद्यालय की बागडोर केवल एक ही शिक्षक के हाथ में है।

'शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं'। यह कहावत आज की हकीकत में कितनी बेमानी लगती है, जब देश के सरकारी स्कूलों में लाखों शिक्षकों की कमी है। सरकारी अनुमानों के मुताबिक, देश में लगभग दस लाख शिक्षकों की तत्काल आवश्यकता है, जिनमें से चार लाख शिक्षकों की जरूरत तो केवल प्राथमिक स्तर पर ही है। हालांकि, संख्या के हिसाब से यह कोई असंभव कार्य नहीं है। ठोस कदम उठाए जाएं, तो एक वर्ष के भीतर ही इन रिक्तियों को भरा जा सकता है। मगर यह न केवल शिक्षण के पेशे के प्रति उदासीनता को दर्शाता है, बल्कि देश के करोड़ों बच्चों के भविष्य के प्रति उपेक्षा भी करता है। भले ही भारत सतत विकास लक्ष्य (एसडीजी) का हस्ताक्षरकर्ता है, पर पिछले एक दशक से शिक्षक भर्ती और शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम लगातार अनेक समस्याओं से जूझ रहे हैं। हर बार कुछ वर्ष में ही शिक्षक और शिक्षा पाठ्यक्रम बिना किसी स्पष्ट दृष्टि के लगातार बनाए और बदले जाते रहे हैं। नीति-निर्माताओं की अटपटी योजनाओं के चलते आज भी इस पर स्पष्टता नहीं है कि एक व्यक्ति को बेहतर शिक्षक बनने के लिए किस तरह की शिक्षा और प्रशिक्षण की आवश्यकता है।

शिक्षा क्षेत्र में सेवा की स्थिति और वेतनमान की समस्या आज गंभीर होती जा रही है और इसके निदान के संकेत नहीं मिल रहे। भर्ती प्रक्रिया की अनवरत देरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे की कमी शिक्षण पेशे को अरुचिकर बनाती जा रही है। नतीजतन, प्रतिभाशाली और योग्य युवा इस क्षेत्र में आने से कतराते हैं। सवाल है कि जब भविष्य गढ़ने वाले स्वयं ही असुरक्षा और आर्थिक असमानता से जूझ रहे हों, तो शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य किस आधार पर सुरक्षित माना जाए?

शिक्षा व्यवस्था में सुधार के नाम पर लिए गए नीतिगत निर्णय स्थिति को और जटिल बना रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षक पेशेवर मानकों (एनपीएसटी) और हर वर्ष पचास घंटे की अनिवार्य सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) जैसी पहल शिक्षण को सशक्त बनाने के बजाय बोझिल बना रही हैं। ये कदम अतिरिक्त नौकरशाही बोझ बनकर उभर रहे हैं, जो उनकी स्वायत्तता को कमजोर करते हुए मनोबल गिरा रहे हैं।

नीतिगत विफलताओं का बोझ सीधे शिक्षकों के कंधों पर डालने से पहले यह जरूरी है कि नीतियों पर फिर से सोच-विचार किया जाए। कागजों में शिक्षकों की तुलना गोविंद से करने की भावपूर्ण भाषा का सहारा लेने के बजाय उन्हें वास्तविक सम्मान, गरिमा और पेशेवर स्वायत्तता मिले। जब तक शिक्षा प्रणाली में ऐसे मौलिक बदलाव नहीं होंगे, तब तक शिक्षक महज आज्ञाकारी वेतनभोगी कर्मचारी बनकर रहेंगे और अपने नियंताओं की वैचारिक प्राथमिकताओं और आदेशों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे।

दुनिया मेरे आगे

आज बढ़ती संख्या वाली कक्षाएं अपनी और राष्ट्र की तकदीर लिखने को तैयार बैठी हैं, लेकिन उनमें वह अभिप्रेरणा नहीं है, जो शिक्षक की उपस्थिति से आती है। भविष्य गढ़ने वाले शिल्पी यानी शिक्षक कक्षाओं में कम होते जा रहे हैं। नतीजतन, लाखों बच्चे बिना किसी मार्गदर्शन के अपनी किस्मत और देश का भविष्य अंधेरे में गढ़ने को विवश हैं।

इक्कीसवीं सदी में शिक्षक होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार कर्तव्य बन चुका है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच को आसान बनाया जा सकता हैं, लेकिन उसे जीवंत, प्रेरणादायी और परिवर्तनकारी बनाने के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि वह प्रेरणास्रोत, मार्गदर्शक और व्यक्तित्व निर्माता होता है जो विद्यार्थियों को सोचने, सवाल करने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज हम इस मानवीय क्षमता में निवेश नहीं करेंगे, तो एक ऐसी व्यवस्था बनेगी, जहां भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बिना किसी मार्गदर्शन के एक भ्रम की दुनिया में गढ़ा जा रहा होगा।

नए समीकरण

तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन ने नई वैश्विक कूटनीति को एक बार फिर चर्चा के केंद्र में ला दिया है। एक ही मंच पर नरेंद्र मोदी, व्लादिमीर पुतिन और शी जिनपिंग का साथ होना एक संकेत है कि अंतरराष्ट्रीय राजनीति तेजी से नई दिशा में झूल रही है। कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रत्याशित नीतियों ने इस समीकरण को जन्म दिया है। भारी अमेरिकी शुल्क का सबसे बड़ा खमियाजा भारतीय निर्यातकों खासकर कपड़ा और चमड़ा उद्योग को उठाना पड़ रहा है। करोड़ों भारतीयों की रोजी-रोटी दांव पर लगी है। ऐसे में यह सवाल वाजिब है कि क्या भारत, रूस और चीन की यह नजदीकी केवल अमेरिका को 'दिखाने' की रणनीति है या फिर वाकई एक रचनात्मक साझेदारी की दिशा में उठाया गया बड़ा कदम है? भारत और रूस के रिश्ते ऐतिहासिक मजबूती के प्रतीक रहे हैं। मगर इस त्रिकोणीय समीकरण में चीन एक चुनौती है। सीमा विवाद का जख्म अभी भी नासूर बना हुआ है। दोनों ही देशों के बीच अविश्वास बहुत गहरा है। यह तालमेल किसी ठोस परिणाम तक पहुंचता है, तो सबसे पहले दोनों देशों को आपसी अविश्वास कायम करना होगा।

- वीरेंद्र बहादुर पांडेय, गोंडा

भाषा की मर्यादा

एक-दूसरे को नीचा दिखाने के लिए अब कोई भी आरोप लगाने में संकोच नहीं किया जाता। इस राजनीतिक संघर्ष में यह मान लेना चाहिए कि विपक्ष कभी भी आपकी प्रशंसा नहीं करेगा। हालांकि, अब तक भाषा की मर्यादा बनी हुई थी, लेकिन वर्तमान में जो स्थिति दिखाई दे रही है, वह आने वाली पीढ़ी के लिए नकारात्मक संदेश प्रस्तुत कर रही है। राजनीति के मंच से न केवल भाषा की मर्यादा टूट रही है, बल्कि एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव भी गायब हो रहा है। इस खेल में नेता ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, जिससे उनकी ही छवि धूमिल हो रही है। सत्ता के लालच में बड़े दल के नेता शब्दों की गरिमा को भूलते जा रहे हैं। भारतीय संस्कृति में बड़ों को सम्मानपूर्वक संबोधित किया जाता है, लेकिन यह भी लोग भूलते जा रहे हैं। नेताओं द्वारा जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया जा रहा है, वह न केवल शर्मनाक है, बल्कि राजनीति की छवि को भी नुकसान पहुंचा रहा है।

- वरुण कुमार, जमशेदपुर

सबसे बड़ा दान

'अंगदान से जुड़ी जीवन की उम्मीदें' (आलेख, 3 सितंबर) पढ़ा। अंगदान कर किसी जरूरतमंद व्यक्ति का जीवन बचाना हम सभी का मानवीय धर्म होना चाहिए। इस तरह की पहल कर हम समाज में एक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं। कोई दोराय नहीं कि अंगदान जीवन के लिए अमूल्य उपहार है। अंगदान करके किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति की जिंदगी में नई उम्मीदों का सवेरा लाया जा सकता है। शोक की घड़ी में ऐसे कई परिवार हैं जो इस तरह के निर्णय लेते हैं और असहाय लोगों को नया जीवन देते हैं। ऐसे परिवारों का सम्मान किया जाना चाहिए। अंगदान के मामले में इंदौर ने जो मिसाल पेश की, वह प्रशंसनीय है। आज भी हर वर्ष लाखों लोग अंग खराब होने के कारण बरसों तक अंगदान की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए मरने के बाद अंग किसी के काम आए, इससे बड़ा कोई दान नहीं हो सकता। हालांकि अब अंगदान के प्रति जागरूकता आ रही है, लेकिन फिर भी काफी कम है।

- साजिद अली, चंदन नगर, इंदौर

खेल की खुमारी

आज बच्चे मनोरंजन के लिए आभासी दुनिया पर निर्भर हो गए हैं। वे इसमें गुम हो रहे हैं। इंटरनेट पर आनलाइन गेम के अलावा कई अवांछित चीजों तक बच्चों की पहुंच हो चुकी है, जो उनके भविष्य के लिए खतरे की घंटी है। इस लत के कारण उन्हें अकेलापन पसंद आ रहा है। यह खतरनाक स्थिति है। कई बार आनलाइन जुआ खेलने के क्रम में बच्चों ने अपने अभिभावकों की बैंक में जमा पूंजी खत्म कर दी। जब इसका पता चलता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अगर अभिभावक बच्चों को आनलाइन गेम खेलने से रोकते है, तो वे आक्रामक हो उठते हैं। कुछ बच्चों ने आत्महत्या जैसा कठोर कदम भी उठा लिया। आनलाइन गेम की वजह से बच्चों में हिंसक प्रवृत्ति भी बढ़ रही है। यह सड़कों से लेकर स्कूलों तक में दिखता है। इंटरनेट की लत से बच्चों को बचाना अभिभावकों के लिए सचमुच बड़ी चुनौती है।

- हिमांशु शेखर, गयाजी

हमें लिखें, हमारा पता : edit.jansatta@expressindia.com | chaupal.jansatta@expressindia.com

https://t.me/AllNewsPaperPaid

अभिमत

समता भवन, रचनात्मक गतिविधियों का भी केन्द्र रहा है। प्राकृतिक खेती उनमें से एक है। जीरो बजट खेती के प्रणेता सुभाष पालेकर के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव-गांव में आयोजित किए गए हैं। इससे प्रभावित होकर कई किसान प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे है। देसी बीजों को बचाने का काम भी किया जा रहा है। इसके अलावा, यह भवन सांस्कृतिक आंदोलनों का केन्द्र भी है। यहां गांव के स्थानीय युवाओं को नाटकों और गीतों का प्रशिक्षण देकर जन जागरण का काम किया जाता है।

प्रेरणा का समता भवन

नवाचार

■ **बाबा मायाराम**

इन दिनों मुझे ओडिशा के बरगढ़ शहर के समता भवन में लंबे प्रवास का मौका मिला है। हालांकि मैं इस बार निजी काम से आया हूं, पर किसान संगठन के कई कार्यकर्ताओं से मिलकर पुरानी यादें ताजा हो गईं हैं। इस कॉलम में किसान संगठन, सामाजिक कार्यकर्ता और विकल्प की राजनीति, सामाजिक परिवर्तन आदि पर चर्चा करना चाहूंगा, जो समता भवन की प्रमुख गतिविधियों में शामिल है।

यह समता भवन का नया कार्यालय है। समाजवादी चिंतक किशन पटनायक की स्मृति में बना है। कुछ साल पहले इसके उद्घाटन कार्यक्रम में भी शामिल हुआ था। इस कार्यक्रम में चुनाव विश्लेषक व स्वराज इंडिया के योगेन्द्र यादव, समाजवादी शिवानंद तिवारी जैसी हस्तियां शरीक हुईं थी।

इस नए कार्यालय के पूर्व में इसी नाम से दो-ढाई किलोमीटर दूर कच्चा खपरैल वाला कच्चा भवन था। समाजवादी चिंतक किशन पटनायक ने बरसों उसी कार्यालय में रहकर काम किया है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण, लेखन, और कई आंदोलनों का नेतृत्व किया है। मैं पुराने समता भवन में भी किशन जी, लिंगराज भाई से कई बार मिलने आया हूं और उससे मेरी बरसों पुरानी स्मृति जुड़ी हुई हैं।

आगे बढ़ने से पहले सोच रहा हूं किशन जी (किशन पटनायक) के बारे में कुछ बताऊं। लेकिन क्या, सिर्फ उनका औपचारिक परिचय दूं। जैसे वे साल 1962 में बहुत ही कम उम्र में सांसद बन गए थे। वे लोकसभा में सबसे युवा सांसद थे। लोहिया के साथी थे, हालांकि वे उनके लेखों व व्याख्यानों में लोहिया का नाम भी नहीं लेते थे। क्योंकि लोहिया की बातों को अपने ढंग से, अपने शब्दों में कहते थे।

साथ ही यह भी बताऊं कि किशन जी का आपातकाल के बाद कुछ बरसों में मुख्यधारा की राजनीति से मोहभंग हो गया तो उन्होंने वैकल्पिक राजनीति खड़ी करने की कोशिश की। पहले उनके साथियों व युवाओं के साथ मिलकर समता संगठन बनाया, फिर जन आंदोलन समन्वय समिति बनाई और बाद में समाजवादी जनपरिषद की स्थापना की। समाजवादी जन परिषद, एक पंजीकृत राजनैतिक दल है, भले ही इसे चुनावी सफलता नहीं मिली, लेकिन कई जन आंदोलन किए, जल, जंगल, जमीन, खदान, किसान, मजदूर, आदिवासियों की लड़ाई लड़ी। जन आंदोलनों का राष्ट्रीय समन्वय (एनएपीएम) के गठन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

किशन जी, सदैव ही उनके मौलिक लेखन और यशस्वी व्याख्यानों से जनसाधारण को चेतनशील बनाने का काम करते रहे। वे मानते थे कि नई राजनीति खड़ी करने के लिए जनसाधारण को ही आगे आना होगा। वे उनके आखिरी समय तक सामयिक वार्ता नामक मासिक पत्रिका के संपादक रहे, इसके माध्यम से कई बहसें, संवाद चलाए, नया नजरिया दिया, जटिल मुद्दों को सरल ढंग से समझाया। उनकी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित बेस्ट सेलर पुस्तक विकल्पहीन नहीं है दुनिया बहुचर्चित रही है। इसके अलावा, किसान आंदोलन-दशा और दिशा, भारतीय राजनीति पर एक दृष्टि भी राजकमल प्रकाशन से प्रकाशित हुई हैं। भारत शूद्रों का होगा, उनकी एक और महत्वपूर्ण पुस्तक है। इसके अलावा, उनके लेखों के संग्रह की कुछ किताबें और प्रकाशित हुई हैं।

किशन जी .युवा कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने में विशेष रूचि लेते थे। देशभर में जहां भी उन्हे संभावनाशील युवा मिले, उनसे लगातार संवाद, संपर्क व उनका राजनैतिक प्रशिक्षण जीवन भर करते रहे। इसी कड़ी में मध्यप्रदेश के इटारसी व पिपरिया के युवा भी किशन जी व समाजवादी विचारधारा होकर समता संगठन से जुड़ गए थे। देश भर में कई जगह उनके प्रभाव से युवा आकर्षित हुए थे।

लेकिन यह सब परिचय अधूरे से हैं, वे समतामूलक धारा और देशज समाजवाद के बीच सेतु थे। किशन जी मौलिक चिंतकों में से एक थे, जिन्होंने देश-दुनिया की समस्याओं पर गहरा चिंतन, विश्लेषण, नजरिया और व्याख्या प्रस्तुत की। वे वैकल्पिक राजनीति के सूत्रधार थे। उनका मानना था कि जन आंदोलन के गर्भ से विकल्प की राजनीति खड़ी की जा सकती है।

सामाजिक कार्यकर्ता व समाजवादी विचारक लिंगराज बताते हैं कि समता भवन की परिकल्पना किशन जी ने की थी, जब साल 1980 में समता संगठन का गठन हुआ और उन्होंने बरगढ़ में ज्यादा समय रहना शुरू किया, तो समता भवन को इसका केन्द्र बनाया गया। उन्हीं दिनों पश्चिम ओडिशा में उस समय गंदमार्दन आंदोलन, खदान विरोधी आंदोलन चल रहे थे, उन सबका केन्द्र समता भवन ही हुआ करता था।

यह सिलसिला बाद में भी चलता रहा। चाहे स्थानीय स्तर पर वह नियमगिरी की लड़ाई हो या काशीपुर की, या फिर राष्ट्रीय स्तर किसान संगठन में सक्रिय होने की बात हो या कृषि के तीन काले कानूनों की लड़ाई हो, सभी में समता भवन में न केवल चर्चा होती थी, बल्कि यहां के कार्यकर्ताओं ने बढ़-चढ़कर इनमें हिस्सा भी लिया।

समता भवन, रचनात्मक गतिविधियों का भी केन्द्र रहा है। प्राकृतिक खेती उनमें से एक है। जीरो बजट खेती के प्रणेता सुभाष पालेकर के किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम गांव-गांव में आयोजित किए गए हैं। इससे प्रभावित होकर कई किसान प्राकृतिक खेती के प्रयोग कर रहे है। देसी बीजों को बचाने का काम भी किया जा रहा है।

इसके अलावा, यह भवन सांस्कृतिक आंदोलनों का केन्द्र भी है। यहां गांव के स्थानीय युवाओं को नाटकों और गीतों का प्रशिक्षण देकर जन जागरण का काम किया जाता है। कई सामाजिक व राजनैतिक मुद्दों पर नाटकों का मंचन किए गए है। इसके साथ कई सामाजिक मुद्दों जैसे शराब बंदी, शादी-विवाह में फिजूलखर्ची व तामझाम पर रोक इत्यादि भी नाटकों के मुद्दे रहे हैं।

आंदोलन के साथ जन शिक्षण को भी बहुत महत्व दिया जाता है। यहां से पहले भूमिपुत्र, व किशन जी के बाद वर्ष 2004 के बाद भी विकल्प विचार नामक पत्रिका का प्रकाशन होता रहा।

किशन पटनायक के निधन के बाद उनकी स्मृति में एक ट्रस्ट भी बनाया गया है। इस ट्रस्ट का नाम किशन पटनायक समता ट्रस्ट है। इसके तहत उनके जन्मदिन पर रक्तदान का कार्यक्रम और पुण्यतिथि पर उनकी स्मृति में व्याख्यान का आयोजन किया जाता है। इन व्याख्यानों में देश की जानी-मानी हस्तियां शामिल हो चुकी हैं। इसी माह 27 सितंबर को किशन जी की पुण्यतिथि भी है, जिसकी तैयारी की जा रही है।

इस कार्यालय का कामकाज पूरी तरह चंदा पर आधारित है। गांव से चावल व नगद राशि एकत्र की जाती है और उसी से कार्यक्रम होते हैं। सरकारी व विदेशी धन से संगठन को परहेज है। यह पूरी तरह लोगों के चंदे से ही चलता है, यह बहुत आदर्श स्थिति है।

समता भवन का परिसर हरा-भरा है। यहां फलदार पेड़ व सब्जियां भी लगी हैं। कार्यालय के प्रबंधन में लगे कार्यकर्ता किशोर भाई पेड़-पौधों की देखरेख में काफी समय. लगाते हैं। इस वर्ष पके जामुन भी कार्यकर्ताओं को खाने मिले। अभी अमरूद खा रहे हैं। इसके अलावा, नींबू, सहजन इत्यादि भी हैं।

आमतौर पर हम देखते हैं कि सार्वजनिक कामों में श्रम की अवहेलना की जाती है, लेकिन समता भवन में इसे प्रमुखता दी जाती है। सादगीपूर्ण और तामझामरहित जीवनशैली यहां की विशेषता है।

कुल मिलाकर, यह भवन सिर्फ ईंट-गारे सीमेंट से ही नहीं बना है, बल्कि इसमें किसान, मजदूर और जनसाधारण के खून-पसीने की गाढ़ी कमाई लगी है। यहां भेदभावरहित और बराबरी का माहौल है। यहां का माहौल पिरामिडनुमा नहीं है, बल्कि खुला और लोकतांत्रिक ढांचा है।

यहां कार्यकर्ता बनाना, किसान संगठन का संचालन करना, आंदोलनों का मार्गदर्शन करना, उन्हें ताकत देना,विकल्प विचारों का निर्माण करना, सांस्कृतिक आंदोलन से जनचेतना जगाना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना, सादगीपूर्ण और प्रकृति से समन्वय की जीवनशैली जीने को प्रेरित करना इत्यादि काम प्रमुख हैं। यानी समता भवन बहुत ही प्रेरणादायक है, जो संघर्ष और रचना के कई महत्वपूर्ण कामों की विरासत संजोए हुए है, जो प्रेरणादायी है।

यहां कार्यकर्ता बनाना, किसान संगठन का संचालन करना, आंदोलनों का मार्गदर्शन करना, उन्हें ताकत देना,विकल्प विचारों का निर्माण करना, सांस्कृतिक आंदोलन से जनचेतना जगाना, प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना, सादगीपूर्ण और प्रकृति से समन्वय की जीवनशैली जीने को प्रेरित करना इत्यादि काम प्रमुख हैं। यानी समता भवन बहुत ही प्रेरणादायकहै, जो संघर्ष और रचना के कई महत्वपूर्ण कामों की विरासत संजोए हुए है, जो प्रेरणादायी है।

बीता सप्ताह

30 अगस्त
- भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी अभिषेक शुक्ला सर्बिया के नए राजदूत नियुक्त हुए है।
- भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के मंगल पर उतरने और इंसानों को बसाने की तैयारी वाली योजनाएं बनाना शुरू कर दी है।
- छग मुख्यमंत्री विष्णु देव साय लोकप्रियता के मामले में एमओटीएन सर्वे के अनुसार दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने।
- इजरायली हमले में हूती प्रधानमंत्री अहमद अल-रहवी की मौत हो गई।

31 अगस्त
- सात साल शंघाई सहयोग संगठन में भाग लेने चीन पहुंचे पीएम नरेन्द्र मोदी।
- अमेरिका की एक अपील अमलित ने ट्रंप के टैरिफ को अवैध असंवैधानिक करार दिया।
- जम्मू कश्मीर का मशहूर आतंकी बाबू खन मारा गया।
- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 1993-1998 तक विधायकी की पेंशन के लिए आवेदन किया।

1 सितम्बर
- एशिया का सर्वोच्च सम्मान मैग्सेसे अवार्ड भारती की प्रमुख सामाजिक संस्था एजुकेट गर्ल्स को 2025 को मिला है।
- अमेरिका के लिए सभी डाक सेवाएं आज एक सितम्बर से निलंबित कर दी गई।
- देश में एक सितम्बर से ही लागू हो गई सिल्वर हॉलमार्किंग।
- चीन के सर्जनों ने पहली बार सुअर के फेफड़े को एक मृत मस्तिष्क वाले मानव में किया प्रत्यारोपित।

2 सितम्बर
- अफगानिस्तान में भूकंप से तबाही से 800 सौ अधिक मौत हो गई।
- चीन में शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद पर दोहरा मापदंड नहीं चलेगा।
- पीओके में पाक सेना का हेलीकाप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने से पांच लोगों की मौत हो गई।
- पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनगड़ ने आवास छोड़ा।

3 सितम्बर
- अफगानिस्तन में भूकंप से 1411 लोगों की मौत हो गई।
- महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण को लेकर अनशनकारी मनोज जटांगे की मांग स्वीकार कर ली।
- इसरो की सेमीकंडक्टर प्रशेगशाला में की गई तैयार पहली स्वदेशी 32 बीट चिप विक्रम हुई देश।
- मुंगबई की तरह पटना में शुरू हुई डबल डेकर बस सेवा।

4 सितम्बर
- केन्द्र सकार ने जीएसटी के दो स्लैब कम कर दिए। अब 5 और 12 फीसदी की स्लैब रहेगी जो 22 सितम्बर से लागू होगी।
- गुजरात सूरत के कतारगाम इलाके में स्थित गणेश प्रतिमा ट्री गणेश को एशिया बुक ऑफ रिकार्डस में मान्यता दी गई।
- केन्द्र सरकार ने अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए अल्पसंख्यकों को राहत दी। अब 2024 तक आए अल्पसंख्यक भारत में रह सकते है।
- भारतीय नौसेना का स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिक्रड-1 सैन्य अभ्यास में शामिल होगा।

5 सितम्बर
- बर्खास्तगी के विरोध में एनएचएम कर्मचारियों ने प्रदेश भर में सौंपा सामूहिक इस्तीफा।
- भाजपा कार्यकर्ताओं की गुंडई पर भड़के लालू कहा बिहारियों को इतने इल्के में ना लें गुजराती।
- आतंकवादी के खिलाफ एकजुटता से लड़ना सभी मानवतावादी देशों का कर्तव्य।
- नीतीश ने सारण में 1203.81 करोड़ रूपए लागत की 27 योजनाओं का किया शिलान्यास।

असहिष्णुता है, 'टैरिफ युद्ध' की वजह

■ **रमाकांत नाथ**

द्वितीय विश्वयुद्ध' के बाद से जारी 'शीतयुद्ध' की समाप्ति ने अमेरिका को विश्व की एकमात्र शक्ति बना दिया था। दुनिया के लगभग सभी देश अमेरिका के इर्द-गिर्द प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे थे। इस अवसर का लाभ उठाकर अमेरिका ने अपने पूंजी बाजार का विस्तार और पूरी दुनिया में पूंजीवाद को सक्रिय करने का प्रयास किया।

अमेरिका के उकसावे पर 'विश्व व्यापार संगठन' (डब्ल्यूटीओ) ने दुनियाभर में व्यापार का विस्तार करके अमेरिकी पूंजी बाजार को अप्रत्यक्ष रूप से मजबूत करने का असफल प्रयास किया था। व्यापार के आधार पर दुनिया के बंट जाने से अमेरिका के हितों को भारी नुकसान पहुंचा। 'शीतयुद्ध' में सोवियत संघ अमेरिका के प्रतिद्वंद्वी के रूप में उभरा था, लेकिन बाद में रूस, चीन और जापान जैसी महाशक्तियां अमेरिका के सामने आईं। भारत, इजरायल और ब्राजील भी विकासशील देशों की सूची से उठकर विकसित देशों की दौड़ में शामिल हो गए। ऐसे में अमेरिका का नेतृत्व दुनिया में काफी हद तक अप्रभावी होता गया।

इसी तरह पाकिस्तान और उत्तर कोरिया के बाद ईरान को परमाणु शक्ति-संपन्न देशों की सूची में शामिल करने से अमेरिका का प्रभाव दिन-प्रतिदिन कम होता जा रहा है। जब व्यापार ने दुनिया को कई क्षेत्रों में बांट दिया है और इसके कारण अमेरिकी पूंजी बाजार को व्यापक नुकसान पहुंच रहा है, तब अमेरिका असहिष्णु हो गया है। इसी असहिष्णुता के परिणामस्वरूप अमेरिका ने अपने आयातों को लेकर पूरी दुनिया को फिर से एक क्षेत्र में बदलने की कोशिश शुरू कर दी है।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जहां दुनिया के कई देशों पर 'व्यापार कर' (टैरिफ) बढ़ाकर उनकी अर्थव्यवस्था को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके अमेरिका को फिर से दुनिया का नंबर एक देश बनाने का सपना देख रहे हैं। इसी वजह से वे 'अमेरिका को फिर से महान बनाओ' (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, 'मागा') का आह्वान कर रहे हैं।

आज व्यापार पूरी दुनिया के देशों, उनकी अर्थव्यवस्थाओं और करोड़ों लोगों को नियंत्रित कर रहा है। देशों के बीच व्यापार आधारित असहिष्णुता फैल रही है। विशेष रूप से अमेरिका इस असहिष्णुता का शिकार हुआ है और इसके परिणामस्वरूप विश्व में एक नया युद्ध शुरू हो गया है, जिसे कई लोग 'टैरिफ युद्ध' या 'व्यापार युद्ध' का नाम दे रहे हैं।

डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में अपने पहले कार्यकाल में 2018 से 2021 के बीच कुछ क्षेत्रों में टैक्स लगाए थे। अपने दूसरे कार्यकाल में ट्रंप 2025 से व्यापार-करों पर अधिक ध्यान दे रहे हैं और अमेरिका को फिर से दुनिया में सर्वश्रेष्ठ बनाने, अमेरिकी सीमा की सुरक्षा, कनाडा और मेक्सिको के साथ संघर्ष को समाप्त करने, विश्व में शांति और स्थिरता बनाए रखने, परमाणु युद्ध की भयावहता से बचने आदि की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए वे 'कर-युद्ध' फांद रहे हैं; लेकिन इसका कारण वह नहीं है जो कहा या प्रकाशित किया जा रहा है।

इस युद्ध का मुख्य कारण असहिष्णुता है। इसी वजह से अमेरिका की पहल पर दुनिया एक 'व्यापार युद्ध' में प्रवेश कर गई है। ट्रंप को अपने पहले कार्यकाल के दौरान चीन पर 20 प्रतिशत 'व्यापार शुल्क' लगाने के लिए आलोचना का सामना भी करना पड़ा था, जिससे अमेरिका में 60 प्रतिशत चीनी आयात प्रभावित हुए थे और अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचा था। मई 2019 में ट्रम्प ने पड़ोसी मेक्सिको पर 25 प्रतिशत 'व्यापार शुल्क' लगाने की धमकी दी थी, जिससे मेक्सिको को अमेरिकी आधीनता स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा।

सन् 2020 में ट्रंप प्रशासन ने कनाडा और मेक्सिको के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसे 'अमेरिका-मेक्सिको-कनाडा समझौता' कहा जाता है, जिसने इन देशों के बीच व्यापार पर टैरिफ को समाप्त कर दिया। इस समझौते के छह महीने बाद ट्रंप प्रशासन ने कनाडा से एल्युमीनियम आयात पर 10 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया, जिसे कनाडा के विरोध के बाद वापस ले लिया गया। ट्रंप का पहला कार्यकाल विवादास्पद था और वे उससे सीखने में विफल रहे। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की दुनिया भर में अमेरिकी 'व्यापार टैरिफ' का विस्तार करने के लिए आलोचना हुई। उसने दुनिया को एक और आर्थिक मंदी में धकेल दिया।

भारत पर अधिकतम 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका ने दुनिया के लगभग 67 देशों पर 'व्यापार टैरिफ' लगाया है। 'व्यापार शुल्कों' में यह वृद्धि और कमी भारत के विरुद्ध एक सुनियोजित लेन-देन के रूप में देखी जा सकती है। स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत पर अमेरिकी 'व्यापार शुल्कों' का प्रभाव बहुत बड़ा होगा और इसका असर शुरू भी हो चुका है। भारत के पास अतिरिक्त कर वृद्धि से बचने का एक अवसर था, लेकिन भारत सरकार ने ट्रंप प्रशासन से इस पर चर्चा नहीं की। परिणामस्वरूप अमेरिका को भारत का वार्षिक निर्यात, जो 48 मिलियन डॉलर का है, सीधे प्रभावित होगा। 'ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव' ने कहा है कि भारत से अमेरिका को होने वाले निर्यात पर 66 प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा। इसका असर वस्त्र, परिधान, आभूषण, पशुओं की खाल, जूते, पशु उत्पाद आदि के निर्यात पर पड़ेगा।

भारत पर अधिकतम 50 प्रतिशत टैरिफ लगाने के अलावा अमेरिका ने दुनिया के लगभग 67 देशों पर `व्यापार टैरिफ´ लगाया है। `व्यापार शुल्कों´ में यह वृद्धि और कमी भारत के विरुद्ध एक सुनियोजित लेन-देन के रूप में देखी जा सकती है। स्पष्ट है, डोनाल्ड ट्रंप भारत को आर्थिक रूप से कमजोर करने का काम कर रहे हैं। भारत पर अमेरिकी `व्यापार शुल्कों´ का प्रभाव बहुत बड़ा होगा

भारत को असली नुकसान उसके पड़ोसी देशों से होगा। अमेरिका ने भारत के पड़ोसियों और अन्य एशियाई देशों जैसे चीन, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम जैसे देशों पर बहुत कम 'व्यापार कर' लगाए हैं। उन देशों का सामान अमेरिकी बाजार में सस्ता होगा और नतीजे में ये पड़ौसी देश भारत से ज़्यादा समृद्ध होंगे। अमेरिका ने भारत में निर्मित इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं, दवाओं और ऊर्जा उत्पादों पर कर नहीं लगाया है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में भारत में बेरोजगारी निश्चित है। ऐसे में भारत के पास यूरोप, दक्षिण पूर्व एशिया, मध्य पूर्व के देशों और अफ्रीकी देशों में अपने व्यापार का विस्तार करने का एक विकल्प है। भारत अमेरिकी आयात पर 'व्यापार कर' बढ़ा सकता है।

'अबकी बार (की) ट्रम्प सरकार' भारतीयों को युद्धबंदी बनाकर हाथ-पैर में हथकड़ी-बेडी लगाकर वापस भेजने, 'ऑपरेशन सिंदूर' को समाप्त करने, विश्व मंच पर भारत को कई बार अपमानजनक परिस्थितियों में डालने और भारत को नुकसान पहुंचाने के अनगिनत प्रयासों के काम कर रही है। अमेरिका के अपराधियों में से एक भारतीय 'साहूकार' को बचाने की कोशिश में 140 करोड़ लोगों को असहनीय पीड़ा में धकेला जा रहा है। यह 'साहूकार प्रेम' और अमेरिका की असहिष्णुता के कारण करोड़ों भारतीयों को युद्ध के परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं।

(लेखकओडिशा के वरिष्ठ पत्रकार एवं स्तंभकार हैं।)

एससीओ सम्मेलनःचीन ने अमेरिका को दिखाई ताकत

■ **डॉ. श्रीकांत कोंडापल्ली**

चीन ने शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के 25वें शिखर सम्मेलन के लिए भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सहित 20 से अधिक विश्व नेताओं को आमंत्रित कर बंदरगाह शहर तियानजिन में शानदार प्रदर्शन किया।

यह चीन की 'संयुक्त मोर्चा' रणनीति के लिए महत्वपूर्ण है कि वह अमेरिका के खिलाफ एक सुरक्षित एन्क्लेव तथा बचाव का निर्माण करे और एशिया व विश्व में उससे आगे अपनी स्थिति को मजबूत करते हुए एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था को बढ़ावा दे जो राष्ट्रपति शी जिनपिंग के प्रतीकात्मक विचार 'फेनफा यूवेई' (कुछ हासिल करें) के अनुरूप हो।

सम्मेलन के प्रतिभागियों ने भी तियानजिन से बहुत कुछ पाया है। उदाहरण के लिए व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेनी संघर्ष व अमेरिका तथा यूरोप के रूस के खिलाफ प्रतिबंध जैसे अत्यधिक दबाव को सह लिया है। एससीओ सभा रूस की शर्तों पर वैश्विक अलगाव को दूर करने के तरीके प्रदान करती है।

तियानजिन शिखर सम्मेलन में मोदी-पुतिन-शी की तस्वीर अमेरिका के भारत के प्रति लगातार बढ़ते अपमान और शुल्क का कड़ा जवाब है। इसके अलावा मोदी न केवल पश्चिम को रणनीतिक स्वायत्तता के संकेत भेजने में सक्षम थे बल्कि जून 2020 में गलवान में खूनी संघर्ष के बाद असहज हो गए चीन-भारत के संबंधों में स्थिरता लाने में भी सक्षम रहे।

भारत एससीओ में 2005 में पर्यवेक्षक बना था। उसने 2014 में पूर्ण सदस्यता के लिए आवेदन किया और अंततः 37 करारों पर हस्ताक्षर करने के बाद 2017 में पूर्ण सदस्य बना। वर्ष 2023 में भारत एससीओ शिखर सम्मेलन का अध्यक्ष भी बना। उस समय भारत ने एससीओ के राष्ट्राध्यक्षों की एक आभासी बैठक आयोजित की थी।

नई दिल्ली शिखर सम्मेलन में भारत ने आधिकारिक संरचनाओं पर ध्यान केंद्रित करने के साथ ही स्टार्ट-अप, नवाचार, बौद्ध धर्म जैसे अन्य क्षेत्रों पर ध्यान आकर्षित करके एक अलग एजेंडा पेश किया। इस एजेंडा को मोदी ने तियानजिन शिखर बैठक में भी दोहराया।

तियानजिन ने एससीओ शिखर सम्मेलन के अधिकांश प्रतिभागियों के लिए अपनी एकजुटता और पुनःसमायोजन का संकेत दिया है जो विशेष रूप से अब वैश्विक और क्षेत्रीय प्रणाली की लगातार बदलती स्थिति को दर्शाती है। बैंड वैगनिंग, यूरेशियन एकीकरण, उनकी ढांचागत और अन्य जरूरतों के लिए वित्त विकल्प हासिल करना व पड़ोसी देशों में व्यापक स्थिरता के मौकों ने रुचि पैदा की है।

उदाहरण के लिए तियानजिन शिखर सम्मेलन में एससीओ विकास बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। चीन ने ऋण में 10 अरब युआन के अलावा सदस्य देशों को 28 करोड़ डॉलर की सहायता की घोषणा की। ब्रिक्स नव विकास बैंक की तरह ही इससे न केवल क्षेत्रीय बुनियादी ढांचे के निर्माण में योगदान करने की उम्मीद है बल्कि सदस्य राज्यों की पश्चिम तथा अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को भी काफी हद तक कम करने की उम्मीद है।

यह महत्वपूर्ण है क्योंकि ब्रेटन वुड्स सिस्टम और संस्थान के तहत आने वाली मौद्रिक प्रणाली ग्लोबल साउथ देशों की बढ़ती आवश्यकताओं और ढांचागत जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ रही है। ऐसा तब है जब कई चीनी-वित्त पोषित परियोजनाएं कर्ज के जाल में फांसने के विवाद में घिर गई हैं।

एससीओ प्रोफाइल अपने आप में प्रभावशाली है। 1996 में केवल पांच देश इसका हिस्सा थे लेकिन 2001 के बाद से यह मध्य एशिया, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया को कवर करते हुए सबसे बड़ा क्षेत्रीय अंतर-सरकारी संगठन बन गया है।

एससीओ वर्तमान में 10 सदस्य देशों, 2 पर्यवेक्षक राज्यों और 14 संवाद भागीदारों तक विस्तारित हो गया है। इसमें वैश्विक आबादी का लगभग 44 प्रतिशत और दुनिया की जीडीपी का एक चौथाई (लगभग 30 लाख करोड़ डॉलर) शामिल है।

एससीओ को सीमावर्ती क्षेत्रों में क्षेत्रीय विवाद समाधान और असैन्यीकरण के लिए जाना जाता है। 1990 के दशक में समझौतों और विश्वास निर्माण उपायों की घोषणा की गई और सीमाओं को समेकित किया गया। ताजिकिस्तान तथा किर्गिस्तान के बीच अंतर-राज्य संघर्ष जैसी कुछ घटनाओं के बावजूद यूरेशियन क्षेत्र शांति प्रदर्शित करता है।

आतंकवाद का मुकाबला करने पर एससीओ का ध्यान है और वह क्षेत्रीय विषयों पर भी नजर रख रहा है। इसने 2002 में क्षेत्रीय आतंकवाद-रोधी संरचना (आरएटीएस) की स्थापना की जिसका मुख्यालय 2022 तक ताशकंद में था लेकिन अब मास्को में स्थानांतरित हो गया। भले ही आतंकी संगठनों से निपटने के बारे में गंभीर विरोधाभास व दोहरे मानदंड मौजूद हों लेकिन आरएटीएस आतंकवादियों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों और अर्धसैनिक अभ्यासों से संबंधित डेटा एकत्र करने में एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय संगठन के रूप में उभर रहा है।

एससीओ सदस्य देशों की भागीदारी, डेटा बेस, आतंकवादी समूहों के खिलाफ जानकारी साझा करने, मादक पदार्थों की तस्करी, हथियारों की तस्करी एवं अन्य मामलों के साथ शांति मिशन अभ्यास जैसे संयुक्त अभ्यासों का आयोजन धीरे-धीरे इसे एक व्यवहार्य विकल्प के रूप में विकसित कर रहा है।

1998 में अपनी नई दिल्ली यात्रा के दौरान जब रूसी प्रधानमंत्री येवगेनी प्रिमाकोव ने बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था के निर्माण का उल्लेख किया था उस समय से ही एससीओ अमेरिका की एकतरफा नीतियों का दृढ़ता से मुकाबला कर रहा है। 2005 में अपनी शिखर बैठक में एससीओ ने कहा था कि अमेरिका मध्य एशिया से सैनिकों को वापस लेने के लिए एक समय सारिणी बनाए।

अफगानिस्तान में अपने सैनिकों की मौजूदगी और अमेरिका की तमाम कोशिशों के बावजूद यूरेशियन क्षेत्र काफी हद तक अमेरिकी प्रभाव की सीमा से बाहर रहा। ट्रम्प प्रशासन द्वारा हाल ही में पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर के साथ चर्चा व मध्य एशिया तथा दक्षिण एशिया के अतिरिक्त कार्यों के साथ भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में सर्जियो गोर की नियुक्ति यूरेशियन क्षेत्र में प्रवेश करने के प्रयास हैं।

भले ही ट्रम्प प्रशासन ऊर्जा के क्षेत्र में ऐसे कनेक्शनों को, विशेष रूप से भारत से जुड़े कनेक्शन को निशाना बना रहा है। इसके बावजूद 2013 में स्थापित एससीओ एनर्जी क्लब,ऊर्जा के सबसे बड़े उत्पादकों (रूस, कजाकिस्तान, ईरान व कुछ अन्य) तथा ऊर्जा उपभोक्ताओं (चीन, भारत एवं अन्य) के रूप में एक अद्वितीय और उपयोगी संयोजन प्रदान करता है।

तियानजिन में सार्वजनिक सौहार्द्र के प्रदर्शन के बावजूद एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के सामंजस्य को लेकर प्रमुख मतभेद हैं। कुछ सदस्य देश मामूली झड़पों, व्यापार बाधाओं या असंतुलन, प्रमुख शक्तियों के साथ समीकरणों और आतंकवाद का मुकाबला करने या संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे मुद्दों पर दोहरे मानकों के साथ एससीओ में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इनमें से कुछ मुद्दों का जिक्र किया।

तियानजिन में सार्वजनिक सौहार्द्र के प्रदर्शन के बावजूद एससीओ सदस्य देशों के राष्ट्रीय हितों के सामंजस्य को लेकर प्रमुख मतभेद हैं। कुछ सदस्य देश मामूली झड़पों, व्यापार बाधाओं या असंतुलन, प्रमुख शक्तियों के साथ समीकरणों और आतंकवाद का मुकाबला करने या संप्रभुता तथा क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा जैसे मुद्दों पर दोहरे मानकों के साथ एससीओ में प्रवेश कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में इनमें से कुछ मुद्दों का जिक्र किया।

एससीओ आम सहमति के आधार पर काम करने वाला संगठन है लेकिन वास्तव में चीन और रूस संगठनात्मक मुद्दों के साथ-साथ एजेंडा सेटिंग में भी महत्वपूर्ण निर्णय ले रहे हैं। इसका परिणाम शक्ति समीकरणों का तीव्र संतुलन या सदस्य राज्यों के बीच तीव्र अंतर भी होता है। यदि मुद्दों का समाधान नहीं किया जाता है तो यह संघर्ष का कारण बन सकता है।

(लेखक जेएनयू में चाईनीज़ स्टडी के प्रोफेसर हैं। सिंडिकेटः द बिलियन प्रेस)

प्रकाशक, मुद्रक : राजीव रंजन श्रीवास्तव द्वारा पत्रकार प्रकाशन प्रा. लि. के लिए 506, आई.एन.एस. बिल्डिंग, 9, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित एवं बीएफएल इंफोटेक लि., सी 9, सेक्टर-3, नोएडा से मुद्रित। सम्पादक : राजीव रंजन श्रीवास्तव, (पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए जिम्मेदार)। आर.एन.आई. नं. DELHIN/2008/24216. दिल्ली कार्यालय :फोन: 011-23718195,23357784, फैक्स: 011-43581404, नोएडा कार्यालय: फोन: 0120-4114404 फैक्स: 0120-4273770
ई-मेल: deshbandhudelhi@gmail.com वेब: www.deshbandhu.co.in

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

चिंतन

भारत-अमेरिका संबंधों को क्यों झकझोर रहे ट्रंप

लगता है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को धीरे-धीरे सही, भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगाकर गलती का अहसास होने लगा है। तभी तो वो कह रहे हैं कि लगता है कि हमने रूस और भारत को चीन के हाथों खो दिया। हालांकि उन्होंने यह बात व्यंग्य के रूप में ट्रुथ सोशल पर लिखी। साथ ही उन्होंने एससीओ समिट की तस्वीर शेयर करते हुए संकेत दिया है कि रूस और भारत के चीन की तरफ जाने को वह अमेरिका के साथ रिश्ते खत्म करने की तरह देख रहे हैं। ट्रंप के इन शब्दों से लगता है कि उन्हें अंदर खाते यह अहसास होने लगा है कि उनकी सनक के कारण भारत से अमेरिकी संबंध सरातल में पहुंच गए हैं। एक के बाद एक भारत को झटके देने वाले ट्रंप अब खुद तरह-तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव को रोकने का बार-बार किया गया विवादास्पद दावा हो, पहलगाम आतंकी हमले में पाकिस्तान का हाथ होने के कारण सैन्य टकराव को भड़काने की बात हो, पाकिस्तानी सेना प्रमुख को दोपहर के भोजन पर आमंत्रित करना हो या रूस के साथ भारत के वैध संबंधों के लिए उसे दंडित करना हो। वो हमेशा अपनी सनक पर ही चलते रहे। असल में अमेरिकी राष्ट्रपति स्थापित परंपराओं के अनुसार चलने की परवाह नहीं करते। ऐतिहासिक मिसालें या परंपराएं ट्रंप के लिए कोई मायने नहीं रखती, जो अक्सर राजनीति को निजी सनक और लाभ के साथ जोड़ देते हैं। डोनाल्ड ट्रंप कभी भारतीय अर्थव्यवस्था को मृत बताकर तो कभी टैरिफ पर टैरिफ लगाकर भारत पर व्यापारिक समझौते के लिए दबाव बनाने की कोशिश करते रहे। भारत झुकने को तैयार नहीं हुआ तो एक के बाद एक दो बार में 50 फीसदी टैरिफ लगाकर दबाने का प्रयास किया। असल में ट्रंप अमेरिका में उत्पादन बढ़ाने का दावा भी करते हैं। कभी वो एप्पल के सीईओ को धमकाते हैं तो कभी एआई कंपनी से अमेरिकी सरकार के नाम शेयर करवाते हैं। ट्रंप एक कारोबारी हैं और फिर भी यह समझने को तैयार नहीं कि यदि पिछले वर्षों में अमेरिका के कारखाने अन्यत्र स्थानांतरित हो गए तो उसका कारण अमेरिका में श्रम का महंगा होना था। खुद अमेरिकी कारोबारी ज्यादा मुनाफे के लिए अपने कारखाने अन्य देशों में ले गए। इससे अमेरिका के लोगों को सस्ता सामान मिलने लगा। भले ही ट्रंप यह मानकर चल रहे हों कि अब वे सब कारखाने अमेरिका आ आएंगे, लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। कारखाने रातोंरात नहीं लगते और यदि कुछ छोटे कारखाने लग भी जाएं तो महंगे श्रम के कारण उनमें तैयार वस्तुएं अन्य देशों में उत्पादित वस्तुओं के मुकाबले महंगी होंगी। आखिर जो सामान विश्व के अन्य देशों में सस्ते में बन सकता है, उसे अमेरिका में महंगा बनाकर वहां के कारोबारी क्या हासिल कर लेंगे। पता नहीं किस अर्थशास्त्री ने ट्रंप को यह समझाया कि वह टैरिफ बढ़ाकर राजकोषीय घाटा कम कर लेंगे। राजकोषीय घाटा इस तरह कम नहीं होता और न ही अंतरराष्ट्रीय व्यापार एक-दूसरे पर समान टैरिफ के आधार पर होता है। कारखानों में तैयार वस्तुओं की लागत के पीछे अनेक कारण होते हैं, लेकिन ट्रंप की सनक है कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही। एक दिन पहले ही अमेरिकी कोर्ट में ट्रंप प्रशासन ने दावा कर दिया कि भारत समेत दुनिया भर के देशों में लगाए गए टैरिफ बहुत जरूरी हैं। लगता है ट्रंप और उनके सलाहकार यह सब समझने को तैयार नहीं हैं कि टैरिफ से सबसे ज्यादा नुकसान अमेरिका का ही होगा।

विवादित बयान
प्रमोद भार्गव

तेल खरीद में जातीय विभाजन की आग

> अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो जातीय वैमनस्य की चिंगारी भड़काने की कोशिश में हैं। उन्होंने रूस से तेल आयात पर निशाना साधते हुए कहा कि 'ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कमा रहे हैं।' दरअसल एससीओ का तियानजिन में एकत्रीकरण ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दबाव का ऐसा प्रभावी संकेत है, जो न केवल अमेरिका, बल्कि जी-7 और यूरोप की आर्थिक शक्ति को भी संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। वर्तमान में भारत में निरंतर जातीय समन्वय बढ़ रहा है। अतएव अब वे किसी परदेसी के बचकाने बयान के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

धर्म और जाति भारत की कमजोर कड़ियां रही हैं। इसकी शुरुआत फिरंगी हुकूमत ने भारत में धर्म के आधार पर बंगाल के विभाजन के साथ की थी, जो कालांतर में अंग्रेजों की कुटिल चाल के परिणाम में भारत विभाजन का मुख्य आधार बनी। अब अमेरिका के भारत विरोधी वाचाल व्यापारी पीटर नवारो एक बार फिर इसी नुस्खे को तूल देकर जातीय वैमनस्य की चिंगारी भड़काने की कोशिश में हैं।

भारत पर लगाए 50 प्रतिशत टैरिफ को लेकर अमेरिका से असंतुष्ट देशों में खासतौर से रूस, भारत, चीन अर्थात आरआईसी ट्राइका शंघाई सहयोग संगठन के सम्मेलन में मजबूती से खड़ा होता दिखा। इससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद हराम हो गई। नतीजतन इसी परिप्रेक्ष्य में ट्रंप के आधिकारिक व्यापारिक सलाहकार पीटर नवारो ने रूस से तेल आयात पर निशाना साधते हुए कहा कि 'ब्राह्मण भारतीय जनता की कीमत पर मुनाफाखोरी कमा रहे हैं।' दरअसल एससीओ का तियानजिन में एकत्रीकरण ट्रंप के टैरिफ के विरुद्ध अंतरराष्ट्रीय दबाव का ऐसा प्रभावी संकेत है, जो न केवल अमेरिका, बल्कि जी-7 और यूरोप की आर्थिक शक्ति को भी संतुलित करने की दिशा में आगे बढ़ने का संकेत दे रहा है। नवारो ने एक साक्षात्कार में कहा कि 'देखिए, नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के महान नेता हैं, लेकिन वे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ खड़े हैं। मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता समझे कि यह क्या हो रहा है। आपके पास जो ब्राह्मण हैं, वे भारतीय लोगों की कीमत पर मुनाफाखोरी कर रहे हैं। हमें इसे रोकने की जरूरत है। यानी पूंजीपति देश का एक उद्योगपति भारत की जनता को बताएगा कि वह क्या करे? मसलन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता नासमझ है। देश की वह जनता नादान है, जिसने आपातकाल में तानाशाह के रूप में पेश इंदिरा गांधी की सरकार को बदल दिया था? इंदिरा गांधी की हत्या के बाद भारी बहुमत से जीते राजीव गांधी की सत्ता को इसलिए बेदखल कर दिया था, क्योंकि साहबानो प्रकरण को लेकर राजीव गांधी इस्लामी कट्टरवादियों के दबाव में आ गए थे। इसी जनता ने उन मनमोहन सिंह को सत्ताच्युत कर दिया था, जिन्होंने देश के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों को सौंप देने की वकालत शुरू की थी और फिर इसी जनता ने देश की कमान उन नरेंद्र मोदी को सौंप दी थी, जो अपने बाल्यकाल में पिता की मदद के लिए रेल के डिब्बों में चाय बेचा करते थे। इन्हीं मोदी को जागरूक मतदाताओं ने फिर से 2019 में जिताया, क्योंकि सुरक्षा सैनिकों को ले जाने वाले एक वाहन को पुलवामा में आत्मघाती आतंकी हमलावर, सीआरपीएफ के 46 जवानों की शहादत का कारण बना था। इस जघन्य घटना का बदला लेने के लिए मोदी ने बालाकोट में वायुसेना से सीमा पार सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देकर आतंकी समूह जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण शिविरों को जमींदोज कर दिया। 2024 के आम चुनाव में इन्हीं मोदी पर देश देश की

जनता ने फिर विश्वास किया और तीसरी बार सत्ता की कुंजी मोदी को सौंप दी। साफ है, जनता उन विदेशी उपदेशकों के बहकावे में आने वाली नहीं है, जो मोदी पर नाजायज दबाव बनाकर अपने अनैतिक हित साधने के

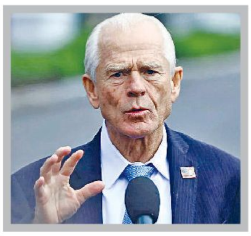

फेर में हैं। दोहरे मापदंड वाले ट्रंप भारत को रूस से तेल खरीदने पर अतिरिक्त शुल्क के रूप में जुर्माना लगा रहे हैं, जबकि भारत, चीन और यूरोपीय देशों की तुलना में कम ईंधन खरीदता है। पीटर नवारो इन देशों के ब्राह्मणों, अर्थात कुलीन वर्ग या कारपोरेट घरानों के लिए क्या कहेंगे ? नवारो भारत के विरुद्ध अनर्गल प्रलापों के लिए जाने जाते हैं। नवारो ने इसके पहले, यूक्रेन संघर्ष को 'मोदी का युद्ध आंशिक रूप से नई दिल्ली होकर गुजरता है' का लांछन लगाया था। इसका सटीक उत्तर पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने यह कहते हुए दिया है कि 'नवारो ने भारत पर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की युद्ध-मशीन को वित्तपोषित करने का आरोप लगाया है, जबकि फरवरी 2022 में रूस के यूक्रेन पर किए हमले के बहुत पहले से पेट्रोलियम उत्पादों का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक देश रहा है। उसी मात्रा में आज भी रूस तेल निर्यात कर रहा है। अर्थात निवारों का बयान भारत, रूस और चीन की एससीओ की बैठक में देखने में आई जुगलबंदी का नतीजा है। चूंकि अब ट्रंप अपने ही देश में बेतुके अड़ियल रुख के कारण घिरते जा रहे हैं। अवाम में नाराजगी बढ़ रही है। अमेरिका के अरबपति रे डेलियो ने तो यहां तक कह दिया कि 'ट्रंप के नेतृत्व में अमेरिका 1930 के दशक जैसी तानाशाही की ओर बढ़ रहा है। निवेशक ट्रंप के डर से चुप हैं। धन एवं मूल्यों की खाई और टूटता भरोसा अमेरिका को चरमपंथी नीतियों की ओर धकेल रहा है।' निवारो का जातिसूचक बयान एक ऐसी साजिश का सूचक है, जो भारत में शहरी नक्सली और वर्णभेदी वामपंथी बीजरूप में आजादी के बाद से ही बोते रहे हैं, जिससे भारत जातीय कुचक्र की आग में जलने लग जाए। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत में जाति की जड़ें आज भी गहरी हैं। लेकिन बीते 75-80 सालों में जनता बौद्धिक-विवेक के रूप में इतनी परिपक्व हो गई है कि वह अब किसी बाहरी व्यक्ति के बहकावे में आने वाली नहीं है। वह जानती है कि भारत में तेल का व्यापार करने वाले जो भी चंद उद्योगपति हैं, उनमें ब्राह्मण कोई नहीं है। यह बयान केवल भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में व्यर्थ हस्तक्षेप और जातिगत विद्वेश भड़काने की निर्लज्ज कोशिश है।

हालांकि यह संभवतः अपवाद है कि किसी परदेशी उद्योगपति के मुख से जातिगत व्यवस्था को भारत सरकार की विदेश नीति से जोड़कर प्रस्तुत किया गया है। नवारो ने जातिसूचक शब्द ब्राह्मण का जो प्रयोग किया है, उसे अभिजात्य या कुलीन वर्ग को लांछित करने के रूप में भी देखा जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा सदस्य सागरिका घोष का कहना है कि बोस्टन ब्राह्मण शब्द अमेरिका में न्यू इंग्लैंड से जाकर बसे धनी वर्ग के लिए प्रयोग में लाया जाता था। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी इस शब्द को एलीट क्लास से जोड़ा है। दरअसल एक समय अमेरिका के बोस्टन में धनी सुशिक्षित प्रोटेस्टेंटों का एक समुदाय था। ये लोग 18वीं और 19वीं सदी में ताकतवर समुदाय थे।

ये अमेरिका के उपनिवेशवादियों के वंशज थे। इन लोगों ने व्यापार में अपने को खफा दिया और सफलता के शिखर छू लिए। अब भारत में शैक्षिक उन्नति, सह-शिक्षा और बहुराष्ट्रीय कंपनियों में पेशेवर युवक-युवतियों की बड़ी संख्या में भागीदारी के चलते अन्तर्जातीय व अन्तर्धार्मिक विवाह आम बात हो गई है। बहुत कुछ जातीय कुचक्र टूट गया है। अलबत्ता यह भी देखने में आ रहा है कि जिस किसी भी वर्ग या जाति के लोग राजनीति, नौकरी या व्यापार में सशक्त होते जा रहे हैं, वे उसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था के अनुगामी बनते जा रहे हैं, जिसे एक एमय वे कोसते रहे हैं। भारत में निरंतर जातीय समन्वय बढ़ रहा है। अतएव अब वे किसी परदेसी के बचकाने बयान के बहकावे में आने वाले नहीं हैं।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)
लेख पर अपनी प्रतिक्रिया haribhoomi@gmail.com पर दे सकते हैं।

सोशल मीडिया
डॉ. मोनिका शर्मा

मनगढ़ंत बातों से सनसनी फैला रहे वीडियो

हाल ही में राजस्थान में शादी से जुड़ी एक प्रथा को लेकर सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में एक युवती द्वारा प्रदेश की मनगढ़ंत रस्म को लेकर बातें की गईं। दुखद है कि उसके विचार समग्र को ठेस पहुंचाने वाले तो थे ही, साथ ही स्त्रियों का अपमान करने वाले भी थे। युवती ने पूरी अभद्रता से साथ यह दावा किया कि राजस्थान में शादी से पहले विवाहिता को ससुर व देवर के साथ संबंध बनाने होते हैं। इसके बाद ही विवाहित महिला पति से संबंध बना सकती है। जबकि समृद्ध रीति-रिवाज के लिए मान पाने वाले देश के इस राज्य में ऐसी कोई प्रथा या यूं कहें कि कुप्रथा प्रचलित नहीं है। अफसोसनाक है कि यह युवती इस वीडियो में यह कहने से भी नहीं चूकी कि विवाहित महिला के लिए गर्भवती होने पर अपना पहला बच्चा गिराना अनिवार्य होता है। मनगढ़ंत बातों की सनसनी फैलाने वाली इन बातों से लोगों में ना केवल भारी नाराजगी पैदा हुई बल्कि ये विचार हर किसी को हैरान-परेशान करने वाले भी रहे। ध्यातव्य है कि राजस्थान में ऐसी कोई परंपरा नहीं है। वहां के स्थानीय लोग भी इस वीडियो को देखकर व्यथित-विचलित हो गए, क्योंकि ऐसे किसी रिवाज के बारे में किसी ने भी कुछ देखा-सुना नहीं है। बाद में राजस्थान पुलिस ने भी युवती के दावे को फेक बताया। अभद्र बातें लिए इस वायरल वीडियो पर राजस्थान पुलिस द्वारा बाकायदा आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए अपने एक्स अकाउंट पर कहा गया कि राज्य में ऐसी कोई परंपरा या रस्म नहीं है। राजस्थान पुलिस ने युवती के दावे को फर्जी बताते हुए लिखा, 'राजस्थान में शादी के बाद पहले ससुर, फिर देवर और फिर पति से संबंध बनाने और पहले बच्चे को गिराने का दावा पूरी तरह फर्जी, झूठा और भ्रामक है। ऐसी कोई परंपरा राजस्थान की संस्कृति में मौजूद नहीं है।' दरअसल, वर्चुअल दुनिया में चल रही कंटेन्ट परोसने की आपाधापी के चलते ऐसी मनगढ़ंत बातों वाले वीडियो हर ओर छाए हुए हैं। रीत-रिवाज से लेकर आध्यात्म और चिकित्सा क्षेत्र से जुड़ी जानकारियों तक को मनचाहे ढंग से साझा करने का यह दुस्साहस अति पार कर रहा है। कभी मज़ाक बनाना तो कभी सनसनी फैलाना ही बहुत से कंटेन्ट क्रियेटर्स का उद्देश्य रह गया है। जबकि ऐसी भ्रामक बातों का जनमानस पर गहरा प्रभाव पड़ता है। लोगों की तीखी प्रतिक्रियाओं और रोष को संभालना मुश्किल हो जाता है।

इतना ही नहीं, बहुत से लोग संस्कृति और सामाजिक व्यवस्था पर सवाल भी उठाने लगते हैं। यही वजह है कि राजस्थान में ऐसा कोई रिवाज होने की बात कहते इस वीडियो को लेकर भी पुलिस द्वारा लोगों से ऐसी अफवाहों और भ्रामक वीडियो पर ध्यान न देने की अपील की गई। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई कि ऐसी फर्जी खबरें फैलाना कानूनन दंडनीय अपराध है। सवाल यह है कि बेवजह बवाल मचाने वाली बातें करने की यह सोच क्यों बढ़ रही है? फेक जानकारियां और भ्रामक सूचनाएं फैलाने का बर्ताव क्यों विस्तार पा रहा है। जिस देश में सचमुच कई तरह की कुप्रथाएं आज भी स्त्रियों की जिंदगी मुश्किल बनाए हुए हैं, वहां ऐसी किसी कुप्रथा से जोड़कर गैर-जिम्मेदाराना बातें करना वाकई अपराध से कम नहीं। हालांकि लाइक, कमेन्ट या व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए कुछ कह देने वाले बाद में अपनी बातों का खंडन भी करते नजर आते हैं। पीड़ादायी यह है कि एक देश हो या कोई राज्य, दायित्वबोध के बिना कही गईं अनुचित-अर्थहीन बातें समग्र समाज को भ्रमित करती है। मान-सम्मान को ठेस पहुंचाती हैं। यह सच है कि सोशल मीडिया मंच आमजन को अपने विचार रखने के लिए मिले हैं। अभिव्यक्ति की स्वतन्त्रता भी हमारे संवैधानिक अधिकारों में शामिल है।कुप्रथाओं पर सवाल उठाना भी उचित है।

अपनी राय देना और किसी विषय पर विमर्श करने को भी देश का हर नागरिक स्वतंत्र है। विचारणीय है तो यह कि सब कुछ कहने की आज़ादी के फेर में निरर्थक बातें ज्यादा होने लगी हैं। इस दुस्साहस के अनगिनत नुकसान हैं।आवश्यक है कि क्लिक भर में संसार के कोने-कोने में पहुंच जाने वाली वर्चुअल सामग्री से जुड़े जोखिमों को समझने का ठहराव बरता जाए। एक बार वायरल हो जाने के बाद सोशल मीडिया मंचों से तस्वीरों, वीडियो या सामग्री को हटाना भी बेहद मुश्किल काम होता है। संयम और मानवीय जिम्मेदारी की सोच के साथ इनका उपयोग किया जाए। साथ ही स्वनुशासन को भूल सीमाओं को लांघकर भ्रामक सूचना फैलाने या आपसी संवाद में आधारहीन बातों को साझा करने वालों को उचित दंड भी दिया जाए।

(लेखिका प्रसिद्ध स्तंभकार हैं, ये उनके अपने विचार हैं।)

हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती है अंतःकरण की आवाज

संकलित
दर्शन

हमारे अंतःकरण की आवाज हमारी मुख्य मार्गदर्शक होती है। यही हमें सही और गलत में अंतर का आभास कराती है। मनोविज्ञान के अनुसार, जब किसी मनुष्य का कोई कार्य, विचार और अभिव्यक्ति नैतिक मूल्यों के विपरीत परिणाम देती है तो अंतर्मन की आवाज उस व्यक्ति में ग्लानि और पश्चाताप की भावना को जन्म देती है, लेकिन जब हमारे कार्य नैतिक मूल्यों के अनुरूप परिणाम देते हैं तो इससे मन भीतर से प्रसन्न होता है। आज के इस कोलाहल भरे समय में हम प्रायः अपने अंतःकरण की आवाज को सुन नहीं पाते या उसे सुनकर उस पर अपेक्षित मनन नहीं करते। यही कारण है कि हम अपने जीवन में भटकाव महसूस करते हैं। महात्मा गांधी तो अंतःकरण की आवाज को ही सर्वोच्च मानते थे। उनके कई निर्णयों का आधार ही अंतःकरण की आवाज थी। इसी कारण गांधीजी सत्य के साथ खड़े रहे। इसीलिए उनके द्वारा किए गए अधिकांश प्रयोग सफल रहे। जीवन में सदैव संतुष्ट एवं प्रसन्न रहने का सरल सा तरीका यही है कि हम अपने अंतःकरण की आवाज सुनें, क्योंकि हमारे अंदर से आने वाली आवाज प्रत्येक परिस्थिति में सही होती है। हम जब कभी भी कुछ गलती या बुरा आचरण कर रहे होते हैं, तब हम अपनी भूल को जानते हैं। हमें कुछ अटपटा सा लगता है। भीतर से आवाज आती है कि यह कार्य उचित नहीं है। यही हमारे अंतःकरण की आवाज होती है। यही आवाज हमें कुछ गलत करने से रोकती है।

जीवन में, सब ईश्वर की दया ही है

संकलित
प्रेरणा

एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था, अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था, संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी। सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया जैसे वह बहुत स्वादिष्ट हो। अमीर सेठ ने पूछाः ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे कैसे खा गये? नौकर बोलाः आप मेरे मालिक है, रोज ही स्वादिष्ट भोजन देते है, अगर एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया, अगर ईश्वर ने इतनी सुख-सम्पदाएँ दी है, और कभी कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना ठीक नहीं।

असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है, सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है अच्छे के लिए ही करता है। हम केवल जीवन में अच्छे व उजले पक्ष को ही देखते हैं। हमें सुख, आराम पसंद है, पर दुख व कष्ट के क्षण आते ही हमारा मन विचलित होने लगता है। जीवन में सुख और दुख दोनों ही पल होते हैं।

अंतर्मन

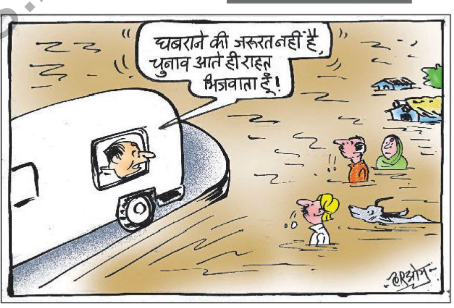

आज की पाती

समाज में शिक्षकों की भूमिका

यद्यपि हिंदी दिवस को हिंदी की तरह ही शिक्षक दिवस को भी शिक्षक के लिए प्रशंसा व महत्वपूर्ण उल्लेखों की बाढ़ आ जाती है, किन्तु शिक्षक की भूमिका समाज में कहीं अधिक सक्रिय, व्यापक तथा जीवंत रहती है और संपूर्ण बरस सामाजिक सोच की रडार के दायरे में रहती है। सर्वप्रथम भारतरत्न से तीन अध्यापकों को पुरस्कृत किया गया था। डा. राधाकृष्णन दार्शनिक शिक्षक, सीवी रमण वैज्ञानिक शिक्षक, राजगोपालाचारी लेखक शिक्षक को 1954 में अलंकृत किया गया उच्चतम सम्मान से। डा. अब्दुल कलाम, राष्ट्रपति-वैज्ञानिक-शिक्षक से पूछा गया कि पुनर्जन्म पर वे क्या बनना चाहेंगे, डा. कलाम का जवाब था एक शिक्षक। अपने भाषण के अंत में वे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने में शिक्षक की महत्ता को प्रतिपादित करते रहे। **-परेश चौहान**, महासमुंद

करंट अफेयर

यूक्रेन संघर्ष ग्लोबल साउथ पर डाल रहा असर : भारत

भारत ने यूक्रेन संघर्ष के 'परोक्ष प्रभावों' खासतौर पर ईंधन की कीमतों पर चिंता व्यक्त की और कहा है कि 'ग्लोबल साउथ' के देशों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। भारत ने साथ ही कहा कि कूटनीतिक प्रयासों के जरिए युद्ध को समाप्त किया जा सकता है और स्थायी शांति लाई जा सकती है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि, राजदूत पर्वतनेनी हरीश ने बृहस्पतिवार को कहा, ''भारत यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है। हमारा मानना है कि निर्दोष लोगों की जान जाना अस्वीकार्य है और युद्ध के मैदान में कोई समाधान नहीं निकलता।'' संयुक्त राष्ट्र महासभा में 'यूक्रेन के कब्जे वाले क्षेत्रों की स्थिति' विषय पर आयोजित चर्चा में हरीश ने कहा कि ''भारत को इस बात की चिंता है कि संघर्ष के परिणामस्वरूप ईंधन की कीमतें और अन्य चीजें पूरे विश्व को प्रभावित कर रहे हैं, विशेष रूप से ग्लोबल साउथ के देशों को, जिन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। हमारा मानना है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी वैध चिंताओं का समुचित समाधान किया जाए।'' 'ग्लोबल साउथ' से तात्पर्य उन देशों से है जिन्हें अक्सर विकासशील, कम विकसित अथवा अविकसित के रूप में जाना जाता है और ये मुख्य रूप से अफ्रीका, एशिया और लातिन अमेरिका में स्थित हैं।

ऑफ बीट

अगर मन बदल जाए तो दिमाग क्या सोचता है

मनोवैज्ञानिक शोध के अनुसार, मन बदलने की प्रक्रिया को समझने के लिए 'मेटाकॉग्निशन' की अवधारणा का उपयोग किया जाता है। सरल शब्दों में, मेटाकॉग्निशन वे मानसिक और जैविक प्रक्रियाएं हैं, जो हमें बताती हैं कि हम किसी कार्य को कितना सही कर रहे हैं-जैसे हमारे भीतर की आवाज़ जो कहती है कि ''कुछ गड़बड़ है'' या ''सब ठीक चल रहा है।''आमतौर पर, जब हमें अपनी पहली पसंद पर भरोसा कम होता है, तब हम मन बदलते हैं। लेकिन शोध से पता चला है कि लोग उतनी बार मन नहीं बदलते जितना कि हम सोचते हैं, भले ही वे अपनी पसंद को लेकर असमंजस में हों। हालांकि, जब लोग अपना मन बदलते हैं, तो अक्सर वे बेहतर निर्णय लेते हैं। इस निर्णय क्षमता को ''मेटाकॉग्निटिव सेंसिटिविटी'' कहा जाता है। शोध में यह भी पाया गया है कि जब लोगों को समय की कमी में निर्णय लेना पड़ता है, तब वे बेहतर ढंग से तय कर पाते हैं कि उन्हें मन बदलना चाहिए या नहीं। मन बदलने से पहले ही दिखने लगती है मस्तिष्क की गतिविधि एक और दिलचस्प सवाल यह है कि हम कब मन बदलते हैं? ज़ाहिर है, यह पहली पसंद के बाद ही हो सकता है। लेकिन प्रयोगशाला में किए गए एक अध्ययन में वैज्ञानिकों ने प्रतिभागियों के मस्तिष्क की गतिविधि को पहली पसंद से पहले ही मापा और कुछ सेकंड पहले ही यह अनुमान लगाया जा सका कि वे मन बदलने वाले हैं।

ट्रेंड

पंजाब में जलप्रलय

पंजाब में जलप्रलय की स्थिति है। फसलें तबाह और बर्बाद हो गई हैं। संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार पंजाब की जनता और किसानों के साथ खड़ी है। पंजाब को इस संकट से बाहर निकालने के लिए अल्पकालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजनाएँ बनानी होंगी।
-शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय कृषि मंत्री

जयंती पर नमन

भारत के पूर्व राष्ट्रपति, महान दार्शनिक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती पर उन्हें सादर नमन। शिक्षक अनुशासन, सम्मान और समानता का पाठ पढ़ाकर विद्यार्थियों का भविष्य संवारते हैं और समाज की मजबूत नींव का निर्माण करते हैं।
- राहुल गांधी, सांसद, कांग्रेस

आपदा में बह गए निर्माण

आपदा रुकने का नाम नहीं ले रही है। हमारे सालों के खून पसीने की कमाई स्वाहा हो रही है। जिंदगी लगाकर जिन घरों को बनाया, जिन सड़कों और पुलों का निर्माण किया आपदा के साथ बह गए।
-जयराम ठाकुर, पूर्व सीएम, हिमाचल प्रदेश

जुनून की परीक्षा

ब्रह्मांड का अपना तरीका है। जुनून जितना ज्यादा होगा, मुश्किलें उतनी ही ज्यादा होंगी। क्योंकि ब्रह्मांड बस आपके जुनून की परीक्षा लेना चाहता है। इसलिए जान लीजिए कि मुश्किलें कब नामुमकिन हैं। ब्रह्मांड आपके साथ है।
- शेखर कपूर, फिल्मकार

अपने विचार
हरिभूमि कार्यालय
टिकरापारा, रायपुर में पत्र के माध्यम से या फैक्स : 0771-42422221 पर या सीधे मेल से **aapkepatra.haribhoomi@gmail.com** पर भेज सकते हैं।

https://t.me/AllNewsPaperPaid1

06 hindi nd-06_page 02.qxd 9/5/2025 6:35 PM Page 1

जीएसटी सुधार

समय रहते उठाया कदम

जीएसटी को बड़े जोर-शोर से लाया गया था, लेकिन जल्द ही यह अपने आप में एक समस्या बन गया। हालांकि पूरे देश में एक समान कर ढांचा लागू करने का यह एक नेक विचार था, लेकिन इसे लागू करने में यह विफल रहा और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में कई समस्याएँ पैदा हुईं। इसके अलावा, इसमें विसंगतियाँ भी थीं और कर-संरचना में भी काफी सुधार की आवश्यकता थी। आखिरकार, सरकार ने अपनी स्थिति को सुधारने के लिए कुछ ठोस कदम उठाए हैं। वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद के हालिया फैसले भारत की कर सुधार यात्रा में एक नया अध्याय जोड़ते हैं। इस सुधार का समय बेहद महत्वपूर्ण है। त्योहारों का मौसम नजदीक आते ही, घरेलू खर्च में आमतौर पर तेजी आ जाती है, जिससे तेज-तर्रार उपभोक्ता वस्तुओं (एफएमसीजी) क्षेत्र और उससे आगे के क्षेत्रों में वृद्धि को बढ़ावा मिलता है। हाल के वर्षों में, सुस्त माँग, मुद्रास्फीति के दबाव और वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता ने भारत की उपभोग की कहानी पर गहरा असर डाला है।

पिछली कुछ तिमाहियों में, मांग में कमी के संकेत स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। बढ़ती लागत और अमेरिकी टैरिफ वृद्धि जैसे वैश्विक व्यापार व्यवधानों के कारण टैरिफ के दबाव ने भारत के निर्यात-उन्मुख और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर भारी असर डाला है। घरेलू स्तर पर, विवेकाधीन उपभोग असमान रहा, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में मांग कम रही। इस पृष्ठभूमि में, साबुन, शैंपू और पैकेज्ड स्नैक्स जैसी जरूरी चीजों पर जीएसटी कम करने से

दो अहम लक्ष्य पूरे होते हैंः घरेलू खर्च कम करना और कंपनियों को बिक्री बढ़ाने का एक कारण देना।

इन सुधारों से उपभोक्ता वस्तुओं की कीमतों में कटौती या उनके ग्रामेज में वृद्धि होने की उम्मीद है, जिससे लाखों परिवारों के लिए रोजमर्रा की जरूरत की चीजें ज्यादा किफायती हो जाएँगी। खास तौर पर बड़े पैक साइज में काफी कमी आने की उम्मीद है, जबकि छोटे पैक बेहतर मूल्य की पेशकश के जरिए लाभ पहुँचा सकते हैं। दवा क्षेत्र को भी काफी फायदा होगा। 33 जीवनरक्षक दवाओं पर जीएसटी 12 प्रतिशत से घटाकर शून्य कर दिया गया है, और तीन गंभीर कैंसर और दुर्लभ बीमारियों के इलाज को भी छूट दी गई है। अन्य दवाओं के लिए, कर 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है। जीएसटी सुधारों का पूरी अर्थव्यवस्था पर कई गुना असर पड़ने की संभावना है। कम कीमतों से उपभोक्ता भावना में सुधार होगा, खासकर ग्रामीण और अर्ध-शहरी भारत में, जहाँ खर्च करने की क्षमता मूल्य परिवर्तनों के प्रति ज्यादा संवेदनशील होती है। नवरात्रि और दिवाली करीब आ रहे हैं, ऐसे में यह सुनिश्चित है कि इसका लाभ सीधे त्योहारी खर्च में प्रवाहित हो, जिससे किराना दुकानों से लेकर बड़ी खुदरा श्रृंखलाओं तक, व्यवसायों को तत्काल बढ़ावा मिले।

वृहद स्तर पर, ये सुधार ₹जीएसटी 2.0₹ की भावना को दशार्ते हैं—कर संरचनाओं को सरल बनाना, वर्गीकरण संबंधी विवादों को कम करना और समावेशी विकास के उद्देश्य के साथ कराधान को संरेखित करना। जीएसटी परिषद के निर्णय भारत के कर ढांचे की विकासशील प्रकृति को रेखांकित करते हैं—उत्तरदायी, व्यावहारिक और आर्थिक वास्तविकताओं के अनुरूप। हालाँकि इस सरकारी उदारता से सरकारी खजाने पर सालाना 1.4 लाख करोड़ रुपये का भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन यह सही दिशा में उठाया गया कदम है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था और आम आदमी का जीवन आसान होगा!

दार्शनिक राष्ट्रपति का शैक्षणिक दर्शन

डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के दर्शन में शिक्षकों को राष्ट्र निर्माण के केंद्र में रखा गया था। एनईपी 2020 उनके इस दृष्टिकोण को जीवंत करता है, शिक्षकों को रचनात्मकता, समावेशिता और समग्र शिक्षा को पोषित करने के लिए स्वायत्तता, संसाधन और मान्यता प्रदान करता है।

सुकांत मजूमदार
लेखक, भारत सरकार में राज्यमंत्री हैं।

हर साल 5 सितंबर को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर, हम भारत में शिक्षकों के प्रयासों, कड़ी मेहनत और योगदान का जश्न मनाते हैं। उनके 137वें जन्मदिन के अवसर पर, यह देखना जरूरी है कि शिक्षा और सीखने के बारे में उनकी गहन अंतर्दृष्टि को राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के माध्यम से व्यवहार में कैसे लाया जा रहा है। और इससे भी बढ़कर, यह नीति शिक्षकों को वह परिवर्तनकारी शक्ति बनने के लिए कैसे सशक्त बनाती है जिसकी उन्होंने हमेशा कल्पना की थी।

1954 में लोकतंत्र और शिक्षा पर लिखते हुए, डॉ. राधाकृष्णन ने घोषणा की, देश की भावी प्रगति सदियों के काम को कुछ दशकों में पूरा करने पर निर्भर करती है। एक नए समाज के निर्माण का अनिवार्य साधन शिक्षा है।₹ इन शब्दों ने शिक्षा के उद्देश्य की एक मौलिक पुनर्कल्पना को चिह्नित किया। डॉ. राधाकृष्णन के लिए, शिक्षा का उद्देश्य कभी भी औद्योगिक अर्थव्यवस्था के लिए श्रमिकों का उत्पादन करना नहीं था; बल्कि अंतर्ज्ञान, करुणा और लोकतांत्रिक भागीदारी में सक्षम पूर्ण मानव का पोषण करना था।

यह दर्शन और दृष्टि एक सरल लेकिन अक्सर उपेक्षित आधार पर आधारित थीः कि सच्ची शिक्षा समझ से उत्पन्न होती है, याद करने से नहीं। अपनी मौलिक पुस्तक, ₹जीवन का एक आदर्शवादी दृष्टिकोण₹ में, उन्होंने केवल सैद्धांतिक बुद्धि के बजाय रचनात्मक अंतर्ज्ञान विकसित करने के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने लिखा, सहज बोध मोक्ष का साधन है... सहज अंतर्दृष्टि स्वतंत्रता के समान है,₹ और सुझाव दिया कि शिक्षा को मन की रचनात्मक क्षमता को मुक्त करना चाहिए, न कि उसे रटने की विद्या से बाधित करना चाहिए।

डॉ. राधाकृष्णन के अनुसार, इस परिवर्तन के मूल में शिक्षक थे। 1953 में पंजाब विश्वविद्यालय में अपने संबोधन में, उन्होंने कहा, ₹हमें यह समझना होगा कि हम अपने बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा प्रदान करते हैं, यह मुख्यतः इस बात पर निर्भर करता है

कि हम किस प्रकार के पुरुष और महिला शिक्षकों को नियुक्त करते हैं।

हालाँकि, स्वतंत्र भारत के इतिहास के अधिकांश समय में, हमारी शिक्षा नीति इन अंतर्दृष्टियों को क्रियान्वित करने के लिए संघर्ष करती रही। जो प्रणाली उभरी, उसने अक्सर रचनात्मक अंतर्ज्ञान और समझ पर यांत्रिक सीखने और रटने को प्राथमिकता दी। शिक्षकों ने खुद को कठोर पाठ्यक्रम, अत्यधिक पाठ्यपुस्तकों और सीमित स्वायत्तता से विवश पाया। डॉ. राधाकृष्णन द्वारा समर्थित समग्र विकास की जगह कठोर विषय सीमाओं ने ले ली, जबकि शिक्षकों को रचनात्मक दिमागों को प्रेरित करने के बजाय निर्धारित पाठ्यपुस्तकों का पालन करने तक सीमित कर दिया गया।

जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने मन की बात में अक्सर कहा है, ₹भारत शिक्षा और ज्ञान की पावन भूमि रही है। हमने शिक्षा को केवल किताबी ज्ञान तक सीमित नहीं रखा है, बल्कि इसे जीवन के एक समग्र अनुभव के रूप में देखा जाना चाहिए।₹

यह समग्र अनुभव राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मूल में है और इस अंतर को पाटने का पहला गंभीर प्रयास है। डॉ. राधाकृष्णन का ₹सहज अंतर्दृष्टि₹ पर जोर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुभवात्मक अधिगम और योग्यता-आधारित शिक्षा पर केंद्रित होने के कारण स्पष्ट होता है, और यह निपुण भारत मिशन से कहीं अधिक स्पष्ट है। शिक्षकों को रटने की शिक्षा तक सीमित रखने के बजाय, निपुण उन्हें शिक्षण/अधिगम प्रक्रिया को आनंदमय, सार्थक और प्रत्येक बच्चे के अनुरूप बनाने की स्वतंत्रता और संसाधन प्रदान करता है। शिक्षकों के पास अब जादुई पिटारा, आकर्षक शिक्षण-अधिगम सामग्री, व्यापक शिक्षक मार्गदर्शिकाएँ और संरचित पाठ कैलेंडर जैसे उपकरण उपलब्ध हैं, जो रचनात्मकता के लिए पर्याप्त जगह छोड़ते हुए योजना को सरल बनाते हैं। यह व्यावसायिक स्वायत्तता शिक्षकों को अपनी शिक्षण शैली में नवाचार करने, नई गतिविधियों के साथ प्रयोग करने तथा अपने विद्यार्थियों की विविध एवं अनूठी आवश्यकताओं के अनुरूप पाठों को अनुकूलित करने की अनुमति देती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों की गुणवत्ता विकसित करने के डॉ. राधाकृष्णन के आह्वान को भी संबोधित किया है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) के माध्यम से, करियर के विभिन्न चरणों में उनकी दक्षताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है

पिछले पांच वर्षों में, शिक्षकों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत निपुण भारत, विद्या प्रवेश और जादुई पिटारा जैसी रचनात्मक सहायता जैसी परिवर्तनकारी पहलों का समर्थन किया है, जिससे मजबूत संज्ञानात्मक नींव रखी गई है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2022 और एकीकृत शिक्षक शिक्षा कार्यक्रमों ने शिक्षकों को अंतःविषय दृष्टिकोण, रचनात्मकता और वैश्विक परिप्रेक्ष्य से समृद्ध किया है।

इसी के आधार पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने शिक्षकों की गुणवत्ता विकसित करने के डॉ. राधाकृष्णन के आह्वान को भी संबोधित किया है। शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय व्यावसायिक मानकों (एनपीएसटी) के माध्यम से, करियर के विभिन्न चरणों में उनकी दक्षताओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है, जिससे शिक्षकों को व्यावसायिक विकास, मूल्यांकन और उन्नति के लिए एक पारदर्शी रोडमैप मिलता है। निष्ठा और दीक्षा जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म शिक्षकों को कभी भी, कहीं भी अपने कौशल को बढ़ाने की अनुमति देते हैं, जिससे उच्च-गुणवत्ता वाली व्यावसायिक शिक्षा तक उनकी पहुँच का विस्तार होता है। ऑनलाइन संसाधनों के अलावा, कई राज्य सरकारों ने वरिष्ठ शिक्षकों के संरक्षक संवर्ग स्थापित किए हैं जो नियमित रूप से कक्षाओं में जाते हैं, शिक्षण का अवलोकन करते हैं और रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करते हैं, जिससे ऐसे समुदायों का निर्माण होता है जहाँ अनुभव और अंतर्दृष्टि साझा और परिष्कृत की जाती हैं।

हमारा मंत्रालय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में प्रौद्योगिकी-सक्षम अनुवाद, भाषा संगम सामग्री और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)-संचालित शिक्षण पोर्टलों के माध्यम से भारतीय और क्षेत्रीय भाषाओं को बढ़ावा देकर शिक्षा में समावेशिता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

एनसीईआरटी और एनआईओएस के साथ एक समझौता ज्ञापन के तहत, भारतीय सांकेतिक भाषा को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, जिससे दिव्यांग बच्चों के लिए समावेशी शिक्षा संभव हो रही है।

3,600 से अधिक स्कूलों का उन्नयन किया गया है, 80,000 से अधिक स्कूलों को नई कक्षाओं के साथ सुदृढ़ किया गया है, और 138,000 स्कूलों को डिजिटल सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है, जो शिक्षकों के अथक प्रयासों से विकसित हुए हैं। पिछले वर्ष 35,000 से अधिक बालिका शौचालयों का निर्माण किया गया, जो प्रतिधारण और गरिमा पर ध्यान केंद्रित करने का एक मौन किन्तु शक्तिशाली प्रमाण है। 2024 में 5.18 करोड़ पौधे लगाने के कार्य में 1.46 लाख इको-क्लबों का नेतृत्व करते हुए, हमारे शिक्षक स्कूली जीवन के मूल में स्थिरता को समाहित कर रहे हैं।

आज की उपलब्धियां, चाहे वह पीएम श्री स्कूलों का विस्तार हो, अटल टिंकरिंग लैब्स को बढ़ावा देना हो, या दीक्षा और स्वयं के माध्यम से डिजिटल शिक्षा को आगे बढ़ाना हो, ये सभी हमारे शिक्षकों की अनुकूलनशीलता और दृढ़ संकल्प की गवाही देती हैं।

कक्षाओं में शिक्षकों को सशक्त बनाना आवश्यक है, लेकिन डॉ. राधाकृष्णन का दृष्टिकोण स्कूल की दीवारों से परे भी फैला हुआ है। इसके लिए व्यापक समाज के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है।

भारत में निर्मित वहनीय व नवाचारी अस्पताल

मेड इन इंडिया अस्पतालों की परिभाषित विशेषता स्वदेशी रूप से निर्मित चिकित्सा उपकरणों, निदान और अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर उनकी निर्भरता होगी।

जितेंद्र शर्मा
लेखक, स्तम्भकार हैं।

आज भारत में स्वास्थ्य सेवा का विरोधाभास बहुत गहरा है। एक ओर, देश दवाइयों और टीकों के क्षेत्र में नवाचार और निर्माण के वैश्विक केंद्र के रूप में उभर रहा है। दूसरी ओर, उन्नत स्वास्थ्य सेवाएँ बड़े पैमाने पर महानगरों में ही केंद्रित हैं। भारत की 70 प्रतिशत से अधिक आबादी टियर-2 टियर-3 शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है, फिर भी उच्च स्तरीय स्वास्थ्य सेवा कैंसर, हृदय रोग या गुर्दे की विफलता जैसी स्थितियों के लिए महत्वपूर्ण अत्यधिक महानगरों पर केंद्रित है। यह शहरी विषमता लाखों परिवारों को देखभाल प्राप्त करने के लिए लंबी दूरी तय करने के लिए मजबूर करती है, अक्सर भारी आर्थिक लागत पर।

इस असंतुलन का समाधान अधिक महानगरीय सुपर-स्पेशलिटी₹ द्वीप बनाने में नहीं, बल्कि मेड इन इंडिया अस्पतालों के निर्माण में निहित है, विश्व स्तरीय लेकिन किफायती संस्थान जो पूरी तरह से स्वदेशी चिकित्सा तकनीकों और बुनियादी ढांचे से संचालित हों। यह दृष्टि आकांक्षात्मक नहीं है; यह कार्यान्वयन योग्य है।

मेड इन इंडिया अस्पतालों की परिभाषित विशेषता स्वदेशी रूप से निर्मित चिकित्सा उपकरणों, निदान और अस्पताल के बुनियादी ढांचे पर उनकी निर्भरता होगी। दशकों से, भारत अपनी 70-80 प्रतिशत चिकित्सा तकनीक का आयात करता रहा है।

एमआरआई और सीटी स्कैनर, सर्जिकल रोबोट या हृदय वाल्व जैसे उच्च-स्तरीय उपकरणों की कीमत विदेशी मुद्रा में तय की गई है, जिससे अस्पतालों और मरीजों, दोनों के लिए लागत में बाधा उत्पन्न हो रही है।

दुनिया के सबसे बड़े एकीकृत चिकित्सा प्रौद्योगिकी पार्क, आंध्र प्रदेश चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र (एएमटीजेड) ने यह दशार्या है कि इस निर्भरता को कैसे तोड़ा जा सकता है। एक आयातित एमआरआई की कीमत कभी लगभग 6 करोड़ थी; आंध्र प्रदेश चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, अब इसे लगभग आधी कीमत पर निर्मित किया जाता है - वैश्विक गुणवत्ता मानकों से समझौता किए बिना। इसी प्रकार, वेंटिलेटर, डायलिसिस मशीनें और हृदय वाल्व स्वदेशी रूप से बनाए जा रहे हैं, जिससे लागत में भारी कमी आई है और साथ ही सुलभता भी सुनिश्चित हुई है।

अस्पतालों को विशेष रूप से ऐसे भारत में निर्मित उपकरणों से लैस करके, विदेशी मुद्रा के बहिर्वाह को समाप्त किया जा सकता है, खरीद लागत को कम किया जा सकता है और वर्तमान मूल्य के एक अंश पर देखभाल भी मुहैया कराई जा सकती है। एक डायलिसिस सत्र जिसकी लागत किसी महानगरीय अस्पताल में 2,500 रुपए हो सकती है, भारत में निर्मित अस्पताल में 800 रुपए में हो सकती है। यह आत्मनिर्भरता की परिवर्तनकारी शक्ति है।

ये अस्पताल न केवल स्वास्थ्य सेवा सुविधाएँ हैं - ये क्षेत्रीय आर्थिक विकास के उत्प्रेरक भी हैं। प्रत्येक अस्पताल सैकड़ों उपकरणों की प्रत्यक्ष मांग उत्पन्न करता हैः सर्जिकल उपकरण, इमेजिंग उपकरण, नैदानिक उपभोग्य वस्तुएं, बिस्तर, मॉनिटर और प्रत्यारोपण। इन्हें घरेलू स्तर पर प्राप्त करके, भारत आंध्र प्रदेश चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र जैसे समूहों और अन्य क्षेत्रों में विनिर्माण को प्रोत्साहित कर सकता है।

एक अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या भारत में निर्मित उपकरण गुणवत्ता के अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों को पूरा कर सकते हैं। इसका उत्तर आंध्र प्रदेश चिकित्सा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में निर्मित कठोर पारिस्थितिकी तंत्र में निहित है। यहां निर्मित उपकरण आईएसओ प्रमाणन, एनएबीएल परीक्षण और सीडीएससीओ अनुमोदन से गुजरते हैं। कई उपकरण पहले ही यूरोप और एशिया के विनियमित बाजारों में निर्यात किए जा चुके हैं, जो साबित करता है कि भारतीय सामर्थ्य वैश्विक गुणवत्ता की कीमत पर नहीं आता है।

इसलिए, भारत में निर्मित अस्पताल ऐसी देखभाल प्रदान करेंगे जो विश्व स्तर पर मानक के अनुरूप हो, फिर भी भारतीय वास्तविकताओं के अनुरूप मूल्यांकित हो। कल्पना कीजिए कि भारत में निर्मित और परीक्षण किया गया एक कार्डियक स्टेंट, एक जिला अस्पताल में अंतर्राष्ट्रीय लागत के एक-चौथाई पर, समान प्रभावकारिता के साथ प्रत्यारोपित किया जाए।

ये अस्पताल भारतीय नवाचारों को अपनाने वाले केंद्रों के रूप में भी काम करेंगे। एएमटीजेड और इसके मेडीवैली इनक्यूबेटर में, स्टार्ट-अप एआई-संचालित डायग्नोस्टिक टूल्स और पहनने योग्य हेल्थ ट्रैकर्स से लेकर रोबोट-सहायता प्राप्त सर्जिकल सिस्टम तक, कई तरह की तकनीकें विकसित कर रहे हैं। दिव्यांगजनों के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाली ट्राइसाइकिल और ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोग के लिए डिजाइन की गई मोबाइल डायलिसिस यूनिट जैसे समावेशी नवाचार भी हैं। इन समाधानों को अस्पताल के वर्कफ़्लो में शामिल करके, हम यह सुनिश्चित करते हैं कि नवाचार केवल प्रयोगशालाओं तक ही नहीं, बल्कि मरीजों तक भी पहुँचे।

मेड इन इंडिया अस्पतालों का आर्थिक प्रभाव कई गुना है। पहला लाभ किफायती स्वदेशी उपकरणों की आपूर्ति के माध्यम से अस्पतालों के निर्माण की कम पूंजीगत लागत है। दूसरा, ये अस्पताल मरीजों के खर्च को कम कर सकते हैं, जिससे परिवारों पर स्वास्थ्य संबंधी अत्यधिक खर्च को रोका जा सकता है। तीसरा, विनिर्माण, स्वास्थ्य सेवा और लॉजिस्टिक्स में स्थानीय रोजगार पैदा होंगे। अंत में, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत एक आयातक से अस्पतालों और उपकरणों का वैश्विक आपूर्तिकर्ता बन जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये स्वास्थ्य सेवा समानता की खाई को पाटते हैं।

किसी तीसरे दर्जे के शहर के कैंसर रोगी को कीमोथेरेपी के लिए 500 किलोमीटर दूर किसी महानगर तक जाने की आवश्यकता नहीं होगी। मेड इन इंडिया अस्पतालों के साथ, देखभाल उनके दरवाजे पर ही पहुंचती है।

मेड इन इंडिया अस्पतालों की अवधारणा केवल आयात कम करने या लागत कम करने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य स्वास्थ्य सेवा वितरण की नई परिकल्पना करना है - हर भारतीय के लिए उन्नत स्वास्थ्य सेवा सुलभ बनाना, रोजगार सृजन करना, विनिर्माण को प्रोत्साहित करना और भारत को स्वास्थ्य सेवा नवाचार में वैश्विक अग्रणी के रूप में स्थापित करना।

आप की बात

जीएसटी गफ़लत दूर हो

सरकार ने व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा पॉलिसी पर जीएसटी शून्य कर दिया है. किन्तु सरकारी/गैरसरकारी कर्मचारी/पेंशनर्स के एम्प्लॉयर्स द्वारा ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी की सुविधा प्राप्त है उनको छूट से अलग रखा है. इसपर अधिकांश ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी होल्डर्स गफलत में पड़ गए हैं. क्योंकि चाहे व्यक्तिगत चिकित्सा बीमा पॉलिसी हो या एम्प्लॉयर्स द्वारा ग्रुप चिकित्सा बीमा पॉलिसी ली जाती है तब बीमा राशि एम्प्लॉयर्स नहीं बल्कि व्यक्तिगत वेतन या पेंशनर्स द्वारा स्वयं के मार्फत ही खरीदी जाती है. मसलन बीमा राशि की किश्त तो व्यक्तिगत रूप से ही वहन की जाती है. तब एम्प्लॉयर्स द्वारा ग्रुप पॉलिसी पर छूट क्यों नहीं और व्यक्तिगत पॉलिसी पर छूट. इसपर बहुत से चिकित्सा बीमा पॉलिसी होल्डर्स गफलत में हैं. अतः सरकार संज्ञान ले और चिकित्सा बीमा चाहे एम्प्लॉयर्स द्वारा अपने कर्मचारी के लिए ग्रुप में कराये या व्यक्तिगत रुप से लोगों/पेंशनर्स द्वारा कराया जाए सब पर समान रूप जीएसटी का लाभ मिलना चाहिए अलग-अलग एक को फायदा दूसरे को नहीं ऐसा क्यों ? क्योंकि इसमें व्यक्तिगत रूप से किसी को जीएसटी की छूट का लाभ मिलेगा तो कोई ग्रुप चिकित्सा पॉलिसी होल्डर्स होगा उससे एम्प्लॉयर्स जीएसटी वसूलेंगे ही. जबकि एम्प्लॉयी/पेंशनर्स का टैक्स भार वे क्यों उठाने लगे।

– **शकुंतला महेश नेनावा**, इंदौर

बारिश का कहर

बारिश हर वर्ष आती है, चली जाती है। कभी वह अपना रौद्र रूप दिखाती है, तो कभी शांत रूप दिखाकर बरखा रानी लौट जाती है। लेकिन इस वर्ष बरखा रानी ने बादल फाड़ जल प्रदाय कर अपना जो रौद्र रूप दिखाया है, वह दिल दहला देने वाला है। यह भारी से भी अति भारी बारिश न केवल इंसानों में दहशत पैदा कर जाती है, लेकिन हमारे समूचे सिस्टम की पोल भी खोल जाती है। इस बार भी बारिश ने जन व माल, जीव जंतु, पेड़ पौधों का इतना नुकसान किया है कि उसका हिसाब किताब भी रखना मुश्किल हो गया है। वह हम सबको तथा सरकार व सिस्टम को चेतावनी भी दे जाती है। लेकिन दुख की बात है कि जिस बारिश व बाढ़ से हम सबको जिन कारणों से नुकसान होता है, बारिश के जाने के बाद उस पर समुचित ध्यान नहीं देते हैं, यानी लापरवाही व अनदेखी की इंतहा ही कही जाएगी। अधिकांश शहरों,कस्बों व गांवों में बारिश व बाढ़ का पानी नुकसान ज्यादा इसलिए करता है कि कि हमने प्राकृतिक जल मार्गों को अपनी लालची प्रवृत्ति से अवरूद्ध करने में कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी है। विकास के नाम पर बेतरतीब ढंग से विकास ने भी गुड़ का गोबर करने का काम किया है। प्रकृति ने जिस तरह से हमें प्राकृतिक रूप से भूमि सौंपी है, उसका सकारात्मक उपयोग न कर, इसका दुरुपयोग ही किया है। यही कारण है कि पानी को जिधर रास्ता मिलता है, उधर रास्ता बनाकर बाढ़ का रूप ले लेता है।

– **हेमा हरि उपाध्याय**, उज्जैन

जीएसटी सुधार से सेहत सुधार

अमेरिका के टैरिफ प्रतिबंध के बाद बेशक विपक्ष सहित कई लोग यह मान बेठे थे कि देश में आम जरूरत की वस्तुओं सहित अमूमन हर चीज के दाम यदि भारत अमेरिका संबंध समय रहते नही सुधरे तो बढ़ सकते हे ! बेकोल भारत सरकार के प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प के अड़ियल रवैये से हैरान जरुर हे किंतु परेशान कतई नही हे ! अमेरिका के भारत के प्रति बदले रुख का फायदा उठाकर चीन भी रूस के सहयोग से भारत को अपने करीब लाने में सफल रहा हे और और प्रधानमंत्री मोदी को बीजिंग बुलाकर राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भारत चीन संबंधो में फिर से प्रगाड़ता लाने का भरोसा दिलाया हे ! बदलते वैश्विक राजनितिक परिदृश्य में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प को चित कर एक बार फिर कूटनीतिक लिहाज से प्रधानमन्त्री मोदी अव्वल ही साबित हुए हे और देश के अंदर ही सरकार विरोधी तमाम विपक्षी दलों को जीएसटी प्रणाली में बड़ा सुधार कर तगड़ा झटका भी दे दिया हे ! बहरहाल वैश्विक अनिश्चितताओं के दोर में जीएसटी कर प्रणाली में बड़ा बदलाव कर देश की जनता को बड़ा आर्थिक तोहफा देना प्रधानमन्त्री नरेंद्र मोदी सरकार का ही जीवटता का कमाल हे ! देश में किसी ने भी यह सोचा तक नही था कि देश की जनता को इतना बड़ा आर्थिक लाभ भी मिल सकता है।

– **अरविंद रावल**, झाबुआ, मप्र

हम शांति प्रिय हैं, शांतिवादी नहीं

चीफ आफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान का कहना है कि भारत एक शांती प्रिय देश है लेकिन हम शांति वादी नहीं है, अतः दुश्मन गलत फहमी में न रहे, कारण देश की सेनाओं को हमेशा ही युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। उनका कहना है कि शक्ति के बिना शांति एक यूरोपियन धारणा है,क्षमा शोभती है उस भुजंग को जिसके पास गरल हो उसको क्या जो दंत हीन विष रहित विनित एवं सरल हो।यह एक लैटिन कोट है जिसका हिन्दी अनुवाद है कि अगर आप शांति चाहते हैं तो युद्ध के लिए तैयार रहें क्योंकि शक्ति से ही शांति आ सकती है। अतः आपरेशन सिंदूर एक न्यू एज वॉर था एवं आज भी हमारा आपरेशन सिंदूर जारी है, क्योंकि हमारा आपरेशन सिंदूर एक आधुनिक संघर्ष था जिससे हमने कई सबक सीखे हैं उनमें से ज्यादातर पर आज अमल चल रहा है। हमारे देश के लिए महाभारत में युद्ध नीति के सबसे बेहतरीन उदाहरण है विशेष करके गीता में फिर हमारे नालंदा के गुरु चाणक्य की नीति चाणक्य नीति कहलाती रही है एवं उसी नीति ने चंद्रगुप्त को विजय दिलाई थी ,अतः कह सकते हैं कि शक्ति उत्साह एवं युक्ती..! ये युद्ध नीति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है फिर शस्त्र एवं शास्त्र को एक साथ फालो करने की जरूरत है, अतः हमारे वर्तमान सीडीएस की बात का अध्धयन जरूरी है।

– **मनमोहन राजावत**, शाजापुर

https://t.me/AllNewsPaperPaid1